

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक
जून 2011

© भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुनःप्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

इस प्रकाशन को इंटरनेट के माध्यम से <http://www.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट की फीडबैक fsu@rbi.org.in पर दी जा सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा जयंत प्रिंटरी,
352/54, गिरगांव रोड, मुरलीधर कम्पाउन्ड, ठाकुरद्वार पोस्ट ऑफिस के पास, मुंबई-400 002 में अभिकल्पित एवं मुद्रित।

विषयवस्तु

	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	
चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची	i से iii
मूल्यांकन और दृष्टिकोण	1
अध्याय I : समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण	7
अध्याय II : वित्तीय बाजार	15
अध्याय III : वित्तीय संस्थाएं	28
अध्याय IV : वित्तीय क्षेत्र नीतियां और बुनियादी सुविधाएं	51
अध्याय V : समष्टिवित्तीय स्ट्रेस टेस्टिंग	70
अनुबंध:	
दबाव परीक्षण कार्यविधाएं	80
बॉक्स की सूची	
2.1 कलन विधि ट्रेडिंग/उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग	26
3.1 क्या हम ऋण धमाके के दौर से गुजर रहे हैं ?	32
3.2 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों में वेतन संशोधन के कारण पेंशन और ग्रैच्युटी संबंधी देयताओं के लिए प्रावधान करना : प्रणालीगत समस्याएं	43
3.3 बीमा क्षेत्र से होने वाले प्रणालीगत जोखिम	48
4.1 बासल III के अधीन पूंजी बफर प्रस्ताव	53
4.2 बैंक सहायक संस्था (सब्सिडियरी) मॉडल और वित्तीय नियंत्रक कंपनी मॉडल	57
4.3 बैंकिंग कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं	59
4.4 भारतीय अंतर-बैंक बाजार का नेटवर्क विश्लेषण - विश्लेषणात्मकता और पद्धति	63
5.1 सीआईएमडीओ - दृष्टिकोण	71
चार्ट की सूची	
1.1 समष्टि आर्थिक जोखिम नक्शा	7
1.2 2011 की वृद्धि की मंदी	8
1.3 यूरोप और अमरीका के पीएमआई	8
1.4 बेरोजगारी दर	8
1.5 वैश्विक असंतुलन	9
1.6 सरकारी शेष और ऋण	9
1.7 विकास के लिए योगदान-आपूर्ति पक्ष	10

1.8	औद्योगिक और पूंजीगत माल उत्पाद	10
1.9	विकास के लिए योगदान-मांग पक्ष	10
1.10	वैश्विक पण्य मूल्य सूचकांक	11
1.11	आवासीय कीमत और आवासीय ऋण	12
1.12	सोने की कीमतों में वृद्धि जारी	12
1.13	तेल व्यापार और मूल्य तथा सीएडी	12
1.14	निवल एफडीआई और पोर्टफोलियो प्रवाह	13
1.15	घाटा और ऋण (केंद्र और राज्य)	13
1.16	कॉर्पोरेट सेक्टर निष्पादन	13
1.17	घरेलू उपभोग और उधार	14
1.18	खुदरा आस्तियों में हानि	14
1.19	आवासीय आस्तियों में हानि	14
2.1	10 वर्षीय बांड प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	15
2.2	उन्नत और उभरते हुए एशियाई मुद्राओं (एडीएक्सवाइ) की तुलना में यूएस डॉलर (डीएक्सवाइ)	15
2.3	फेडरल फंड फ्यूचर्स संविदा के आधार पर दिसंबर 2011 को हुई फेडरल ओपन बाजार समिति बैठक में संघीय कोष लक्ष्य दर की निहित संभावना	16
2.4	स्टॉक सूचकांक (सामान्यीकृत, 1 जुलाई, 2010=100)	16
2.5	अमेरिकी डॉलर/जापानी येन तथा 1महिने की अस्थिरता (प्रतिशत में)	17
2.6	5 वर्ष में अवधिपूर्णता वाले यूरोपीय सर्वोत्तम सी.डी. (आधार अंकों में)	17
2.7	निकट में ऊर्जा का भावी मूल्य (अमेरिकी डॉलर में)	18
2.8	ओपेक क्षमता विरुद्ध वास्तविक उत्पादन और ओपेक कोटा	18
2.9	कमोडिटी मूल्य चलन (सामान्यीकृत, 2 जुलाई 2010 = 100)	19
2.10	विभिन्न आस्तियों के साथ 30 दिनों का रोलिंग कोररिलेशन रॉयटर्स-जैफरीज सीआरई सूचकांक	19
2.11	बैंकिंग प्रणाली की तरलता को प्रभावित करनेवाले कारक	19
2.12	भारत में मुद्रा बाजार की दरें (प्रतिशत में)	20
2.13	भारतीय सर्वोत्तम प्रतिफल वक्र आकार	20
2.14	थोकमूल्य सूचकांक पूर्वानुमान तथा वास्तविक, तथा आरबीआई रिपो दर (प्रतिशत में)	20
2.15	10 वर्ष परिपक्वता में बांड बाजार प्रतिफल (प्रतिशत में)	21
2.16	विदेशी संस्थागत निवेश इक्विटी तथा ऋण दैनिक निवल प्रवाह (अमेरिकी मिलियन डॉलर में) तथा रुपये की विनिमय दर	21
2.17	10-वर्ष में ईसीबी तथा एफसीसीबी प्रवृत्ति तथा ब्याज दर विभेदकों की प्रवृत्ति	22
2.18	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	23
2.19	अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए तथा अमेरिकी डॉलर/सीएनवाई हेतु 6 महीने की परिपक्वता में 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल (प्रतिशत में)	23
2.20	एफसीसीबी का मोचन प्रोफाइल (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	24
2.21	ईक्विटी बाजार में एफआईआई की कुल मासिक खरीद एवं बिक्री (करोड़ ₹ में)	25

2.22	ऋण बाजार में एफआईआई की कुल मासिक खरीद एवं बिक्री (करोड़ ₹ में)	25
2.23	वित्तीय तनाव संकेतक (अगस्त 2011 तक के अनुमान हरे रंग में)	26
3.1	सरकारी निधीयन आवश्यकता	29
3.2	बैंकिंग निधीयन आवश्यकता	29
3.3	चुनिंदा तुलन-पत्र घटकों में वृद्धि	29
3.4	देयताओं में सीडी तथा उधार का अंश	30
3.5	तरल आस्तियों का स्तर	30
3.6	जमाराशियों तथा अग्रिमों का परिपक्वता प्रोफाइल	30
3.7	कुल जमाराशियों में सीडी तथा उधार तथा सीएएसए जमाराशियों का अनुपात	30
3.8	तेजी तथा मंदी की अवधियों में ऋण तथा एनपीए की वृद्धि (प्रतिशत में)	31
3.9	क्रेडिट में वृद्धि, एनपीए और टियर I निधियों की तुलना में उनके विकास की प्रवृत्ति	32
3.10	क्रेडिट वृद्धि की तुलना में उसकी लंबी अवधि की प्रवृत्ति	32
3.11	सकल क्रेडिट में वाणिज्यिक रियल इस्टेट, खुदरा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण का शेयर	33
3.12	संयुक्त एक्सपोजर की वृद्धि (खुदरा, वाणिज्यिक रियल इस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण)	33
3.13	रियल इस्टेट ऋणों में वृद्धि	33
3.14	सकल क्रेडिट में रियल इस्टेट ऋणों का शेयर	34
3.15	रियल इस्टेट एनपीए का अनुपात	34
3.16	सकल अग्रिमों और सकल एनपीए में खुदरा ऋण और उनके एनपीए का शेयर	34
3.17	आवास एवं वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि	35
3.18	खुदरा ऋण एनपीए में वृद्धि	35
3.19	खुदरा ऋण एनपीए का अनुपात	35
3.20	इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण एवं उनके एनपीए में वृद्धि	35
3.21	कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट में मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का शेयर	36
3.22	इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वृद्धि	36
3.23	इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र और बैंक में एनपीए एक्सपोजर का अनुपात	36
3.24	उद्योगों को बैंक ऋण देने का जोखिम वार विभाजन	37
3.25	उच्च जोखिम उद्योगों में बैंक ग्रुप एक्सपोजर	37
3.26	बकाया जोखिम और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एनपीए आस्तियों में वृद्धि	37
3.27	बैंक ग्रुपों के बीच ओबीएस एक्सपोजर में वृद्धि	38
3.28	ओबीएस एक्सपोजर का वितरण	38
3.29	ओबीएस घटकों की संरचना	38
3.30	बैंक ग्रुपों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात	39
3.31	बैंक ग्रुपों का लीवरेज अनुपात	39
3.32	सकल और निवल एनपीए का अनुपात	40

3.33	अग्रिमों और एनपीए की वृद्धि	40
3.34	वर्षों के दौरान स्लिपेज का अनुपात	40
3.35	वर्ग वार एनपीए	41
3.36	बैंक ग्रुपों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)	41
3.37	कुल आय और व्यय के अनुपात में आय और व्यय घटक	41
3.38	आय और व्यय के चुनिंदा घटकों की वृद्धि	42
3.39	निवेशों में व्यापार से लाभ का शेयर और अन्य आय/व्यय में स्टाफ व्यय	42
3.40	लाभप्रदता अनुपात	44
3.41	बैंकिंग स्थिरता नक्शा	45
3.42	बैंकिंग स्थिरता संकेतक	45
3.43	सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सकल एनपीए अनुपात	46
3.44	अनुसूचित यूसीबीयों के चुनिंदा वित्तीय निष्पादन के संकेतक	46
3.45	एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधार राशियां	47
3.46	एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय सुदृढता संकेतक	47
3.47	एनबीएफसी-डी का वित्तीय सुदृढता संकेतक	47
4.1	सीआरएआर अनुमान (2012)	52
4.2	सीआरएआर अनुमान (2013)	52
4.3	जीडीपी में ऋण का अनुपात	54
4.4	जीडीपी में ऋण का अनुपात (सीजन के अनुसार समायोजित)	54
4.5	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	54
4.6	कुल आस्तियों में से ब्याज आय	54
4.7	आस्तियों में से कर पूर्व लाभ	55
4.8	अर्जन पर कीमत (पीई) अनुपात	55
4.9	परिवर्तनीय और दबावग्रस्त रेटिंग आधारित जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि	56
4.10	चार बैंकिंग समूहों के अग्रणी बैंकों का द्विपक्षीय निरूपण	61
4.11	सभी बैंकों का निवल द्विपक्षीय एक्सपोजर	61
4.12	प्रथम बीस बैंकों का निवल द्विपक्षीय एक्सपोजर	61
4.13	एक ट्रिगर बैंक की असफलता का प्रभाव	62
4.14	दो ट्रिगर बैंक की असफलता का प्रभाव	62
4.15	शीर्ष 20 बैंकों की असफलता का प्रभाव (एक बार में एक ही)	63
4.16	दस जोड़ी ट्रिगर बैंक की असफलता का प्रभाव (एक बार में एक जोड़ी ही)	63
4.17	मात्रा में प्रवृत्तियां	64
4.18	मूल्य में प्रवृत्तियां	64
4.19	भारतीय परिदृश्य में अंतर-प्रणाली सहसंबंध	67

4.20	विविध भुगतान एवं निपटान प्रणाली में सामान्य सहभागी	67
5.1	जेपीओडी तथा बीएसआई	72
5.2	अलग-अलग पीओडी तथा जेपीओडी :प्रतिशतता परिवर्तन	72
5.3	टॉक्सिसिटी सूचकांक: बैंकवार	72
5.4	असुरक्षा सूचकांक: बैंकवार	73
5.5	प्रप्राती प्रभाव: बैंकवार	73
5.6	तनाव की स्थिति का अनुरूपण सकल जोखिम संकेतकों की सघनता में परिवर्तन - आस्तियों पर प्रतिलाभ -मार्च 2011	74
5.7	इक्विटी का डयूरेशन - प्रवृत्ति (वाणिज्य बैंक)	74
5.8	इक्विटी का डयूरेशन - बारंबारता वितरण (परिदृश्य I -बचत जमाराशि आहरण -एक माह के भीतर)	75
5.9	इक्विटी का डयूरेशन - बारंबारता वितरण (परिदृश्य II -बचत जमाराशियां आहरण - 3 से 6 माह के भीतर)	75
5.10	बैंकों की चलनिधि स्थिति मार्च 2010 का आधार स्तर और दबाव परिदृश्य	75
5.11	बैंकों की चलनिधि स्थिति मार्च 2011 का आधार स्तर और दबाव परिदृश्य	75
5.12	चलनिधि धारणीयता अनुपात: मार्च 2011	76
5.13	दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत अनुत्पादक अग्रिमों का अनुपात	76
5.14	बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात: दबाव परिदृश्य के अंतर्गत अनुत्पादक आस्तियों से अंतरित	76
5.15	संचित इम्पल्स रिस्पोन्स में घट-बढ़	77
5.16	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का दबाव परीक्षण: पूंजी स्थिति पर आघातों का प्रभाव	78

सारणी की सूची

2.1	रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत ईसीबी (मिलियन अमेरिकी डालर में)	22
2.2	वीएआर ग्रेगर कॉजलिटी	22
2.3	पैरामीटर अनुमान	22
2.4	ईसीबी के उधारदाताओं का प्रोफाइल (मिलियन अमेरिकी डालर में)	23
2.5	भारत में इक्विटी तथा ऋण में दैनिक निवल विदेशी संस्थागत निवेशक प्रवाह हेतु प्रथम तथा द्वितीय चरण में स्वसहसंबंध गुणांक	24
3.1	एससीबी, सीआरएआर और कोर सीआरएआर का वितरण	39
3.2	बैंकिंग स्थिरता नक्शा और बैंकिंग स्थिरता सूचक के निर्माण हेतु संकेतक	44
5.1	पूर्वानुमानित तुलन-पत्र पर तनाव परीक्षण	74
5.2	आधार स्तरीय पूर्वानुमान	76
5.3	दबाव परिदृश्य	76
5.4	दबावयुक्त परिस्थितियों में अनर्जक अग्रिम अनुपात	77

प्राक्कथन

उन्नत तथा विकासशील बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं में विशिष्ट प्रकार से अलग-अलग परिस्थितियां वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए उल्लेखनीय जोखिम पैदा करती हैं। मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता के बीच उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समुत्थान अभी भी निश्चित नहीं है। अमेरिका में, जून 2011 में आर्थिक सहायता का दूसरा दौर समाप्त होगा और उसके बाद के परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता है। जुलाई 2008 के बाद से पहली बार, अप्रैल 2011 में यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दर में वृद्धि की। इसका उद्देश्य यूरोजोन में लगातार बनी हुई मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था। सरकारी जोखिम के संबंध में बढ़ी चिंता, विशेषकर यूरो क्षेत्र में, तथा वित्तीय क्षेत्र में इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण अनिश्चितता और भी बढ़ गयी है। दूसरी ओर, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत देशी मांग, त्वरित ऋण वृद्धि तथा विशाल पूंजीगत प्रवाहों के बीच मुद्रास्फीति चिंता का एक प्रमुख विषय बन गयी है।

स्फीतिकारक दबावों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत ने मौद्रिक नीति को कड़ा करने के लिए सबसे पहले पहल की। मार्च 2010 के बाद से एब्जाप्शन के स्थान पर इंजेक्शन विधि अपनाने के कारण नीतिगत दरों में 400 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। मौद्रिक नीति के संकेतों के अनुसरण में बैंक उधार दरों में वृद्धि हुई क्योंकि क्रमिक रूप से बैंकों ने बढ़ी हुई लागत को पास-ऑन कर दिया। वैश्विक पण्य मूल्य, विशेषकर तेल तथा मानसून का निष्पादन आगामी महीनों में मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में प्रमुख जोखिम है। वर्तमान वर्ष के लिए वृद्धि में कुछ कमी होने की आशंका है। उच्चतर सब्सिडी बिल के रूप में व्यय पर दबावों के कारण राजकोषीय प्रबंधन में और अधिक चुनौतियां हो सकती हैं।

हालांकि 2010-11 के लिए चालू खाता घाटा लगभग 2.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, लेकिन कुछ बाह्य क्षेत्र संकेतक कुछ गिरावट दिखाते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कम रहे हैं, लेकिन निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मजबूत हैं और बाह्य वाणिज्यिक उधार में उल्लेखनीय उछाल आया है। परिणामस्वरूप, बैंकों द्वारा ऋण जोखिम तथा स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा के निधीयन की असुरक्षित स्थितियों पर बैंकों द्वारा लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है।

भारतीय वित्तीय क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है; रिज़र्व बैंक सजग है तथा उसने बैंकिंग प्रणाली की मजबूती में वृद्धि करने के लिए कुछ विवेकपूर्ण तथा समष्टि-विवेकपूर्ण उपाय किये हैं। हालांकि गैर-बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करने का ध्यान लगातार लीवरेज तथा प्रणालीगत परस्पर सम्बद्धता पर केंद्रित है, फिर भी, इस क्षेत्र की आर्थिक भूमिका तथा विविधता तथा हाल ही के अंतरराष्ट्रीय अनुभव को ध्यान में रखते हुए विनियामक ढांचे के कुछ स्थूल सिद्धांतों की व्यापक समीक्षा करना जारी है।

वित्तीय स्थिरता की निरंतर निगरानी करने के लिए एफएसडीसी तथा उसकी उप-समिति के रूप में दो-स्तरीय संस्थागत व्यवस्था प्रारंभ कर दी गयी है। मुख्य एफएसडीसी तथा उसकी उप समिति ने अब तक दो-दो बैठकें की हैं। वित्तीय बाजारों तथा वित्तीय प्रणाली की गतिविधियों का आकलन करने के अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ, विचार-विमर्श में वित्तीय महासंघों की निगरानी के फ्रेमवर्क, विनियामक कमियों को दूर करने तथा अंतर-विनियामक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

रिज़र्व बैंक में, प्रणालीगत जोखिम के विभिन्न स्रोतों का पूरा आकलन करने के लिए वित्तीय स्थिरता विश्लेषण में सुधार लाने के लिए कई प्रकार की पहल की गयी। हालांकि प्रणालीगत जोखिम मापन अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन नेटवर्क एनालिसिस मॉडल तथा बैंकिंग स्थिरता उपायों का प्रयोग करते हुए प्रणाली में कमजोर बिन्दुओं के विश्लेषण के माध्यम से प्रणालीगत परस्पर सूत्रों की पहचान, निगरानी तथा नियंत्रण करने का एक प्रयास किया गया। वित्तीय स्थिरता के लिए सामूहिक विनियामक प्रयासों को दिखाते हुए, इस एफएसआर को तैयार करने में सेबी तथा आईआरडीसी ने अपने-अपने खंड के संबंध में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

वित्तीय स्थिरता को किसी एक नियम आधारित दृष्टिकोण से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। नीति निर्माताओं के लिए प्रयास होना चाहिए - “रूढ़िगत विचारों, कुछेक श्रेणियों तथा पूर्वनिर्धारित कथनों में न उलझा जाए” और हर चीज को ‘एक ही सांचे’¹ में फिट करने का प्रयास न किया जाए।

मुंबई
14 जून 2011

डी.सुब्बाराव
गवर्नर

¹ तालीब, नसीम: “दि बेड ऑफ प्रोक्स्टीज”, रैंडम हाउस।

चयनित संक्षेपाक्षरों की सूची

एडीएफ	संवर्धित डिकी फुली	सीपी	वाणिज्यिक पत्र
एडीएक्सवाई	ब्लूमबर्ग - जे पी मॉर्गन एशिया डॉलर सूचकांक	सीआरएआर	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात
ईईएस	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
एएलएम	परिसंपत्ति देयता प्रबंध	सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
एआरसीएच	स्वतः अवरोही सशर्त असंबद्ध प्रकीर्णन (ऑटो रिग्रेसिव कंडिशनल हिटिरोस्केडैस्टिसिटी)	डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
एआरआईएमए	ऑटो रिग्रेसिव इन्टोग्रेटेड मूविंग एवरेज	डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति	डीआईडीई	संकट निर्भरता
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	डीजेआईए	डो जॉस औद्योगिक औसत
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड	डीओई	इक्विटी के ड्युरेशन
बीओजे	बैंक ऑफ जापान	डीआरएस	पंजीकरण और स्टैप विभाग
बीएसई	मुंबई शेयर बाजार	डीवीपी	सुपुर्दगी बनाम भुगतान
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक	डीएक्सवाई	अमरिकी डॉलर सूचकांक
बीएसएम	बैंक सहायक मॉडल	ईएडी	एक्सपोजर एट डिफाल्ट
बीएसएमडी	बैंकिंग प्रणाली पोर्टफोलियो बहुआयामी घनता	ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार/यूरोपीय केंद्रीय बैंक
सीएडी	चालू खाता घाटा	ईसीएन	इलैक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क
सीएमईएलएस	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, चलनिधि, प्रणाली	ईसीएस	इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली
सीएसए	चालू खाता बचत खाता	ईएम	उभरती बाजार
सीबीएलओ	संपार्श्वकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता	ईएमडीई	उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था
सीबीआरसी	चीनी बैंकिंग विनियामक आयोग	ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
सीबीएस	मूल बैंकिंग समाधान	एफसी	वित्तीय समूह
सीसीए	आकस्मिक दावे विश्लेषण	एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी	एफआई	वित्तीय संस्था
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	एफआईआई	विदेशी संस्थागत निवेशक
सीडीएस	ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप)	एफएमसी	वायदा बाजार आयोग
सीआईएमडीओ	सुसंगत सूचना बहुआयामी अनुकूलन घनता	एफओएमसी	फेडरल खुले बाजार समिति
सीएलआई	समग्र अग्रणी संकेतक	एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
		एफएसएमडी	वित्तीय प्रणाली पोर्टफोलियो बहुआयामी घनता

एफएसआई	वित्तीय दबाव संकेतक	एमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यम
एफएसएलआरसी	वित्तीय क्षेत्र वैधानिक परिवर्तन आयोग	एमटीएम	बाजार मूल्य को बही में अंकित करना (मार्क-टू-मार्केट)
एफएसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
जीएआरसीएच	सामान्यीकृत स्वतः अवरोही सशर्त असंबद्ध प्रकीर्णन (जनरलाईज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडिशनल हिटिरोसेडैस्टिसिटी)	एनबीएफसी-डी	जमाराशियां लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- जमा स्वीकार न करनेवाली- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एनबीएफसी-एसआई	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
एचसीएम	धारित कंपनी मॉडल	एनसीडी	अपरिवर्तनीय डिबेंचर
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित / उच्च आवृत्तित व्यापार	एनईएफटी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
आईबीए	भारतीय बैंक संघ	एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	एनपीए	अनर्जक परिसंपत्ति/अग्रिम
आईडीआरबीटी	बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान	एनआरआई	अनिवासी भारतीय
आईएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सूचना मानक	एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार
आईआईएफ	औद्योगिक वित्त संस्थान	ओबीएस	तुलन पत्र बाह्य (आफ बैलेस शीट)
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक / अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	ओएमओ	खुले बाजार का परिचालन
इन्फिनेट	भारतीय वित्तीय नेटवर्क	ओटीसी	काउंटर पर
आईएनआर	भारतीय रुपया	पी/ई	उपार्जन की तुलना में कीमत का अनुपात
आईआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
आईआरएफ	ब्याज दर फ्यूचर्स	पीसीई	कास्कैडि प्रभाव की संभावना
जेपीओडी	संकट का संयुक्त अनुमान	पीसीआर	प्रावधानन कवरेज अनुपात
एलएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा	पीआईओ	भारतीय मूल के व्यक्ति
एलईआई	दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव	पीआईएस	निवेश संविभाग योजना
एलएसआर	चलनिधि स्थिरता अनुपात	पीएमआई	क्रय प्रबंधकों के सूचकांक
एमएजी	समष्टि आर्थिक मूल्यांकन समूह	पीएमएस	संविभाग प्रबंध सेवा
एमईएनए	मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रिका	पीओडी	संकट का अनुमान
एमएफ	पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड)	पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं	पीएसएस	भुगतान तथा निपटान प्रणाली
एमओयू	सहमति ज्ञापन (समझौता ज्ञापन)	क्यूई	मात्रात्मक सहजता
		आरईआईआर	वास्तविक प्रभावी विनिमय दर
		आरओए	परिसंपत्तियों पर आय

आरओई	इक्विटी पर आय	एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	एसओआर	स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग
आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
आरडब्ल्यूए	जोखिम-भारित परिसंपत्तियां	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एसएंडपी	स्टैंडर्ड एंड पुअर	यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	वीएआर	जोखिम-मूल्य
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	वीएआर	वेक्टर स्वतः पश्चगमन
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	वीआई	भेद्यता सूचकांक
एसआई	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण	वीआईएक्स	उतार चढाव सूचकांक
एसआईएफआई	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था	डब्ल्यूओ	विश्व आर्थिक दृष्टिकोण
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात	डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
एसएलआरआई	प्रणालीगत चलनिधि जोखिम सूचकांक	वाइ-ओ-वाइ	वर्ष-दर-वर्ष

मूल्यांकन और दृष्टिकोण

वैश्विक स्थूल वित्तीय परिवेश में कुछ नाजुक स्थितियां होने के बावजूद भारतीय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता बनी हुई है। वैश्विक असंतुलन और यूरोप में सॉवरेन ऋण संकट के जारी रहने के कारण दुनिया के अधिकतर देशों में संवृद्धि की गति/दर धीमी हुई है। वैश्विक वातावरण में अनिश्चितता और लगातार ऊंची ऊर्जा और पण्य कीमतों ने भारत की संवृद्धि गति को कुछ धीमा करने में भी योगदान दिया है। तथापि, भारत के लिए स्थूल आर्थिक मूलभूत संरचना काफी मजबूत बनी हुई है, इस तथ्य के बावजूद कि मुद्रास्फीति के दबाव और राजकोषीय मामलों में चिंता बनी हुई है।

दिसंबर 2010 में प्रकाशित पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बाद की अवधि में भारतीय वित्तीय बाजार तनाव/दबाव-मुक्त हैं, इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू फर्मों का वित्त के विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों पर भरोसा बढ़ रहा है। विनियामक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, जिसमें समन्वयात्मक पद्धति पर बल दिया जा रहा है, जो कि प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और परंपराओं के अनुस्यू हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है, यद्यपि महत्वपूर्ण ढंग से 'संबंधित' और 'गोलबंद' बैंक इसकी विशेषताएं हैं, बैंकिंग क्षेत्र के ढांचे में कुछ अंतर्भूत जोखिम हैं, जैसाकि नेटवर्क एनालिसिस, जोकि इस एफएसआर में आरंभ की गई नई विश्लेषण तकनीक है, द्वारा बैंकिंग स्थिरता सूचकांक में बैंकिंग क्षेत्र में समग्र सुधार दर्शाया गया है, यद्यपि वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ऋणों में जबरदस्त संवृद्धि लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता में आरंभिक चिंता का संकेत देते हैं। विभिन्न स्थूल वित्तीय तनाव परीक्षण, हाल ही में प्रारंभ परीक्षणों सहित, जो अधिक परिशुद्ध परिकलन पद्धतियों पर आधारित हैं, भी यह दर्शाते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त पूंजी है और इतनी लचीली है कि स्थूल आर्थिक परिदृश्य में आस्ति गुणवत्ता और अन्य संभावित प्रतिकूल बदलावों के झटके सह सकती है।

वैश्विक समष्टि आर्थिक गतिविधियां

**जोखिम परिदृश्य में सुधार के बावजूद संवृद्धि दर धीमी हुई...
किंतु वैश्विक असंतुलन बना हुआ है**

1. पिछले छः माह के दौरान वैश्विक जोखिम परिदृश्य में सुधार आया है, यद्यपि एशिया में कुछ विकासशील देशों सहित अधिकतर देशों में वर्ष 2011 के दौरान संवृद्धि दर धीमी होने के चिह्न हैं। वैश्विक संवृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं: खाद्य, पण्य वस्तुओं तथा ऊर्जा मूल्यों की ऊंची कीमतें, राजकोषीय सुधार की ओर कदम बढ़ाना, यूरोप में सोवरीन ऋण समस्या, तथा कुछ विकसित देशों में सरकारी ऋणों का उच्च स्तर। इसके अलावा, वैश्विक असंतुलन के पीछे मुख्य कारणों पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण वैश्विक सुधार के पथ में अनिश्चितता बढ़ रही है।

सॉवरेन ऋण संकट अन्य क्षेत्रों में फैलने का खतरा है

2. ग्रीस, पुर्तगाल और आयरलैंड जैसे देशों में सोवरीन ऋण संकट ने पूरे यूरोप में स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। अन्य विकसित देशों में सरकारी ऋणों के बढ़ते हुए उच्च स्तर भी राजकोषीय सुधार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता

को बढ़ा रहे हैं। यद्यपि विकासशील बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादा आश्वासक राजकोषीय स्पेस और बेहतर संवृद्धि की संभावनाएं हैं, फिर भी, संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच जटिल आपसी संबंध को देखते हुए राजकोषीय मुद्दे पर अब भी काफी जोखिम बनी हुई है।

घरेलू स्थूल आर्थिक गतिविधियां

राजकोषीय स्थिति और मुद्रास्फीति के प्रबंधन को वरीयता देने के कारण संवृद्धि दर में हल्की गिरावट

3. वैश्विक सुधार की गति धीमी पड़ना, ऊंची तेल और पण्य कीमतें, घरेलू औद्योगिक संवृद्धि में गिरावट, कृषि क्षेत्र में सुदृढ़ संवृद्धि जारी रहने संबंधी साशंकता और मौद्रिक नीति कार्यान्वित करने के असर के कारण वर्ष 2011-12 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कमी का जोखिम है।

आस्ति मूल्य ऊंचे बने रहने के कारण मुद्रास्फीति एक बड़ी चुनौती है

4. वर्ष 2011-12 के दौरान खाद्य, ऊर्जा और पण्य कीमतें महंगी बनी रहना अपेक्षित है। यद्यपि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में कुछ कमी आई है, किंतु इससे मुद्रास्फीति प्रबंधन में कोई मदद नहीं

मिलेगी, क्योंकि पहले की वृद्धि का ही पूरा प्रभाव अभी देखना बाकी है। सरकारी सब्सिडी पर और अधिक व्यय तथा मजदूरी और कच्चे माल की कीमतों बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ने की संभावना है। मकानों की/आवासीय कीमतों में कुछ सुधार हुआ है, किंतु वे अब भी मजबूत बनी हुई हैं। जोरदार मांग के चलते सोने की कीमत भी लगातार बढ़ रही है।

चालू खाता घाटा पर दबाव बना रहेगा

5. भारत के निर्यात में हाल की संवृद्धि के कारण बढ़ी हुई तेल और पण्य कीमतों की वजह से आयात बिल में प्रत्याशित वृद्धि को आंशिक रूप से ही सही, संतुलित किया जा सकेगा। सीएडी के वित्तीयन के लिए कोई आसन्न दबाव दिखाई तो नहीं देता, फिर भी, चूंकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं समायोजक मौद्रिक नीति से बाहर हैं, इसलिए आगे चल कर पूंजीगत अंतर्प्रवाह में कमी आ सकती है।

राजकोषीय समेकन/एकीकरण की गुणवत्ता और गति चिंता का विषय बना रहेगा

6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंची तल और पण्य कीमतों के मद्देनजर वर्ष 2011-12 में घाटे का बजट प्रावधान बनाने पर काफी दबाव रहेगा। सरकारी व्यय, विशेषतः सब्सिडी बिल का प्रबंध राजकोषीय समेकन/सुधार के लिए काफी चुनौतियां खड़ी करेगा। एक कड़ी संवृद्धि, जिससे राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, के कारण यह चुनौती अधिक सुस्पष्ट होगी।

वित्तीय बाजार

वैश्विक और घरेलू स्तर पर वित्तीय बाजारों की स्थिरता में सुधार

7. जापान में भूकंप और लीबिया तथा मध्य-पूर्व और उत्तर अफ्रीका (एमईएनए) में राजनैतिक तनाव के कारण अत्यधिक अस्थिरता के एक छोटे से दौर से गुजरने के बाद पिछले छः महीनों के दौरान वैश्विक वित्तीय बाजार लचीले बने हुए हैं। भारत के लिए वित्तीय तनाव सूचकांक (एफएसआई) का पूर्वानुमानित मूल्य, जो विभिन्न बाजार खण्डों में तथा बैंकिंग क्षेत्र में समसामयिक गतिविधियों की गंभीरता को नापने/जोखने का मापक है, निकट भविष्य में अनुकूल स्थितियों का संकेत देता है।

सॉवरेन ऋण संकट संस्थाओं और बाजारों को प्रभावित कर सकता है

8. सोवेरीन ऋण संकट के कारण कुछ अपेक्षाकृत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने का खतरा हो गया है। इस तथ्य के बावजूद कि यूएस, यूके और जापान जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं

में घाटे और ऋण के उच्च स्तर के कारण उनके सोवेरीन रेटिंग दृष्टिकोण में और अधिक दबाव ला सकती हैं। इस देशों में निम्न संवृद्धि दर के साथ उच्च ऋण स्तर के कारण बाजार के रूझान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि सोवेरीन जोखिम संबंधी चिंता जारी रही तो इससे तुलन-पत्र पर विपरीत/नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विनियामक परिवर्तन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाएं नई पूंजी लाएं, इसके बावजूद कि ऐसे समय, जबकि एईज में सोवेरीन्स ने बड़े ऋण लेने की तैयारी की है, उन्हें पुनर्वित्त में अड़चन आ सकती है।

पण्य बाजारों में बढ़ते वित्तीयन के कारण आस्ति-सहसंबंध स्थापित होना

9. ईएमईज में अनवरत मांग और संवृद्धि के कारण पण्य कीमतों में सुदृढ़ वेग बना हुआ है, किंतु पण्य बाजारों के बढ़ते वित्तीयन के कारण पण्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके फलस्वरूप वित्तीय और पण्य बाजारों में सह-संबंध बढ़ने की संभावना है, जिससे बाजारों में भय/आघात/झटकों का तेजी से प्रसार होगा।

घरेलू बाजार बिना किसी दबाव के चल रहे हैं, जबकि बैंकिंग प्रणाली के लिए चलनिधि की स्थिति तंग बनी हुई है

10. चालू वित्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के पास सरकार के नकदी शेष में तेज घुमजाव/बदलाव के बावजूद प्रणाली में चलनिधि कम रही, जिससे अर्थव्यवस्था में नकदी की मांग/आवश्यकता में वृद्धि परिलक्षित होती है। यह वृद्धि मुख्यतः मजबूत ऋण मांग तथा अत्यधिक मात्रा में मुद्रा प्रचलन में होने के कारण है। तथापि, ओवरनाइट कॉल दरें एक दायरे के भीतर रही हैं। संपार्श्विकीकृत बाजार अब भी मुद्रा बाजार का प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। सभी परिपक्वता वाले सरकारी बांड से प्रतिफल सख्त हुए हैं। यह वृद्धि लघु अवधि में ज्यादा सुस्पष्ट है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिफल की वक्र रेखा सपाट/सीधी हो गई है। स्पया एक दायरे/सीमा के भीतर रहा है, जिससे इस अवधि के दौरान एक अपेक्षाकृत संतुलित बाह्य/विदेशी खाता परिलक्षित होता है और यूएस डॉलर को सामान्यतः कमजोर अनुभव किया है।

विदेशी धन पर भारतीय फर्मों की निर्भरता का बढ़ना मुद्रा असंतुलन पैदा कर रहा है...

11. पिछले कुछ वर्षों में निधीयन के वैकल्पिक स्रोतों/चैनलों की उपलब्धता के कारण फर्मों की घरेलू बैंक ऋणों पर निर्भरता घटी है। बढ़ते घरेलू प्रतिफल/आय के कारण ब्याज दर अंतर बनाम एईज बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)

के लिए भारतीय फर्मों की पहुंच बढ़ी है। इस प्रवृत्ति के कारण उनके तुलनपत्रों में असंतुलन बढ़ा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र का मुद्रा जोखिम एक्सपोजर बढ़ा है, साथ ही, निवल देयताएं स्थिति भी बढ़ी हैं। इसका मतलब यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में रूपांतरण जोखिम भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण उत्पन्न होगी।

....एफसीसीबी की परिपक्वता के कारण कंपनियों के पुनर्वित्त का जोखिम बढ़ा

12. वर्ष 2005 से 2008 तक की अवधि के दौरान अनेक भारतीय कंपनियों ने विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के माध्यम से बढ़े हुए परिवर्तन/रूपांतरण प्रीमियम के साथ बड़ी रकमें इकट्ठा कीं। उनमें से अधिकांश मार्च 2013 में परिपक्व हो जाएंगी। अनुमान दर्शाते हैं कि इन एफसीसीबी का एक बड़ा भाग इक्विटी में रूपांतरित नहीं होगा, और इसप्रकार उसके लिए वर्तमान में लागू उच्चतर ब्याजदरों पर पुनर्वित्त की आवश्यकता होगी।

पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह - भेड़चाल का सबूत

13. वर्ष 2010 के दौरान भारतीय पूंजी बाजारों में निवल पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह में बहुत बड़ी राशि प्राप्त हुई। इन प्रवाहों की प्रवृत्ति काफी अस्थिर है, यद्यपि घरेलू स्थूल आर्थिक परिस्थितियों में उनका अब तक सीमित प्रभाव रहा है। एफसीसीबी विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पैसा बाहर ले जाने के कारण भारत के इक्विटी बाजार में कुछ अवसान/उतार देखा गया है, जबकि बांड बाजार में आकर्षक प्रतिफल और हाल ही में कॉर्पोरेट और सरकारी बांडों में एफआईआई निवेश की सीमा एक आंतरिक अध्ययन ने पोर्टफोलियो पूंजीप्रवाह को स्व-सहसंबंधित बताया है और इसप्रकार अच्छे और तनावपूर्ण, दोनों ही समयों में भेड़चाल को स्वाभाविक बताया है।

भारतीय स्टॉक बाजार में प्रोग्राम ट्रेडिंग प्रणाली

14. एल्गोरिथमिक व्यापार तथा उच्च आवृत्ति व्यापार (Algorithmic trading and high frequency trading) (एचएफटी) बाजारों की कुशलता और चलनिधि को बढ़ाता है, किंतु कुछ जोखिम भी साथ लाता है। भूतकाल में भारतीय प्रतिभूति बाजार ने बिना किसी बड़े विघ्न के प्रणालीगत घटनाओं को सह लिया है। अब जबकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग (एसओआर) जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, यूएस इक्विटी बाजार में मई 2010 में देखी गई प्लैश क्रैश जैसी घटनाओं के प्रति चौकन्ने रहने की आवश्यकता है।

वित्तीय संस्थाएं

बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा स्वास्थ्य और जबरदस्त ऋण संवृद्धि अतिसंवेदनशीलता की ओर संकेत करते हैं

15. वर्ष 2010-11 में आर्थिक संवृद्धि में सुधार के साथ ही मजबूत ऋण संवृद्धि हुई है और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में थोड़ी कमी आई है। 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंकिंग क्षेत्र का तुलन-पत्र 19 प्रतिशत से बढ़ा है, जो ऋण उठान में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि से चालित है। जमा-संग्रहण में लगभग 18 प्रतिशत वृद्धि ऋण संवृद्धि के साथ गति बनाए नहीं रख सकी और इस दरार/खाई को बाजार उधार के बढ़े हुए भाग से भरा/पाटा गया। उधार ली गई निधियों पर बढ़ती निर्भरता ने बैंक की चलनिधि स्थिति के प्रति चिंता बढ़ाई, जो कि कुल आस्तियों में चल/नकद आस्तियों के भाग में कमी के साथ बढ़ते हुए परिपक्वता बेमेलपन के कारण उत्पन्न हुई।

आस्तिगुणवत्ता में सुधार के बावजूद कुछ क्षेत्रों में ऋणों में अव्यवस्थित संवृद्धि के कारण यह चिंता का विषय है

16. आस्ति गुणवत्ता में सुधार मुख्यतः ऋण-संवृद्धि के बाद आया है, जिसने एनपीए की वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। बैंकों द्वारा उनके तुलन-पत्र को सुधारने के लिए एनपीए को बट्टे-खाते डालने के कारण भी सकल एनपीए अनुपात कम होने में सहायता मिली है। काफी वैविध्यपूर्ण ऋण संविभाग/पोर्टफोलियो होने के बावजूद तीन क्षेत्रों में ऋण संवृद्धि गैरआनुपातिक रूप से ऊंची रही है - रिटेल, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और आधारभूत संरचनाएं। चूंकि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट आस्ति गुणवत्ता समस्याएं हैं, वर्ष 2010-11 में देखी गई तेज संवृद्धि कुछ चिंताएं जगाती हैं। प्राथमिकता क्षेत्र के उधार, विशेषतः कृषि, में आस्ति गुणवत्ता समग्र आस्ति गुणवत्ता की तुलना में ज्यादा तेजी से गिरी है, जो कि चिंता का विषय है।

पूंजी के जोखिम भारत आस्ति अनुपात में अत्यल्प कमी के बावजूद बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है

17. मार्च 2011 के अंत में बासल II मानदंडों के तहत प्रणाली स्तर का सीआरएआर 14.3 प्रतिशत पर रहा, जो विनियामक न्यूनतम 9 प्रतिशत से काफी अधिक था। तथापि मार्च 2010 के अंत में बहुत बड़ी मात्रा में ऋण लिए जाने के कारण 14.5 के सीआरएआर में हल्की गिरावट आई। सभी बैंकों के समूह का

सीआरएआर मार्च 2011 के अंत में बासल II मानदंडों के तहत 12 प्रतिशत से ऊपर रहा।

मजबूत निवल ब्याज आय द्वारा लाभप्रदता

18. करीब-करीब स्थिर ब्याज रहित आय और जोखिम प्रावधानों में वृद्धि के बावजूद, एनआइआइ में वृद्धि के कारण बैंकिंग प्रणाली के समग्र निवल लाभ में लगभग 20 प्रतिशत की संवृद्धि हो पाई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लाभ में निम्न संवृद्धि दर्ज की मुख्यतः व्यापारिक लाभों में कमी, स्टाफ व्यय (पेंशन देयताओं संबंधी व्यय सहित) प्रावधानों तथा अनर्जक आस्तियों के प्रति वृद्धि के कारण। ब्याज दर में वृद्धि तथा निधियों की लागत में होने वाली वृद्धि के साथ बढ़ते हुए ऋण संवृद्धि धीमी होना अपेक्षित है जो लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। बचत खातों की ब्याज दर में वृद्धि, पेंशन देयताओं का परिशोधन तथा अनर्जक आस्तियों हेतु सशक्त रूप से बढ़ाए गए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं भी लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती हैं।

विदेशी बैंकों के तुलन-पत्र से इतर एक्सपोजर में और अधिक तेजी

19. पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में डेरिवेटिव्स के प्रयोग में विदेशी बैंकों की उच्च स्तरीय गतिविधि / सहभागिता के बारे में उल्लेख किया गया था। इस वर्ष के दौरान यही प्रवृत्ति जारी रही। डेरिवेटिव एक्सपोजर के समकक्ष ऋण कम रहा तथा तुलन पत्र के आकार के अनुपात में, ऐसे एक्सपोजर की अनुमानित राशि से अधिक होने के बावजूद, कम होती हुई प्रवृत्ति दर्शाई। डेरिवेटिव सौदों में, विशेष रूप से काउंटर पर कारोबारों (ओटीसी) में अन्य वाणिज्य बैंकों के साथ विदेशी बैंकों के सौदे जिनका अभिप्राय प्रणालीगत है, शामिल हैं। अतः विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक है।

बीमा क्षेत्र का प्रणालीगत महत्व

20. उदारीकरण के बाद दशक में बीमा क्षेत्र की तेज संवृद्धि ने इस क्षेत्र के महत्व को, मुख्य रूप से इस क्षेत्र की अन्य वित्तीय संस्थाओं से बढ़ती हुई अन्तर-सहलग्नता के कारण, और अधिक बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र के समक्ष, गतिविधियों का वास्तविक स्वरूप होने के कारण शोध क्षमता, निवेश वापसी, आर्थिक गिरावट और 'निरन्तरता' से संबंधित मुद्दे आते हैं, हालांकि सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि प्रणालीगत जोखिम में इस क्षेत्र का अंशदान बैंकों की तुलना में कम है।

विनियामक परिवेश

विनियामक ढाँचे को मजबूत करना - वित्तीय स्थिरता के लिए समन्वित निगरानी

21. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना सभी विनियामकों और सरकार के बीच सहयोग के लिए संस्थागत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए की गई। एफएसडीसी को रिज़र्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एक उप समिति द्वारा सहायता दी जाती है, जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह शान्ति के समय वित्तीय स्थिरता के लिए एफएसडीसी के साथ व्यापक सहायक संस्था तथा संकट के समय में अहम भूमिका निभाए।

बैंकिंग विधान के लिए प्रस्तावित संशोधन नियामक संरचना को मजबूत बनायेगा

22. बैंकिंग क्षेत्र विधान के लिए संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं ताकि नियामक संरचना को मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके जिससे पूंजी बाजार तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पहुँच आसान हो सके। इसके साथ ही, वित्तीय क्षेत्र कानून सुधार (एफएसएलआरसी), वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को सुधारने के लिए स्थापित किया गया है।

बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के साथ कार्यान्वयन की समस्याएं बनी हुई हैं

23. फिलहाल, भारतीय बैंक कुल मिलाकर पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं। बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण के प्रति प्रगति कुछ चुनौतियों के बीच स्थिर बनी हुई है। माइग्रेसन के लिए मुख्य कार्यान्वयन मुद्दे, जोखिम की मात्रात्मकता और मॉडलिंग हेतु डाटा, उपकरणों, तरीके और आवश्यक कौशल की कमी से संबंधित है।

बासल III के लिए डाटा और विश्लेषणात्मक अपेक्षाएं चुनौतीपूर्ण होंगी...

24. चूंकि वर्ष 2013 से बासल III उपायों की अवधि शुरू हो रही है, बैंकों को संशोधित तरलता ढाँचे के लिए डाटा और विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं की बढ़ती मांग के लिए स्वयं को एकजुट होना पड़ेगा। पूंजी संबंधी स्थिति हालाँकि अच्छी है लेकिन कुछ एकल बैंकों को पूंजी लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है जिससे कुछ मुश्किलें आ सकती हैं यदि शेयर बाजार का सुस्त कार्य-निष्पादन बना रहता है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आइएफआरएस) की ओर जाने पर 1 अप्रैल 2013 तक पेंशन देयताओं के आमेलित किये जाने वाले अपरिशोधित हिस्से के कारण बैंक की पूंजीगत आवश्यकताएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

...प्रति - चक्रीय बर्फस का सम्यक् निर्धारण भी सहायक होगा

25. बासल III के अंतर्गत प्रस्तावित प्रति -चक्रीय सुरक्षा के अंशशोधन को सही मूल्यांकन की आवश्यकता होगी कि क्या ऋण संवृद्धि अत्यधिक है और / या यह प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है। सामान्यतः प्रयुक्त संकेतकों जिसमें जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात शामिल है, भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। सुरक्षा (बफर) लागू करने का समय या उसे हटाने की आवश्यकता के आकलन करने हेतु गुणात्मक निर्णय और मात्रात्मक संकेतकों का संयोजन उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

वित्तीय समूहों हेतु पर्यवेक्षी ढांचे को बढ़ाया जा रहा है

26. देश में बड़े और जटिल वित्तीय संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में सुधार लाने का कार्य जारी है। एफसी की पहचान के मानदंडों को सुदृढ़ किया गया है तथा सामूहिक जोखिम प्रोफाइल को सुधारने हेतु एक संशोधित ऑफसाइट रिपोर्टिंग प्रासूप शुरू किया गया है। कोर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा और प्रबंधन पर दिशा-निर्देश / अंतर-समूह लेन-देनों और एक्सपोजर से उत्पन्न जोखिमों की निगरानी को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

...भारत के लिए एक वित्तीय होल्डिंग कंपनी मॉडल पर चर्चा शुरू होने के बावजूद...

27. रिजर्व बैंक के एक कार्यदल ने सिफारिश की है कि वित्तीय होल्डिंग मॉडल भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए पसंदीदा मॉडल के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तथापि, रिजर्व बैंक के नियमन के तहत ऐसी कंपनियों के लिए एक इष्टतम संरचना को विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ विचार विमर्श के माध्यम से आवश्यक विधेयक और अन्य परिवर्तन आवश्यक होंगे।

चूंकि क्षेत्र की संस्थाएं काफी अंतरसहलग्न रहती हैं; एनबीएफसी के लिए नियामक ढांचे में अंतराल वही रहा है

28. कई एनबीएफसी जो दोनों, बाजार और बैंकों से उधार ले रही हैं, उनमें ओवरलीवरेज होने की क्षमता है और चूंकि वे गहराई से अंतर सहलग्न हैं, वे प्रणालीगत जोखिम उठा सकते हैं। ऐसी संस्थाओं के लिए, विभिन्न नियामकों के दायरे में आनेवाली एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्र के साथ-साथ नियामक आवश्यकताओं में अंतर के कारण नियामक अंतरपणन की गुंजाइश रहती है। नियामक परिधि में अंतराल और कमजोरियां रहती हैं - धन प्रबंधन गतिविधियां, संरचित उत्पादों, वैकल्पिक निवेश निधि जैसे हेज निधि, पीई निधि आदि जिस पर ध्यान देना जरूरी है। गत वर्षों में सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी का प्रणालीगत महत्व बढ़ा है और ऐसी संस्थाओं के लिए नियामक ढांचे की पुनः जांच की जा रही है।

सहकारी सोसाइटियों को किसी नियामक दायरे के बाहर धन जुटाने की अनुमति प्रदान करने के विनियमन में अंतराल पर ध्यान देना

29. देश की नियामक व्यवस्था में कमियाँ सहकारी सोसाइटियों को बिना किसी विवेकपूर्ण ढांचे के सदस्यों से जमा जुटाने और बाहरी स्रोतों से निधि जुटाने की अनुमति देता है। इन संस्थाओं द्वारा विशेषकर बाहरी स्रोतों से निधि जुटाने के मामलों के पूरे गेमट की जांच करना आवश्यक है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का एक विश्लेषणात्मक पूर्वानुमान अंतरसंपर्क की महत्वपूर्ण अवस्था दर्शाता है

30. भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क के आकलन हेतु एक विश्लेषणात्मक ढांचे से यह पता चलता है कि यह प्रणाली काफी जुड़ी और सामूहिक है। किसी भी प्रणाली में बैंकिंग प्रणाली की इस प्रकार का अंतरसहलग्न स्वरूप उसे एक या एक से अधिक बैंकों की विफलता के मामले में डोमिनो प्रभाव से दोषपूर्ण बना सकता है। जबकि कन्टेजियन प्रभाव अंतर बैंक एक्सपोजर पर नियामक सीमाओं के कारण अपेक्षाकृत निहित है, वित्तीय प्रणाली में अंतर सहलग्नता की लगातार निगरानी की आवश्यकता बनी हुई है ताकि जोखिम के कारण / प्रणाली में आधिक्य पहचानने तथा नीतिगत कार्रवाई को मार्गदर्शन देने पर ध्यान दिया जा सके।

वित्तीय बाजार संरचना

भुगतान और निपटान प्रणाली - मजबूत कामकाज... परन्तु अंतरनिर्भरता से दोषपूर्णता की निगरानी आवश्यक...

31. भारत में भुगतान और निपटान संरचना का परिचालनात्मक कार्यनिष्पादन मजबूत है हालाँकि भुगतान और निपटान प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में शामिल प्रणालियों, प्रक्रियाओं और संस्थानों के बीच उच्चतम एकीकरण और अंतर -संबंधों से दोष उभर सकते हैं। ऐसी अंतरनिर्भरता से उत्पन्न सहक्रियाओं के लाभ के साथ - साथ जोखिम भी होता है जबकि ऋण पर स्ट्रेस / एक क्षेत्र में तरलता पहलू / संस्थान / प्रक्रिया, क्रास सहलग्नता के कारण निपटान प्रणाली के अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है।

केन्द्रीय प्रतिपक्षों के तरलता जोखिम के प्रबंधन में दोषपूर्णता पर ध्यान देना आवश्यक

32. सीसीपी द्वारा अभिमुख तरलता प्रबंधन के जोखिम से यह अनिवार्य हो जाता है कि संपार्श्विक की गुणवत्ता और सीमा, मार्जिन की मात्रा और मॉडल जोखिम से उत्पन्न दोषपूर्णता पर ध्यान दिया जाए। भारतीय संदर्भ में दोषपूर्णता है जो बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजरों

और निपटान प्रणाली (भारतीय समाशोधन कोर्पोरेशन लि. अर्थात् सीसिल के मामले में) को समाप्त करने हेतु वित्तीय संस्थानों से निधियों और प्रतिभूतियों की बेक-अप तरलता पर निर्भरता से उत्पन्न होता है चूंकि संपार्श्विक बैंक जमा, बैंक गारंटी आदि के रूप में स्वीकार की जाती है (अन्य सीसीपी के मामले में)। एक सीसीपी की विफलता का जोखिम, जिसकी संभावना नहीं हो पर ध्यान देना आवश्यक है बशर्ते ऐसी घटना से संभावित संपार्श्विक नुकसान हुआ हो।

भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाज़ार हेतु मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्था को लिवरेज की आवश्यकता

33. भारत में ओटीसी बाज़ार अपने विषम भागीदारी संरचना के साथ मानकीकरण और केन्द्रीय समाशोधन की शुल्कात की ओर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जबकि कुछ क्षेत्रों को कम मात्रा का सामना करना पड़ रहा है जिससे इन बाज़ारों के लिए गारंटी समाशोधन करना मुश्किल हो रहा है। ओटीसी बाज़ार के लिए मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्था में विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, सरकारी प्रतिभूतियां, कंपनी बांडों और मुद्रा बाज़ार लिखतें सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हुए, सीसीआइएल की मौजूदा रिपोर्टिंग व्यवस्थाओं के समेकन और निर्माण की आवश्यकता है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सीसीआइएल से उत्पन्न हो रहे गवरनेंस मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में जमा बीमा प्रणाली के व्यापक मुद्दे प्रासंगिक बने हुए हैं

34. जमा बीमा निधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति की समय-सीमा को घटाना, जमा बीमा प्रणाली के कवरेज को सुधारना और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) के मेंडेट को व्यापक बनाना, देश में जमा बीमा प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना है। एक कार्यदल मामलों की समीक्षा कर रहा है।

तनाव परीक्षण

हालांकि लाभप्रदता प्रभावित हुई, पूंजी पर्याप्तता में लचीलापन बरकरार है

35. पिछले एफएसआर में इस्तेमाल की गई तकनीक में दो नए स्ट्रेस परीक्षण उपकरण जोड़े गए। इनमें से प्रथम है : संकट निर्भरता के विभिन्न कांभिनेशन से वित्तीय स्थिरता विश्लेषण करने के लिए बैंकिंग प्रणाली की पोर्टफोलियो बहुभिन्नस्वी घनत्व (बीएसएमडी) दृष्टिकोण के रूप में बैंकिंग स्थिरता उपायों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संकट के समय प्रणालीगत जोखिम एकल जोखिम से अधिक तेजी से बढ़ता है। दूसरा उपकरण, वेक्टर आटोरिग्रेशन (वीएआर) दृष्टिकोण जो विभिन्न मेक्रो आर्थिक झटके पर बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन को पहचानने के लिए मेक्रो आर्थिक वेरयेबल्स और बैंक स्थिरता वेरयेबल्स के बीच अंतःक्रिया ग्रहण करके यह दर्शाता है कि बैंकों के स्लीपेज अनुपात पर ब्याज दर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव (नकारात्मक) था।

36. ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम और तरलता जोखिम के संबंध में स्ट्रेस परीक्षण के माध्यम से वाणिज्य बैंकों के प्रस्तावित तुलन-पत्रों के लचीलेपन का अध्ययन किया गया। एनपीए झटकों पर आधारित स्ट्रेस परिस्थितियों के अंतर्गत यह देखा गया कि बैंकों की लाभप्रदता उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित हो रही थी हालांकि पूंजी पर्याप्तता की स्थिति काफी लचीली दिखाई दी। अध्ययन ये यह पता चलता है कि कुछ बैंक, गंभीर स्ट्रेस परिदृश्य के अंतर्गत चरम तरलता की कमी का सामना कर सकते हैं। कुल मिलकर, विभिन्न परिदृश्यों का उपयोग करके मेक्रो -स्ट्रेस से यह सुझाव प्राप्त होता है कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा मौजूदा मुद्रास्फिति और ब्याज दर की स्थिति से बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की उम्मीद है इसके बावजूद बैंकिंग क्षेत्र मेक्रो आर्थिक झटके झलने हेतु सक्षम होगा।

अध्याय I

समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण

वैश्विक स्तर पर समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार के कारण वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों में कुछ कमी आई है। तथापि अभी भी बड़ा जोखिम टला नहीं है। यूरो क्षेत्र में राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण की समस्या, कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उच्च लीवरेजिंग, कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र के ऋणों की चुकौती में चूक का प्रचलन, जापान में आए भूकंप का असर, एमईएनए में निरंतर चल रही उथल-पुथल और ऊर्जा तथा पण्यों की कीमतों में निरंतर तेजी निवेशकों के विश्वास और कारपोरेशन्स तथा गृह स्वामियों के व्यय करने के निर्णय को नकरात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

अब हम अपने देश की बात करें तो वृद्धि में कमी के आसार हैं जबकि पण्यों की बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में मजबूती बने रहने के लक्षण दिख रहे हैं। इन सबके चलते राजकोषीय समेकन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तेल और पण्यों की ऊंची कीमतों के कारण आयात में वृद्धि रहेगी जिसके कारण चालू खाते का घाटा बढ़ा हुआ ही रहनेवाला है और साथ ही वित्तीयन की चुनौतियाँ रहेंगी क्योंकि वैश्विक स्थितियाँ पूंजी प्रवाह में अस्थिरता को बढ़ाती हैं। वस्तुओं की उच्च कीमतें और ब्याज की लागत का परिणाम कारपोरेट्स के मार्जिन पर अधोगामी दबाव होगा। वर्ष के दौरान वैश्विक रिकवरी की धीमी गति, घरेलू वृद्धि में कमी, मुद्रास्फीति के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम और वित्तीय क्षेत्र पर उच्च ब्याज दरों का सकल प्रभाव संभवतः कुछ हद तक प्रतिकूल रहेगा।

वैश्विक जोखिम में कमी परंतु मुद्रास्फीति और पूंजी प्रवाह का उच्च बने रहना

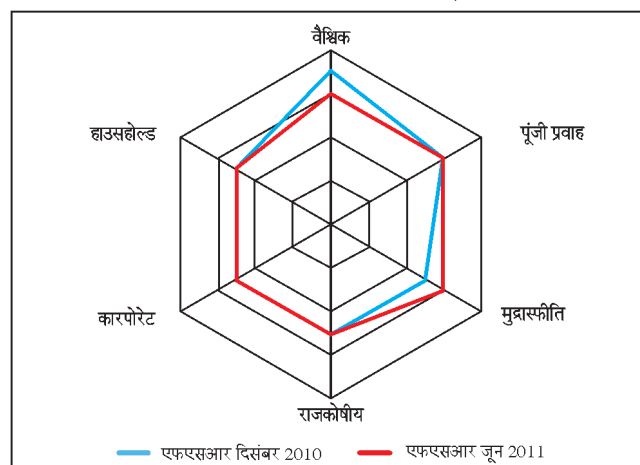
1.1 दिसंबर 2010 में रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगे थे। तथापि यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण जोखिमों को लेकर कुछ चिंताएं उभरीं। लेकिन कुल मिलाकर वैश्विक जोखिमों में सुधार तो दिखाई दिया लेकिन उनका स्तर बढ़ा हुआ ही रहा। अपने देश में पूंजी प्रवाहों में कमी के कारण जोखिमों में हुई कमी को पोर्टफोलियो प्रवाहों में अस्थिरता में हुई वृद्धि ने बेअसर कर दिया। कारपोरेट और हाउसहोल्ड जोखिम जैसे थे वैसे ही बने रहे (चार्ट 1.1)।

वैश्विक गतिविधियां

वैश्विक वृद्धि में गिरावट चिंता का विषय.....

1.2 वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (अप्रैल 2011) ने अक्टूबर 2010 में अपने पिछले मूल्यांकन के बाद से अब वैश्विक जोखिमों में कमी का संकेत दिया है जो समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार आने के कारण है। 2011 में मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीकन (एमईएनए) तथा सहारा के छोटे देशों को छोड़कर अधिकांश देशों में जीडीपी वृद्धि में गिरावट की उम्मीद है। यह गिरावट एशिया

चार्ट 1.1: समष्टि आर्थिक जोखिम नक्शा



स्रोत: स्टाफ अनुमान

के नए औद्योगिकृत और विकासशील देशों में सर्वाधिक प्रखर रूप से पाई जाएगी (चार्ट 1.2)।

1.3 ओईसीडी सम्मिश्र लीडिंग संकेतक के अद्यतन आंकड़े (सीएलआइ) मार्च 2011 के दौरान विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की गति की ओर संकेत करते हैं। जहाँ नॉर्थ अमरीका, चीन और रशिया के सीएलआइ निरंतर विस्तार की ओर संकेत करते हैं वहीं दूसरी ओर ब्राजील और भारत के संकेतक इस प्रवृत्ति में कमी का संकेत देते हैं।

1.4 अमरीका और यूरोप के विनिर्माण क्रय प्रबंधक संकेतक (पीएमआई) भले ही विस्तार मोड में हैं लेकिन उनमें कमी पाई गई है (चार्ट 1.3)। अमरीका में हाल ही में बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि हुई है।

1.5 वैश्विक वृद्धि से जुड़े अधोमुखी जोखिम में निम्नांकित सम्मिलित हैं:

- उच्च खाद्य, पण्य और ऊर्जा की कीमतें
- राजकोषीय सहायता उपायों तथा राजकोषीय समेकन को वापस लिया जाना
- यूरो एरिया की हद में सरकारी ऋण की समस्या का पुनः सिर उठाना तथा कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय ऋण का स्तर उच्च रहना
- संरचनागत वैश्विक असंतुलन का बने रहना
- अमरीका में मंदी
- कुछ विकसित देशों में वास्तविक संपदा और हाउसहोल्ड आय में कमियाँ
- जापान के जीडीपी में गिरावट
- एमईएनए देशों में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक उथल-पुथल

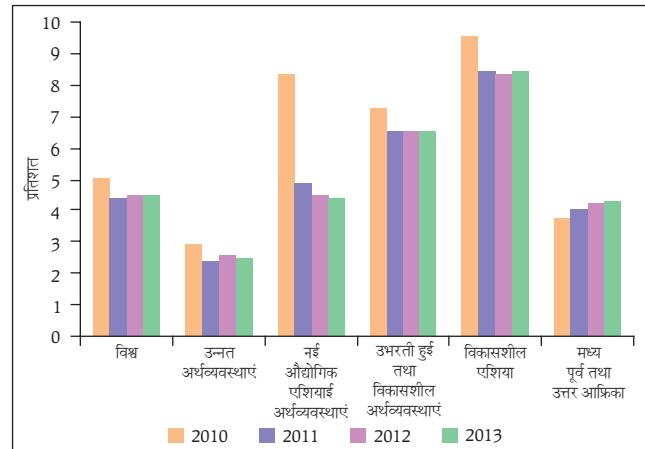
.....लेकिन बेरोजगारी की दर में आई कमी से कुछ आशाएं बंधी हैं

1.6 बेरोजगारी जो 2009-10 में अपने चरम पर थी, अब अधोगामी हो चली है और उम्मीद की जाती है कि सकल मांग में सुधार होगा (चार्ट 1.4)।

वैश्विक असंतुलन की निरंतरता उम्मीद से अधिक लंबी होती जा रही है

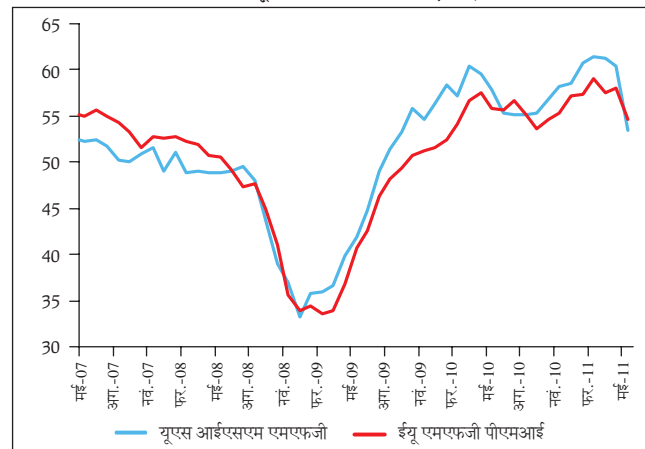
1.7 वैश्विक असंतुलन के संरचनागत कारणों का निराकरण पूरी तरह नहीं किया गया और वैश्विक असंतुलन की निरंतरता में ये प्रतिबिंबित होते हैं। भले ही चीन के व्यापार संतुलन में उतार-चढ़ाव बड़े पैमाने पर हैं लेकिन आमतौर पर वे आधिक्य जोन में ही हैं।

चार्ट 1.2: 2011 की वृद्धि की मंदी



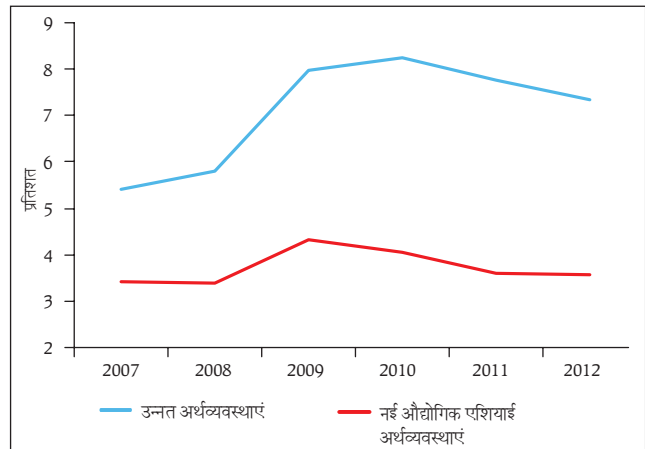
स्रोत: आईएमएफ

चार्ट 1.3: यूरोप और अमरीका के पीएमआई



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.4: बेरोजगारी दर



स्रोत: आईएमएफ

अमरीका का नकारात्मक व्यापार संतुलन, संकट के बाद कुछ हद तक कम होने के बावजूद, लगातार बड़े पैमाने पर रहा है (चार्ट 1.5)। जैसाकि पिछले एफएसआर में इंगित किया गया है, बाह्य और घरेलू असंतुलों के पुनः संतुलन की प्रक्रिया जारी है लेकिन धीमी गति से।

....और सरकारी ऋणों के साथ भी यही अनुभव रहा

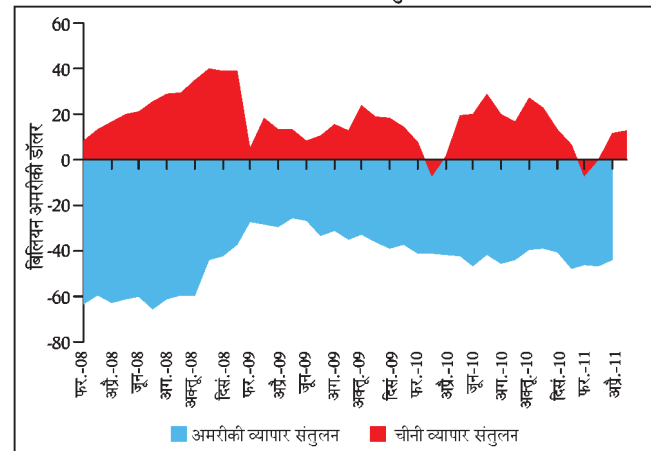
1.8 यूरोप में सरकारी ऋण संकट की समस्या घूम फिरकर पुनः उसी जगह पर आ ठहरी जहाँ एक वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ था। सरकारी सहायता के पैकेज के होते हुए भी ग्रीक अपने बजट घाटे को कम करने के अपने लक्ष्य से पीछे खिसक रहा है। सरकारी ऋण संकट से ग्रस्त देशों के लिए बाजार तक पहुँच बनाने के लिए उनकी साख और योग्यता पहले जैसी नहीं रह गई। इन परिस्थितियों में ऋण संकट जो अब तक हद के आस-पास ही फैला हुआ था, बढ़ते-बढ़ते यदि कोर यूरो जोन के देशों तथा ईस्ट यूरोपियन देशों को भी अपने चपेट में ले ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। सरकारी ऋण आम तौर पर बड़ी मात्रा में है और अन्य विकसित देशों में भी बढ़ रहा है (चार्ट 1.6)।

1.9 कुछ इंपीरिकल अध्ययन¹ में बढ़े हुए राजकोषीय स्ट्रेस जोखिम की निरंतरता को कुछ विकसित देशों में संकटपूर्व के जोखिम से भी ऊपर पाया गया जिसके लिए बढ़े हुए ऋण शोधन क्षमता जोखिम को जिम्मेदार माना गया है। यद्यपि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर राजकोषीय गुंजाइश, और उच्च वृद्धि की संभावना के कारण राजकोषीय स्ट्रेस कम पाया गया लेकिन वृद्धि और मुद्रास्फीतिकारी डायनेमिक्स में बढ़ते हुए टेशन के कारण राजकोषीय जोखिम लगातार उच्च रहे।

विश्व व्यापार में सुधार लेकिन धीमी वृद्धि दर्ज हो सकती है....भारतीय निर्यात में मजबूती बनी रही

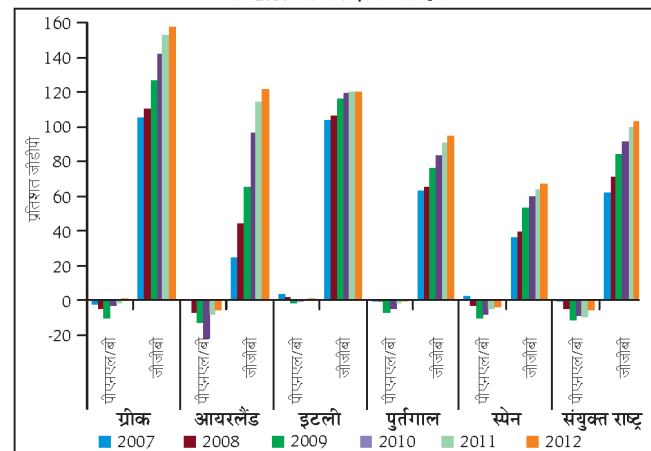
1.10 एशिया की अगुवाई में विश्व के वणिज्य व्यापार के मूल्यों में सुधार के साथ ही विश्व व्यापार में सुधार का प्रारंभ हो चुका है, माना जाता है कि 2009 की चौथी तिमाही की तुलना में 2010 की चौथी तिमाही में वृद्धि तेज गति से हुई। मात्रा के संदर्भ में विश्व व्यापार में 2010 में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) विश्व आयात संकट पूर्व की स्थिति को पुनः प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन विकसित देश बहुत पीछे हैं। जापान में प्रकृति की विनाश लीला का प्रभाव पूर्व एशियन देशों, जो व्यापारिक और वित्तीय दृष्टि से जापान के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, पर हो सकता है लेकिन यह तबतक जबतक पुनर्संरचना प्रेरित सुधार नहीं प्रारंभ हो जाते।

चार्ट 1.5: वैश्विक असंतुलन



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.6: सरकारी शेष और ऋण



पीएनएल/बी: प्राथमिक निवल उधार देना (+)/ उधार लेना (-)

जीडीबी: सकल सरकारी ऋण

स्रोत: डब्ल्यूईओ, आईएमएफ

¹ बाल्डाक्की, एमॅन्युएल, इवा पेद्रोवा, नजिम बेल्लोसिन, गॉब्रिएला डोब्रेस्कू और समाह माजारानी (2011) एक्सेसिंग फिस्कल स्ट्रेस, *आइएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/11/1100*

1.11 भारत के निर्यातों में सर्वांगीण वृद्धि में श्रम केंद्रित विनिर्माण से लेकर इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम क्षेत्रों में उच्च मूल्य वर्द्धित उत्पाद बल्कि उभरते बाजारों और विकसित देशों के गंतव्यों की विविधता प्रतिबिंबित होती है। एमईएनई देशों में भू-राजनीतिक अस्थिरता और जापान में प्राकृतिक आपदा प्रत्यक्ष रूप से भारत के व्यापार की स्थिति को संभवतः प्रभावित नहीं कर सकती क्योंकि भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इन देशों की हिस्सेदारी कम है; अप्रत्यक्ष प्रभाव संभावित तेल मूल्यों में वृद्धि और अन्य पण्य सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि के रूप में हो सकता है। जैसाकि अध्याय V में कहा गया है बैंकिंग आस्तियों की गुणवत्ता पर निर्यातों का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण पाया गया और यही कारण है कि हमें निर्यात क्षेत्र के एक्सपोजर की निगरानी सूक्ष्मता से करने की आवश्यकता है।

देशी अर्थव्यवस्था

वास्तविक गतिविधियों में मज़बूती बनी रही, यद्यपि गिरावट के संकेत स्पष्टगोचर हैं

1.12 2010-11 के दौरान वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी मुख्यतया 'कृषि और आनुषंगिक गतिविधियों' में तीव्र वृद्धि के कारण थी, जबकि उद्योग और सेवाओं में योगदान में कमी आई (चार्ट 1.7)।

औद्योगिक वृद्धि में गिरावट, निवेश की मांग में आंशिक कमी को दर्शाता है

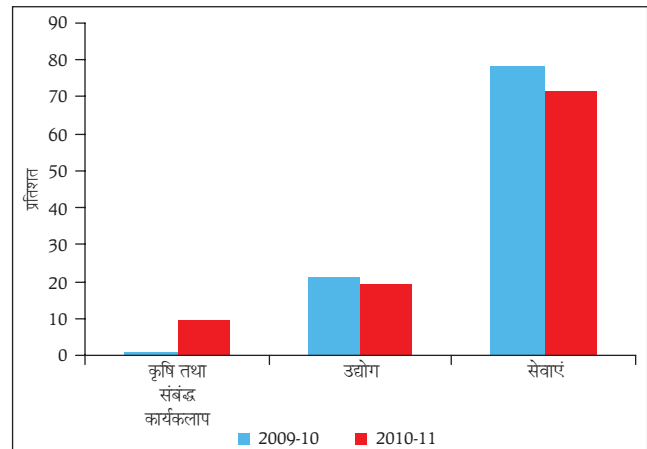
1.13 पिछले एफएसआर में जैसा प्रक्षेपित किया गया है, औद्योगिक उत्पादन में घट-बढ़ बड़े पैमाने पर रही। यह घट-बढ़ आमतौर पर पूंजीगत माल के उत्पादन में आए उतार-चढ़ाव के कारण थी (चार्ट 1.8)। यद्यपि पूंजीगत माल क्षेत्र में तेज वृद्धि पाई गई, उतार-चढ़ाव अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का सूचक है।

1.14 मांग पक्ष में 2010-11 के दौरान वृद्धि में तेजी आमतौर पर आयात की तुलना में निर्यात तथा निजी अंतिम उपभोग व्यय व सकल निर्यात पूंजी में तेज वृद्धि दर्शाती है। 2010-11 में सरकारी अंतिम उपभोग की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट रही जो राजकोषीय समेकन के प्रयासों को प्रतिबिंबित करता है: जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी में भी कमी आई (चार्ट 1.9)।

1.15 2011-12 के दौरान अधोगामी जोखिमों में निम्नांकित सम्मिलित हैं:

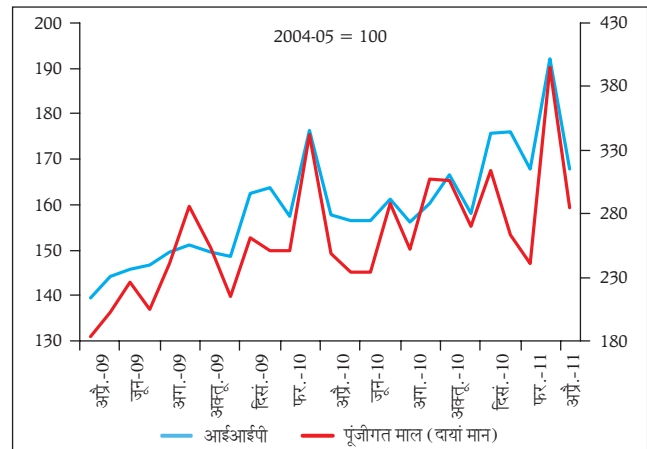
- वैश्विक सुधार और बाह्य मांग स्थितियों की गति धीमी पड़ना
- निवेश में कमी
- तेल और पण्य की उच्च कीमतें
- भूत और भविष्य में मौद्रिक नीति कार्रवाइयों का प्रभाव

चार्ट 1.7: विकास के लिए योगदान-आपूर्ति पक्ष



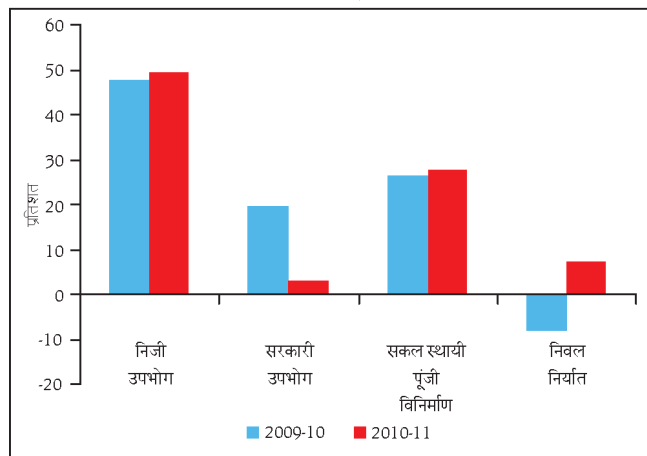
स्रोत: सीएसओ, स्टाफ की गणनाएं

चार्ट 1.8: औद्योगिक और पूंजीगत माल उत्पाद



स्रोत: सीएसओ

चार्ट 1.9: विकास के लिए योगदान-मांग पक्ष



स्रोत: सीएसओ, स्टाफ की गणना

उच्च पूंजी प्रभार के लिए बासल III प्रस्ताव का प्रभाव न्यूनतम रहने की संभावना

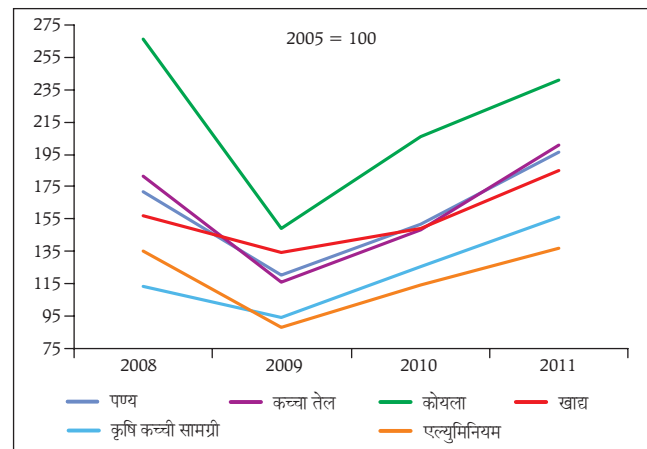
1.16 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति के समष्टि आर्थिक समूह (एमएजी) ने अनुमान किया है कि पूंजी आवश्यकताओं में प्रत्येक एक प्रतिशत बिंदु की वृद्धि पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि में 0.03 प्रतिशत बिंदुओं की कमी आ जाएगी। दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव कार्यदल (एलईआइ) ने अनुमान किया है कि पूंजी अनुपात में एक प्रतिशत बिंदु की वृद्धि उत्पादन में 0.09 प्रतिशत की स्थायी कमी ला देगा। इटली के लिए इसी प्रकार किए गए अध्ययन में आठ वर्ष के होरिजोन में उत्पादन में कमी को 0.00-0.33 प्रतिशत आंका गया है जो अनुमान विधि पर आधारित है।² लेकिन द इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ने अपने मूल्यांकन में कहा है कि यूरोप और अमरीका में बासल III के लिए जीडीपी की लगभग³ प्रतिशत लागत आएगी। दि फ्रेंच बैंकिंग एसोसिएशन ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए इन आंकड़ों को दुगुना अनुमानित किया है। वैश्विक व्यय पर कुछ अन्य अध्ययनों में दर्शाया गया है कि पूंजी और चलनिधि अपेक्षाओं में वृद्धि की समष्टि आर्थिक लागत प्रभावित होती है कार्यान्वयन अवधि की समय सीमा, बैंकों द्वारा उपयोग में लाई जानेवाली समायोजन युक्तियां और मौद्रिक नीति के प्रति स्थान पर।

1.17 रिजर्व बैंक द्वारा जीडीपी³ पर बढ़ी हुई पूंजीगत अपेक्षाओं के प्रभाव के प्राथमिक मूल्यांकन को देखने से पता चलता है कि अन्य बातों में यदि कोई परिवर्तन न हो तो जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरआर) पर पूंजी में एक प्रतिशत की वृद्धि का कारण मध्यम अवधि होरिजोन में औसत वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर में मामूली कमी हो सकती है जो बैंक क्रेडिट वृद्धि तथा कर्ज ब्याज दर पर सीआरआर के प्रभाव से उपजित है।

मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ा हुआ जबकि अंतर्निहित कारक बदलते हैं

1.18 वैश्विक खाद्य, ऊर्जा और अन्य पण्यों की कीमतें 2011 में उच्च बनी रहने की संभावना है (चार्ट 1.10)। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति चिंता की बात है क्योंकि उच्च वैश्विक पण्य कीमतों के परिणामस्वरूप वृद्धि में कमी आएगी और पूरे विश्व में उच्च मुद्रा स्फीति का प्रसार होगा।

चार्ट 1.10: वैश्विक पण्य मूल्य सूचकांक



नोट: 2011 के आंकड़े अनुमान

स्रोत: आईएमएफ

² लोकानों, एलबर्टों (2011), द मैक्रोइकोनोमिक इम्पैक्ट ऑफ बासल III ऑन द इटालियन इकोनॉमी, बैंक ऑफ इटाली, मई

³ यह मूल्यांकन छोटे विश्लेषणात्मक सांख्यिकी मैक्रो मॉडल पर आधारित है जिसके आंकड़े बैंकिंग क्षेत्र के वार्षिक तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा तथा मैक्रोआर्थिक के सकल से प्राप्त किए गए हैं। इस अध्ययन में एकबारगी के प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, कन्वर्जेंस पैटर्न की तरह नहीं जो कुछ अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों, बीआइएस अध्ययन सहित, का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाए गए परिणाम सांकेतिक और अस्थायी हैं। और विभिन्न कल्पनाओं के अधीन हैं जिसमें मुख्य कल्पना यह भी सम्मिलित है कि बैंकों द्वारा पूंजी बफर, बेसलाइन सीनरी के अनुसूप धारण किया जाएगा। इन कल्पनाओं के अभाव में बासल III का कोई प्रभाव वास्तविक जीडीपी वृद्धि पर नहीं पड़ेगा।

1.19 अपने देश में मुद्रास्फीति पर तेल और कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी, सरकार द्वारा दिए जानेवाले उच्च आर्थिक व्यय, वेतन तथा कच्ची सामग्री के मूल्य में वृद्धि के कारण दबाव रहने की संभावना है। अधोगामी मुद्रास्फीति की बीमारी उच्च वैश्विक खाद्य कीमतों के साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति के संरचनागत घटकों से भी उपजती है।

स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि जारी है, जबकि कुछ केंद्रों में आवासीय कीमतों में सुधार दिखाई दे रहा है ...

1.20 विभिन्न राज्य सरकारों के पंजीकरण और मुहर विभाग (डीआरएस) से एकत्र किए गए संपत्ति खरीद / बिक्री विलेखों के पंजीकरण पर आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर विभिन्न केन्द्रों के लिए त्रैमासिक आवासीय मूल्य सूचकांक (एचपीआई) कुछ केन्द्रों में आवासीय कीमतों में जारी दृढ़ता और कुछ अन्य में मामूली सुधार दर्शाते हैं (चार्ट 1.11)। कुछ केन्द्रों में न बेचे गए प्लॉटों की रिपोर्टों में आगे सुधार हो सकता है। ऋण अपनी प्रवृत्ति दर से बढ़ रही है और आवासीय एनपीए अनुपात में परिलक्षित इन परिसंपत्तियों की सर्विसिंग से सुधार जारी है। (चार्ट 1.19)

1.21 संकट के बाद से, स्वर्ण की कीमतों में एक साधारण वृद्धि दर्ज की गई है। (1.12 चार्ट) उदाहरण स्वरूप साक्ष्य से इस संपार्श्विक के रूप में इसकी भूमिका से ज्यादा चिंता नहीं है और यह कम प्रतीत होती है।

उच्च वैश्विक तेल की कीमतों के संयुक्त प्रभाव और निर्यात में साधारण वृद्धि के कारण सीएडी बढ़ा रहेगा

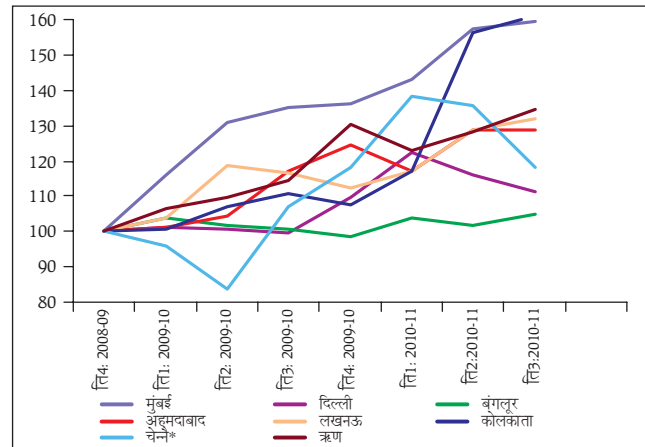
1.22 यदि तेल और पण्य की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी, सीएडी महत्वपूर्ण बने रहेंगे (चार्ट 1.13), हालांकि सॉफ्टवेयर निर्यात और विप्रेषण उच्च वृद्धि के लिए कुछ सहारा प्रदान कर सकते हैं। सीएडी का वित्तपोषण एक चुनौती होगी क्योंकि उन्नत देश अपनी उदार मौद्रिक नीति के खर से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। निवेशकों द्वारा अपने पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करने से भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के पूंजी प्रवाह धीमे हो सकते हैं।

सीएडी का अस्थिर पोर्टफोलियो प्रवाह द्वारा वित्त पोषण किया जाना जारी है जबकि एफडीआई कम बने हुए हैं

1.23 पूंजी प्रवाह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अधिक अस्थिर पाये गये हैं। इसके अलावा, संकट के बाद की अवधि में, यह देखा गया है कि ऋण निर्माण प्रवाह के हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी हुई है। आईएमएफ ने पाया है कि अमेरिका द्वारा मौद्रिक दृढ़ता खासकर अगर अप्रत्याशित हो, अमेरिका एक्सपोजरवाली अर्थव्यवस्थाओं के पूंजी प्रवाह में गिरावट लाएगी।

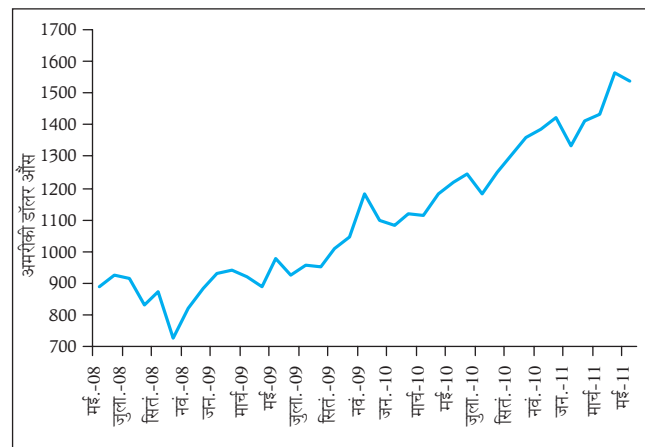
1.24 भारत के मामले में, वर्ष 2009-10 के दौरान पोर्टफोलियो प्रवाह स्थिर थे, लेकिन 2010-11 के दौरान अस्थिर हो गये जो वैश्विक और

चार्ट 1.11: आवासीय कीमत और आवासीय ऋण



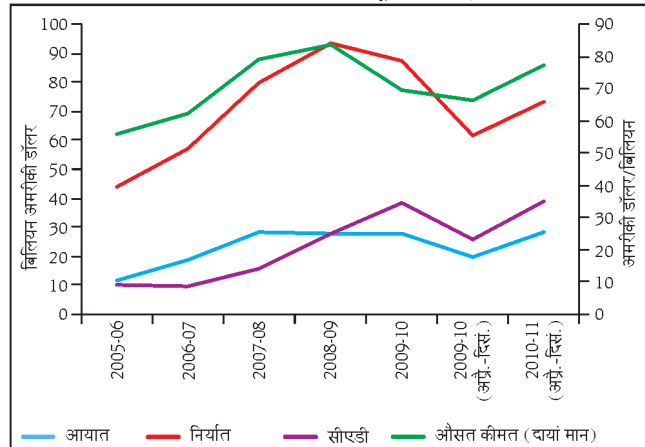
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.12: सोने की कीमतों में वृद्धि जारी



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.13: तेल व्यापार और मूल्य तथा सीएडी



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

घरेलू दोनों स्तर पर अनिश्चितताओं को दर्शाते हैं (चार्ट 1.14)। अतः सीएडी का वित्तपोषण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में काफी जोखिम भरा होगा, हालांकि स्थिर है उसकी गति दिखाई नहीं दे रही है। इस तरह से, एफडीआई में स्थिरता के बावजूद गति पकड़ने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अतः सीएडी के वित्तपोषण के समक्ष काफी जोखिम पैदा हो सकता है। पूंजी प्रवाहों की संरचना और अस्थिरता से बाहरी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस पर पैनी नजर जरूरी है।

1.25 पूंजी प्रवाहों से पैदा होने वाले जोखिमों से बचने के लिए किए गए उपायों के अंतर्गत गहरे और चलनिधि संपन्न अंतर्देशी वित्तीय बाजार, सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक एवं विवेकपूर्ण नीति व पर्यवेक्षण तैयार करना, वित्तीय संयम तथा मजबूत संस्थाएं स्थापित करना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2011-12 में वित्तीय समेकन की प्रक्रिया जारी रहेगी, किंतु उसकी गुणवत्ता और गति का काफी महत्व होगा

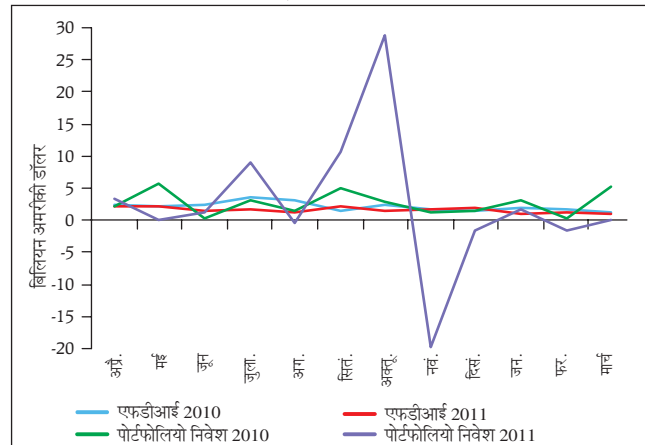
1.26 वर्ष 2011-12 के केंद्रीय बजट में वित्तीय समेकन की प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई, जिसे संकट के चलते अस्थायी रूप से टाला गया था। अंतरराष्ट्रीय पण्य-वस्तुओं के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी होने की वजह से बजट प्रावधानों की तुलना में सब्सिडी काफी बढ़ने की आशंका है, जिसके कारण 2011-12 में होने वाले घाटे के संबंध में किए गए अनुमान चूक जाने की संभावना है (चार्ट 1.15)। 2011-12 के बजट में सब्सिडी के संबंध में यह मानते हुए निम्नतर पूर्वानुमान किया गया है कि 2011-12 की संपूर्ण अवधि में अंतरराष्ट्रीय उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होने वाला है, किंतु स्थिति इसके विपरीत है। वित्तीय समेकन की प्रक्रिया में आय और व्यय दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है, जिसमें भी व्यय पक्ष पर अधिक ध्यान अपेक्षित है। पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के अंतर्देशी मूल्यों को बढ़ाकर सब्सिडी को काबू में रखना इस कार्यनीति का उद्देश्य होना चाहिए।

1.27 यदि तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी होती है, जिसके अनुस्वरूप अंतर्देशी मूल्यों में आवश्यक समायोजन नहीं होता हो तो संकटग्रस्त सार्वजनिक तेल इकाइयों को राहत दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सब्सिडी पर व्यय बढ़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति डगमगा सकती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल प्रस्तुत किए जाने से व्ययजन्य बोझ बढ़ सकता है। इससे वित्तीय समेकन की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है।

ब्याज और पण्य-वस्तुओं की ऊंची लागतों से कार्पोरेट मार्जिनों पर दबाव पड़ सकता है

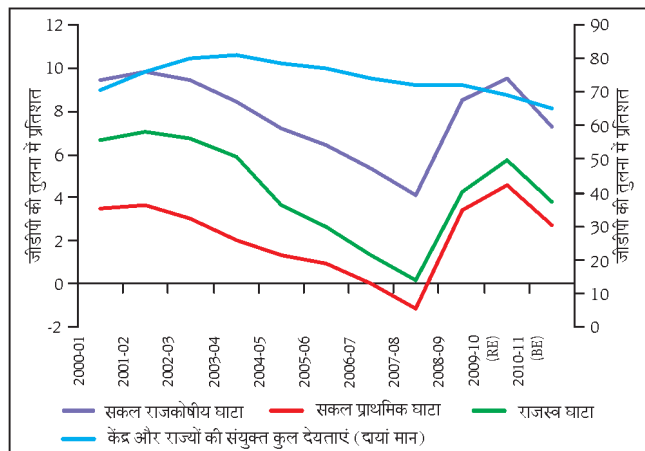
1.28 सख्त मौद्रिक नीति के कारण कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज में बढ़ोतरी हो रही है और यह स्थिति निकट भविष्य में भी जारी रहेगी (चार्ट 1.16)। इससे मार्जिनों पर बुरा असर पड़ सकता है। घरेलू क्षेत्र में ऋण की हिस्सेदारी में कमी आई

चार्ट 1.14: निवल एफडीआई और पोर्टफोलियो प्रवाह



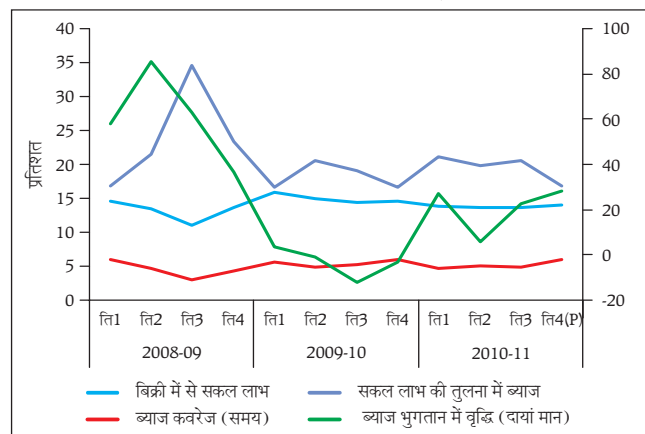
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.15: घाटा और ऋण (केंद्र और राज्य)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.16: कार्पोरेट सेक्टर निष्पादन



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

है परंतु प्रणालीगत औसत की तुलना में घरेलू क्षेत्र की आस्ति में होने वाली कमी अधिक बनी हुई है। इसके अलावा, पण्य की ऊंची और बढ़ती हुई कीमतें कंपनियों पर दबाव बनाती हैं और परिवारों के पास खर्च करने के लिए उपलब्ध वास्तविक निजी आय भी कम हो जाती है।

हाउसहोल्ड क्षेत्र के ऋण के हिस्से में गिरावट दर्ज हुई है किन्तु हाउसहोल्ड क्षेत्र की आस्तियों में होनेवाली कमी प्रणालीगत औसत की तुलना में अधिक बनी हुई है

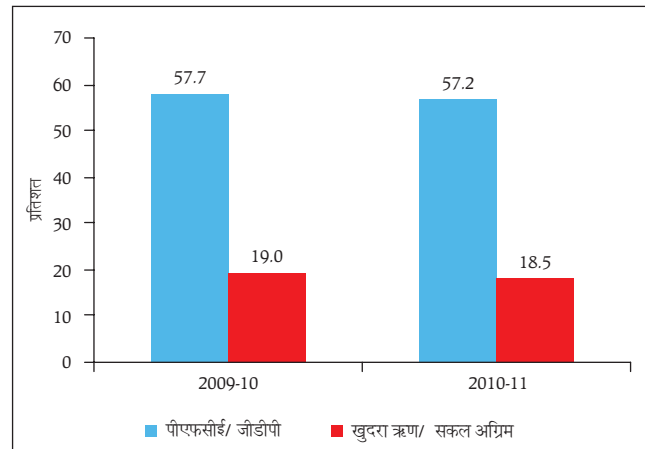
1.29 निजी उपभोग की हिस्सेदारी में 2010-11 के दौरान आंशिक गिरावट आने की संभावना है। इसके अनुसूप ही, कुल अग्रिमों में से खुदरा ऋण की भागीदारी में भी कमी आने की संभावना है जो यह दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से परिवारों के ऋणी होने के जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है (चार्ट 1.17)। बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो में आस्तियों में होने वाली कमी प्रणालीगत औसत की तुलना में अधिक बनी हुई है परंतु इसमें कुछ कमी आ रही है (चार्ट 1.18)। कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के विपरीत आवास क्षेत्र में आस्तियों में कमी अपेक्षाकृत कम है और इसमें कुछ कमी आ रही है (चार्ट 1.19)।

निष्कर्ष टिप्पणी

1.30 वैश्विक समष्टि आर्थिक वातावरण और संबंधित वैश्विक जोखिमों में कुछ सुधार आने के बावजूद वैश्विक जोखिमों के उच्चतर स्तर पर बने रहने में अनिश्चितताओं की भी काफी कुछ भागीदारी है। वर्तमान वर्ष के दौरान अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उभरती हुई तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भी संवृद्धि में कमी आने की आशंका है। साथ ही, विश्व व्यापार में गिरावट आने की भी संभावना है। इसमें कुछ कमी आने के बावजूद वैश्विक असंतुलन जारी रहेगा जो यह दर्शाता है कि पुनः संतुलन कायम करने में लंबा समय लग सकता है और इसके लिए अधिक कठोर नीतिगत उपाय करने होंगे। शासकीय ऋण संकट के पुनः उभरने और उसके बने रहने से नए संकट खड़े हो गए हैं और वैश्विक रिकवरी के लंबा खिंचने की संभावना बन गई है।

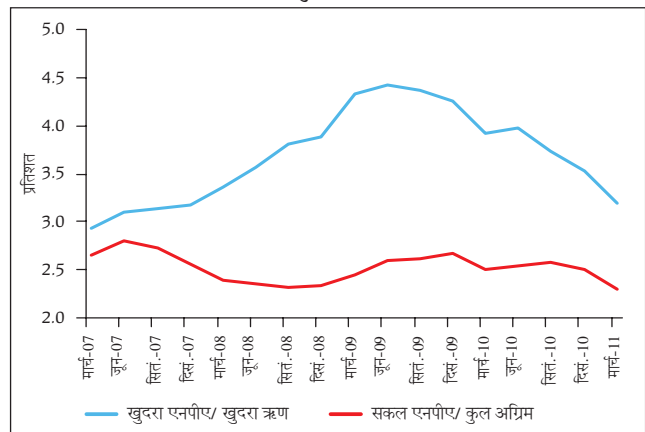
1.31 वैश्विक रिकवरी में धीमापन, तेल और पण्य की ऊंची कीमतें, यूरो क्षेत्र में बढ़ती हुई शासकीय ऋण संकट और घरेलू निवेश मांग में आई कुछ कमी घरेलू अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में कुछ कमी का जोखिम उत्पन्न कर सकती है। तेल सहित पण्यों की ऊंची कीमतें भी चालू खाते के संतुलन, राजकोषीय संतुलन, पारिवारिक खर्च और कारपोरेटों के मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं जिससे समग्र रूप से वित्तीय क्षेत्र के निष्पादन में कुछ कमी होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। बढ़ी हुई मुद्रास्फीति दर और बढ़ती हुई ब्याज दरें भी वित्तीय संस्थाओं के तुलन पत्र को प्रभावित कर सकती हैं।

चार्ट 1.17: घरेलू उपभोग और उधार



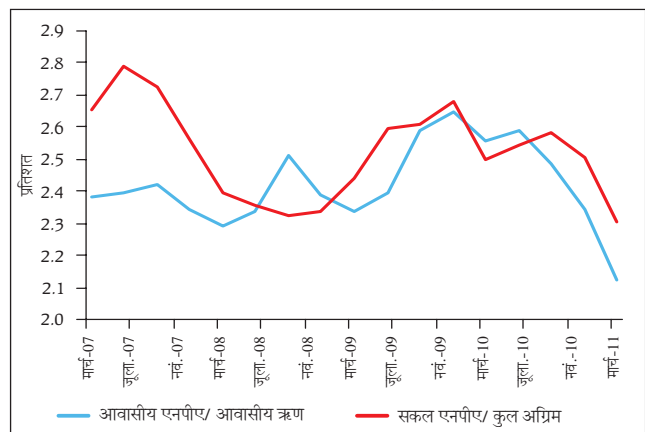
स्रोत: सीएसओ, भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.18: खुदरा आस्तियों में हानि



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 1.19 आवासीय आस्तियों में हानि



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

अध्याय II

वित्तीय बाज़ार

अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाएं निम्न विकास एवं उच्च कर्ज के परस्पर मजबूत करने वाले चक्र को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कही जा सकने वाली बहुत कम ऐसी प्रगति हुई है। बहुत अधिक सरकारी जोखिम की समस्या न केवल सरकार के लिए बल्कि ऐसे वित्तीय संस्थानों के लिए भी निधीयन लागत में बढ़ोतरी करेगी जो कि अभी भी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मजबूत आधार ढूंढ रहे हैं। निधीयन के लिए विभिन्न देशों एवं वित्तीय संस्थानों में प्रतियोगिता एक ऐसे समय पर आ रही है जब निवेशकों में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में मजबूत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस पृष्ठभूमि में एक छोटा झटका भी नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रभाव के लिए काफी हो सकता है, जोकि विकसित देशों के बाहर के बाजारों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उभरते हुए बाजार अपने वित्तीय व्यवस्था में बढ़ते असंतुलन को रोकने के लिए अपनी दोहन क्षमता से अधिक पूंजी निवेश को रोक रहे हैं। भारत में निवेश के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता पर अधिक विश्वास के शुरूआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भारतीय बाजारों, संस्थानों, एवं निधीयन के बड़े स्तर पर वैश्वीकरण का निवेश एवं स्टॉक पर होने वाले प्रभाव को सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने तथा व्यवस्थित करने की जरूरत है।

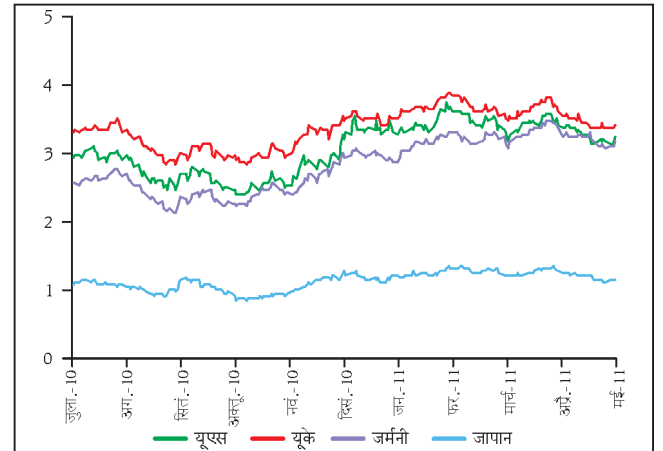
अंतरराष्ट्रीय बाजार

2.1 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के जारी किए जाने के पश्चात की अवधि से अब तक वैश्विक वित्तीय बाजार स्थिर रहे हैं। इस प्रणाली के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाओं, जापान में भूकंप और लीबिया में विद्रोह ने वित्तीय बाजारों में बड़ी तेजी से गिरावट पैदा की लेकिन इनका तत्काल प्रभाव धीरे-धीरे गायब होने लगा।

यूएस में इस वर्ष के लिए दर वृद्धि की अपेक्षा खत्म हो गई है

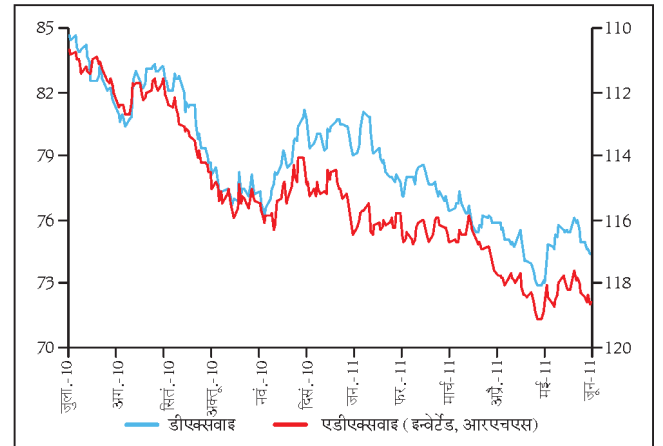
2.2 विकसित देशों में मौद्रिक नीति अभी भी उदार बनी हुई है। फेडरल रिजर्व नीति दर, फेडरल फंड टारगेट दर 0-0.25 प्रतिशत है, 600 बिलियन यूएस डॉलर वाली द्वितीय संख्यात्मक सहायता कार्यक्रम को जून 2011 तक पूरा किए जाने की संभावना है, लेकिन फेडरल रिजर्व अपनी आरक्षित निधि से प्रमुख भुगतान को पुनर्निवेश करना जारी रखेगी। जून के आरम्भ में (चार्ट 2.1) यूएस पेट्रोल डाटा में आशा से कम वृद्धि होने के कारण 10-वर्षीय यूएस पूंजी बांड प्रतिलाभ 3 प्रतिशत नीचे पर बेची जा रही थी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बर्नान्के ने “वास्तविक स्थापित लाभ” के साथ “लंबी अवधि के लिए रोजगार निर्माण” को जोड़ दिया है। इस अवधि की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति अधिकतर मुद्राओं की तुलना में विकसित तथा विकासशील दोनों बाजारों में यूएस डॉलर में अनवरत गिरावट आई है (चार्ट 2.2)। यूएस वित्तीय डाटा इतना उदार रहा है कि ब्याज दर वृद्धि की अपेक्षाओं को नियंत्रित कर सके, लेकिन इतना कमजोर भी नहीं रहा है कि विकास दर को बनाए न रख सके। वर्ष के आरंभ से ही संभावनाएं व्याप्त थी कि फेडरल रिजर्व द्वारा दिसंबर 2011 तक दर में बढ़ोतरी करेगा पर अब ये संभावनाएं

चार्ट 2.1: 10 वर्षीय बांड प्रतिलाभ (प्रतिशत में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.2 उन्नत और उभरते हुए एशियाई मुद्राओं (एडीएक्सवाइड) की तुलना में यूएस डॉलर (डीएक्सवाइड) की तुलना में



स्रोत: ब्लूमबर्ग

अब कम हो गई हैं (चार्ट 2.3)। इस कारण से जोखिम लेने की प्रवृत्ति प्रबल बनी रही और जोखिम आस्ति कारोबार के लिए अमेरिकी डालर को निधियन मुद्रा के तौर पर प्रयोग किया गया। इस अवधि में (चार्ट 2.4)। अमेरिकी ईक्विटी सूचकांक ने सकारात्मक रुख के साथ कारोबार किया और निवेशकों ने उन स्टॉक में अधिक रुचि दिखाई जिनका उभरते हुए बाजार में अधिक एक्सपोजर था।

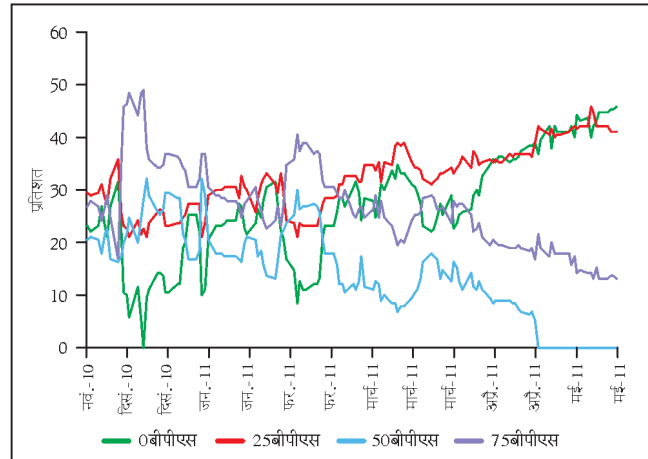
यूरो क्षेत्र में अनिश्चित रफ्तार से मौद्रिक समायोजन को वापस लेने की शुरुआत

2.3 इस दौरान, यूरोप में, यूरो क्षेत्र में नीति के सामान्य होने के पूर्वानुमान के कारण अन्य मुद्राएं विशेषकर अमेरिकी डालर की तुलना में यूरो के मूल्य में बढ़ोतरी हुई, जबकि लम्बे समय तक समायोजन की नीति बनी रही। यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने 7 अप्रैल 2011 को अपनी बैठक में अपने नीतिगत दर और पुनर्वित्त दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया। हालांकि ईसीबी द्वारा मई 2011 के अपने बैठक में नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखने के बाद मुद्रा में गिरावट आई और प्रेसिडेंट त्रिचेत ने दर में बढ़ोतरी संबंधी बाजार³ की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। मई 2011 की बैठक के पश्चात, अन्य मुद्राओं की तुलना में यूरो में भारी गिरावट आई और ग्रीस के संबंध में अत्यधिक अनिश्चितता आने से इसमें नरमी बनी रही। यूरोप की ईक्विटी निश्चित सीमा के भीतर बनी रही।

यूके और जापान के भविष्य की संभावनाएं अनिश्चित

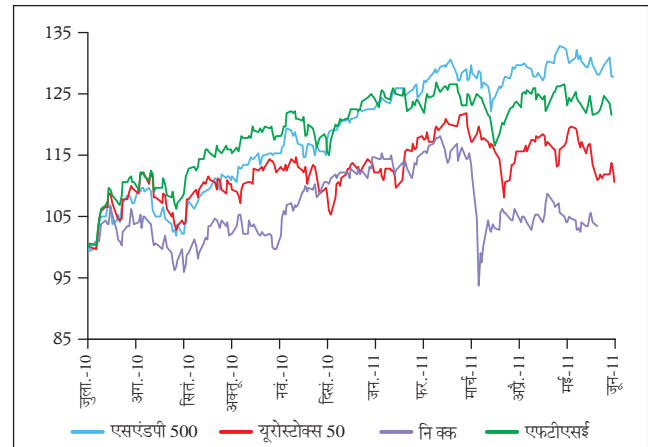
2.4 यूके में मुद्रास्फिति बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा तय लक्ष्यों से अधिक रही जबकि संवृद्धि कम रही। बैंक ऑफ इंग्लैंड को उम्मीद है कि इस वर्ष मुद्रास्फिति में और अधिक वृद्धि हो सकती है और वर्ष 2012 में यह 2 प्रतिशत के तय लक्ष्य से ऊपर रह सकती है। यूके का ईक्विटी और बांड बाजार सुव्यवस्थित पर दिशाहीन रहा। अमेरिकी डालर के सामान्य कमजोरी के कारण पाउंड स्टर्लिंग में तेजी आई। जापान में मार्च 2011 में आए भूकंप के फलस्वरूप कैपिटल स्टॉक में हुई अत्यधिक तबाही के कारण वित्तीय बाजार लड़खड़ा गया। जापान के उत्पादन और संवृद्धि में मंदी रहने के आसार अगले वर्ष तक हैं। मरम्मत का कार्य पूरा हो जाने पर अर्थव्यवस्था के आउटपुट को बढ़ावा मिलेगा। ईक्विटी बाजार को अपने प्रारंभिक नुकसान की अभी भरपाई करनी है जबकि बांड बाजार का प्रतिफल दुबारा मौद्रिक विस्तार

चार्ट 2.3: फेडरल फंड फ्यूचर्स संविदा के आधार पर दिसंबर 2011 को हुई फेडरल ओपन बाजार समिति बैठक में संघीय कोष लक्ष्य दर की निहित संभावना



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.4: स्टॉक सूचकांक (सामान्यीकृत, 1 जुलाई, 2010=100)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

¹ डीएक्सवाइ अथवा डॉलर सूचकांक 6 प्रमुख विश्व की करेन्सियों के समूह की तुलना में यूएस डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य का संकेत देता है। यूरो को जापानी येन के 13.6 प्रतिशत के बाद 57.6 प्रतिशत सूचकांक का अधिकतम महत्व है। पाउंड स्टर्लिंग 11.9 प्रतिशत पर है। केनेडियन डॉलर 9.1 प्रतिशत पर है। स्वीडिश क्रोन 4.2 प्रतिशत पर है और स्विस् फ्रैंक 3.6 प्रतिशत पर है। इसके मूल्य में वृद्धि यह संकेत देती है कि डॉलर का मूल्य बढ़ गया है।

² एडीएक्सवाइ ब्लूमबर्ग जेपी मॉर्गन एशिया डॉलर सूचकांक है अर्थात् वह यूएस डॉलर की तुलना में दस एशियन करेन्सियों के व्यापार और चलनिधि भारित सूचकांक है। चाइनीज येन का मूल्य 35.9 पर है, जो अधिकतम मूल्य है और भारतीय रुपये का मूल्य 7.8 पर है। इसके मूल्य में वृद्धि यह संकेत देती है कि यूएस डॉलर में मूल्यवृद्धि हुई है।

³ दर निर्धारित करने की बैठक के बाद प्रेसिडेंट त्रिचेत की प्रेस कांफ्रेंस वित्तीय बाजार के लिए एक प्रमुख घटना है जो मूल्य स्थिरता लक्ष्य के संबंध में आगे दर में वृद्धि के संकेत के रूप में 'कड़ी सतर्कता' के रूप में कही जा सकती है। प्रेसिडेंट त्रिचेत द्वारा इस शब्द का प्रयोग करने के बारे में अनिच्छा से दरों में वृद्धि के अगले चरण के बारे में बाजार को निराश किया।

की आशंका से प्रारंभ में तेजी दिखाते हुए नीचे आ गया क्योंकि इसका प्रभाव खत्म हो गया था। भूकंप के कारण जापानी येन में तेजी आई क्योंकि आशंका थी कि जापानी वित्तीय फर्म अपने विदेशी निवेशों को बड़ी मात्रा में देश में प्रत्यावर्तित करेंगे। इस आशंका से जापानी येन तेज हो गया कि भूकंप के मद्देनजर जापानी वित्तीय कंपनियों द्वारा विदेश में उनके निवेशों का बड़े पैमाने पर प्रत्यावर्तन होगा। यह आशंकाएं हालांकि निराधार साबित हुईं। मार्च 2011 में भूकंप के बाद की अवधि में मुद्रा बहुत अस्थिर बनी रही (चार्ट 2.5)। जापान और अन्य उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों के संयुक्त हस्तक्षेप से मुद्रा में आयी तीव्र वृद्धि को सफलतापूर्वक पलट दिया।

वित्तीय प्रणाली को झटके पहुंचाता भूकंप

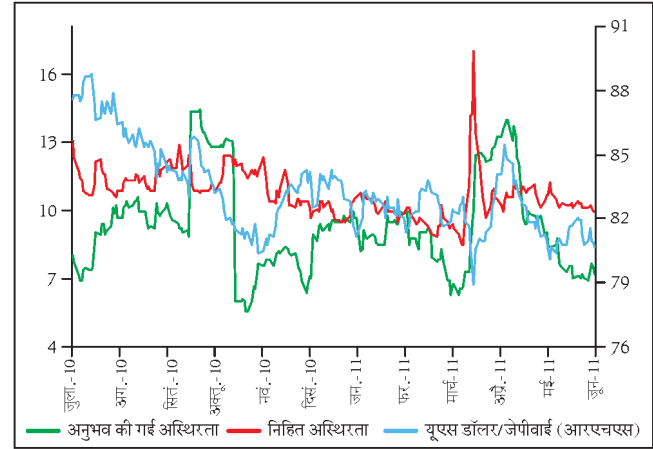
2.5 जापानी केबिनेट कार्यालय द्वारा किए गए प्रारंभिक आकलन में अर्थव्यवस्था की शेयर पूंजी को होनेवाली हानि 240 बिलियन डॉलर के आसपास बतायी गयी है, जो कि 1995 में कोबे में आए भूकंप के बाद हुई हानि से दोगुने से भी अधिक है। जापान द्वारा वर्ष की दूसरी छमाही में शुरू किए जाने वाले पुनर्निर्माण के बृहत प्रयासों के बावजूद जापान के लिए 2011 में सकल घरेलू उत्पाद के विकास के लिए पहली तिमाही वृद्धि के साथ (-) 3.7 प्रतिशत की भारी गिरावट होने की संभावना है। भूकंप के बाद पहले दो कारोबारी दिनों में, निक्की शेयर सूचकांक लगभग 20 प्रतिशत गिर गया तथा 5 वर्षीय सीडीएस स्प्रेड वाली जापानी सरकारी प्रतिभूतियाँ 100 आधार अंक से करीब 50 आधार अंक के आस-पास ऊपर उठीं और 10 वर्षीय सरकारी बांड प्रतिफल 1.2 प्रतिशत से 10 आधार अंक ऊपर उठे। आपदा के बाद जापानी येन बहुत अस्थिर हो गया।

2.6 बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने चुनौती के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। भूकंप के बाद के पहले सप्ताह में उसने वित्तीय बाजारों में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए 37 ट्रिलियन येन (439 बिलियन अमेरिका डॉलर) प्रविष्ट की। इससे जोखिम परिसंपत्ति पर कम प्रीमियम रखने के उद्देश्य से इसकी आस्ति खरीद कार्यक्रम की राशि में 5 ट्रिलियन येन की भी वृद्धि हुई। येन के तीव्र उठाव के जवाब में, बैंक ऑफ जापान ने अन्य जी-7 देशों के साथ मिलकर, विदेशी मुद्रा बाजार में एक समन्वित हस्तक्षेप शुरू कर दिया।

यूरोपीय सरकारी ऋण की स्थिरता पर प्रश्न

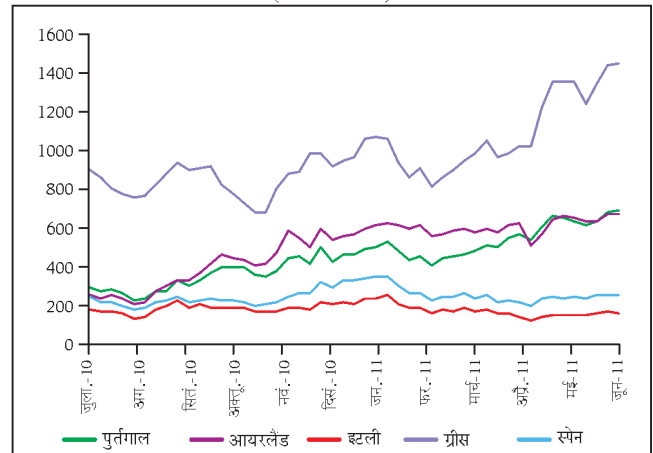
2.7 यूरो-क्षेत्र में सर्वोत्तम ऋण की स्थिरता की चिंताओं का संबंध ग्रीस, आयरलैंड, और पुर्तगाल (चार्ट 2.6) तक ही सीमित होता दिखाई नहीं देता जिन्होंने यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता पैकेज की मांग की है। समस्या के प्रतिकूल और परस्पर मजबूत पहलुओं, अर्थात्, कम आर्थिक विकास और कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ए ई) में उच्च ऋणग्रस्तता के कारण एक अस्थिर संतुलन बन गया है।

चार्ट 2.5: अमेरिकी डॉलर/जापानी येन तथा 1महिने की अस्थिरता (प्रतिशत में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.6: 5 वर्ष में अवधिपूर्णाता वाले यूरोपीय सर्वोत्तम सी.डी. (आधार अंकों में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

राजकोषीय चिंताएँ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी फैल सकती हैं

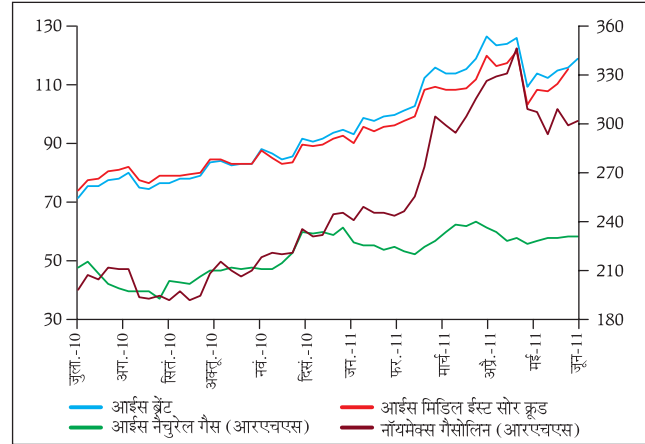
2.8 यूरोपीय ऋण की चिंताएँ अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाओं ग्रीस, आयरलैंड, और पुर्तगाल से संबंधित हैं। इसके बड़ी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में पहुँच जाने के प्रारंभिक लक्षण दिखायी देते हैं। एस एंड पी और फिच ने इटली और बेल्जियम को मई 2011 में नकारात्मक दृष्टिकोण पर रखा है। आनेवाले समय में दोनों देशों में भारी ऋण, कठिन राजकोषीय संभावनाएँ और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं। इस कदम से पस्त यूरो क्षेत्र के लिए अतिरिक्त दबाव पड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते ऋण और घाटे ने भी रेटिंग एजेंसियों का ध्यान आमंत्रित किया है। उनके द्वारा व्यक्त चिंताओं को अभी तक इन सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थाओं की लंबी अवधि के ऋण पर जोखिम या अवधि प्रीमियम को खारिज नहीं किया है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वित्तीय बाजारों से बड़ी रकम जुटाने की आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय बैंकों, मुख्य रूप से यूरोपीय बैंकों की महत्वपूर्ण धनवापसी अपेक्षाओं के साथ संपातिक है। इन बैंकों द्वारा पुनर्वित्त के बचाव को न केवल घरेलू सर्वोत्तम आस्तियों के साथ, बल्कि उभरते बाजारों की आस्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा में ले जाना होगा जिन्हें अधिक अनुकूल जोखिमधारक विशेषताएँ माना जाता है।

भू राजनीतिक तनाव और मुद्रास्फीतिजनित मंदी जोखिम

2.9 अरब दुनिया में सतत तनाव और लीबिया में सैन्य संघर्ष का ऊर्जा बाजारों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। वित्तीय बाजारों में आम तौर पर राजनीतिक जोखिम लेने की भूख कम ही होती है। लीबिया में हिंसा के कारण इक्विटी, बांड, ऋण, और विदेशी मुद्रा बाजार सुधर गए हैं। लीबिया में चल रहे लंबे संघर्ष के साथ ही संभवतः फुकुशीमा के पश्चात परमाणु ऊर्जा की क्षमता के बारे में अनिश्चितताएँ, ऊर्जा की वैश्विक कीमतों पर निरंतर ऊर्ध्वगामी दबाव डालती हैं (चार्ट 2.7)। यह न सिर्फ उभरती मध्यम अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) बल्कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एईए) में जहाँ विकास अभी भी उत्तम स्तर पर नहीं है-मुद्रास्फीति के दबावों के बारे में मौजूदा चिंताएँ पैदा कर सकता है।

2.10 तेल उद्योग की आपूर्ति की गतिशीलता हमेशा से कम अतिरिक्त क्षमता और इन्वेंट्री स्तरों के कारण व्यवधान प्रवण रही है (चार्ट 2.8)। ऐसे राजनीतिक तनाव के दौरान एहतियाती अंबार लगाने के कारण ऊर्जा बाजार में कीमतों में वृद्धि को बढ़ा सकता है जिससे आयातक देशों में संकट पैदा हो सकता है। उसी प्रकार, जब मूल्य की गति तीव्र होती है, उत्पादकों द्वारा अर्जित किया गया उच्च राजस्व, दूसरों के लिए किसी भी निर्यात क्षमता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि में परिवर्तित नहीं होता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहे हैं जब विश्व में खाद्य और ऊर्जा की उच्च मुद्रास्फीति व्याप्त है। यदि अशांति बड़े तेल निर्यातकों तक फैल जाए तो तेल की आपूर्ति में होनेवाले झटकों के कारण दशकों पहले की मुद्रास्फीतिजनित मंदी के पुनःउभराव से इंकार नहीं किया जा सकता।

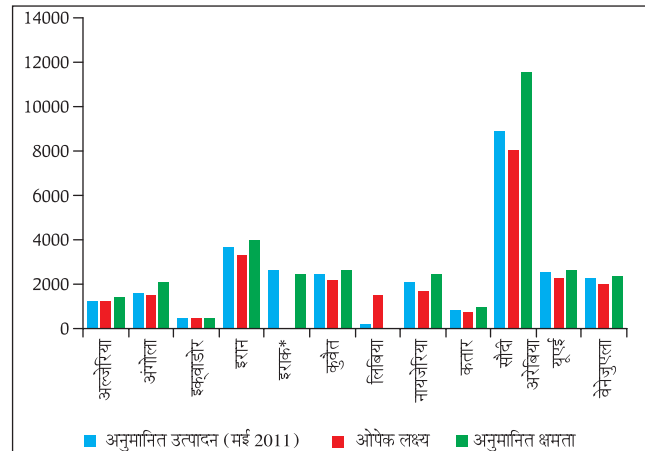
चार्ट 2.7: निकट में ऊर्जा का भावी मूल्य (अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.8: ओपेक क्षमता विरुद्ध वास्तविक उत्पादन और ओपेक कोटा

(000 बैरल प्रतिदिन)



* इराक को कोई औपचारिक उत्पादन ओपेक कोटा नहीं है
स्रोत: ब्लूमबर्ग

कमोडिटी बाजार के वित्तीयकरण से आस्ति सहसंबंध बढ़ जाता है

2.11 कमोडिटी की कीमतों ने (चार्ट 2.9) वैश्विक समुत्थान बाद से एक सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार किया है तथा आलोच्य अवधि के दौरान इसे जारी रखा गया। पण्य की कीमतों में घूर्णनों की व्याख्या प्रायः वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से उभरती मध्यम अर्थव्यवस्थाओं की बदलती संभावनाओं के प्रारंभिक संकेतक के रूप में की जाती है। ऊर्जा और कमोडिटी बाजार के बढ़ते वित्तीयकरण अर्थात् प्रतिभूतिकृत कमोडिटी से जुड़े उपकरणों जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, संरचित उत्पादों और अन्य उपायों के माध्यम से निवेश के बजाय जोखिम प्रबंधन उपकरण माना जाता है इनके कारण यह आशंका पैदा हो गयी है कि वास्तविक बचाव करनेवालों (हेजर) को भीड़ जैसे ठेल दिया जाएगा। तथापि, आज उच्च कमोडिटी कीमतों के लिए वित्तीय निवेशकों के जिम्मेदार होने के कोई सबूत नहीं है। हालांकि उनकी कार्रवाई से कीमतों में अस्थिरता आ सकती है और वित्तीय और कमोडिटी बाजार (चार्ट 2.10) का सहसंबंध जोड़ा जा सकता है। यह घटना दबाव का तेज उत्सर्जन कमोडिटी से वित्तीय बाजारों में कराने में सहायक होता है।

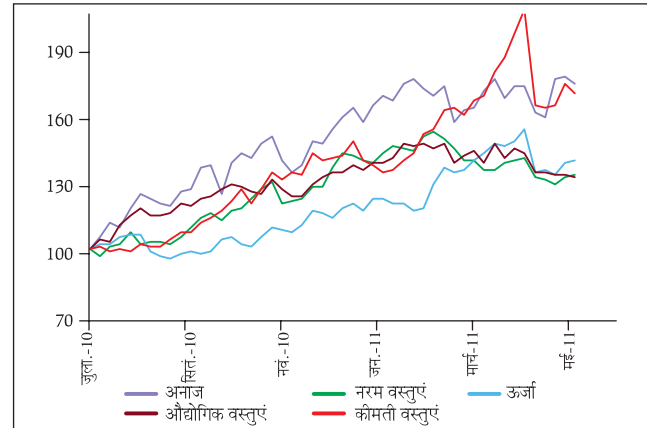
घरेलू बाजार

2.12 घरेलू बाजार बिना किसी दबाव के अनुशासित बने रहे। यह वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआई)⁵ (चार्ट 2.19) द्वारा प्रमाणित होता है।

स्वायत्त कारकों से बैंकिंग प्रणाली की तरलता का घाटा बना रहता है

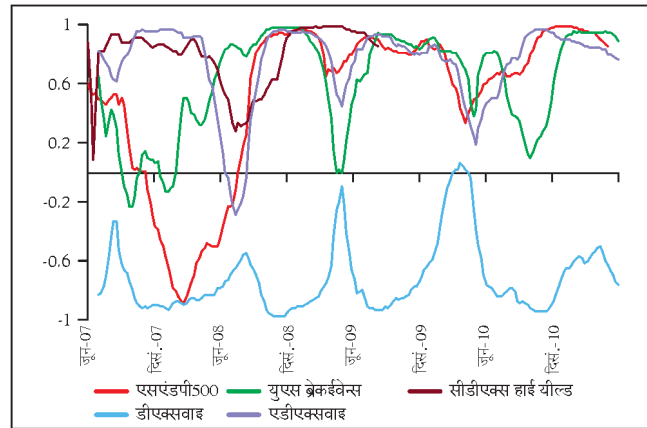
2.13 जैसा कि रिजर्व बैंक (चार्ट 2.11) के चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के परिचालन में परिलक्षित होता है लगभग एक वर्ष से बैंकिंग प्रणाली की तरलता की स्थिति घाटे की बनी हुई है। बैंक ऋण में अपेक्षित रिजर्व वृद्धि और शुद्ध मांग और समय देयताएं (एनडीटीएल) और संचरण - मुद्रा में वृद्धि इसे प्रभावित करने वाले कारक रहे हैं। वित्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक के पास रखे सरकारी नकदी शेष में तीव्र मोड़ आने के बावजूद प्रणाली में तरलता की स्थिति घाटे की रही जो अर्थव्यवस्था की तरलता अपेक्षाओं में वृद्धि को दर्शाती है। तरलता की स्थिति में अस्थिरता को रिजर्व बैंक द्वारा सक्रियतापूर्वक प्रबंध करने की आवश्यकता है।

चार्ट 2.9: कमोडिटी मूल्य चलन⁴
(सामान्यीकृत, 2 जुलाई 2010 = 100)



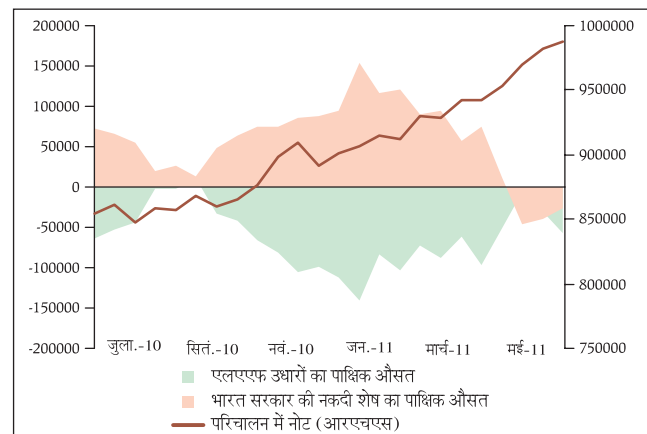
स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.10: विभिन्न आस्तियों के साथ 30 दिनों का रोलिंग कोररिलेशन रॉयटर्स-जैफरीज सीआरबी सूचकांक



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.11: बैंकिंग प्रणाली की तरलता को प्रभावित करनेवाले कारक



स्रोत: आरबीआई

⁴ चार्ट में वस्तुओं के विविध खंडों में प्रत्येक घटक रॉयटर्स-जैफरीज सीआरबी सूचकांक घटकों के अनुसार है।

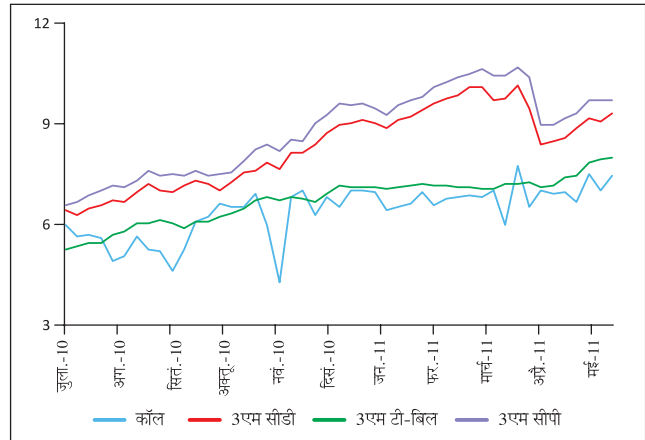
⁵ वित्तीय दबाव संकेतक गतिविधियों की समकालीन गंभीरता को पकड़ने के लिए बनाया गया है क्योंकि वह ईक्विटी बाजार, बांड बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और बैंकिंग क्षेत्र में प्रकट होते हैं। वित्तीय दबाव की परिभाषा इस प्रकार की जाती है- वित्तीय बाजार और संस्थाओं में अनिश्चितता और हानि के बदलते अनुमानों द्वारा आर्थिक एजेंटों पर पड़नेवाला दबाव। यह दबाव बढ़ता है क्योंकि वित्तीय हानि में वृद्धि की अनिश्चितता या अनुमान बढ़ता है। चर वस्तुओं का चयन उन की समयनिष्ठता, भविष्य की सूचनाएं और प्रणालीगत सुसंगतता तथा आंकड़ों की उपलब्धता के लिए किया गया है।

2.14 स्वायत्त और घर्षण कारकों के कारण चलनिधि स्थिति में कसावट मुद्रा बाजार दरों में परिलक्षित हुई (चार्ट 2.12)। कॉलमनी दरें आम तौर पर एलएएफ सुविधा के ऊपरी सीमा के आसपास मँडराती रही। इसी तरह, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) बाजार में ब्याज दरें कॉल दरों के आगे-पीछे रहीं, सिवाय 31 मार्च, 2011 तक एक संक्षिप्त अवधि के दौरान, जब बैंकों ने वार्षिक लेखाबंदी करने से पहले निधि उठायी। वाणिज्यिक पेपर (सीपी) और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दरों ने दोहरे अंक को छुआ और राजकोष बिल दर भी कुछ अवसरों पर 8 प्रतिशत से ऊपर उठी। संपार्श्विकीकृत क्षेत्रों में दर आम तौर पर कॉल दर के आगे-पीछे बनी रही तथा उससे नीची रहीं। संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व (सीबीएलओ) और बाजार रेपो क्षेत्रों में लेन - देन की मात्रा 2010-11 की तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में मामूली सुधार दिखाया। बैंक और प्राथमिक डीलर संपार्श्विकीकृत क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के प्रमुख समूह बने रहे जबकि म्यूचुअल फंड इन क्षेत्रों में निधि के प्रमुख उधारदाताओं के समूह में बने रहे। मुद्रा बाजार का संपार्श्विकीकृत खंड प्रमुख मुद्रा बाजार खंड बना रहा, जो इस अवधि के दौरान कुल मात्रा का 80 प्रतिशत से अधिक रहा।

2.15 समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकारी बांड प्रतिफल छोटी परिपक्वताओं के थोड़ा तेजी से बढ़ने के साथ ही प्रतिफल वक्र के पार बढ़े (चार्ट 2.13)। परिणामस्वरूप, प्रतिफल वक्र मंद पड़ गया। सेबी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए अनुपयोगी निवेश की सीमा की नीलामी की घोषणा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रैल - सितंबर की उधार राशि अपेक्षित से कम घोषित करने के कारण प्रारंभ में प्रतिफल का झुकाव नीचे गिरता हुआ था। तथापि, सितम्बर 2010 के बाद प्रत्येक अवसर पर (मई, अप्रैल, मार्च और फरवरी 2011 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) क्रमशः 9.1, 8.7, 8.9 और 8.3 प्रतिशत पर स्थिर रहे) मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक बढ़ने से प्रतिफल कठोर हो गए जिसने और अधिक मौद्रिक संकुचन की संभावनाएँ बढ़ा दी (चार्ट 2.14 और चार्ट 2.15)। जून के प्रारंभ में, दो वर्षीय बांड प्रतिफल 10 वर्षीय बांड से अधिक हो गए जिससे प्रतिफल वक्र में एक मामूली उलटाव आया।

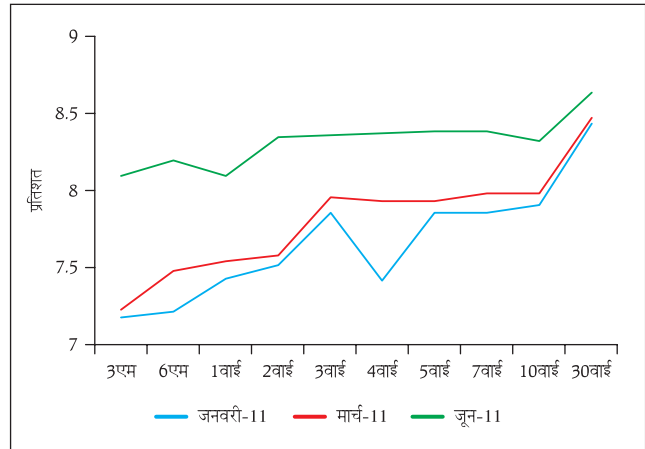
2.16 अनेक प्रतिकूल कारकों जैसे, कच्चे तेल की ऊँची कीमतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में मंदी के बावजूद आलोच्य अवधि के दौरान भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के विरुद्ध एक सीमा में बना रहा। प्रारंभ में इसे इक्विटी और ऋण पूंजी (ऋण पूंजी

चार्ट 2.12: भारत में मुद्रा बाजार की दरें (प्रतिशत में)



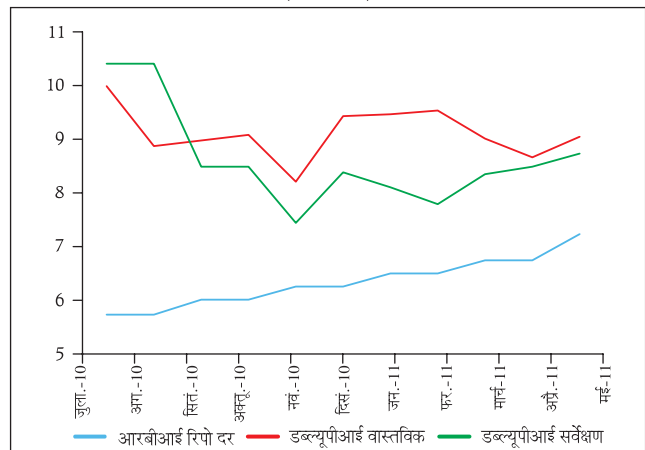
स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.13: भारतीय सर्वोत्तम प्रतिफल वक्र आकार



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.14: थोकमूल्य सूचकांक पूर्वानुमान⁶ तथा वास्तविक, तथा आरबीआई रिपो दर (प्रतिशत में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

⁶ थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करने से पूर्व व्यावसायिक अनुमानकर्ताओं, बैंक अर्थशास्त्रियों और निवेश विश्लेषकों के ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण का उपयोग किया गया है।

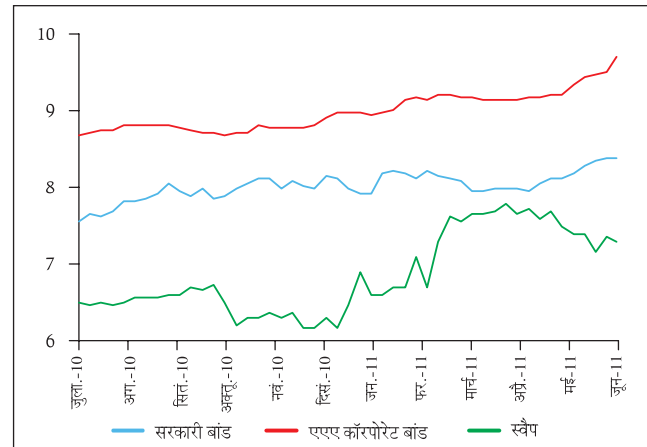
प्रवाह पिछले वर्ष के बाद से मजबूत बना रहा है) सहित निवेश सूची में समुत्थान होने (चार्ट 2.16) और चालू खाता घाटा में संकुचन होने से सहायता मिली थी। बैंकिंग पूंजी जिसमें 2010-11 की तीसरी तिमाही में निवल बहिर्गमन देखा गया था 2010-11 की चौथी तिमाही में सकारात्मक रूप में परिवर्तित हो गया। साथ ही अमेरिकी डॉलर की विश्वव्यापी सामान्य कमजोरी ने रुपये को लाभ दिलाया। उच्च मुद्रास्फीति और इस अवधि के दौरान अनुवर्ती दर में वृद्धि के परिणाम के रूप में इक्विटी बाजार में सुधार आया, रुपया जो अपने अधिकांश लाभ छोड़ चुका था, कमजोर हो गया।

वित्तीयकरण बनाम रुपया का अंतरराष्ट्रीयकरण

2.17 भारतीय रुपये की अपतटीय कारोबारी गतिविधियाँ बाजार सहभागियों के अनुमान से कहीं अधिक दर पर बढ़ रही है (2010, बीआईएस का त्रैवार्षिक सेंट्रल बैंक सर्वेक्षण। रॉबर्ट मैकाले और मिशेला स्काटिना (बीआईएस त्रैमासिक समीक्षा - मार्च 2011 और पूर्व में हो एट अल (2005) और मैकाले (2010)) द्वारा अपतटीय बाजारों की हिस्सेदारी पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन में मुद्रा व्यापार पर 'टर्नओवर' और 'स्थान' के लिए सरल मानक प्रदान करने के लिए कोशिश की गयी है तथा उन मानकों से विचलन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डाला है। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होने पर मुद्रा देशीय अर्थव्यवस्था में विशाल गुणकों में अंतरनिहित अंतरराष्ट्रीय कारोबार करती है ("वित्तीयकरण") तथा अपने देशीय बाजार से बाहर बड़े पैमाने पर कारोबार करती है ("अंतरराष्ट्रीयकरण")।

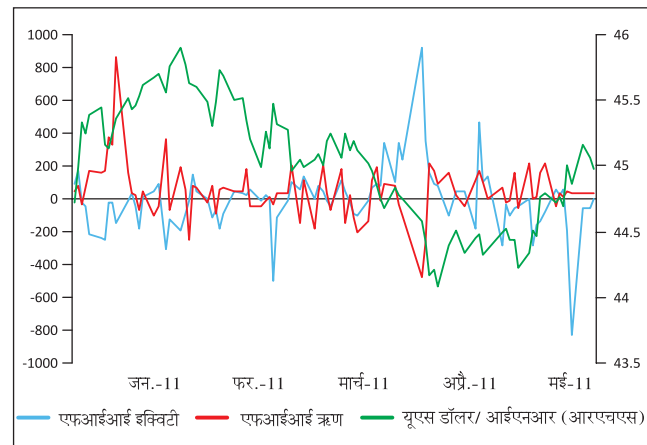
2.18 टर्नओवर और आय के बीच संबंधों के आधार पर, भारतीय रुपया दृढ़तापूर्वक टिका रहा क्योंकि, यह भारत के व्यापार (निर्यात और आयात) और आय के अनुपात में अधिक कारोबार करता है। इसे भारत के इक्विटी बाजार में अपेक्षाकृत बड़े एकमुश्त विदेशी निवेश द्वारा और तटवर्ती रुपया वायदा बाजार में तेजी के विकास द्वारा आंशिक रूप से समझा जा सकता है। साथ ही, भारतीय रुपये में टर्नओवर, जो, उच्च प्रतिलाभ देता है, वायदाबाजार में कैरी ट्रेड की रणनीति (दोनों वितरणयोग्य और गैर वितरणयोग्य) और वायदा (गैलेटी एट अल (2007)) से लाभान्वित होता है। चीनी रॉन्ग्मिन्बी की तुलना में भारतीय रुपये का अपेक्षाकृत उच्च वित्तीयकरण, भारत में अधिक उदार विदेशी मुद्रा शासन का होना दर्शाता है। भारत पहले से ही चालू खाता परिवर्तनीयता हासिल है और उसका पूंजी खाता अधिक खुला है।

चार्ट 2.15: 10 वर्ष परिपक्वता में बांड बाजार प्रतिफल (प्रतिशत में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.16: विदेशी संस्थागत निवेश इक्विटी तथा ऋण दैनिक निवल प्रवाह (अमेरिकी मिलियन डॉलर में) तथा स्रये की विनिमय दर



स्रोत: ब्लूमबर्ग

विदेशी मुद्रा उधार पर कंपनियों की बढ़ती निर्भरता

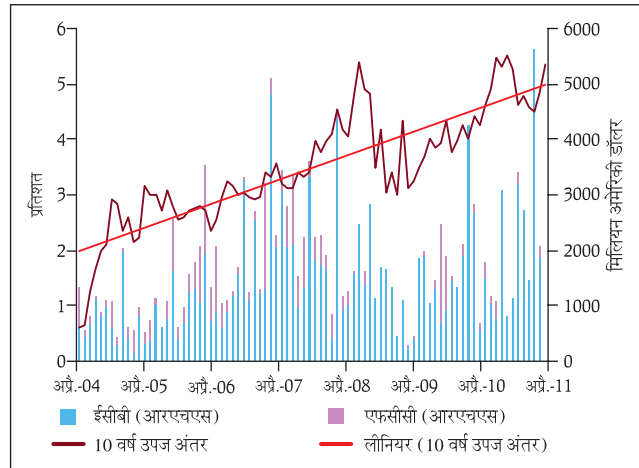
2.19 आई की तुलना में ईएमई में अपनायी गयी मौद्रिक नीति की द्विमार्गी वृद्धि तथा भिन्न मार्ग से ब्याज दर में अंतर बढ़ रहा है। इसका ईएमई (चार्ट 2.17) में ब्याज दर संवेदी पूंजी प्रवाहों के लिए नैसर्गिक निहितार्थ है। पिछले कुछ महीनों में, रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बाह्य वाणिज्यिक उधार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा स्वमेव तथा अनुमोदित मार्ग दोनों के माध्यम से हुआ है (सारणी 2.1) तथा 2010-11 के लिए कुल बाह्य वाणिज्यिक उधार लगभग संकट के पूर्व स्तरों पर था। विदेशी मुद्रा उधार पर कंपनियों की बढ़ी हुई निर्भरता से उनके तुलनपत्रों में मुद्रा असंतुलनों में भी वृद्धि होती है।

देशी बैंक ऋण का प्रतिस्थापन

2.20 भारत में कंपनियों के लिए बैंक ऋण हमेशा से ही निधीयन का प्रमुख स्रोत रहा है। तथापि, विदेशी मुद्रा ऋण आसानी से उपलब्ध होने तथा देशी वैकल्पिक निधीयन चैनल उपलब्ध होने के चलते, विशेषकर कंपनी ऋण बाजार, अब वित्तीय प्रणाली में कुछ अमध्यस्थता देखने में आ रही है। बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा कंपनी बांड बकाया राशियों के बीच संबंधों को दिखलाने के लिए एक आंतरिक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के लिए बैंक बकाया ऋण ग्रेंगर कौजेलिटी परीक्षण वीएआर (1)⁷ फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया। इन तीनों वेरिफबल का पहला लाग अंतर मॉडलिंग प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया गया। कंपनी बांड की बकाया राशियों में परिवर्तनों के लिए ग्रेंगर कौजेलिटी का परिणाम तथा बकाया बैंक ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधार सारणी 2.2 में दिया गया है जबकि बैंक ऋण ईक्वेशन के लिए अनुमानित पैरामीटर सारणी 2.3 में दिये गये हैं।

2.21 यह देखा जा सकता है कि नल धारणा - कंपनी बांड तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार संयुक्त रूप से बैंक ऋण में परिवर्तन नहीं लाते - स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, दो वेरिफबल, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा कंपनी बांड संयुक्त रूप से बैंक ऋण पर प्रभाव डालते ही हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा कंपनी बांड के को-एफीशिएन्ट नकारात्मक होते हैं, जिसका मतलब है कि दो वेरिफबल में वृद्धि के कारण रुपये की प्रमुखता वाले देशी बैंक ऋण में कमी हो जाती है। चूंकि मूल्य तथा राशि के लिए विदेशी मुद्रा उधार विनियमित होता है, इसलिए पूंजी खाता प्रबंधन फ्रेमवर्क को देखते हुए, बैंकिंग प्रणाली से हटकर सही अमध्यस्थता उल्लेखनीय रूप से गहन कंपनी बांड बाजार के विकास पर निर्भर करेगी।

चार्ट 2.17 : 10-वर्ष में ईसीबी तथा एफसीसीबी प्रवृत्ति तथा ब्याज दर विभेदकों की प्रवृत्ति



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और ब्लूमबर्ग

सारणी 2.1 : रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत ईसीबी (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
ईसीबी	22,224	15,462	17,363	24,481
एफसीसीबी	6,103	463	3,362	1,270
जोड़	28,327	15,925	20,725	25,751

सारणी 2.2 : वीएआर ग्रेंगर कौजेलिटी

अपवर्जित चर	डीएल कॉरपोरेट बांड	डीएलईसीबी	सभी
ची-एसक्यू	5.94	2.36	7.50
पी- मूल्य	0.01	0.12	0.02

स्रोत: आरबीआइ स्टाफ की गणना

सारणी 2.3 : पैरामीटर अनुमान

इक्वेशन	वेरिफबल	पैरामीटर अनुमान	पी- मूल्य
डीएलबैंक_क्रेडिट	कॉन्स्टेंट	0.10	0.00
	डीएलबैंक_क्रेडिट (-1)	-0.28	0.11
	डीएलईसीबी (-1)	-0.13	0.14
	डीएल कॉरपोरेट-बांड (-1)	-0.45	0.02

स्रोत: आरबीआइ स्टाफ की गणना।

⁷ वेक्टर ऑटोरेग्रेसन (1)

राष्ट्रीय तुलन पत्र में बढ़ता करेंसी असंतुलन

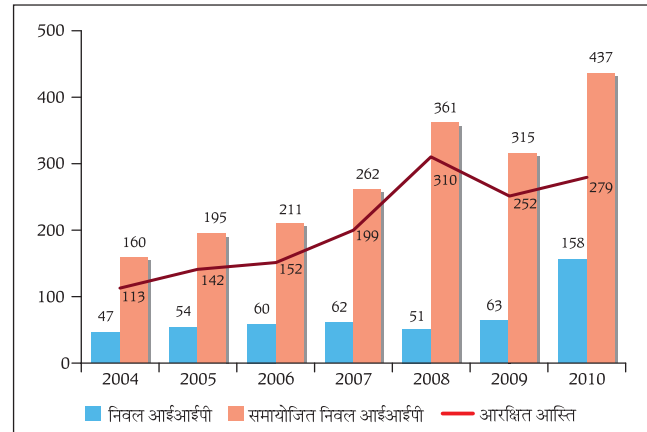
2.22 पिछले कुछ वर्षों में भारतीय फर्मों की बाह्य उधारियों पर बढ़ती निर्भरता की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में देश की बढ़ती हैसियत को दर्शाती है। अनिवासियों की तुलना में बढ़ती हुई निवल देयता स्थिति के साथ पिछले कुछ वर्षों में अनिवासी की तुलना में बढ़ी हुई करेंसी जोखिम की तुलना में गैर-आधिकारिक क्षेत्र का एक्सपोजर बढ़ गया है (चार्ट 2.18)। भारतीय आस्तियों पर भारतीय मुद्रा में मूल्यवर्गित विदेशी दावे निवासियों के विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित विदेशी आस्तियों के दावे की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। भारत की निवल बाह्य देयताएं 31 मार्च 2004 के 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 31 मार्च 2010 को बढ़कर 158 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन बाह्य देयताओं में विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण भी शामिल हैं जो विदेश में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं ने घरेलू कंपनियों को उपलब्ध कराए हैं। पिछले कुछ वर्ष में ऐसी उधारियों में अनवरत वृद्धि हो रही है (सारणी 2.4)।

2.23 गैर-आधिकारिक क्षेत्र (चार्ट में समायोजित निवल आईआईपी के रूप में दर्शाया गया) की निवल देयता में और भी बढ़ोत्तरी हुई है एवं यह 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि गैर-आधिकारिक क्षेत्र का सकल अंतरण जोखिम स्थानीय मुद्रा यानी भारतीय रुपए में होने वाले अवमूल्यन से उत्पन्न होता है। अपनी आईआईपी में चीन की निवल आस्ति स्थिति है। इसकी निवल आईआईपी 2007 के 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2009 में 1.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है तथा इसका एक्सपोजर इसकी अपनी करेंसी रेनेंबी की वृद्धि के प्रति है। राष्ट्रीय तुलन पत्र का वैषम्य जोखिम एक्सपोजर विदेशी मुद्रा विनिमय दर की 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल⁸ मूल्यों में देखा जा सकता है। भारतीय रुपए के मामले में यह आंकड़ा सदैव सकारात्मक ही रहा है मगर चालू खाते में बेशी से समर्थित चीनी रेनेम्बी केवल 2008-09 के अत्यधिक जोखिम प्रतिकूलता के दौरान शून्य से ऊपर उठ सकी (चार्ट 2.19)।

कंपनियों के बढ़ते धन-वापसी जोखिम

2.24 2005-06 से 2007-08 के तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय फर्मों ने उस समय बेहद लोकप्रिय विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड

चार्ट 2.18: भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

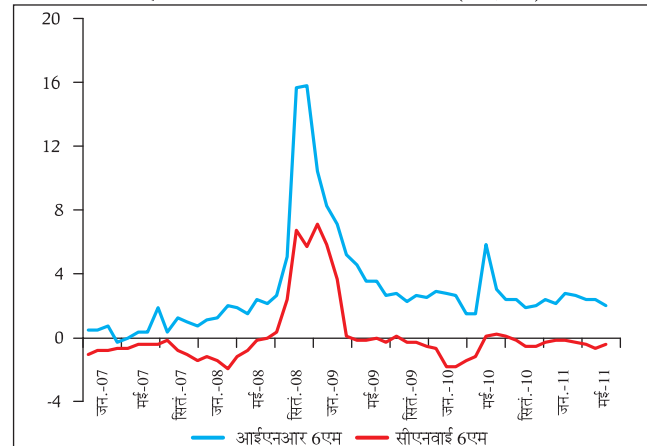
सारणी 2.4: ईसीबी के उधारदाताओं का प्रोफाइल (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
कुल ईसीबी	28,327	15,925	20,725	25,751
इन्होंने उधार दिया:				
भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं	2,880 (10.2)	1,495 (9.4)	2,303 (11.1)	5,127 (19.9)
विदेशी बैंक	17,272 (61.0)	8,864 (55.7)	8,438 (40.7)	13,692 (53.2)
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	1,180 (4.2)	2,643 (16.6)	3,133 (15.1)	2,849 (11.1)
अंतरराष्ट्रीय निवेशक	6,373 (22.5)	463 (2.9)	3,334 (16.1)	1,455 (5.7)
विदेशी सहयोगी/ईकविटी धारक	621 (2.2)	2,458 (15.4)	3,514 (17.0)	2,597 (10.1)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक श्रेणी के उधारदाता के प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 2.19: अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए तथा अमेरिकी डॉलर/सीएनवाई हेतु 6 महीने की परिपक्वता में 25 डेल्टा रिस्क रिवर्सल (प्रतिशत में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

⁸ रिस्क रिवर्सल आउट-ऑफ-दि-मनी आप्शन की मांग के कम अंकन की तुलना में उच्च अंकन तिरछा (स्क्यू) है क्योंकि आप्शन बाजार का रुख अगली परिपक्वता तारीख पर स्पॉट मूवमेंट का संभावित निदेश होगा। इसको बेस करेंसी पर पुट आप्शन की निहित अस्थिरता घटाते हुए कॉल आप्शन की निहित अस्थिरता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय रुपए तथा चीनी यूआन दोनों के लिए ही बेस करेंसी अमेरिकी डॉलर ही है। सकारात्मक संख्या का मतलब है कि यदि अमेरिकी डॉलर में पुट आप्शन या अन्यथा की तुलना में बाजार प्रतिभागी कॉल आप्शन में खरीद के लिए कुछ अधिक कीमत देने के लिए तैयार हैं।

(एफसीसीबी) के माध्यम से विदेशी मुद्रा उगाही। ऐसे बांडों पर परिवर्तनीय कीमत जारी करते समय की स्टाक कीमत की तुलना में 25-150 प्रतिशत ज्यादा थी तथा इन पर शून्य या बहुत ही कम कूपन था। 2005-08 में जारी होने वाले एफसीसीबी की वृद्धि से यह प्रदर्शित होता है। फर्मों द्वारा दाखिल किए गए विवरणियों के अनुसार एफसीसीबी से प्राप्त धन विदेशी अधिग्रहण (19 प्रतिशत) एवं पूंजीगत माल (16 प्रतिशत) के आयात के लिए था।

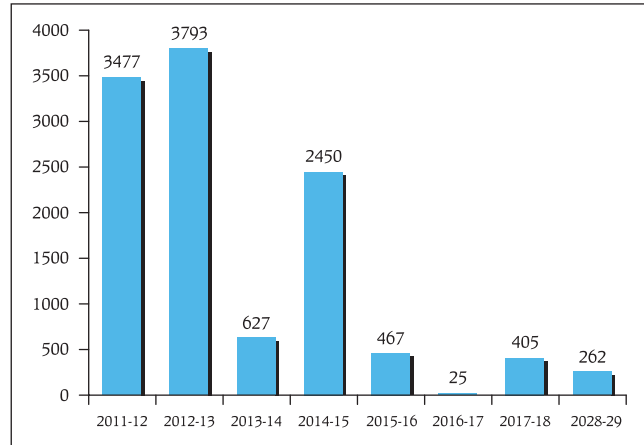
2.25 सामान्यतः पांच या इससे अधिक वर्ष की अवधि की परिपक्वता वाली एफसीसीबी का मूल्य 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक था और ये मार्च 2013 में परिपक्व हो रही हैं (चार्ट 2.20)। क्रिसिल के अनुमान के अनुसार "220-240 बिलियन रुपए की एफसीसीबी ईक्विटी शेयर में परिवर्तित नहीं होंगी क्योंकि जारीकर्ता कंपनियों के शेयर की कीमत परिवर्तित कीमत से काफी नीचे चल रही है। निफ्टी जनवरी 2008 की अपनी ऊंचाई से अभी केवल 10 प्रतिशत नीचे चल रहा है। आधे से ज्यादा बकाया राशि की एफसीसीबी वाली इन कंपनियों में से कई जनवरी 2008 के अपने मूल्य से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा कम मूल्य पर ट्रेड हो रही हैं।" कुछ फर्मों अगले दो वर्ष में निधि संबंधी समस्या का गंभीर सामना कर सकती हैं जो कि केवल उनके उद्योग तक ही सीमित नहीं रहेगी।

पोर्टफोलियो पूंजी की भेड़चाल

2.26 2010 में भारतीय पूंजी बाजार को बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा व्यापार ऋण के तहत मिली बड़ी राशि के अलावा निवल पोर्टफोलियो पूंजी प्रवाह (ईक्विटी में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा ऋण में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर) में बड़ी मात्रा में राशि प्राप्त हुई है। अगस्त तथा अक्टूबर 2010 के बीच पोर्टफोलियो ईक्विटी पूंजी के तहत 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि "अर्थमितीय परिणाम दर्शाते हैं कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पोर्टफोलियो प्रवाह जारी रहेगा एवं उच्च स्तर का सहसंबंध रहेगा.....उच्च स्तर का प्रवाह कई बार भेड़चाल का परिणाम होता है।"

2.27 प्रवाह की सुदृढ़ता की जांच के लिए 2007 की विभिन्न अवधियों हेतु भारत में पूंजी प्रवाह हेतु सहसंबंध की जांच की गई (सारणी 2.5)। इससे ज्ञात होता है कि पोर्टफोलियो ईक्विटी प्रवाह सहसंबंधित (पर्याप्त रूप से सांख्यिकी रूप में) हैं जबकि कर्ज प्रवाह पहले और दूसरे क्रम में नहीं हैं (दैनिक अवलोकनों का पहला और दूसरा चरण)। निवल समग्र पोर्टफोलियो प्रवाह भी सभी अवधियों हेतु सहसंबंधित (सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण) होते हैं,

चार्ट 2.20: एफसीसीबी का मोचन प्रोफाइल (मिलियन अमेरिकी डॉलर)



नोट: मार्च 2011 के अनुसार मोचन प्रोफाइल

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

सारणी 2.5: भारत में ईक्विटी तथा ऋण में दैनिक निवल विदेशी संस्थागत निवेशक प्रवाह हेतु प्रथम तथा द्वितीय चरण में स्वसहसंबंध गुणांक

अवधि	चरण	एफआईआई ऋण	एफआईआई ईक्विटी	कुल एफआईआई
जनवरी 2007 से मई 2011 तक	1	-0.03(0.39)	0.41(0.00)	0.29(0.00)
	2	0.04(0.33)	0.29(0.00)	0.24(0.00)
जनवरी 2010 से मई 2011	1	0.23(0.00)	0.43(0.00)	0.36(0.00)
	2	0.05(0.00)	0.33(0.00)	0.25(0.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जांच सांख्यिकी हेतु पी-मान हैं। यह महत्व का न्यूनतम स्तर है जो कि शून्य कल्पना है जो यह बताती है कि जांच सांख्यिकी का कोई भी सहसंबंधता नहीं है (निर्दिष्ट: चरण स्तर तक)।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना, ब्लूमबर्ग

⁹ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अक्टूबर 2010।

पर इन पर ईक्विटी प्रवाह का प्रभुत्व रहता है। भारत में सरकार एवं कॉरपोरेट बांड बाजार में विदेशी संस्थागत निवेश के ऋण प्रवाह पर समग्र उच्चतम सीमा है।

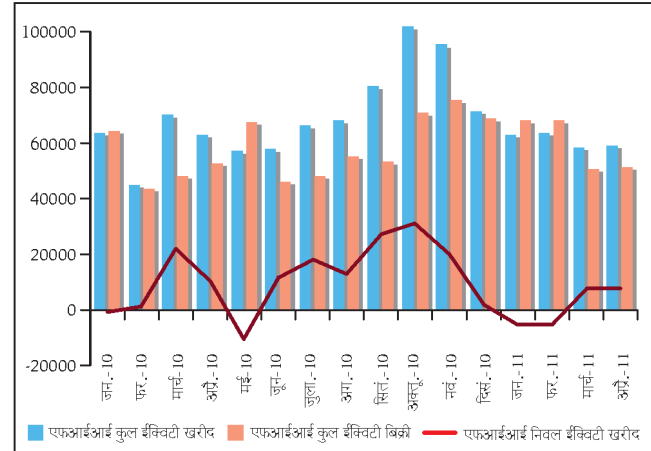
2.28 अध्ययन यह दर्शाता है कि पूंजी प्रवाह पिछली प्रवृत्ति से प्रभावित रहता है। भारत सरीखे उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में फंड द्वारा आरंभिक निवेश की सफलता प्रायः स्व-समर्थित होती है जिससे यही फंड और आबंटन करता है जिसके चलते अन्य इसका अनुकरण करते हैं। इसी तरह, दबाव के समय कुछेक के द्वारा किया गया आहरण भेड़चाल के चलते विपरीत असर डालता है चाहे भले ही बुनियाद मजबूत होने के कारण किसी भी तरह की कार्रवाई की आवश्यकता न रही हो। मध्य-पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका (एमईएनए) की जिन परेशानियों का जिक्र ऊपर किया गया है उन्होंने वैश्विक बाजारों को अस्थिर किया है एवं इससे अत्यधिक उथल-पुथल एवं जोखिम प्रतिकूलता की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

ऋण अंतर्वाह से ईक्विटी बहिर्वाह का प्रतिसंतुलन

2.29 भारत में जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों के पैसा बाहर निकालने से ईक्विटी बाजारों में गिरावट आई है वहीं बांड का बाजार सापेक्षतः स्थिर रहा है। जनवरी तथा फरवरी 2011 में ईक्विटी बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवल बहिर्वाह बांड बाजार के निवल अंतर्वाह के प्रति संतुलन से अधिक रहा है(चार्ट 2.21 एवं 2.22)। बांड बाजार में अंतर्वाह का कारण हाल ही में कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश की वृद्धि था तथा एक हकीकत यह भी है कि अंतर बैंक बाजार में चलनिधि की संकुचित स्थिति से बांड का प्रतिफल पिछले कई बरसों में अपनी ऊंचाई पर है।

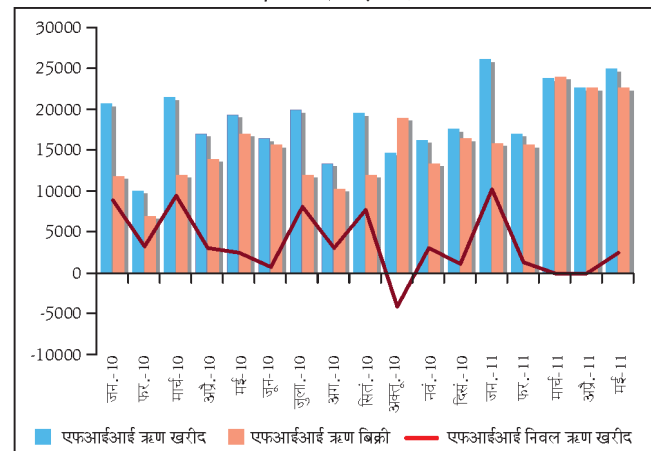
2.30 अमेरिकी फेड तथा अन्य केंद्रीय बैंकों की आसान मौद्रिक नीति के अनुसरण तथा इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई वैश्विक चलनिधि ने अब तक घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति पर थोड़ा असर डाला है। ऐसी नीतियों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए रिजर्व बैंक नीतिगत लिखतों के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करने के लिए दृढ़संकल्प है। साथ ही, यह समझना चाहिए कि वैश्विक रिकवरी को तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः अपनी संभाव्य वृद्धि को पुनः हासिल न कर ले एवं संकट-पूर्व की अपने न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को हासिल न कर ले। यह सब हासिल करने के लिए बनाई गई कोई भी अमेरिकी नीति उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के हित में है तथा इन सबको हासिल करने के लिए बनाई गई नीतियों के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पूर्ववर्ती को अपने पास उपलब्ध समुचित नीतिगत लिखतों का सहारा लेना चाहिए।

चार्ट 2.21: ईक्विटी बाजार में एफआईआई की कुल मासिक खरीद एवं बिक्री (करोड़ ₹ में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 2.22: ऋण बाजार में एफआईआई की कुल मासिक खरीद एवं बिक्री (करोड़ ₹ में)



स्रोत: ब्लूमबर्ग

भारतीय ईक्विटी में स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग से अल्गोट्रेडिंग सुगम बनाना

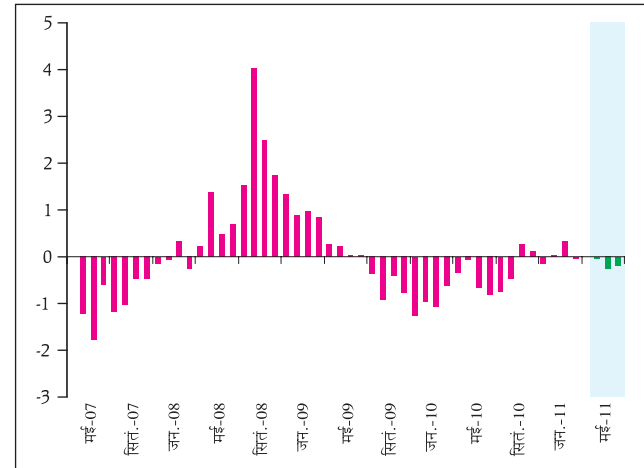
2.31 स्टाक एक्सचेंजों एवं बाजार सहभागियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने एसओआर की सुविधा उपलब्ध कराई है जिससे ब्रोकर का ट्रेडिंग इंजन कीमत, लागत, गति, निष्पादन और निपटान, आकार, स्वरूप या आदेश के निष्पादन से संबंधित अन्य किसी तथ्य¹⁰ को क्रमवार तरीके से चुन सके। इस सुविधा से ब्रोकर उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग (एचएफटी) या अल्गोट्रेडिंग (बॉक्स 2.1) के माध्यम से विभिन्न ट्रेडिंग स्थानों (स्टाक एक्सचेंज) पर ग्राहकों के आदेशों को दक्षतापूर्वक सर्वोत्तम कीमतों पर पूरा कर सकेंगे। भारतीय प्रतिभूति बाजार ने पिछली सर्वांगी घटनाओं के प्रति बेहतरीन लचीलापन दिखाया है। इसे 'आकस्मिक तबाही' के प्रति सुरक्षा चाहिए जिसने 06 मई 2010 को अमेरिकी ईक्विटी बाजार को धराशायी कर दिया था।

एफएसआई की भविष्यवाणी के अनुसार सुसाध्य स्थितियां अगस्त 2011 तक ही हैं

2.32 वित्तीय दबाव संकेतक वह उपाय है जो कि घटनाओं की समकालीन स्थिति को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है क्योंकि ये ईक्विटी बाजार, बांड बाजार, विदेशी मुद्रा विनियम बाजार तथा बैंकिंग सेक्टर को पारदर्शी

बनाता है। एफएसआई की भविष्यवाणी करने के लिए एकल चर समय श्रृंखला (यूनीवेरिएट टाइम सीरिज एनालाइसिस) मॉडल (अरीमा, आर्च एवं गार्च) का प्रयोग एफएसआई के प्रत्येक संघटक संकेतक की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया है। अगस्त 2011 तक की अवधि हेतु प्रस्तावित एफएसआई के 0.9 के निर्मित सीमा मान¹¹ (कनस्ट्रिक्टेड थ्रेसहोल्ड वैल्यू) से काफी नीचे है (चार्ट 2.23)।

चार्ट 2.23 वित्तीय तनाव संकेतक (अगस्त 2011 तक के अनुमान हरे रंग में)



निष्कर्ष टिप्पणी

2.33 पिछली एफएसआर के जारी होने के बाद से पिछले कुछ महीनों में स्थिरता के समष्टि आर्थिक माहौल में सुधार आया है। तथापि, कतिपय परेशानियां बरकरार हैं जिनमें से कुछ तबसे बढ़ी ही हैं। यूरोप में सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण की स्थिति बाकी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी फैल रही है जो कि एक बड़ी समस्या है तथा जिसका प्रणालीगत महत्व बहुत ही ज्यादा है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ मांग एवं वृद्धि की कॉमोडिटी की कीमतों पर सुदृढ़ संरचनागत एवं चक्रीय असर होता है मगर उच्चतर कल्पित हितों के साथ कॉमोडिटी बाजार के बढ़ते हुए वित्तीयकरण से कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं एवं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति एवं वृद्धि के बीच चुनाव की दुविधा पैदा हो जाती है तथा इससे अस्थिरता बढ़ जाती है। कॉमोडिटी बाजार में इससे उत्पन्न होने वाले आघात अन्य बाजारों में भी फैल जाते हैं। विशेषतः यदि बांड बाजार की संवेदनाएं मुद्रास्फीति के भय के चलते प्रभावित होती हैं तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के वे बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान जो अभी वित्तीय संकट की त्रासदी से उभर ही रहे हैं वे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। समीक्षाधीन अवधि में घटी दो महत्वपूर्ण

प्रणालीगत घटनाओं अर्थात् लीबिया का संघर्ष (एमईएनए की अशांति सहित) एवं जापान में आए भूकंप का असर अब तक सीमित ही रहा है। यदि एमईएनए में तनाव बरकरार रहता है एवं इसका असर क्षेत्र की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है तो भारतीय वित्तीय बाजार पर इसके असर को रोक पाना दुरूह होगा विशेषतः उस स्थिति में जब भारत की राजकोषीय स्थिति में सुधार की स्थिति धीमी रहने के आसार हैं।

2.34 भारत में ऊंची मुद्रास्फीति एवं ब्याज दर में की गई वृद्धि ने विदेशी उधारी को ब्याज दर अंतर एवं ऋण की उपलब्धता के चलते आकर्षक बना दिया है। अब फर्में धन उगाहने के लिए विदेशी बाजार खोज रही हैं मगर इस कारण होने वाली विदेशी मुद्रा देयता की स्थिति में सुधार के लिए कुछ भी किए बिना ही यह किया जा रहा है। इसके अलावा, इनमें से कई अगले दो वर्ष में एफसीसीबी की परिपक्वता की स्थिति का सामना करेंगे। निवासियों की ऊंची एवं बढ़ती हुई निवल बाध्य देयता स्थिति देश को उस जोखिम में डाल सकती है जहां करेंसी में तेज गिरावट का जोखिम हो सकता है। अन्यत्र कहीं की जा रही निभावी मौद्रिक नीतियों के संभाव्य दुष्प्रभाव से निपटने के लिए समुचित नीतिगत कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी।

अध्याय III

वित्तीय संस्थाएं

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बैंकों को मंद ऋण वृद्धि का निरंतर सामना करना पड़ा। इसके साथ ही, उन्हें निधियों के अपर्याप्त तथा कमजोर पूंजीकरण का भी सामना करना पड़ा जो अभी भी जनता से सहायता पर निर्भर है। नवीकृत सरकारी ऋण जोखिम, विशेषकर यूरो क्षेत्र में, के कारण बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत, भारत में, बैंक पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं और पिछले वर्ष की तुलना में उनकी आस्ति-गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2009-10 में देखी गई मंद वृद्धि की तुलना में, 2010-11 में ऋण के उपयोग में मजबूत वृद्धि दिखलाई पड़ी। इन गतिविधियों के बीच, ऋण वृद्धि में उछाल को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अक्सर कुछ कम कड़े ऋण जोखिम आकलन तथा ऋण चक्र में कमी के दौरान आस्तियों को क्षति पहुंचा सकती है। अर्थव्यवस्था में मंदी के डर से मौद्रिक सख्त तथा समष्टि आर्थिक उपायों के चलते ऋण वृद्धि के जारी रहने के बारे में भी आशंका उत्पन्न हो गई। हालांकि ओवर हीलिंग को रोकने के लिए मौद्रिक सख्ती तथा समष्टि विवेकपूर्ण उपाय भी किए गए। जमाराशियों तथा ऋण की वृद्धि दरों में बढ़ते असंतुलन के कारण बैंकों की चलनिधि स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दीर्घावधि की बुनियादी सुविधा परियोजनाओं में निरंतर बढ़ते एक्सपोजर के कारण उनकी आस्तियों तथा देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल में अंतरों जैसे अन्य संरचनात्मक घटकों के कारण भी ऐसा हुआ। किसी विशेष अवधि में बैंकिंग प्रणाली के कुछ चुनिंदा जोखिम पैरामीटर की सापेक्ष हलचल दिखलाने के लिए पिछली एफएसआर में प्रारंभ किए गए बैंकिंग स्थिरता मैप से पिछले वर्ष की तुलना में चलनिधि के बारे में जोखिम में कुछ वृद्धि का पता चला। तथापि, पिछली एफएसआर में ही प्रारंभ किए गए बैंकिंग स्थिरता संकेतक से समग्र बेहतर स्थिरता का पता चला। सहकारी क्षेत्र में, हालांकि शहरी सहकारी बैंकों को समेकित करने तथा उन्हें मजबूत बनाने के उपाय जारी रहे लेकिन इस संबंध में उठाए गए कदमों के कारण बिना लाइसेंस के ग्रामीण सहकारी बैंकों की संख्या में कमी हुई। तथापि, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं का वित्तीय मजबूती संकेतक चिंता का कारण बना रहा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निष्पादन में सुधार हुआ जिसके परिणामस्वरूप उनका मजबूती संकेतक भी बेहतर हो गया। इन कंपनियों की विनियामक संरचना में सख्ती जारी रही ताकि विनियामक अंतरों को कम किया जा सके तथा विनियामक आर्बिट्रिज को रोका जा सके। पहली बार एफएसआर में बीमा क्षेत्र को शामिल किया गया है। हालांकि जिस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र प्रणालीगत जोखिम में योगदान करता है, उस प्रकार बीमा क्षेत्र नहीं करता, लेकिन फिर भी वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख सहभागी होने के कारण यह वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में, कालांतर में बीमा क्षेत्र गहन और व्यापक हुआ है, विशेषकर इस क्षेत्र को निजी सहभागियों के लिए खोल देने के बाद और यह मजबूत तथा भली भांति विनियामित है।

संकट के बाद विश्व की स्थिति

वैश्विक प्रणाली में 'टू स्पीड रिकवरी' दिखाई देने के बावजूद सरकारी ऋण तथा बैंक निधीयन जोखिम वित्तीय अस्थिरता के प्रमुख स्रोत बने रहे

3.1 2011 तथा 2012 के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। इसके विपरीत, उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 6.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि केवल 2.5 प्रतिशत होने की आशा है। (वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ, अप्रैल 2011)। इस 'टू स्पीड रिकवरी' ने देशों के लिए अभूतपूर्व नीतिगत चुनौतियां सामने रख दी हैं।

3.2 सरकारी तुलन-पत्र वित्तीय अस्थिरता का एक प्रमुख स्रोत बने रहे, विशेषकर बैंकों के साथ उनकी परस्पर सम्बद्धता के कारण। दूसरी ओर, सार्वजनिक ऋण को बनाए रखने को लेकर चिंता ने बैंकों के तुलनपत्रों को प्रभावित किया है जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल फीडबैक लूप बन गए हैं। दूसरी ओर, सरकारी ऋण जोखिमों के कारण यूरो क्षेत्र में उथल-पुथल से निवेशकों की मांग में कमी आई है जिससे सरकारी यील्ड तथा सीडी स्प्रेड के साथ-साथ सरकारी निधीयन अनिश्चित हो गई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है - बैंकों तथा सरकारों का निधीयन, विशेषकर कुछ असुरक्षित यूरो क्षेत्र देशों में (चार्ट 3.1 तथा 3.2)

3.3 वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के कुछ खंडों को और अधिक आघात पहुंच सकता है। तुलनपत्रों में सुधार तथा उल्लेखनीय नीतिगत पहल के बावजूद, कुछ बैंकों की पूंजी अपर्याप्त है तथा वे बढ़ती निधीयन लागत से असुरक्षित हैं जो बढ़ते तथा अन्य बैंक सीडी स्प्रेड से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उधार की परिस्थितियां सहज होने के बावजूद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण वृद्धि मंद रही। इसके विपरीत, कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर एशिया तथा लेटिन अमेरिका में ऋण वृद्धि उच्च स्तरों पर पहुंच गई।

देशी गतिविधियां - अनुसूचित वाणिज्य बैंक

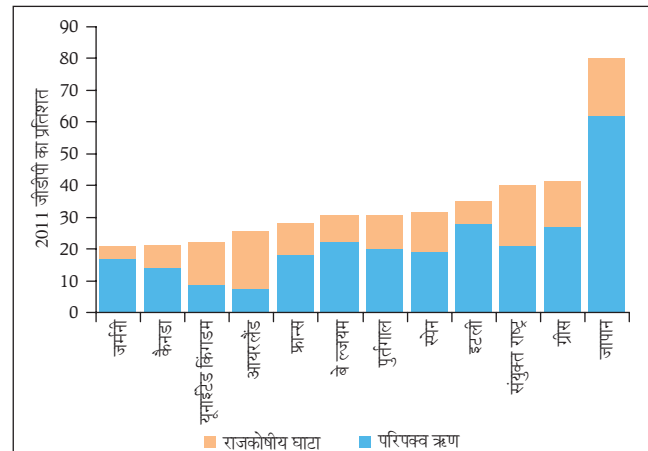
तुलन - पत्र

मजबूत ऋण वृद्धि के निधीयन के लिए बाजार की निधियों पर बढ़ती निर्भरता के कारण चिंता

3.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का तुलन-पत्र ढांचा¹ मजबूत बना रहा। तुलन-पत्र के देयता पक्ष में जमाराशियों की प्रमुखता बनी रही जबकि बैंक आस्तियों का प्रोफाइल, बैंकिंग बही के रूप में धारित, भी अपरिवर्तित रहा। तथापि, तुलन-पत्र के ढांचे में कुछ चिंता की बात दिखलाई पड़ी, अर्थात्, आस्तियों के निधीयन के लिए बाजार उधार पर बड़ी निर्भरता, आस्तियों तथा देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल में बढ़ते असंतुलन तथा आस्ति-क्षति में संभावित वृद्धि जो ऋण लेने में वृद्धि के बाद आ सकती है।

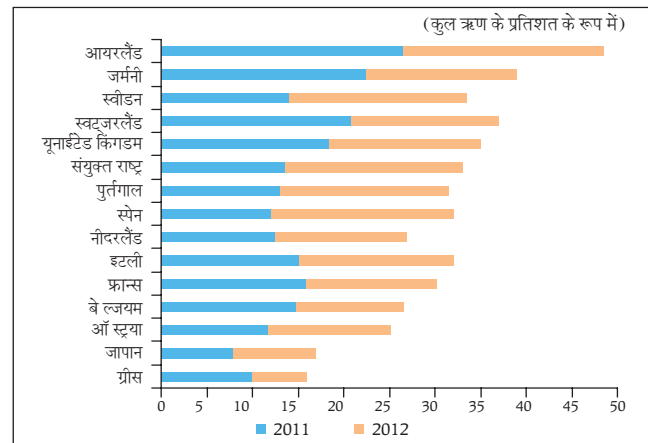
3.5 मार्च 2011 के अंत में, मुख्यतया बेहतर ऋण आफ टेक के कारण अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलन-पत्र के आकार में लगभग 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान बकाया ऋण में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (पिछले वर्ष में 17 प्रतिशत) (चार्ट 3.3)। इसके विपरीत, 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जमाराशियां कम रहीं। इस अंतर को बाजार से निधियां लेकर पूरा किया गया। (सीडी निर्गम तथा उधार) जो मार्च 2010 के अंत की स्थिति की तुलना में 34.5 प्रतिशत बढ़े। 2006 में 7.5 प्रतिशत

चार्ट 3.1: सरकारी निधीयन आवश्यकता



स्रोत: जीएफएसआर, अप्रैल 2011

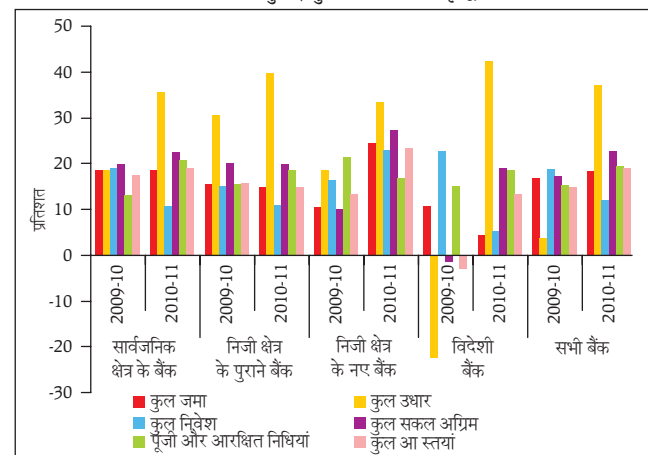
चार्ट 3.2: बैंकिंग निधीयन आवश्यकता



स्रोत: जीएफएसआर, अप्रैल 2011

टिप्पणी: आंकड़े प्रत्येक देश में नमूना बैंकों के लिए हैं।

चार्ट 3.3: चुनिंदा तुलन-पत्र घटकों में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

¹ निवेश कुल आस्तियों के 30 प्रतिशत होने के कारण जमाराशि कुल देयताओं के 79 प्रतिशत के बराबर हुई और ऋण निवेश संविभाग (अग्रिम और निवेश) आस्तियों के 87 प्रतिशत तक हो गए।

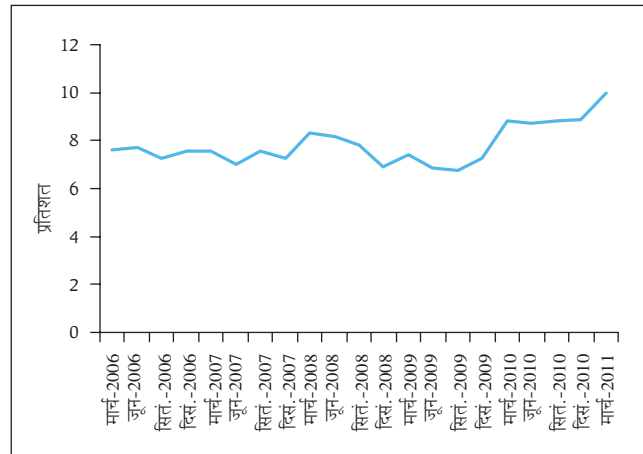
की तुलना में 2011 में बैंकों की देयताओं में उधार तथा सीडी का अंश बढ़ कर लगभग 10 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.4)।

3.6 उधार ली गई निधियों पर बैंकों की बढ़ी निर्भरता से उनकी चलनिधि की स्थिति के संबंध में चिंता उत्पन्न हो गई, विशेषकर यदि यह निर्भरता और भी बढ़ जाए। बैंकों की कुल आस्तियों (चार्ट 3.5) में तरल आस्तियों का अंश कम हो जाने के कारण यह चिंता और भी बढ़ गई। विशेषकर, प्रणालीगत चलनिधि में दबाव पड़ने पर, अक्टूबर 2010 से फरवरी 2011 के दौरान सीडी के अधिक निर्गम देखने में आए और ब्याज दरें बढ़ कर 9-10 प्रतिशत हो गईं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा नए निजी क्षेत्र के बैंकों में बाजार से उधार में वृद्धि विशेष रूप से दिखलाई पड़ी।

3.7 उधार ली गई निधियों पर बढ़ती निर्भरता के बारे में चिंता और भी बढ़ गई जब जमाराशियों तथा अग्रिमों की परिपक्वता प्रोफाइल में असंतुलन बढ़ गए। (एक वर्ष से कम) अग्रिमों की तुलना में अधिक जमाराशियों का पुनः मूल्यन किया जा रहा था, 1-3 वर्ष तथा 3-5 वर्ष के ब्रैकेट में जमाराशियों की तुलना में अधिक अग्रिम परिपक्व हो रहे थे (चार्ट 3.6)। इस असंतुलन के कारण बैंकों को उल्लेखनीय रोल ओवर जोखिम हुआ।

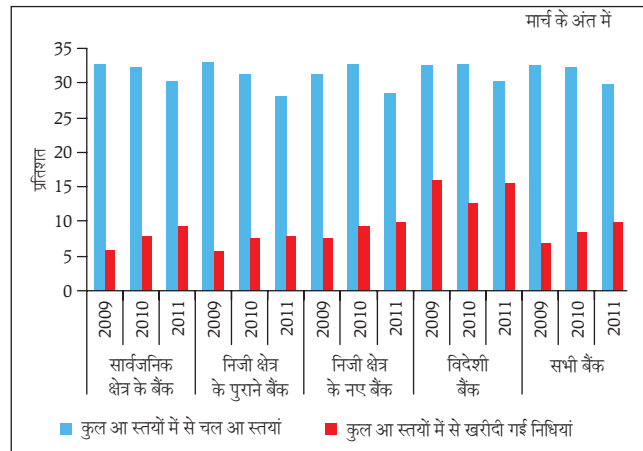
3.8 इस समय, कुल मात्रा में, बाजार उधार पर निर्भरता बहुत अधिक नहीं है। साथ ही, बैंकों की सीएएसए जमाराशियों तक पहुंच के कारण यह चिंता और भी बढ़ गई जो कुल जमाराशियों का लगभग 35 प्रतिशत था (चार्ट 3.7)।

चार्ट 3.4: देयताओं में सीडी तथा उधार का अंश



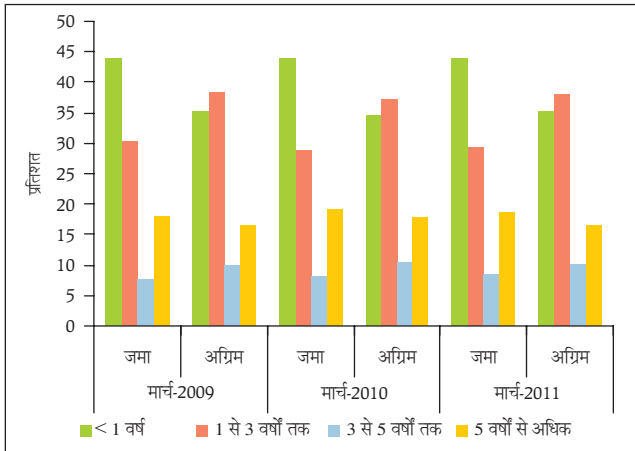
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.5: तरल आस्तियों का स्तर



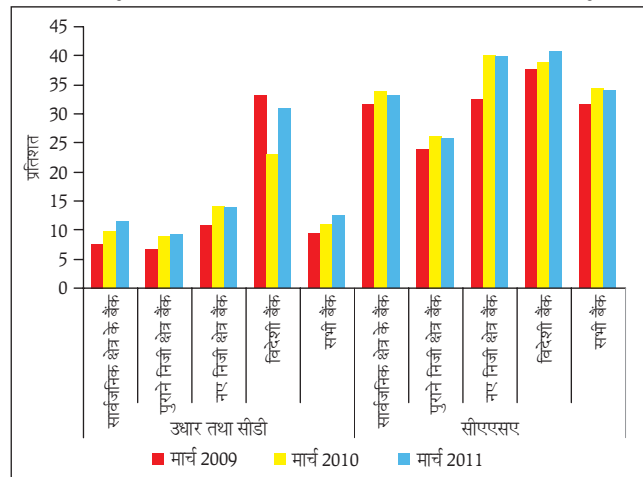
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.6: जमाराशियों तथा अग्रिमों का परिपक्वता प्रोफाइल



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.7: कुल जमाराशियों में सीडी तथा उधार तथा सीएएसए जमाराशियों का अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

ऋण में वृद्धि

ऋण में फिर से वृद्धि; फिर भी आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी जरूरी

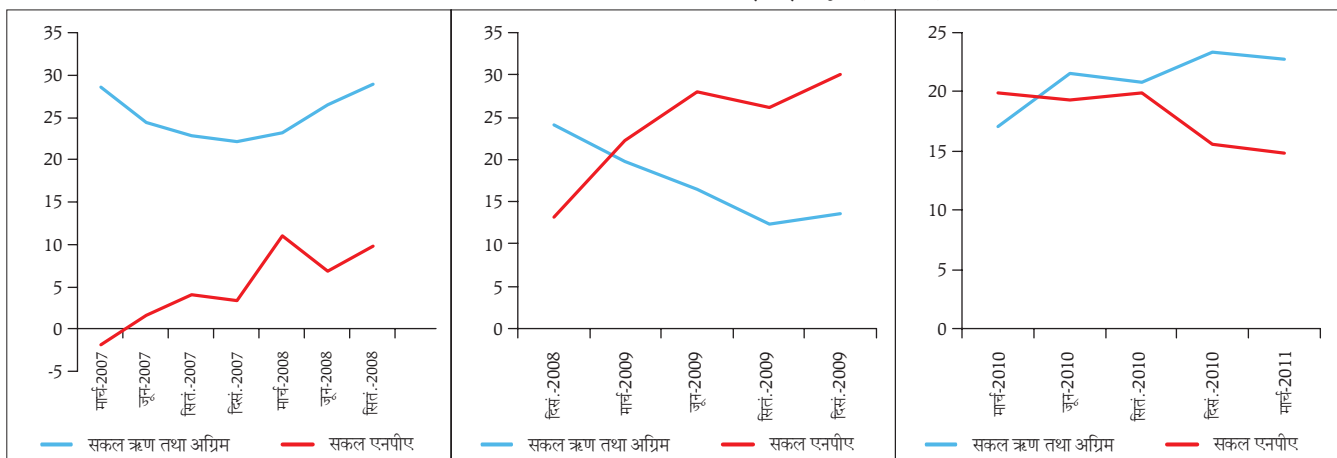
3.9 पिछले वर्ष में मंद निष्पादन के बाद 2010-11 में बकाया ऋण में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ऋण में वृद्धि फिर से देखने में आई। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए उच्च जीडीपी वृद्धि बनाए रखने तथा देश के वित्तीयकरण के स्तर में सुधार के लिए (दिसंबर 2010 के अंत में जीडीपी में ऋण का अनुपात लगभग 73 प्रतिशत था) ऋण में मजबूत वृद्धि होना जरूरी है। लेकिन साथ ही, ऋण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हामीदारी मानकों को सख्त बनाना होगा।

3.10 बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर भारत में ऋण वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने के लिए, एक अध्ययन किया गया ताकि वैश्विक वित्तीय संकट से पहले, उसके बाद तथा संकट के बाद की अवधि में संबंधित प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जा सके। इस अध्ययन से पता चला कि मजबूत ऋण वृद्धि से जोखिम भावना में कमी हुई जिससे आस्ति-गुणवत्ता में सुधार हुआ जबकि ऋण वृद्धि में कमी के बाद क्षत आस्तियों में वृद्धि हुई (चार्ट 3.8)। मार्च 2007-सितंबर 2008 के दौरान, जब बकाया ऋण वृद्धि लगभग 24 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी एनपीए या तो कम हुए या उनमें 10 प्रतिशत

से कम की वृद्धि हुई (बायां पेन), जबकि मंदी की अवधि में (बीच का पेन) ऋण लेने में कमी की शुरुआत हुई और दिसंबर 2009 में कम हो कर 12-13 प्रतिशत रह गया, दिसंबर 2008 में लगभग 13 प्रतिशत की तुलना में दिसंबर 2009 में एनपीए बढ़ कर 30 प्रतिशत हो गए। 2010-11 के दौरान, ऋण वृद्धि संकट से पहले की अवधि की वृद्धि जैसी दिखी। यह भी देखा गया कि एनपीए की वृद्धि में उल्लेखनीय कमी हुई (दायां पेन)। चक्रीयता को दिखलाने के अतिरिक्त, इस पैटर्न से तीव्र ऋण वृद्धि की अवधियों में आस्तियों को क्षति पहुंचने का भी संकेत मिला। इसलिए ऋण के चयन में अधिक सावधानी तथा कठोर निगरानी मानक आवश्यक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंदी होने पर ऋण वृद्धि संभावित क्षति से बची रहे।

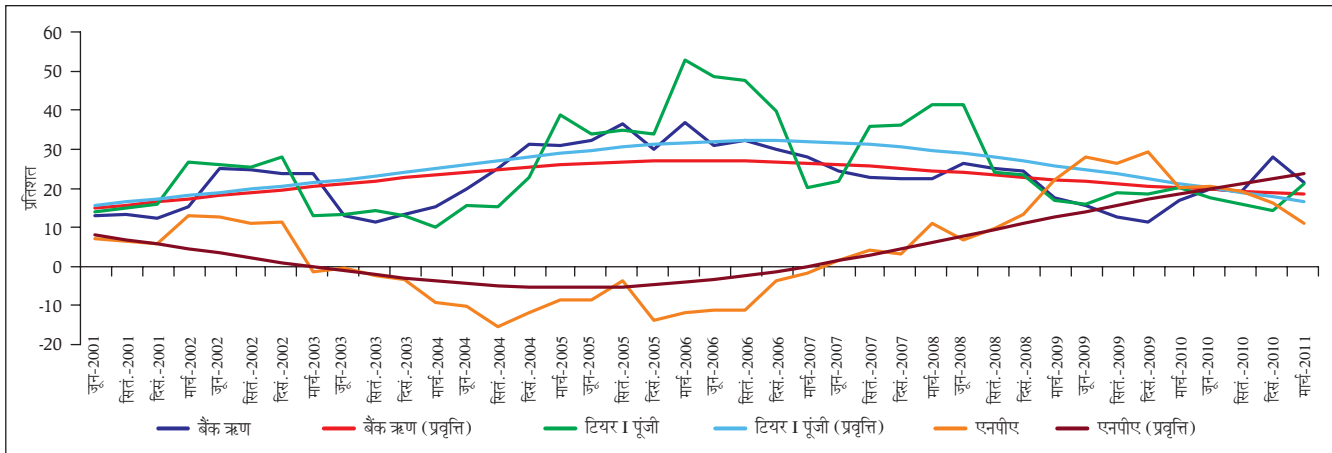
3.11 पिछले एक दशक में बकाया ऋण कुल एनपीए तथा टियर-1 पूंजी निधियों की वृद्धि के विश्लेषण से भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति का पता चलता है। इस विश्लेषण से यह भी पता चला कि पूंजी निधियों में वृद्धि अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति से अधिक (कम) थी जब ऋण वृद्धि अपनी दीर्घावधि प्रवृत्ति से अधिक (कम) थी। इस प्रकार, मजबूत ऋण टेकआफ को सावधानी से देखने की जरूरत है क्योंकि ये ऋण कमी के दौरान आस्तियों में क्षति तथा पूंजी स्तरों में कमी के संकेतक हो सकते हैं (चार्ट 3.9)।

चार्ट 3.8: तेजी तथा मंदी की अवधियों में ऋण तथा एनपीए की वृद्धि (प्रतिशत में)



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणना

चार्ट 3.9: क्रेडिट में वृद्धि, एनपीए और टियर I निधियों की तुलना में उनके विकास की प्रवृत्ति



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणनाएं

3.12 ऋण की ऊँची वृद्धि वाली अवधियों में ऋण में सहस्रावृद्धि जैसी परिस्थितियां पैदा होने की संभावना होती है (बॉक्स 3.1), जिन्हें प्रायः ऋण गुब्बारों के फूटने और वित्तीय संकटों का पूर्वराग माना गया है। तथापि, ऋण वृद्धि के चलते सिस्टम में ओवरहीटिंग के विश्वसनीय आकलन की विधियां निकालना मुश्किल है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं विकास के अलग-

अलग चरणों पर हैं और इसके चलते इन विधियों की उपयोगिता बड़े अहम रूप से सीमित हो जाती है। जैसी कि अध्याय IV में चर्चा की गई है, ओवरहीटिंग का निर्धारण करने का एक तरीका, जिसमें ऋण और जीडीपी के अनुपात के ट्रेड का उपयोग करने की कोशिश की गई है, कोई भरोसेमंद आकलन नहीं दे पाया।

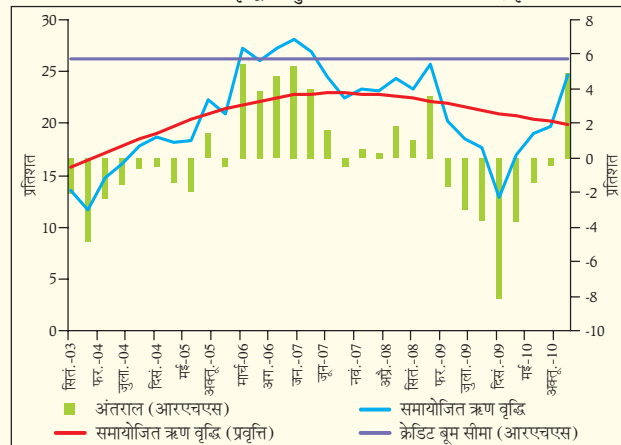
बॉक्स 3.1: क्या हम ऋण धमाके के दौर से गुजर रहे हैं?

ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि अधिकांश वित्तीय या बैंकिंग संकटों के पहले ऋण धमाकों का दौर चला है। पहले के वित्तीय संकटों के एक विश्लेषण और मेंडोजा व टेरोंस द्वारा परिभाषित ऋण धमाके के प्रसंगों में, एक बीआईएस पर्चे (बीआईएस क्वार्टरली रिव्यू, सितंबर 2010) में यह नोट किया गया है कि वित्तीय संकट के 27 मामलों में 17 ऐसे थे जिसमें संकट के पहले ऋण धमाकों का दौर चला था।

अतिरिक्त ऋण धमाकों के ऐसे दौर तब आते हैं जब ऋण का चक्रिय घटक औसत ऐतिहासिक चक्रिय घटक से ऋण परिवर्ती के मानक विचलन का 1.75 गुना अधिक हो जाए। इस परिभाषा के आधार पर, ऋण धमाके (क्रेडिट बूम) की निचली सीमा को चार्ट 3.10 में आकलित और प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से यह देखा जा सकता है कि जिस अवधि का विश्लेषण किया गया है, उसमें ऋण वृद्धि के चक्रिय घटक ने निचली सीमा कभी भी पार नहीं की है, फिर भी हो सकता है, मार्च 2006 और मार्च 2007 के बीच की अवधि में यह सीमा के काफी करीब पहुँच गया हो। अतः इस परिभाषा के आधार पर, उस अवधि में देश ऋण धमाके के काफ़ी नजदीक पहुँचा हुआ प्रतीत हुआ। यह अवधि बैंकिंग सिस्टम में ऋण की धीमी वृद्धि और अनर्जक आस्तियों में उच्चतर वृद्धि की अवधि के पहले आयी। चार्ट ने यह भी दर्शाया कि ऋण की ऐसी वृद्धि 2010-11 के दौरान हुई होगी जबकि चक्रिय घटक उपर्युक्त सीमा के नजदीक पहुँच गया।

उपर्युक्त अध्ययन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुसंगत है। अलबत्ता भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में इसकी सीमाएं हैं, जहाँ कि आर्थिक वृद्धि की ऊँची दर के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए ऋण में वृद्धि एक जरूरत है। फिर भी भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऋण धमाकों को मापने से ऐसी अवधियों का पता लगाने में

चार्ट 3.10: क्रेडिट* वृद्धि की तुलना में उसकी लंबी अवधि की प्रवृत्ति



* सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गये उधार को छोड़कर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, एनबीएफसी के साथ बकाया उधार (निजी) के संबंध में।
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणना

मदद मिल सकती है जिसमें मजबूत ऋण वृद्धि देखी गई और जैसी कि इस अध्याय के पैरा 3.10 और 3.11 में चर्चा की गई है, इसके बाद क्षतिगस्त आस्तियों में अधिक वृद्धि का दौर आता है। इससे ऋण चयन में सावधानी, विकास के पहिये को आगे ले जाने वाले कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जोखिम एकत्रित होने की महत्वपूर्ण सीमा के निर्धारण, ऋण वृद्धि होने पर क्रेडिट क्वालिटी खराब न होने देने के लिए खातों की अधिक कड़ी निगरानी के साथ पर्याप्त पूंजी रखने व अनर्जक आस्तियों के संभावित वृद्धि के लायक प्रावधान करने की जरूरत का संकेत भी मिल सकता है।

कुछ खास क्षेत्रों में लगे पैसे ने ऋण वृद्धि को बढ़ाया है

3.13 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण संविभाग (क्रेडिट पोर्टफोलियो) में उद्योगों, भूगोल व क्षेत्रों की दृष्टि से अच्छी विविधता थी। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह देखा गया कि वर्धमान ऋण वृद्धि का मुख्य कारण खुदरा (रिटेल), वाणिज्यिक रियल इस्टेट और आधारभूत क्षेत्र (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जैसे कुछ क्षेत्रों में हुई ऋण वृद्धि रही। मार्च 2011 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिम में इन क्षेत्रों का अंशदान क्रमशः 19 प्रतिशत, 4 प्रतिशत और 13 प्रतिशत रह (चार्ट 3.11)। वर्धमान कुल बकाया ऋण में इन तीन क्षेत्रों का सम्मिलित योगदान 40 प्रतिशत तक का था। सम्मिलित रूप से इनमें लगे पैसे (एक्सपोजर) ने 2009-10 के 20.4 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 के दौरान 27.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई (चार्ट 3.12)। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों में सर्वाधिक वृद्धि (क्रमशः 27.9 प्रतिशत और 30.6 प्रतिशत) देखने को मिली।

3.14 इनमें से प्रत्येक सेक्टर की अपनी एसेट क्वालिटी थी और बैंकों के ऋण संविभाग (क्रेडिट पोर्टफोलियो) में उनके बड़े हिस्से को देखते हुए इन पर सावधानी से निगाह रखने की जरूरत थी।

क्षेत्रवार ऋण और उनकी एसेट क्वालिटी

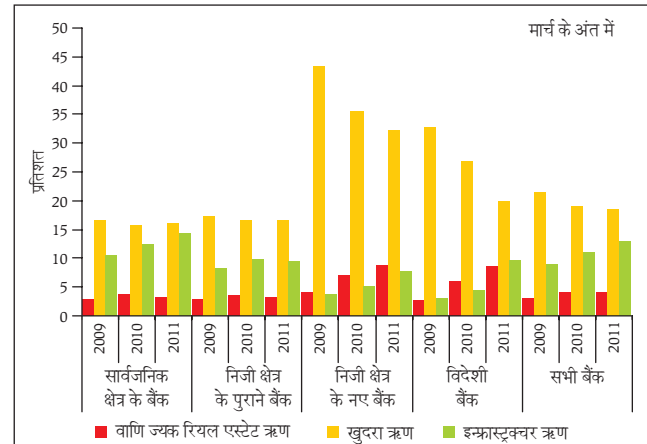
रियल इस्टेट

ऋण और क्षतिग्रस्त आस्तियों में वर्धमान हिस्सा अधिक रहा

3.15 मार्च 2011 में कुल अग्रिमों में 17.7 प्रतिशत भूसंपदा ऋण थे जिसमें निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत था। इस क्षेत्र में जाने वाले ऋण में 2010-11 में लगभग 24.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात् 22.6 प्रतिशत की समग्र ऋण वृद्धि दर से एक प्रतिशत अधिक। इसके पहले के दो वर्षों में इस क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों की वृद्धि दर क्रमशः 17 और 11 प्रतिशत रही (चार्ट 3.13 और 3.14)।

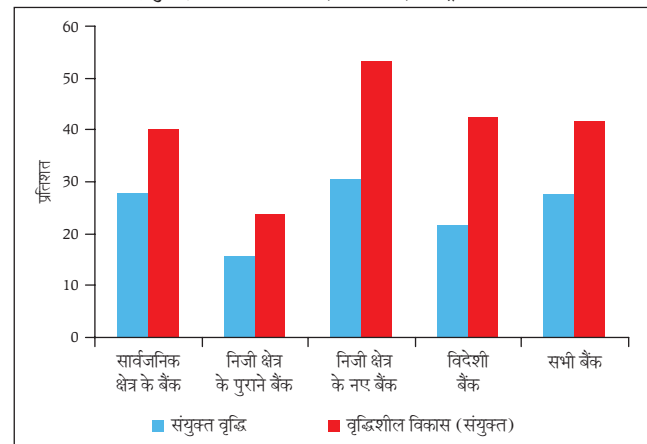
3.16 रियल इस्टेट सेक्टर के दो प्रमुख वर्ग आवासीय बंधक और वाणिज्यिक (कमर्शियल) रियल इस्टेट - दोनों ने लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों ने वाणिज्यिक रियल इस्टेट में अपना एक्सपोजर क्रमशः 59 और 69 प्रतिशत बढ़ाया। यह दर दूसरे दो बैंक समूहों के एकल अंकीय वृद्धि दर से काफी अधिक रही। इस वर्ग में अनर्जक आस्तियों की 19.8 प्रतिशत की वृद्धि दर भी 14.8 की अनर्जक आस्तियों की

चार्ट 3.11: सकल क्रेडिट में वाणिज्यिक रियल एस्टेट, खुदरा और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण का शेयर



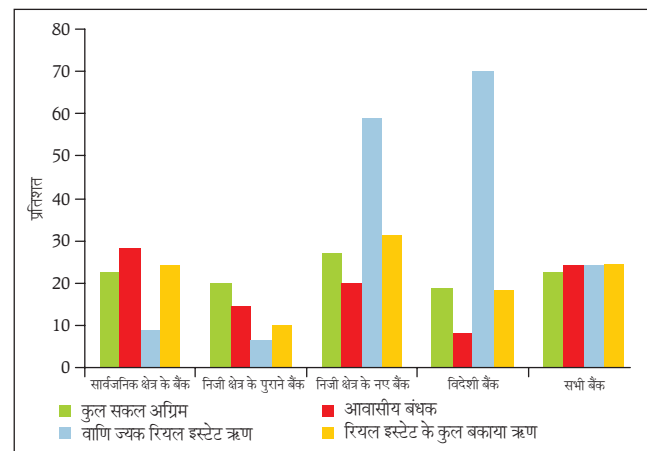
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.12: संयुक्त एक्सपोजर की वृद्धि (खुदरा, वाणिज्यिक रियल इस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण)



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.13: रियल इस्टेट ऋणों में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

समग्र वृद्धि दर से अधिक रही। विशेष तौर पर, वाणिज्यिक रियल इस्टेट वर्ग में अनर्जक आस्तियां मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, 70.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी और अनर्जकता का अधिकांश अंश सावर्जनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में देखा गया।

3.17 कुल अनर्जक आस्तियों में रियल इस्टेट की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का हिस्सा 15 प्रतिशत रहा। कुल ऋण में इस क्षेत्र वाले ऋण के 17.7 प्रतिशत हिस्से से कम। 1.8 प्रतिशत का कुल अनर्जक आस्ति अनुपात (एनपीए अनुपात) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 2.3 प्रतिशत समग्र एनपीए अनुपात, से कम रहा। आवासीय बंधक ऋणों के एनपीए अनुपात में सुधार हुआ (2.5 से 2.2 प्रतिशत), परंतु वाणिज्यिक रियल इस्टेट ऋणों के मामले में ऋणों बिगड़ा (1.6 प्रतिशत से 2.3 प्रतिशत हो गया) (चार्ट 3.15)।

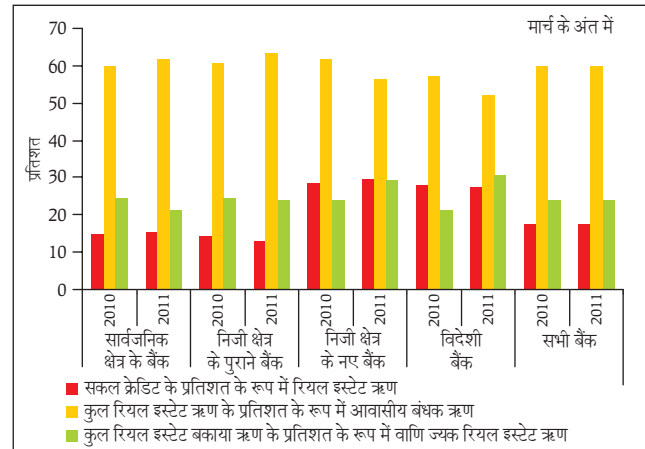
3.18 ऊपर बताए गए सकारात्मक घटनाक्रम के बावजूद, बैंकों के क्रेडिट पोर्टफोलियो में इन कर्जों की बड़ी और बढ़ती हिस्सेदारी, समूचे सिस्टम स्तर की एनपीए की वृद्धि की तुलना में इनके एनपीए वृद्धि के अधिक होने और एनपीए की ओर अधिक लुढ़कने की संभावना को देखें तो रियल इस्टेट क्षेत्र ने कुछ चिंताएं खड़ी कीं।

3.19 आगे चलकर, बढ़ते ब्याज दर परिवेश में इस वर्ग की आस्ति गुणवत्ता पर दबाव बढ़ सकता है²। एक ओर जहाँ कीमतें अधिक बनी हुई हैं, वहीं इस क्षेत्र में के इनवेन्टरी बढ़ती स्तर के सबूत मिलने की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। इसे देखते हुए, इस क्षेत्र में ऋण के आधिक्य पर रोक लगाने और बैंकिंग प्रणाली³ की आधार सहनीयता को बल प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ समष्टि स्तर पर कई विवेकसम्मत उपाय घोषित किए।

खुदरा ऋण ने गत वर्ष घटने के बाद वृद्धि दर्ज की

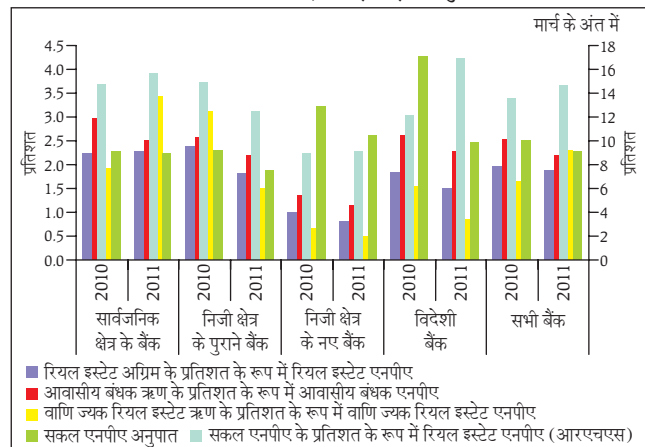
3.20 मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण व अग्रिमों का 18.5 प्रतिशत खुदरा क्षेत्र (रिटेल सेक्टर) को गया जो कि मार्च 2010 के 19 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है (चार्ट 3.16)। 2009-10 में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद मजबूत वापसी करते हुए 2010-11 के दौरान खुदरा ऋणों ने 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस बढ़ोतरी में बड़ा हाथ निजी ऋण वाले वर्ग का रहा, जिसमें प्राथमिक रूप से अधिक जोखिम

चार्ट 3.14: सकल क्रेडिट में रियल इस्टेट ऋणों का शेयर



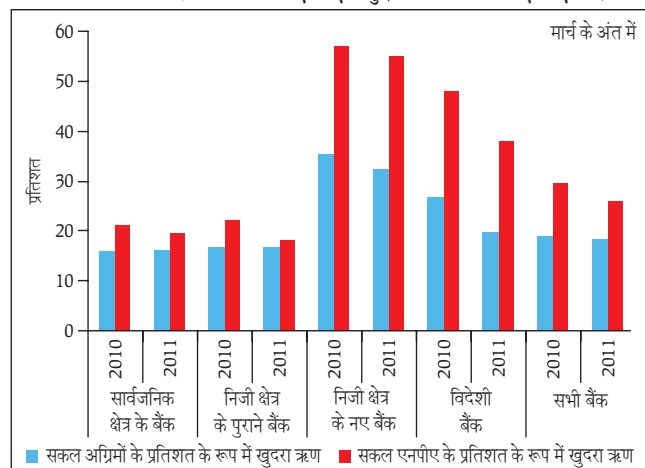
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.15: रियल इस्टेट एनपीए का अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.16: सकल अग्रिमों और सकल एनपीए में खुदरा ऋण और उनके एनपीए का शेयर



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

² मुद्रास्फीतिकारी स्थितियों को संबोधित करने के लिए किये गये कड़े मौद्रिक उपायों के परिणामस्वरूप मार्च 2010-मई 2011 के दौरान संदर्भ दर को 4.75 से 7.25 प्रतिशत तक (रिपो दर) नौ बार बढ़ाया गया। इसी अवधि में चयनित बैंकों की आधार दरों में 1.25 से 2.0 प्रतिशत की श्रेणी में वृद्धि हुई।

³ रिजर्व बैंक ने नवंबर 2010 में मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में श्रृंखलाबद्ध रूप से कई उपाय घोषित किये, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आवास ऋणों के 80 प्रतिशत तक मूल्य अनुपात पर 20 लाख रुपए तक के ऋणों पर 90 प्रतिशत) रोक लगाई ताकि 125 प्रतिशत तक बड़े आवासों ऋणों पर (75 लाख रुपए और उससे अधिक), 0.40 प्रतिशत से 2.00 प्रतिशत आदि तक 'टीजर' ब्याज दरों के साथ ऋणों की बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण में वृद्धि को टाला जा सके।

वाले और गैर-जमानती/अरक्षित ऋण शामिल थे (चार्ट 3.17)। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, 31 प्रतिशत खुदरा ऋण अरक्षित थे और वर्ष के दौरान इस वर्ग ने 24.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

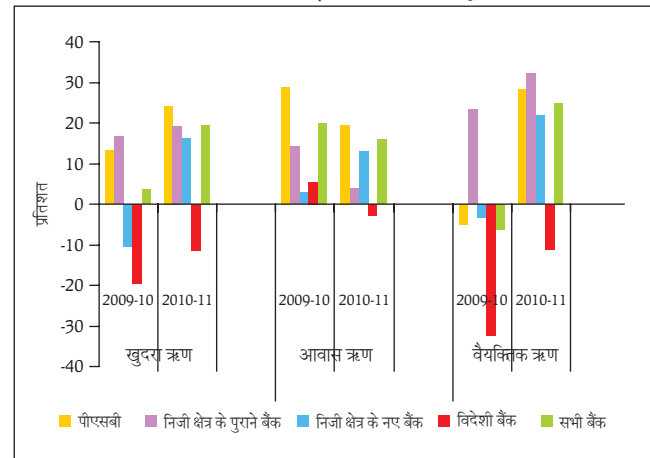
3.21 खुदरा ऋणों/उधार का 3.2 प्रतिशत का कुल एनपीए अनुपात अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 2.3 प्रतिशत और समग्र एनपीए अनुपात, से अधिक रहा। वैसे, रिटेल एनपीए की 2009-10 के लगभग 7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में 2.2 प्रतिशत की कमी रही (चार्ट 3.18 और 3.19)। आवास ऋण में अनर्जक आस्तियों की मात्रा भी घटी, जबकि निजी ऋण की अनर्जक आस्तियों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई।

3.22 हाल की तिमाहियों में खुदरा ऋणों में मजबूत वापसी के मद्देनजर कड़ी निगरानी की जरूरत है क्योंकि बढ़ते ब्याज दर परिवेश में ऐसे ऋणों की एसेट क्वालिटी पर दबाव पड़ सकता है। इन ऋणों की स्थिति व्यक्तिगत आय व धन के स्तरों से करीब से जुड़ी हुई होती है जो कि आर्थिक से जुड़ी हुई जोखिमों, जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय I में कहा गया है, के वास्तविक रूप में घटित हो जाने पर प्रभावित हो सकती है।

आधारभूत क्षेत्र ऋण बहुत तेजी से बढ़े, तो इस क्षेत्र की अनर्जक आस्तियां भी बढ़ीं; तथापि, क्षेत्र का कुल अनर्जक आस्ति अनुपात (एनपीए रेशियो) कम स्तर पर ही रहा

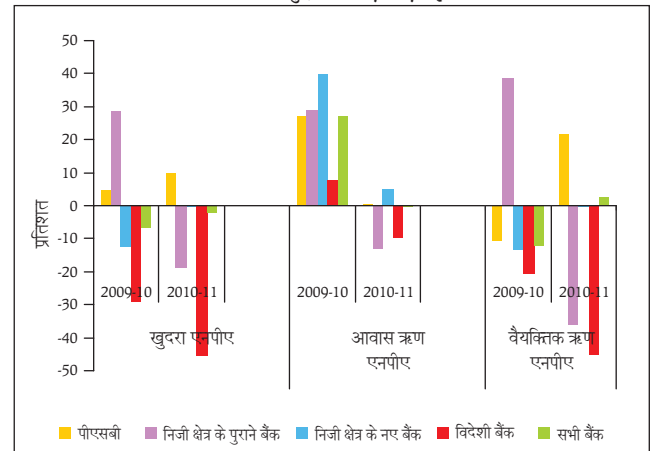
3.23 वर्ष 2010-11 (चार्ट 3.20) में आधारभूत क्षेत्र के अग्रिम मजबूती से 40 प्रतिशत से अधिक पर बढ़ते रहे। फलस्वरूप, कुल अग्रिम में आधारभूत संरचना की उधारी का अंश मार्च 2010 के 11

चार्ट 3.17: आवास एवं वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि



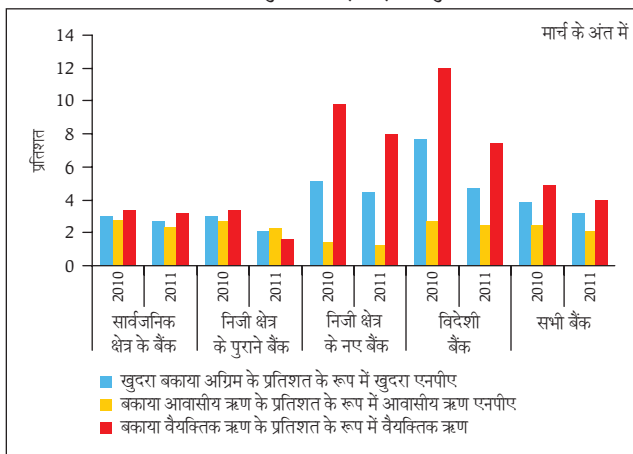
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.18: खुदरा ऋण एनपीए में वृद्धि



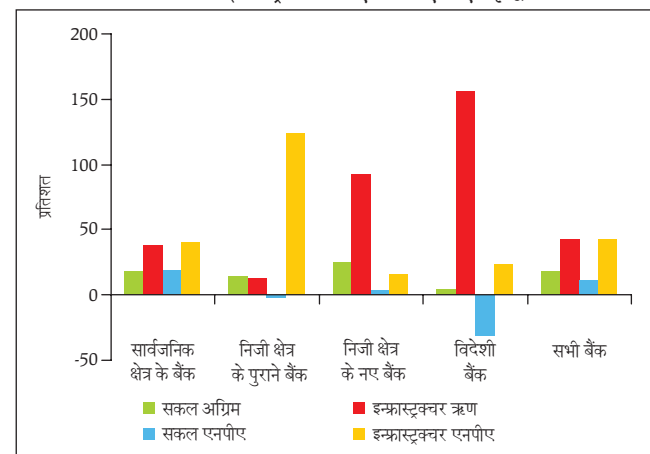
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.19: खुदरा ऋण एनपीए का अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.20: इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण एवं उनके एनपीए में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2011 में 12.9 प्रतिशत हो गया। बैंक समूहों में, एक्सपोजर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में केंद्रित था, जोकि इस वर्ग में बैंकिंग क्षेत्र के कुल एक्सपोजर का 84.8 प्रतिशत था।

3.24 2010-11 के दौरान अर्नजक आधारभूत ऋणों में 42.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। फिर भी, ऐसे ऋणों के कुल एनपीए रेशियो लगभग 0.5 प्रतिशत के कम स्तर पर बने रहे।

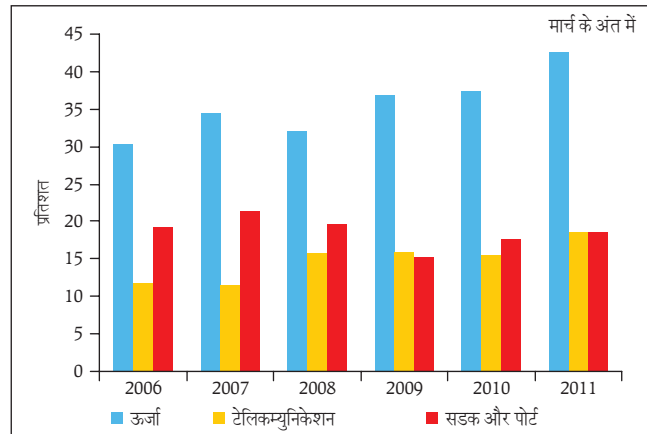
3.25 बिजली, दूरसंचार, सड़कों और बंदरगाहों में लगे पैसे बैंकों के आधारभूत क्षेत्र के ऋण के महत्वपूर्ण वर्ग हैं। बिजली क्षेत्र को आधारभूत क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण का 42 प्रतिशत गया जबकि अन्य दो घटकों में प्रत्येक को 18 प्रतिशत दिया गया (चार्ट 3.21)। पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का बिजली क्षेत्र को एक्सपोजर औसतन 50 प्रतिशत बढ़ा है जबकि अन्य दो क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि दर में बड़ा असंतुलन देखने को मिला है (चार्ट 3.22)। आधारभूत संरचना ऋण के विभिन्न घटकों में कुल एनपीए अनुपात इन वर्षों में घटता-बढ़ता रहा है परंतु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र एनपीए अनुपात से काफी नीचे रहा है (चार्ट 3.23)।

3.26 पिछले एफ़एसआर में कहा गया था कि आधारभूत क्षेत्र में एक्सपोजर बढ़ने से बैंकों के लिए आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के जोखिम बढ़ेंगे। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल अग्रिम में आधारभूत क्षेत्र ऋण का हिस्सा बढ़ने से ये जोखिम बढ़ गए हैं। जैसा कि पिछले एफ़एसआर में कहा गया है, परियोजनाओं के पूरा होने में काफ़ी देरी होने की संभावना को देखते हुए आधारभूत क्षेत्र ऋण से जुड़े हुए आस्ति देयता प्रबंधन मुद्दों के गंभीर होने की संभावना है। ये सभी बातें आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण (लाँग टर्म फंडिंग) विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

अधिक जोखिम वाले उद्योगों में संकेंद्रण कम रहा

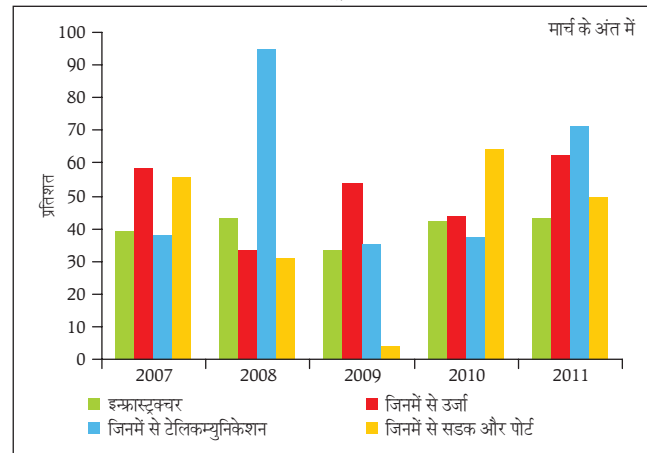
3.27 38 प्रमुख उद्योगों में लगे बैंक ऋण पर एक अध्ययन किया गया ताकि अधिक जोखिम वाले उद्योगों में संकेंद्रण और तत्संबंधी रुझानों⁴ का जायजा लिया जा सके। पिछले छह वर्षों की अवधि में अधिक जोखिम वाले उद्योगों में ऋण का हिस्सा कम रहा है जबकि संकट के पश्चात इसमें कुछ वृद्धि नोटिस की गई। मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार ऐसे ऋण का हिस्सा लगभग 16 प्रतिशत रहा।

चार्ट 3.21: कुल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट में मुख्य इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का शेयर



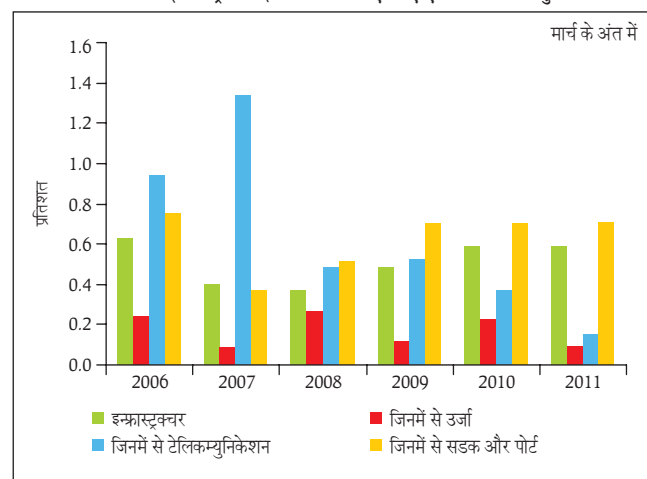
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.22: इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.23: इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र और बैंक में एनपीए एक्सपोजर का अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

⁴ विविध उद्योगों का जोखिम वर्गीकरण अवधियों के क्रिसिल उद्योग जोखिम स्कोअर पर आधारित है जबकि मार्च 2011 तक के बैंकिंग क्षेत्र के आंकड़े रिजर्व बैंक के स्रोतों से लिये गये हैं।

कुछ बैंक अपवाद भी थे जिनका अधिक जोखिम वाले उद्योगों में हिस्सा उद्योग के औसत से अधिक रहा (चार्ट 3.24 से 3.25)।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में एक्सपोजर⁵

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों में एक्सपोजर में वृद्धि तो हुई, किंतु अनर्जक परिसंपत्तियों का उच्च स्तर चिंता का कारण बना रहा

3.28 वर्ष 2010-11 में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि उसकी अनर्जक परिसंपत्तियों में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने में आई। इस प्रकार, बैंकिंग क्षेत्र के समग्र अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात के मुकाबले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, विशेषकर कृषि क्षेत्र, में किए गए एक्सपोजर की परिसंपत्ति गुणवत्ता निरंतर प्रतिकूल ही रही। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र का सकल अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात 3.3 प्रतिशत से बिगड़कर 3.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.26)।

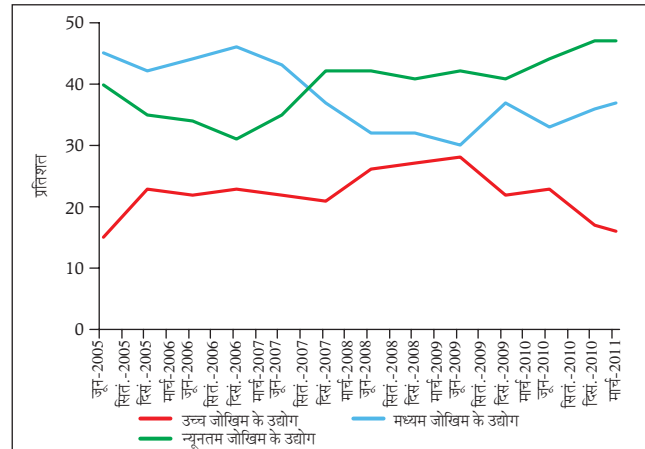
3.29 कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण से संबंधित सकल अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात, जो मार्च 2010 में 2.4 प्रतिशत था, मार्च 2011 में बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया। कृषि ऋण में 19 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले अनर्जक कृषि परिसंपत्तियों में 60 प्रतिशत की वृद्धि होने से इस अनुपात में विकृति आया। गत वर्ष अनर्जक परिसंपत्तियों के उपचय में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि होने से सूक्ष्म और लघु उद्यमों का सकल अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात भी 3.5 प्रतिशत पर उच्च बना रहा। प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण देने से जुड़ी सभी समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा एक समिति का गठन किया जा रहा है ताकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की परिभाषा का पुनरावलोकन किया जा सके विशेषकर उन मामलों में जिनमें बैंक-वित्त अन्य संस्थाओं के माध्यम से भेजा जा रहा है।

तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर

विदेशी बैंकों के तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने में आई

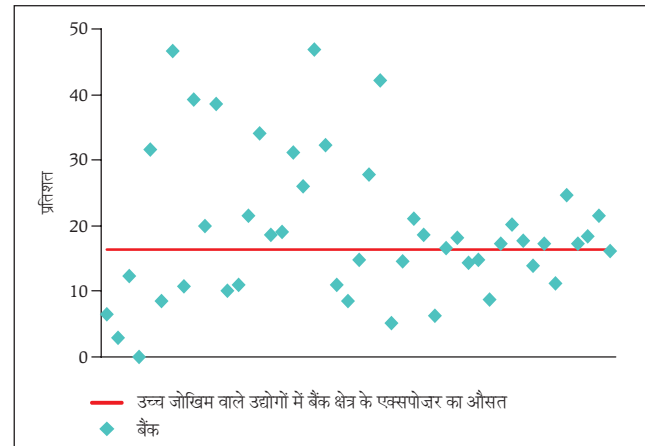
3.30 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की सकल आनुमानिक राशि तुलन-पत्र के समग्र आकार के प्रतिशत के रूप में मार्च 2010 के अंत के 178 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में 198 प्रतिशत हो गई। विदेशी बैंकों के मामले में, वर्ष के दौरान, तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के अनुपात के रूप में तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर 1554 प्रतिशत से बढ़कर 1860 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 3.24: उद्योगों को बैंक ऋण देने का जोखिम वार विभाजन



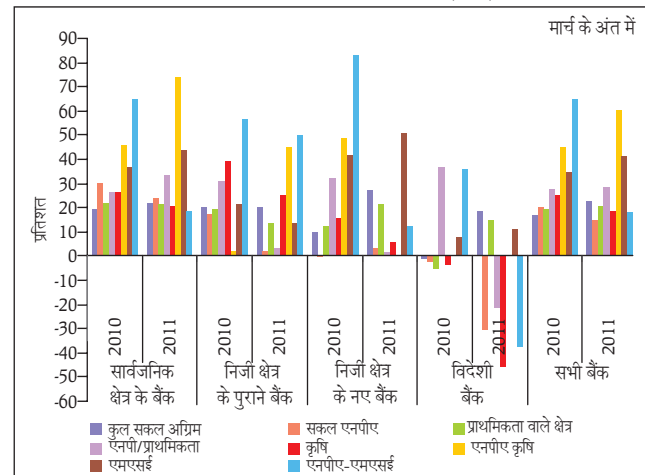
स्रोत: आरबीआई

चार्ट 3.25: उच्च जोखिम उद्योगों में बैंक गुण एक्सपोजर



स्रोत: आरबीआई स्टाफ की गणना

चार्ट:3.26 बाकाया जोखिम और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एनपीए आ स्तरों में वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

⁵ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए एक ऐसी निर्देशित बैंक ऋण व्यवस्था है जो बैंक ऋणों के बाध्यकारी माध्यम के अभाव में बुरी स्थिति में है। वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि को सुनिश्चित करने के अलावा बैंकों को देश के आर्थिक विकास में एक विशेष भूमिका सौंपी गई है जिसमें कृषि जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों, जैसे एमएसई शिक्षा, आवास, सूक्ष्म ऋण, जनसंख्या के कमजोर वर्गों आदि को ऋण का निश्चित भाग देना शामिल है।

3.31 वर्ष के दौरान, इन के आनुमानिक मूलधन में 32.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि गत वर्ष 5.8 प्रतिशत की गिरावट हुई थी (चार्ट 3.27)। तुलन-पत्र बाह्य की समग्र आनुमानिक राशि का बैंक-समूहों में संवितरण करने से ज्ञात होता है कि इसका विदेशी बैंकों में लगाया गया 68 प्रतिशत तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के नए बैंकों में लगभग 15 प्रतिशत संकेंद्रीकरण हुआ है (चार्ट 3.28)।

3.32 तुलन-पत्र के आकार के अनुपात के रूप में डेरिवेटिव एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि कम रही और वस्तुतः इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आई (मार्च 2009 में 8.8 प्रतिशत से मार्च 2010 में 5.3 प्रतिशत तथा मार्च 2011 के अंत में और गिरकर 4.5 प्रतिशत) विदेशी बैंकों के मामले में, मार्च 2010 में यह अनुपात 51 प्रतिशत के उच्च स्तर पर था, जो मार्च 2011 में घटकर 47 प्रतिशत रह गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूतियों के सकल दैनिक बाजार मूल्य की स्थिति सकारात्मक रही।

3.33 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, तुलन-पत्र बाह्य घटकों में से ऋण अनुषंगी लेनदेन तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के अनुपात के रूप में गिर गया, जबकि डेरिवेटिव लेनदेन के हिस्से, विशेषकर विदेशी मुद्रा संविदाओं, में वृद्धि हुई है। इसमें और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है (चार्ट 3.29)।

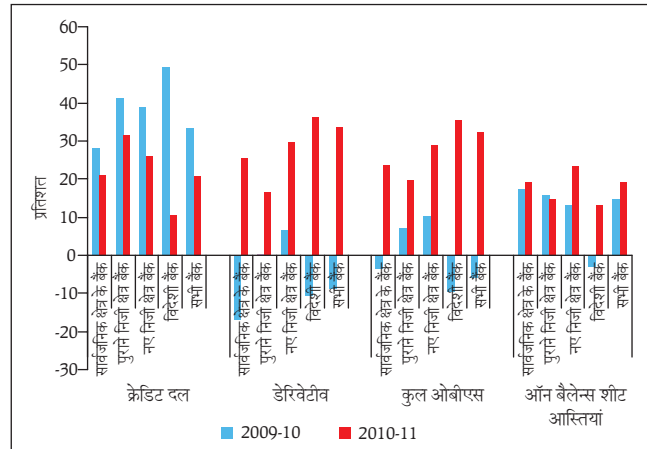
3.34 भारत में तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर में सामान्यतया साधारण उत्पाद/लेन-देन शामिल होते हैं। वायदा संविदाओं में अधिकांश विदेशी मुद्रा संविदाएं होती हैं जिनका बचाव बैंकों द्वारा सामान्यतया पारस्परिक आधार पर किया जाता है। किंतु वायदा संविदाओं एवं ओटीएस ब्याज दर लेन-देनों में ऋण जोखिम निहित होता है जिसके लिए चौकस जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता है।

वित्तीय स्थिरता संकेतक

जोखिम भारित परसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात बैंकों में पूंजी की स्थिति अच्छी रही, हालांकि ऋण उठाव में सुधार से पूंजी-पर्याप्तता अनुपात में मामूली गिरावट आयी

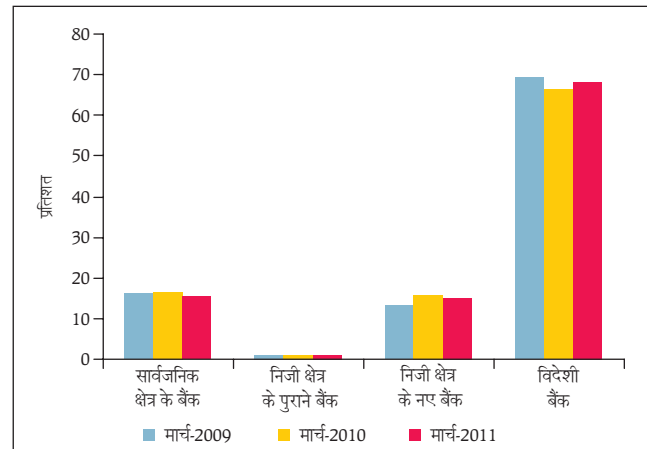
3.35 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में मार्च 2011 के अंत में पूंजी की स्थिति अच्छी रही। बासल-II मानदंडों के अंतर्गत सिस्टम केवल सीआरएआर 14.3 प्रतिशत रहा जो 9 प्रतिशत के विनियामक न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर था। किंतु मार्च 2010 के अंत में 14.5 प्रतिशत सीआरएआर की स्थिति की तुलना में तनिक गिरावट दर्ज की गई। इसका कारण मुख्यतः वर्ष 2010-11 के दौरान तीव्र ऋण-उठाव रहा है। बासल-II मानदंडों के अंतर्गत, मार्च 2011 के अंत में

चार्ट 3.27: बैंक गुणों के बीच ओबीएस एक्सपोजर में वृद्धि



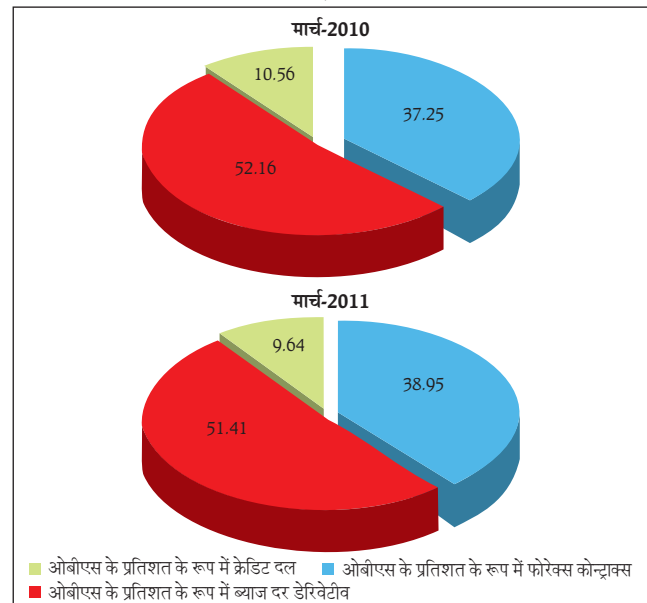
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.28: ओबीएस एक्सपोजर का वितरण



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.29: ओबीएस घटकों की संरचना



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

सभी बैंक समूहों का सीआरएआर 12 प्रतिशत से अधिक रहा। किंतु बासल-I मानदंडों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सीआरएआर 12 प्रतिशत से तनिक कम अर्थात् 11.9 प्रतिशत रहा (चार्ट 3.30)।

3.36 भारत में पूंजी आवश्यकताओं, विशेष रूप से मुख्य पूंजी के संबंध में विनियामक कड़ाई के कारण बासल III की शर्तों का प्रारंभ हुआ क्योंकि बैंकों के लिए यह अनिवार्य था कि वे 01 अप्रैल 2010 से निरंतर आधार पर 6 प्रतिशत का टियर I पूंजी अनुपात बनाये रखें। परिणामस्वरूप, मार्च 2011 के अंत में मुख्य सीआरएआर बैंकिंग प्रणाली के लिए, प्रत्येक बैंक समूह तथा निजी बैंकों के लिए सुविधाजनक रूप से 6 प्रतिशत के ऊपर था। (सारणी 3.1) आगे चलकर, जैसे कि बासल III मानदंडों का प्रारंभ होगा, कुछ बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाना आवश्यक होगा, विशेष रूप से यदि ऋण लेना अधिक मात्रा में जारी रहा, जैसा कि इस रिपोर्ट के चौथे अध्याय में चर्चा की गई है।

लीवरेज अनुपात

भारत में लीवरेज अनुपात की स्थिति अच्छी रही

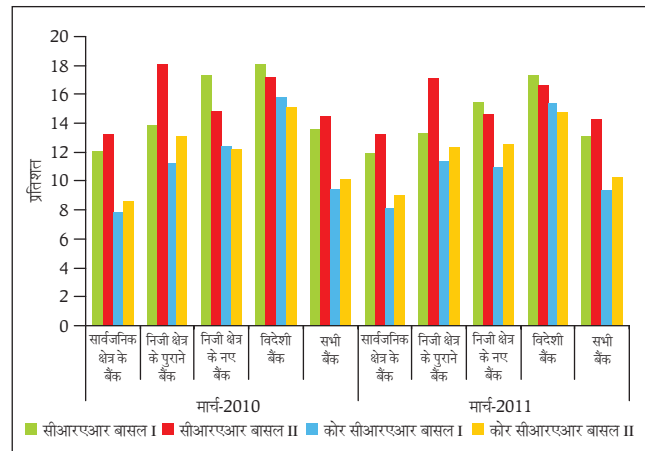
3.37 संबंधित बैंक के स्तर पर पूंजी-मानदंडों के सुदृढीकरण द्वारा प्रणालीगत सुदृढता लाने के प्रयास में, बासल-III विनियामक पूंजी ढांचे द्वारा गैर जोखिम आधारित लीवरेज अनुपात लागू किया गया है जो जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षा के लिए रोक का काम करेगा। यह प्रस्ताव किया जाता है कि वर्ष 2013 से तुलन-पत्र एवं तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजरों दोनों के संबंध में न्यूनतम 3 प्रतिशत के टियर-I लीवरेज अनुपात को परखा जाए। भारत में मार्च 2011 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लीवरेज अनुपात लगभग 6 प्रतिशत के अच्छे स्तर पर रहा (चार्ट 3.31)। अधिकांश बैंकों ने अलग-अलग स्तर पर 4 प्रतिशत से अधिक टियर-I लीवरेज अनुपात के साथ कार्य किया। (केवल एक बैंक का लीवरेज अनुपात 3 प्रतिशत से अनधिक रहा)

समग्र परिसंपत्ति गुणवत्ता

परिसंपत्ति की अनर्जकता की गति मंद हुई है, हालांकि इसका निम्न स्तर पर खिसककर आने का जोखिम बना हुआ है

3.38 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 2009-10 में हुई समग्र अनर्जक परिसंपत्तियों की 19.9 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2010-11 में यह वृद्धि 14.8 प्रतिशत रही। अग्रिमों की 22.6 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर हुए समग्र अनर्जक परिसंपत्ति अनुपात 2.5 प्रतिशत से सुधरकर 2.3 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की

चार्ट 3.30: बैंक गुणों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात

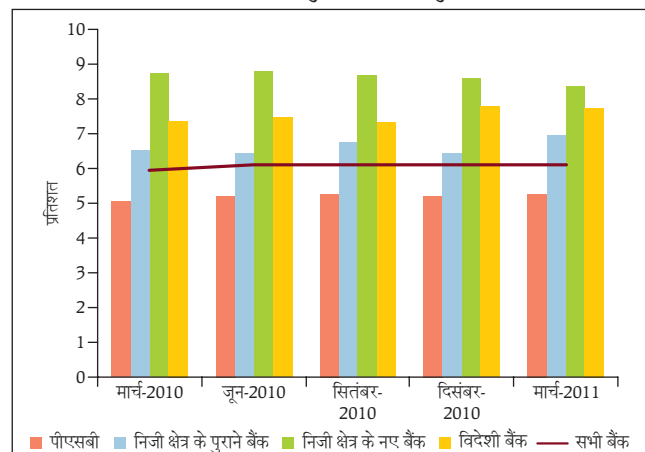


स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

	2010	2011
सीआरएआर		
> 3 प्रतिशत <= 6 प्रतिशत	-	-
> 6 प्रतिशत <= 9 प्रतिशत	1	-
> 9 प्रतिशत <= 12 प्रतिशत	2	6
> 12 प्रतिशत	79	75
कोर सीआरएआर		
3 प्रतिशत तक	-	-
> 3 प्रतिशत और <= 6 प्रतिशत	1	-
> 6 प्रतिशत <= 8 प्रतिशत	9	2
> 8 प्रतिशत	72	79

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.31: बैंक गुणों का लीवरेज अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

शुद्ध अनर्जक परिसंपत्तियां 1.1 प्रतिशत से सुधरकर 0.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट 3.32)। सकल अनर्जक परिसंपत्ति में निजी क्षेत्र के बैंकों में हुई 5 प्रतिशत से कम वृद्धि तथा विदेशी बैंकों के मामले में हुई 30 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में उच्चतर वृद्धि (23 प्रतिशत) दर्ज की गई (चार्ट 3.33)। हालांकि, समय के साथ-साथ, यदि ऋण-वृद्धि की गति मंद पड़ी, तो बैंकों को परिसंपत्ति गुणवत्ता में और अधिक गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जैसाकि इस अध्याय के पैरा 3.10 में चर्चा की गई है।

3.39 अनर्जक परिसंपत्तियों की वृद्धि दर में कमी, कुछ सीमा तक, अनर्जक परिसंपत्तियों को बट्टे-खाते लिखने और वसूली किए जाने से हुई थी। हालांकि, मार्च 2011 के अंत में दोनों में थोड़ी सी गिरावट देखने में आई थी। बट्टे-खाते लिखने संबंधी राशि, वसूलियों के 87 प्रतिशत के बराबर (2009-10 में 97 प्रतिशत) तथा बकाया ऋण के 20 प्रतिशत के बराबर थी (2010 में 28 प्रतिशत)। अनर्जक परिसंपत्तियों को यदि इस प्रकार बट्टे-खाते न लिखा जाता तो सकल अनर्जक परिसंपत्तियों की स्थिति वर्तमान यथासूचित स्थिति से कहीं ज्यादा खराब होती।

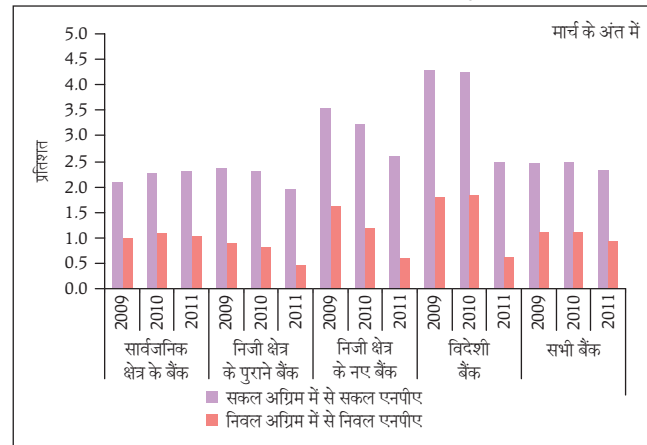
पुनर्व्यवस्थित खातों की वृद्धि में गिरावट

3.40 वित्तीय संकट से अस्थायी रूप से प्रभावित संस्थाओं के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2008-09 में दी गई एकबारगी विशेष छूट की चर्चा पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में की गई है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 में विशेष छूट के अंतर्गत बकाया राशि के लगभग 3 प्रतिशत तक की मानक परिसंपत्तियों का पुनर्निर्धारण किया गया था। इन दो वर्षों के दौरान, पुनर्निर्धारण परिसंपत्तियों की राशि में क्रमशः 192 प्रतिशत और 60.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विशेष छूट की समाप्ति के बाद, इस प्रकार के पुनर्निर्धारण के मामलों में तेजी से गिरावट आई तथा पुनर्व्यवस्थित खातों में केवल 10.7 प्रतिशत की वृद्धि देखने में आई।

हालांकि स्लिपेज में सुधार हुआ है, तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह प्रणालीगत-औसत से ऊपर रहा

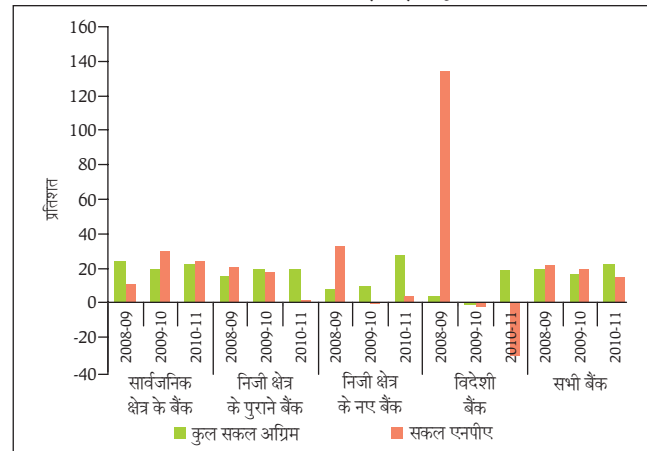
3.41 अनर्जक परिसंपत्तियों की वृद्धि में 14.8 प्रतिशत तक की गिरावट आ जाने से (चार्ट 3.34) स्लिपेज अनुपात, जो वर्ष के आरंभ में अनर्जक परिसंपत्तियों के स्टाक में हुई ताजा वृद्धि का मानक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में माप है, मार्च 2010 के अंत के 2.2 प्रतिशत के मुकाबले मार्च 2011 के अंत में सुधरकर 1.6 प्रतिशत हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह अनुपात 1.7 प्रतिशत, उद्योग औसत से तनिक उच्च रहा।

चार्ट 3.32: सकल और निवल एनपीए का अनुपात



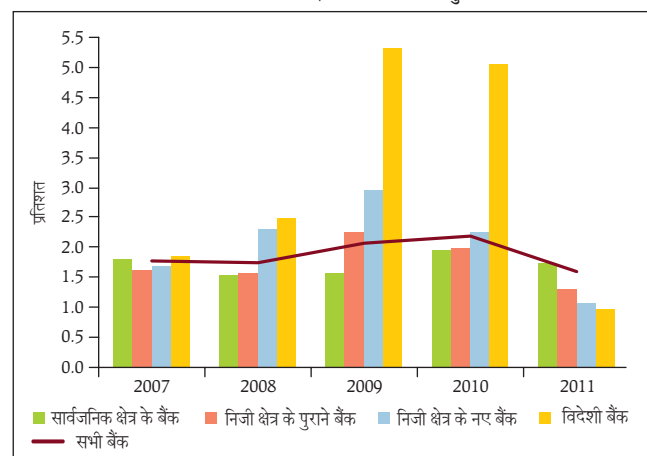
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.33: अग्रिमों और एनपीए की वृद्धि



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.34: वर्षों के दौरान स्लिपेज का अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

अप्राप्य अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि देखने में आई

3.42 वर्ष के दौरान, अनर्जक परिसंपत्तियों के प्रवर्गवार संवितरण में परिवर्तन करने से निम्नस्तरीय परिसंपत्तियों के मुकाबले संदिग्ध परिसंपत्तियों में वृद्धि देखने को मिली। इससे यह ज्ञात होता है कि अनर्जक परिसंपत्तियां अत्यधिक अप्राप्य होती जा रही हैं। निजी क्षेत्र के नये बैंकों कि मामले में यह प्रवृत्ति और भी ज्यादा दिखाई दी। इन्हें निगरानी की सख्त जरूरत है (चार्ट 3.35)।

प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

समष्टिगत विवेकपूर्ण उपाय स्लिपेज के विरुद्ध कुशन का कार्य करेंगे

3.43 दिसंबर 2009 में बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे अपने 70 प्रतिशत अनर्जक अग्रिमों के पीसीआर (प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात) सितंबर 2010 के अंत तक हासिल कर लें। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों ने अपेक्षित अनुपात बनाये रखा था। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में यह अनुपात 70 प्रतिशत से तनिक कम था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप के मामले में अंतर⁶ अपेक्षाकृत अधिक था (चार्ट 3.36)।

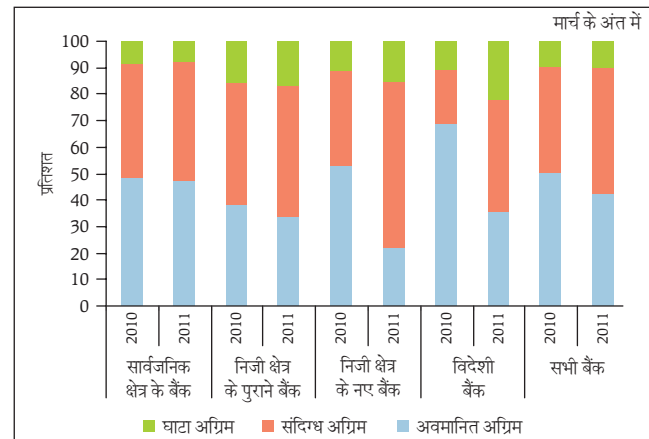
3.44 वर्ष 2010-11 में ऋणवृद्धि की ऊर्ध्वगामी तीव्र प्रवृत्ति को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने अप्रैल और मई 2011 में और समष्टि-विवेकपूर्ण उपाय घोषित किए। बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार, विवेकपूर्ण मानदंडों के तहत अपेक्षित प्रावधानों तथा पीसीआर के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के बेशी को 'प्रतिचक्रीय बफर' नामक खाते में अलग से लिख लें। बैंकों को यह 'बफर' आर्थिक अधोगति के दौरान, विशेष प्रावधान करने हेतु उपलब्ध रहेगा। तदनुसार, सितंबर 2010 के बाद, बैंकों को यह आवश्यकता नहीं रही कि वे वर्धमान अग्रिमों पर 70 प्रतिशत पीसीआर बनाए रखें। इसके साथ-साथ अनर्जक और पुनर्निर्धारित अग्रिमों⁷ के कतिपय प्रवर्गों पर अनर्जक परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधानीकरण अपेक्षाएं भी बढ़ा दी गईं।

लाभप्रदता

लाभप्रदता में तगड़ी वृद्धि होना वृद्धिगत कार्य-निष्पादन का संकेत है, किंतु ब्याज से इतर आय में वृद्धि न होने तथा स्टाफ संबंधी व्यय बढ़ने से कुछेक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं

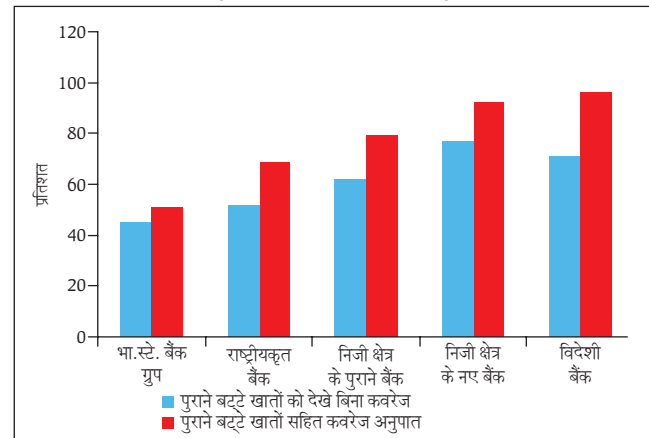
3.45 वर्ष 2009-2010 के मुकाबले वर्ष 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में तगड़ी वृद्धि हुई है (चार्ट 3.37)

चार्ट 3.35: वर्ग वार एनपीए



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

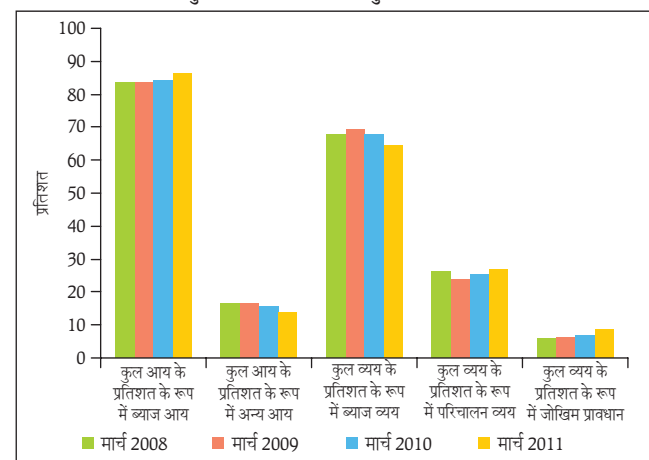
चार्ट 3.36: बैंक ग्रुपों का प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)#



पीसीआर = किया गया प्रावधान (विशिष्ट+फ्लोटिंग) + तकनीकी राईट ऑफ के स्टाक निवल एनपीए + तकनीकी राईट ऑफ * के स्टाक x 100

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.37: कुल आय और व्यय* के अनुपात में आय और व्यय घटक



*कुल व्यय में प्रावधान शामिल है लेकिन कर नहीं

स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

⁶ कुछ बैंकों को उनके अनुरोध पर 70 प्रतिशत का प्रावधान कवरेज अनुपात को प्राप्त करने के लिए निर्धारित तारीख अर्थात् 30 सितंबर, 2010 के बाद समय बढ़ाकर मंजूर किया गया था, उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे 30 सितंबर 2010 को 70 प्रतिशत के लिए आवश्यक प्रावधान को परिकल्पित करें और उसमें से कमी की गणना करें। इन बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे शीघ्रतः उस कमी को पूरा करें।

⁷ <http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=6415&Mode=0>

गत वर्ष के 7.5 प्रतिशत के मुकाबले, इस वर्ष ब्याज-आय में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गत वर्ष के 4.0 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष ब्याज-व्यय में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2010-11 में बैंकों की निवल ब्याज-आय में 34.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्याज से इतर आय में कोई परिवर्तन न होने के बावजूद, निवल लाभ में 19.5 प्रतिशत, जोखिम प्रावधानीकरण में 49 प्रतिशत तथा परिचालन व्यय में हुई 24 प्रतिशत की वृद्धि में निवल ब्याज-आय का प्रभाव देखने को मिला (चार्ट 3.38)।

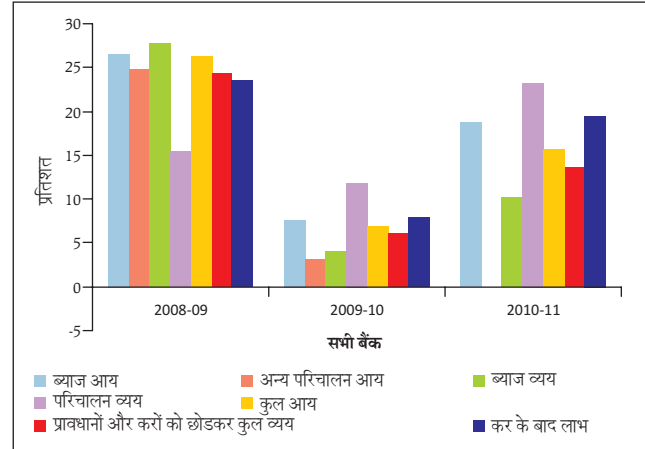
3.46 ब्याज-आय में हुई 18.6 प्रतिशत की यह वृद्धि ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं थी, जो वर्ष 2010-11 में 22.6 प्रतिशत थी। ब्याज-आय पर ब्याज की घोषित दर को न्यूनतम ब्याज दर के रूप में लागू करने से भी कोई ठोस परिणाम देखने को नहीं मिला। जमाराशियों की मात्रा और लागत के बढ़ जाने, उच्च ब्याज दर पर अधिक ऋण लिए जाने तथा बचत खातों के शेष पर दैनिक आधार पर ब्याज लगाए जाने के बावजूद, ब्याज-व्यय में केवल 10 प्रतिशत से तनिक ज्यादा वृद्धि देखने को मिली।

3.47 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शुल्क-आय में वृद्धि एवं निवेश संविभाग संबंधी ट्रेडिंग में 77 प्रतिशत हास हो जाने से विदेशी मुद्रा परिचालनों से हुए लाभों के लगभग ऑफ-सेट हो जाने से उनकी ब्याज से इतर आय गत वर्ष के मुकाबले अपरिवर्तित रही। यह हास संभवतः बढ़ती हुई ब्याज दरों एवं वर्ष की दूसरी छमाही में चलनिधि संबंधी प्रणालीगत दिक्कतों से हुआ। विदेशी बैंकों को उनकी प्रतिभूति ट्रेडिंग गतिविधियों में लगातार अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ा। बैंकों की ब्याज से इतर आय के प्रतिभूति ट्रेडिंग लाभों के हिस्से में भी वर्ष 2008-09 के बाद लगातार गिरावट आती रही (चार्ट 3.39)।

3.48 बैंकों के ब्याज से इतर व्यय में भी मुख्यतः स्टाफ संबंधी व्यय के कारण गत वर्ष के व्यय से 24 प्रतिशत ज्यादा वृद्धि देखने में आई। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए वेतन संशोधनों के कारण स्टाफ संबंधी व्यय में 30.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ब्याज से इतर व्यय में स्टाफ संबंधी व्यय का हिस्सा प्रणालीगत स्तर पर 58 प्रतिशत (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में 65 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में 60 प्रतिशत) दर्ज किया गया।

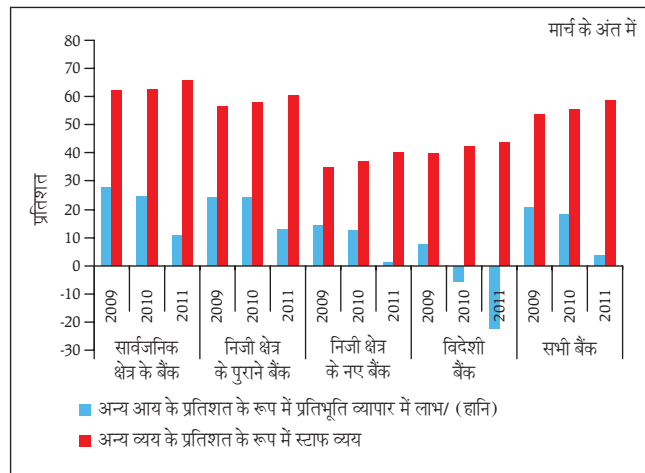
3.49 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में वेतन संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बढ़ी हुई उपदान-सीमा तथा उन स्टाफ सदस्यों के लिए पेंशन का विकल्प खोला जाना शामिल है जिन्होंने पहले इसके लिए विकल्प नहीं दिया था। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, बैंकों से

चार्ट 3.38: आय और व्यय के चुनिंदा घटकों की वृद्धि



स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.39: निवेशों में व्यापार से लाभ का श्रेय और अन्य आय/व्यय में स्टाफ व्यय



स्रोत: रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

अपेक्षा की गई कि वे सेवारत कर्मचारियों की पेंशन देयताओं और ग्रैच्युटी की बढ़ी हुई सीमा (5 वर्षों में परिशोधन योग्य) और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन देयताओं और ग्रैच्युटी की बढ़ी हुई सीमा (बिना परिशोधन के) के लिए प्रावधान करें। वर्ष 2011 में स्टाफ पर होने वाले व्यय का एक बड़ा हिस्सा, पेंशन और ग्रैच्युटी संबंधी प्रावधानों के कारण विशेषकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में, एकबारगी प्रावधान के कारण था, लेकिन सेवारत कर्मचारियों के लिए पेंशन देयताओं के परिशोधन का आने वाले वर्षों के दौरान भी लाभप्रदता पर असर पड़ेगा। आगे चलकर, बैंकों को ऐसी देयताओं के लिए निरंतर पर्याप्त प्रावधान करना आवश्यक होगा ताकि विशेष विनियामक व्यवस्था की जरूरत न पड़े (बॉक्स 3.2)।

3.50 वर्ष के दौरान सकल जोखिम प्रावधान में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वृद्धि मुख्य रूप से एनपीए संबंधी प्रावधानों की अपेक्षा में वृद्धि (सितम्बर 2010 के अंत में एनपीए के लिए 70 फीसदी के प्रॉविजनिंग कवरेज अनुपात की विनियामक शर्त) के कारण हुई।

प्रणालीगत स्तर पर लाभप्रदता अनुपात बढ़े थे, फिर भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामलों में कुछ गिरावट देखी गई

3.51 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लाभप्रदता अनुपातों में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार देखा गया और बैंकों का परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ और इक्विटी पर प्रतिलाभ 2009-10 के 1.0 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2010-11 में 1.1 प्रतिशत और 13.7

बॉक्स 3.2: सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों में वेतन संशोधन के कारण पेंशन और ग्रैच्युटी संबंधी देयताओं के लिए प्रावधान करना : प्रणालीगत समस्याएं

अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक आईएस 19 पर आधारित वर्तमान लेखाकरण मानक एस 15 के अनुसार कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के लाभों के लिए, जिसमें पेंशन और ग्रैच्युटी जैसी निर्दिष्ट लाभ योजनाएं भी शामिल हैं, बैंकों को निरंतर विवेकपूर्ण ढंग से प्रावधान करने होते हैं। यह पहलू किसी भी वेतन संशोधन के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 9वें द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत आए निजी क्षेत्र के 10 पुराने बैंकों के पिछले वेतन संशोधन पर अप्रैल 2010 में हस्ताक्षर किए गए। इस वेतन संशोधन में कुछ नई बातें शामिल की गईं, जैसे - (क) वेतन में %17.5 की भारी वृद्धि, (ख) सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन का दूसरा विकल्प देना, और (ग) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में किए गए संशोधन के बाद ग्रैच्युटी की सीमा रु.3.5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख किया जाना। सरकारी क्षेत्र के 25 बैंकों के संबंध में भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशित अतिरिक्त देयता रु.30,366 करोड़ है जिसमें पेंशन का दूसरा विकल्प (रु. 22,488 करोड़) और ग्रैच्युटी बढ़ना करोड़ (रु.7,878 करोड़) शामिल है। यह देयता काफी बड़ी है और बैंकों के वर्ष 2009-10 के निवल लाभ का 81.9% है। लेखाकरण मानकों के अनुसार इन देयताओं को लाभ-हानि लेखा में शामिल किया जाना आवश्यक था। चूंकि उपर्युक्त कारणों से पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ के प्रभाव को बैंक सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए भारतीय बैंक संघ ने अपने सदस्य बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक से अतिरिक्त देयताओं के परिशोधन के लिए अनुमोदन मांगा। भारतीय बैंक संघ ने तर्क दिया कि ये दोनों बातें अप्रत्याशित थीं और ऐसा बार-बार नहीं होता। उपर्युक्त को ध्यान में रखकर और सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर इन देयताओं के व्यापक प्रभाव को देखते हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से परामर्श करके, इस संबंध में कुछ शर्तों के अधीन पाँच वर्षों के लिए परिशोधन की विनियामक व्यवस्था करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया। इस व्यवस्था का लाभ सेवानिवृत्त/अलग हो चुके कर्मचारियों से संबंधित देयताओं के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। इस सुविधा का लाभ, आवश्यक परिवर्तनों सहित, निजी क्षेत्र के उन 10 पुराने बैंकों को भी दिया गया जिन्होंने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पेंशन के लिए रु.4971 करोड़ और ग्रैच्युटी के लिए रु.1677 करोड़ की राशि को 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा में और पेंशन के लिए रु.16,897 करोड़ और ग्रैच्युटी के लिए रु.2903 करोड़ के अपरिशोधित व्यय को 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार तैयार किए गए तुलन-पत्र में शामिल कर लिया।

सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों से अलग, भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी तीसरे लाभ के रूप में पेंशन प्राप्त करते हैं। 9वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसरण में वेतनमानों में संशोधन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2011 के लिए बैंक की पेंशन निधि देयता रु.11,707 करोड़ तय की गई। भारतीय स्टेट बैंक ने यह अनुरोध किया था कि 9वें द्विपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप पेंशन में संशोधन के कारण पेंशन देयताओं के अतिरिक्त बोझ को कर्मचारियों के जीवनकाल के अनुसार बराबर बांटना चाहिए जिससे रिजर्व बैंक सहमत नहीं हुआ क्योंकि देयताओं में वृद्धि वेतनमानों में संशोधन से जुड़ी हुई थी और तर्कसंगत तरीके से इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक की लाभप्रदता पर पड़ने वाला प्रभाव बहुत बड़ा था, इसलिए प्रणालीगत स्थिरता को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त पेंशन देयताओं को पूरा करने के लिए, देयताओं में से चालू वर्ष की निवल देयताओं को घटाकर, शेष देयताओं का आरक्षित निधि में से समायोजन करने की विनियामक व्यवस्था की अनुमति दी गई। ऐसी स्थिति में बैंक ने लाभ-हानि लेखा में रु.2473 करोड़ का प्रावधान किया और रु.7927 करोड़ की शेष राशि आरक्षित निधि में प्रभाषित की गई।

आगे, यह आवश्यक है कि ऐसी देयताओं के लिए बैंक चरणबद्ध तरीके से प्रावधान करें ताकि विनियामक व्यवस्था की जरूरत न पड़े और समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले वर्ष में ही सारा बोझ केन्द्रित न हो। इसमें आवश्यकता से कम प्रावधान करने और प्रचलित लेखा-मानकों का अनुपालन न करने से उभरने वाले प्रणालीगत स्थिरता के मुद्दे भी शामिल हैं, वे भी विशेषकर तब जबकि भारतीय लेखाकरण मानक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के अनुरूप बनाए ही जाने वाले हैं। इस मामले को भारतीय बैंक संघ के साथ उठाया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी जा रही है कि वे अधिवर्षिता संबंधी अपनी देयताओं का सही ढंग से आकलन करें और संबंधित प्रावधान उस वर्ष से करना शुरू कर दें जिस वर्ष में वेतन समझौता वास्तव में किया जाना था, न कि उस वर्ष से जिस वर्ष में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.40)। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अनुपातों में गिरावट देखी गई (1.0 प्रतिशत और 16.2 प्रतिशत से घटकर क्रमश 0.9 और 15.4 प्रतिशत)। ब्याज स्प्रेड में अंतर में सुधार देखा गया और यह 2.7 से बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया।

3.52 इसके आगे, बढ़ती ब्याज दरों, बचत खाते के ब्याज दर में वृद्धि और अनर्जक आस्तियों तथा पेंशन देयताओं के लिए अधिक प्रावधान करने की संभाव्य अपेक्षाओं का प्रभाव बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ सकता है।

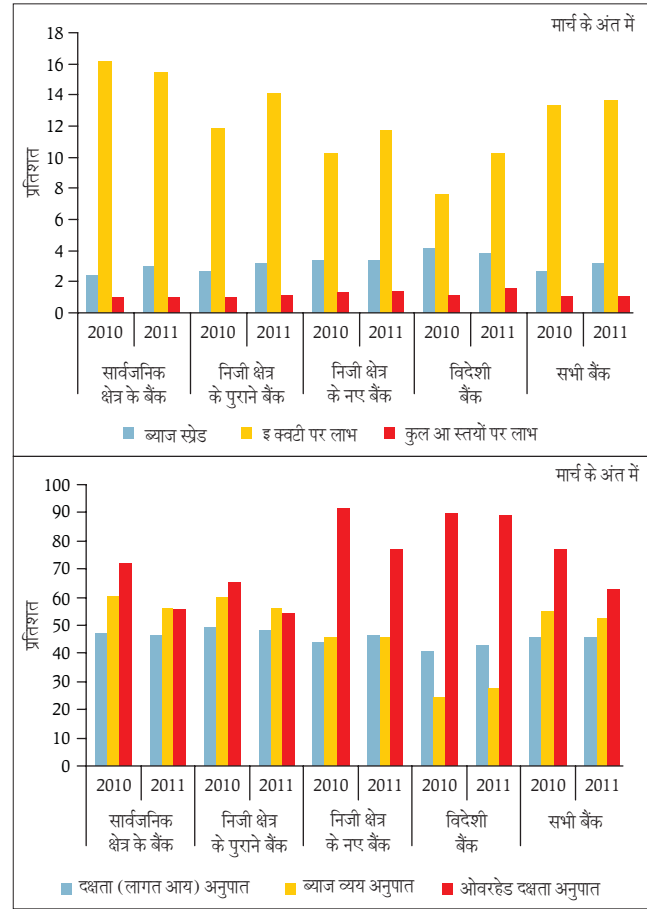
बैंकिंग स्थिरता का खाका

चलनिधि संकेतकों में अधिक जोखिम देखा गया

3.53 बैंकिंग स्थिरता का खाका और संकेतक को वित्तीय स्थिरता की पिछली रिपोर्ट में पहली बार शामिल किया गया था जिससे बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली अंतर्निहित परिस्थितियों और जोखिम के कारकों में हुए परिवर्तनों का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। संबंधित अवधि के दौरान यह मूल्यांकन पाँच आयामों पर आधारित था। सभी पाँच आयामों⁸ में कुछ और संकेतक शामिल करके इस प्रक्रिया को और व्यापक बना दिया गया (सारणी 3.2)।

3.54 बैंकिंग स्थिरता का खाका यह दर्शाता है कि मार्च 2009 और मार्च 2010 की तुलना में मार्च 2011 में सुदृढ़ता और चलनिधि पर जोखिम बढ़े जबकि कुशलता, आस्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता

चार्ट 3.40: लाभप्रदता अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

सारणी 3.2: बैंकिंग स्थिरता नक्शा और बैंकिंग स्थिरता सूचक के निर्माण हेतु संकेतक

आयाम	अनुपात			
सुदृढ़ता	सीआरएआर	टियर II पूंजी से टियर I पूंजी	पूंजी और प्रारक्षित निधियों के कुल आस्तियों के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति गुणवत्ता	कुल अग्रिमों में से निवल एनपीए	कुल अग्रिमों में से सकल एनपीए	सकल एनपीए में से अवमानक अग्रिम	मानक अग्रिमों में से पुनर्गठित मानक अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों में से आय	निवल ब्याज मार्जिन	लाभ में वृद्धि	
चलनिधि	कुल आस्तियों में से तरल आस्तियां	कुल आस्तियों में से ग्राहक जमा	ग्राहक जमाओं में से गैर बैंक अग्रिम	कुल जमाओं में से 1 वर्ष के अंतर परिपक्व होने वाले जमा
दक्षता	आय में से लागत	कुल कर्मचारियों में से व्यापार (ऋण + जमा)		

⁸ पांच संयुक्त सूचकांक सुदृढ़ता, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और सक्षमता इन पांच आयामों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी आयाम का प्रतिनिधित्व करनेवाला प्रत्येक सूचकांक शून्य (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) का मूल्य रखता है। प्रत्येक सूचकांक उसके निर्माण के लिए इस्तेमाल किये गये नमूना अवधि के दौरान संबंधित माप है, जहां उच्च मूल्य का अर्थ है, आयाम उच्च है। अतः किसी भी विशिष्ट आयाम के सूचकांक के मूल्य में वृद्धि यह संकेत देती है कि उस अवधि में अन्य अवधि की तुलना में उस आयाम के जोखिम में वृद्धि हुई है। प्रत्येक अनुपात के लिए बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है, जहां पर भार ही कुल बैंकिंग प्रणाली आस्तियों में से व्यक्तिगत बैंक की आस्तियों के अनुपात है। प्रत्येक सूचकांक को नमूना अवधि के लिए दी हुई तारीख को अनुपात माइनस नमूना अवधि में न्यूनतम मूल्य डिवाइडेड बाय नमूना अवधि में अधिकतम मूल्य माइनस नमूना अवधि में न्यूनतम अवधि के रूप में सामान्य बनाया जाता है। प्रत्येक आयाम में लाये गये सामान्यीकृत अनुपातों के भारित औसत के रूप में परिकलित किया जाता है, जहां भार बैंक के कैमल रेटिंग के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए सौपे गए गुणों पर आधारित होते हैं।

के कारण पैदा हुए जोखिम घटे (चार्ट 3.41)। बैंकिंग क्षेत्र के चलनिधि जोखिम के आकार में वृद्धि के लिए, कम से कम आंशिक रूप से, तरल परिसंपत्ति के स्तर में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सुदृढ़ता के संकेतकों से पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट का पता चला, लेकिन फिर भी ये अनुपात विनियामक अपेक्षाओं से पर्याप्त ऊपर रहे।

बैंकिंग स्थिरता संकेतक

कुछ उतार-चढ़ाव को छोड़कर बीते वर्षों के दौरान बैंकिंग स्थिरता संकेतक मजबूत हुआ है

3.55 प्रत्येक आयाम के लिए अलग-अलग मिले-जुले सूचकों के आधार पर बैंकिंग स्थिरता संकेतक सारणी 3.2 में उल्लिखित पाँच मिले-जुले उप सूचकों का साधारण औसत निकालकर तैयार किया जाता है। संकेतकों की तिमाही शृंखला बैंकिंग क्षेत्र में, सितंबर 2010 में थोड़ी गिरावट को छोड़कर, समग्र रूप से बेहतर स्थिरता का सूचक है (चार्ट 3.42)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

श्रेणी- II और श्रेणी- III के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यानिष्पादन को मॉनिटर करना आवश्यक है

3.56 ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का बहुत बड़ा नेटवर्क (11861) है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सभी वाणिज्य बैंकों के कुल शाखा नेटवर्क का करीब 37 प्रतिशत है। लाभ और लाभ प्राप्त करने की क्षमता जैसे चुनिंदा मापदंडों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तीन वर्गों में बांटा गया है - जिन्हें अर्थक्षम बनाए रखा जा सकता है (वर्ग -I - 55 आर.आर.बी) वर्तमान में अर्थक्षम (वर्ग -II - 24 आर.आर.बी) और घाटे में चल रहे (वर्ग -III - 3 आर.आर.बी)। घाटे में चल रहे तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और श्रेणी II के 24 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यानिष्पादन के विश्लेषण से कुछ चिंताएं उभरकर सामने आईं। जिस तरह से अन्य बैंक सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रोडक्ट अपनाकर परिचालन संबंधी दक्षता प्राप्त कर चुके हैं उसी तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को परिचालन संबंधी दक्षता दिलाने के लिए कोर बैंकिंग सोल्यूशन अपनाने की एक कार्य-योजना को अंतिम रूप दिया गया है और यह लक्ष्य सितंबर 2011 तक प्राप्त कर लेने का निर्णय लिया गया है।

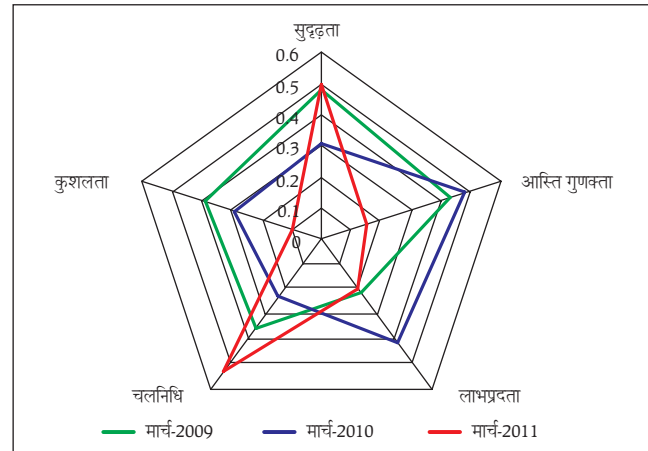
सहकारी बैंकिंग क्षेत्र

ग्रामीण सहकारी ऋण

वित्तीय सुदृढ़ता चिंता का विषय बना हुआ है

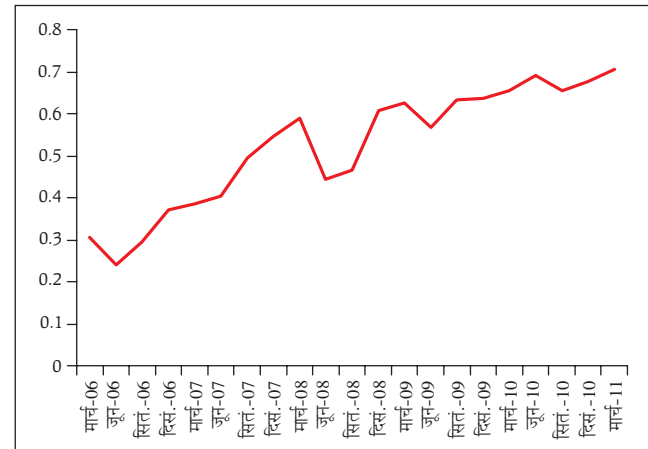
3.57 समग्र रूप से, अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं (राज्य सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) के मामले में मार्च 2010⁹

चार्ट 3.41: बैंकिंग स्थिरता नक्शा



केंद्र से दूर अधिक जोखिम का प्रतीक है
 स्रोत: पर्यवेक्षी डाटा और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 3.42: बैंकिंग स्थिरता संकेतक



उच्च मूल्य अधिक स्थिरता का प्रतीक है
 स्रोत: पर्यवेक्षी डाटा और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

⁹ अद्यतन आंकड़े उपलब्ध। 2010 के आंकड़े अंतिम हैं। कुछ राज्यों के मामलों में आंकड़े 2007-08 और 2008-09 से संबंधित हैं।

के अंत की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक परिसंपत्ति के अनुपातों में सुधार आया है। दीर्घकालिक संस्थाओं (राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के मामले में इन अनुपातों में और गिरावट देखी गई (चार्ट 3.43) देखें। 52 प्रतिशत राज्य सहकारी बैंकों और 40 प्रतिशत जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी के 9% या उससे अधिक का अनुपात प्राप्त कर लिया था। लाइसेंस देने के लिए जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में कम से कम 4% की पूँजी रखने की पूर्व शर्त जैसे विनियामक उपाय लागू किए गए हैं। यद्यपि ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के लिए न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात संबंधी मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन मार्च 2008 से इसका (पूँजी का) प्रकटीकरण आवश्यक कर दिया गया है।

3.58 वर्ष 2009-10 के दौरान, राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता में थोड़ा सुधार (क्रमशः 8 प्रतिशत और 2 प्रतिशत) हुआ, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में स्थित बैंकों ने ही लाभ अर्जित किया। दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थाओं की धारा उठाने वाली शाखाओं की संख्या काफी बढ़ गई।

3.59 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से लाइसेंस देने के लिए शेष बचे राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 7 बनी हुई है। लेकिन जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामलों में कुछ सुधार देखा गया क्योंकि लाइसेंस देने के लिए शेष बची संस्थाओं की संख्या 164 से घटकर 150 रह गई।

शहरी सहकारी बैंक

सुधरती वित्तीय स्थिति के बीच सुदृढीकरण के प्रयास जारी रहे

3.60 विलय के लिए 11 अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार 103 अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अलावा) और 18 विलयों की अधिसूचनाएं (सितंबर 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार 71 अधिसूचनाओं के अलावा) जारी करने के साथ शहरी सहकारी बैंकों का सुदृढीकरण जारी रहा। सुदृढीकरण के इन उपायों से इस क्षेत्र में कमजोर और बिना लाइसेंस वाले बैंकों की संख्या घटी है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढता के संकेतकों में सुधार देखा गया (चार्ट 3.44)।

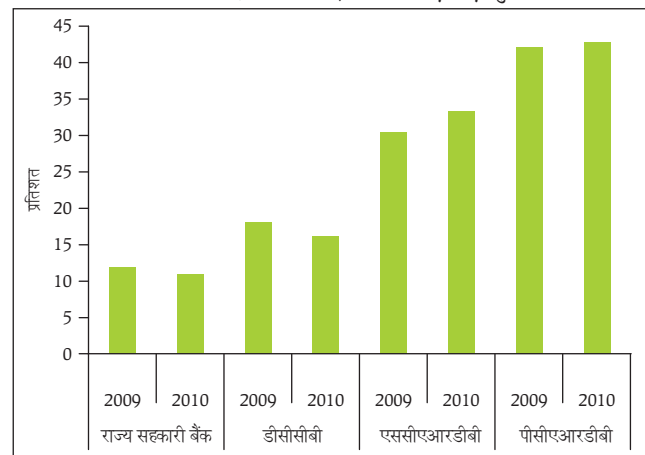
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

वित्तीय सुदृढता के संकेतकों में सुधार के साथ-साथ कारोबार में भी वृद्धि हुई

जमा स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

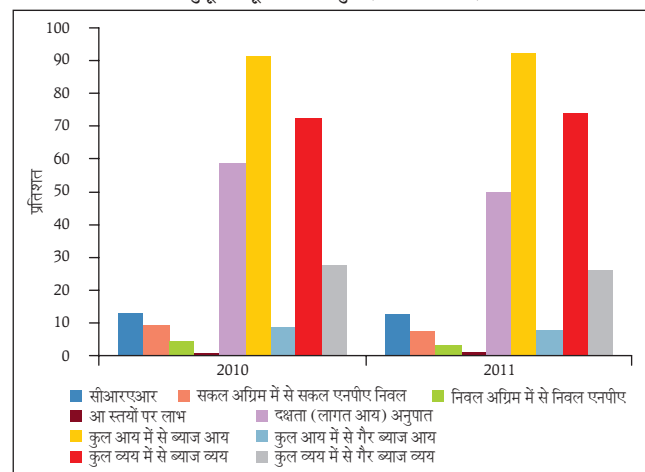
3.61 वर्ष 2010-11 के दौरान एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तुलन-पत्र के आकार में 21.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः

चार्ट 3.43: सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सकल एनपीए अनुपात



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.44: अनुसूचित यूसीबीयों के चुनिंदा वित्तीय निष्पादन के संकेतक



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

उधार में हुई 25.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ। उनकी कुल उधार राशि का बड़ा हिस्सा (30.3 प्रतिशत) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिया गया उधार रहा। परिसम्पतियों की ओर ऋणों तथा अग्रिमों में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिसम्पति गुणवत्ता तथा लाभप्रदता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ। पूंजी पर्याप्तता अनुपात में थोड़ी गिरावट आने के बावजूद यह विनियामक न्यूनतम निर्धारित अनुपात के काफी ऊपर रहा (चार्ट 3.45 और 3.46)।

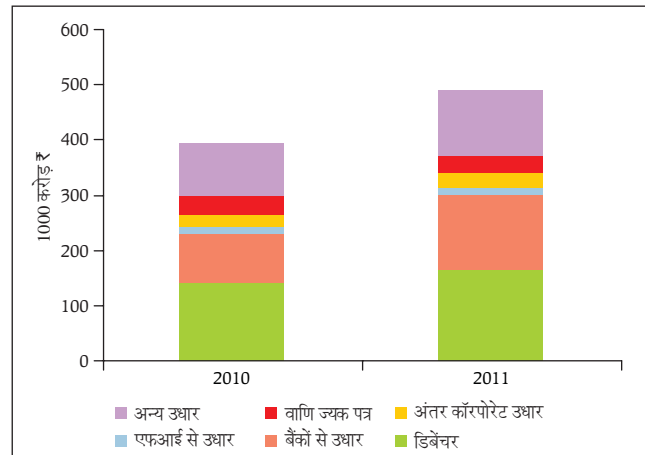
जमा राशि लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी- डी)

3.62 एनबीएफसी जमाओं के मामले में सितंबर 2010¹⁰ के अंत तक ऋणों तथा अग्रिमों में पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिसम्पति गुणवत्ता तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात में सुधार देखा गया। (चार्ट 3.47)।

विनियामक संरचना- प्रणालीगत अंतर-संबंधता की दृष्टि से संशोधन

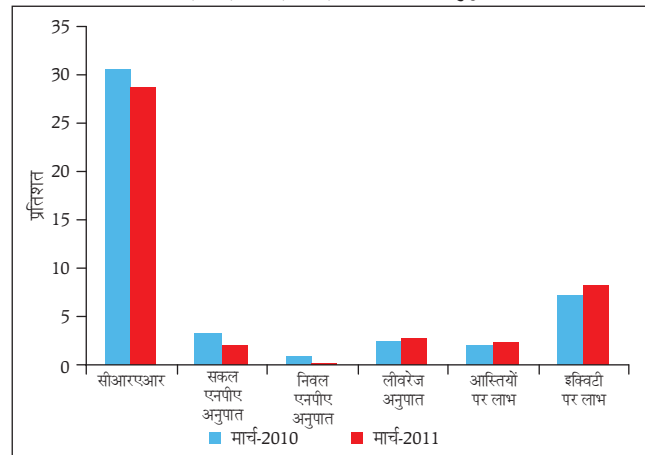
3.63 एनबीएफसी सेक्टर की आर्थिक भूमिका व विविधता और इसकी प्रणालीगत अंतर-संबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विनियमन में उत्तरोत्तर कठोरता लाई गई है। इस संबंध में हाल में लिए गए महत्वपूर्ण विनियामक उपायों की कड़ी में एनबीएफसी-एनडी-एसआई और एनबीएफसी-डी दोनों का सीआरएआर पहले के निर्धारित 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया गया। (एनबीएफसी-डी के संबंध में अनुबंध मार्च 2012 के अंत में लागू होगा)। मानक परिसंपत्ति के लिए 0.25 प्रतिशत का प्रावधान और ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंडों में बैंकों के निवेश पर विवेकसम्मत सीमा भी निर्धारित की गई है। जो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मुख्यतः सोना गिरवी रखकर ऋण प्रदान करती हैं, उनमें संकेद्रन जोखिम, इन कंपनियों द्वारा उच्च ब्याज दर लेने, फंडों का प्रयोजनपरक उपयोग सुनिश्चित करने में कठिनाई, ऐसे निवेशों में होने वाले संपार्श्विक जोखिम आदि के कारण चिंताएं रहीं। इन मामलों को हल करने के उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने यह निदेश जारी किया कि सोना गिरवी रखकर ऋण देने हेतु गैर-वित्तीय संस्थाओं को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण आगे से कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत होने के पात्र नहीं होंगे। इसके बाद अलग से किए गए एक उपाय में यह घोषणा की गई कि उन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को छोड़कर जो हाल ही में लाई गई कुछ पात्रता शर्तों (जैसा कि अगले पैराग्राफ में दिया गया है) को पूरा करती हैं, अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र नहीं होंगे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन संबंधी मामलों के सभी पहलुओं के निराकरण के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसकी चर्चा पाठ IV में की गई है।

चार्ट 3.45: एनबीएफसी-एनडी-एसआई की उधार राशियां



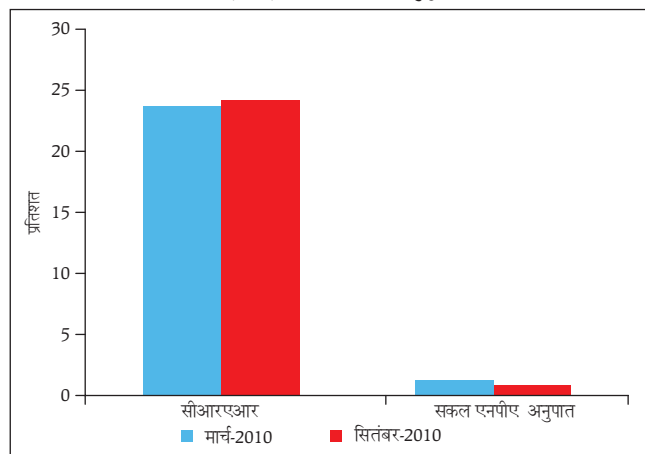
स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.46: एनबीएफसी-एनडी-एसआई का वित्तीय सुदृढता संकेतक



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 3.47: एनबीएफसी-डी का वित्तीय सुदृढता संकेतक



स्रोत: रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां

¹⁰ नवीनतम ऑफ-सेट डाटा उपलब्ध

माइक्रो फाइनेंस संस्था क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना

3.64 माइक्रोफाइनेंस सेक्टर पर मालेगाम समिति की सिफारिशों के अनुसार एमएफआइ के रूप में काम करने वाली एनबीएफसी सहित सभी माइक्रो फाइनेंस संस्थान (एएफआइ) को दिए जाने वाले बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में वर्गीकृत होने के पात्र तभी होंगे जब उनकी कुल परिसंपत्तियों का निर्धारित प्रतिशत 'क्वालिफाइंग परिसंपत्ति' के रूप में हों और वे इस संबंध में जारी किए जाने वाले 'प्राइसिंग ऑफ इन्टरेस्ट' दिशानिर्देशों का पालन करते हों। बैंकों द्वारा अन्य एनबीएफसी को दिए जाने वाले ऋण 01 अप्रैल, 2011 से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में नहीं माने जाएंगे। साथ ही आंध्र-प्रदेश में स्थित एमएफआइ द्वारा वसूली में गिरावट और अन्य राज्यों में इस तरह के आरंभिक संकेतों के फलस्वरूप उन पुनर्गठित एमएफआइ खातों को विशेष विनियामक परिसम्पत्ति लाभ प्रदान किया गया जो पुनर्गठन के समय स्तरीय थे भले ही वे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे।

बीमा क्षेत्र- वित्तीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग

3.65 बीमा कंपनियों वित्तीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं और आंतरिक एवं वैश्विक दोनों स्तर पर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इनका सुचारु रूप से कार्य करना आवश्यक है। इस क्षेत्र में शोधक्षम/सोलवेंसी

संबंधी जोखिम, निवेश लाभ, आर्थिक मंदी, बीमाओं के बने रहने संबंधी मामले¹¹ आदि जैसे जोखिम हैं - हालांकि ऐसा समझा जाता है कि प्रणालीगत जोखिम में इनका योगदान बैंकों की तुलना में कम होता है (बॉक्स 3.3)।

इस क्षेत्र को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने से इसके विकास में तेजी आई है और देश में बीमा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है

3.66 वर्ष 2000 में भारत में बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के साथ ही जीवन बीमा के क्षेत्र में 22 और गैर जीवन बीमा क्षेत्र में 15 कंपनियों ने प्रवेश किया। साथ ही तीन बीमाकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में एकल आधार पर कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त है। विदेशी कंपनियों को इस क्षेत्र में किसी भारतीय प्रोमोटर के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में 26 प्रतिशत की निर्धारित एफडीआई सीमा के साथ प्रवेश करने की अनुमति है। 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) के साथ पंजीकृत बीमाकर्ताओं की कुल संख्या 48 है। इसमें शामिल हैं- 23 जीवन बीमाकर्ता, 19 सामान्य बीमाकर्ता, 3 एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियां और 2 विशेष कंपनियां जिनमें से एक ऋण बीमा व फसल बीमा के क्षेत्र में कार्यरत है जबकि दूसरा पुनर्बीमाकर्ता है। अंशतः इन उपायों के परिणामस्वरूप बीमा क्षेत्र का विस्तार (जो

बॉक्स 3.3: बीमा क्षेत्र से होने वाले प्रणालीगत जोखिम

बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में बीमा क्षेत्र से प्रणालीगत जोखिम कम होता है। बैंकिंग क्रियाकलापों के विपरीत, जो परिपक्वता पर भुगतान करना है, बीमा क्षेत्र अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रीमियम की वसूली बाद में करने के बजाए अग्रिम रूप में करता है। इस तरह की अग्रिम फंडिंग नकदी जोखिम तथा लीवरेज पर निर्भरता कम करता है यदि प्रीमियम का मूल्य निर्धारण सही हो। बीमा क्षेत्र की एक और अलग विशिष्टता यह है कि पॉलिसी बैंक खातों की तरह नहीं होती। अर्थात् उपलब्ध शेष इच्छानुसार आहरित नहीं किए जा सकते हैं। पॉलिसी धारकों को पॉलिसी में शेष से पैसा निकालने की अनुमति नहीं होती है तथा इस प्रकार के अनुरोध पर दंड स्वरूप भारी शुल्क लगाए जाते हैं। अतः बीमा क्षेत्र में 'बैंक रन' जैसी स्थिति सामान्यतः नहीं होती है। एक ओर जहां परिसम्पत्ति मूल्य में देयताओं की तुलना में भारी गिरावट होने पर 'बैंक रन' के कारण बैंकों में तत्काल विफलता देखने को मिलती है वहीं बीमा क्षेत्र में दिवालियापन धीरे-धीरे कई वर्षों में आता है। इसका कारण बीमा प्रोडक्टों पर दावों की अवधि लंबी होना तथा भुगतान दिनांक का अधिक फैला हुआ होना है। बैंकों की तुलना में बीमाकर्ताओं के पास संकट से निपटने

के लिए अधिक स्वतंत्रता और समय होता है क्योंकि बैंकों को जमाराशियों के आहरण पर अल्पावधि में भुगतान करना होता है।

चूंकि बीमा कंपनियों वित्तीय समूह का एक हिस्सा हैं, इनके दिवालियापन से प्रणालीगत जोखिम पैदा हो सकता है क्योंकि ऐसा होने से समूह के वाणिज्यिक बैंक की ऋणपात्रता पर प्रश्नचिह्न लगता है, विशेषकर यदि बैंक काफी बड़े आकार के हों। बावजूद इसके, किसी वित्तीय समूह के अंदर पूंजी का अनेक तरह से प्रयोग निषेध इस तरह के प्रणालीगत जोखिम को प्रभावी रूप से कम करता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ बीमा कार्यकलापों का इंटरलिंगेज वित्तीय व्यवस्था में व्यवधान का स्रोत हो सकता है (मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र)। उदाहरण के तौर पर बीमाकर्ता अनेक वित्तीय बाजारों- इक्विटी और सरकारी प्रतिभूति में बड़े निवेशक होते हैं और स्टॉक बाजार गतिविधियों को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। नॉन-लाइफ बीमा कारोबार के मामले में घरेलू विनियम दर में उतार-चढ़ाव अहम हो सकता है जहां विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को बड़ी मात्रा में प्रीमियम दिए जाते हैं।

¹¹ वैसे जीवन बीमा या अन्य बीमा पॉलिसियों का प्रतिशत, जो चालू है, वैसे पॉलिसियों का प्रतिशत जो व्यपगत न हों। प्रतिशत जितना उच्च होगा, सातत्य (persistence) उतना ही अधिक होगा। चूंकि यह कंपनी के जीवन बीमा कारोबार को जारी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, अधिकतर कंपनियां सातत्य बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

किसी एक वर्ष में उस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से निवेश किए गए प्रीमियम के अनुपात द्वारा आंकी जाती है) 2000 के 2.3 से बढ़कर 2009 में 5.4 हुआ।

3.67 जीवन बीमा उद्योग का लिंकड¹² तथा नॉन-लिंकड कारोबार 2003 - 04¹³ के क्रमशः 8.5 और 91.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2010-11 में निवेश किए गए प्रीमियम का 42.1 और 57.9 प्रतिशत रहा।

3.68 भारतीय परिप्रेक्ष्य में बीमा कंपनियों को कई विवेकपूर्ण मानदंडों अर्थात् जीवन और सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए न्यूनतम पूंजी, सोलवेंसी अनुपात, निवेश मानदंड, निवेश का स्वरूप आदि को पूरा करना पड़ता है। साथ ही बीमा कंपनियों को कमोडिटी बाजार में जाने, बैंकों से ऋण प्राप्त करने तथा बीमा धारकों के फंडों को विदेशों में निवेश करने की अनुमति नहीं है। “ जोखिम आधारित पूंजी “ और “ जोखिम आधारित पर्यवेक्षण “ पद्धति की दिशा में पहले कदम के रूप में अब जीवन बीमा कंपनियों को उनके वार्षिक बीमाकिक और अन्य रिपोर्टों के भाग के रूप में आइआरडीए को “आर्थिक पूंजी“ रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है। आर्थिक पूंजी परिकलन में विशिष्ट जोखिमों का परिमाणन और बीमाकर्ताओं को होने वाले विभिन्न जोखिमों के संदर्भ में प्रणालीगत जोखिमों के प्रबंधन में मदद मिलती है। तथापि मूल बीमा कार्यकलापों से प्रणालीगत हलचल न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए बाकी वित्तीय प्रणाली के साथ इस क्षेत्र के इंटरलिकेज की ध्यानपूर्वक निगरानी आवश्यक है।

निष्कर्ष टिप्पणी

3.69 भारत में 2010-11 के दौरान ऋण के कुल व्यापार में बढ़ोत्तरी पिछले कई वर्षों की प्रवृत्ति से ऊपर रही। ऋण बढ़ोत्तरी कुछ खास क्षेत्रों में केंद्रित रही जिससे इस दिशा में सतर्कता बरतने की आवश्यकता पड़ी ताकि जोखिम उत्पन्न होने/अत्याधिकता को रोका जा सके। क्रेडिट विकास में सुधार के फलस्वरूप अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन-पत्र में 19 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। हालांकि जमाराशि में धीमी वृद्धि के कारण ऋण तथा विस्तार के लिए फंड हेतु अन्य अल्पकालिक साधनों पर निर्भरता लगातार बनी रही। जमाओं तथा अग्रिमों की परिपक्वता अवधि प्रोफाइल में

बढ़ती संरचनात्मक असंतुलन के कारण भी नकदी संकट से संबंधी चिंताएं रहीं।

3.70 ऋण विस्तार के अनेक क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद इसमें मुख्यतः रिटेल, वाणिज्यिक रियल एस्टेट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण का योगदान रहा। अड़तीस प्रमुख उद्योगों में बैंक ऋण परिनियोजन के अध्ययन से उच्च जोखिम उद्योगों में निवेश का घटता चलन उजागर हुआ। बैंकों के ऑफ बैलेंस शीट निवेश में लगातार वृद्धि हुई जिसमें विदेशी बैंकों के निवेश में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। ऑन बैलेंस शीट निवेशों की तुलना में इनका ऑफ बैलेंस शीट आनुपातिक निवेश 18 गुणा से भी अधिक रहा।

3.71 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण पर्याप्तता काफी मजबूत रही हालांकि मजबूत क्रेडिट ऑफ-टेक के कारण इसमें मामूली गिरावट देखी गई। भारत में बैंकों का लीवरेज अनुपात (leverage ratio) 3 प्रतिशत से काफी ऊपर रहा, जैसा कि बासल III मानकों के अंतर्गत अपेक्षित है।

3.72 एनपीए में वृद्धि के अनुपात में ऋण विकास अधिक रहा जिससे क्रेडिट ऑफ-टेक में सुधार हुआ। इसके फलस्वरूप परिसम्पत्ति गुणवत्ता में सुधार देखा गया। साथ ही बेतहाशा ऋण विकास के कारण बड़े पैमाने पर चूक की गुंजाइश बनी रही जिस कारण निरंतर सतर्कता की आवश्यकता बनी रही। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति चक्रीय उपाय, जिसमें 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार एनपीए के स्तर पर 70 प्रतिशत का न्यूनतम प्रावधान कवरेज अनुपात निर्धारित किया गया, एनपीए में संभावित वृद्धि के विरुद्ध कुशन का काम कर सकता है।

3.73 2010-11 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में सुधार हुआ। हालांकि पेंशन देयताओं हेतु प्रावधान में वृद्धि के कारण सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की स्टाफ पर खर्च में काफी अधिक वृद्धि हुई। साथ ही बढ़ती ब्याज दर, बचत खाता ब्याज दर में बढ़ोत्तरी, पेंशन तथा उपदान देयताओं का परिशोधन और संभवतः एनपीए के लिए अधिक प्रावधान बैंकों की लाभप्रदता पर असर डाल सकता है।

¹² ये प्रोडक्ट (यूनिट लिंकड बीमा योजना - यूलिप) पॉलिसीधारक को बीमा कवर देने के साथ इक्विटी और ऋण लिखतों में विविध निवेश के कारण दीर्घ अवधि में उच्च लाभ प्रदान करते हैं। यूलिप परंपरागत प्रोडक्टों से इस रूप में भिन्न होते हैं कि बीमा कंपनी द्वारा निवेश किए गए प्रीमियम में होने वाले जोखिम और लाभ पूरी तरह पॉलिसी धारक द्वारा वहन किए जाते हैं। बीमा धारक बीमाकर्ता द्वारा दिए अनेक विकल्पों में से निवेश के स्वरूप का चयन करता है अर्थात् ऋण, इक्विटी और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात क्या हो। यह अनुपात उसके जोखिम वहन करने की क्षमता पर आधारित होता है।

¹³ स्रोत: आइआरडीए

3.74 बैंकिंग स्थिरता स्थिति मार्च 2010 की तुलना में मार्च 2011 के अंत में नकदी जोखिम में वृद्धि दर्शाती है। हालांकि बैंकिंग स्थिरता संकेतक स्थिरता के मामले में बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती को दर्शाता है।

3.75 सहकारी क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता चिंता का विषय बनी रही हालांकि इसमें सुधार के उपाय जारी रहे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन में लगातार कड़ाई की गई ताकि विनियमन में कमियों को दूर किया जा सके तथा विनियामक अंतरपणन को रोका जा सके।

3.76 बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने और संयुक्त उद्यम के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के फलस्वरूप इसके विस्तार में वृद्धि हुई है। भारत में बीमे के लिए विनियामक फ्रेमवर्क ने इस क्षेत्र को मजबूत ओर सुविनियमित क्षेत्र बनाया है। हालांकि बीमा कारोबार की आवश्यक संरचना अपेक्षाकृत कम प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करती है, बैंकिंग तथा बाकी वित्तीय प्रणाली के साथ इसका जुड़ा होना बाधा का कारण बन सकता है जिसकी सावधानीपूर्वक निगरानी करने की आवश्यकता हो सकती है।

अध्याय IV

वित्तीय क्षेत्र की नीतियां और बुनियादी सुविधाएं

वित्तीय स्थिरता के लिए स्वस्थ विनियामक नीतियां, वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं तथा सुचाह रूप से चल रहे वित्तीय बाजार जैसी मूलभूत सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। 2013 में, बासल III उपायों के लिए फेज-इन अवधि प्रारंभ होगी। बासल II के अधीन उन्नत उपाय करने के लिए प्रयास पहले ही प्रारंभ किए जा चुके हैं। पूरे विश्व में विनियामकों तथा बैंकों को, और विशेषकर भारत जैसे उभरते बाजारों में, भविष्य में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटानी पड़ सकती है। सभी बैंकों को बासल II के अधीन संशोधित चलनिधि फ्रेमवर्क तथा उन्नत उपायों के लिए कड़े आंकड़ों तथा विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। वित्तीय महासंघों के लिए पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क को मजबूत किया जा रहा है, देशों में बड़ी वित्तीय इकाइयों के लिए वित्तीय धारिता कंपनी माडल को बेहतर माना जा रहा है। संकट की संभावना को कम करने के लिए क्रस बार्डर पर्यवेक्षी सहयोग की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। विनियामक कमियां विशेषकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में, आर्बिट्रेज के अवसर देती हैं हालांकि वित्तीय क्षेत्र के कानूनों में बदलाव किया जा रहा है और विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विधान में संशोधन किया जा रहा है। सहकारी समितियों द्वारा, विवेकपूर्ण मानदंडों के बिना बाह्य स्रोतों सहित अन्य स्रोतों से जमाराशियां जुटाने के लिए, विनियामक व्यवस्था की कमियों को दूर किया जाना आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति से वित्तीय स्थिरता के लिए एक और अधिक सक्रिय, मौके पर कार्रवाई के लिए संस्था के रूप में कार्रवाई करना अपेक्षित है, तथापि संकट के समय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद पर्यवेक्षण करेगी तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय बैंकों का द्विपक्षीय नेटवर्क आपस में बहुत जुड़ा हुआ है जिससे किसी बैंक के असफल हो जाने से परस्पर प्रभाव का जोखिम बढ़ जाता है। अंतर बैंक जोखिम की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से डौमिनो प्रभाव सीमित हो जाता है, लेकिन परस्पर सम्बद्धता के नेटवर्क पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है। देश की भुगतान तथा निपटान प्रणालियां मजबूत हैं, लेकिन उनमें परस्पर काफी निर्भरता है जिससे वे अतार्किक आघातों के प्रति असुरक्षित हो जाते हैं। सुरक्षा नेट व्यवस्थाओं को निधियों की पर्याप्तता तथा उनके प्रबंधन, कवरेज, वसूली निष्पादन तथा निपटान के लिए लिए गए समय के संबंध में अति महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना होगा।

4.1 2007 में प्रारंभ हुए वित्तीय संकट ने प्रणाली को मजबूत बनाने तथा भावी वित्तीय और आर्थिक व्यवधानों को सीमित रखने के लिए नए पर्यवेक्षी तथा विनियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर किया है। यह दृष्टिकोण समष्टि विवेकपूर्ण प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हाल ही की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि वैयक्तिक स्तर पर तर्कसंगत विकल्प भी नकारात्मक प्रणालीगत परिणाम दे सकते हैं। वस्तुतः बेहतर विनियमन, एक प्रभावकारी विनियामक व्यवस्था तथा जोखिमों की पहचान करने के लिए आंकड़ों तथा सूचना का प्रभावी विश्लेषण वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है।

4.2 अध्याय के पहले भाग में भारतीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाने तथा बासल III की आवश्यकताओं के लिए तैयार होने के साथ वर्तमान चुनौतियां दी गई हैं। यह वित्तीय क्षेत्र की नीतियों को मजबूत और बेहतर

बनाने के लिए विनियामक प्रयासों को भी रेखांकित करता है। अध्याय के दूसरे भाग में देश में वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के लिए व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है, विनियामक पैरामीटर में कमियों को रेखांकित किया गया है और विनियामक आर्बिट्रेज के अवसरों को चिह्नित किया गया है। तीसरे भाग में भारत में बैंकिंग प्रणाली में अंतर बैंक जोखिमों के नेटवर्क के विश्लेषण का अध्ययन किया गया है। अध्याय के अंतिम भाग में भुगतान तथा निपटान प्रणालियों में जोखिम और असुरक्षा तथा सुरक्षा व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं।

वित्तीय क्षेत्र की नीतियां

4.3 बैंकिंग क्षेत्र की समुत्थान शक्ति को मजबूत करने तथा जोखिमों के चक्रीय निर्माण के लिए उत्तरदायी त्रुटियों को दूर करने के लिए वैश्विक विनियामक सुधार कार्यसूची तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति

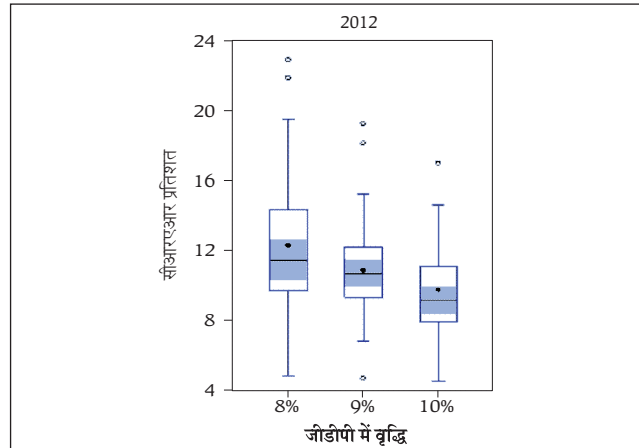
हुई है। पिछली एफआरएस में इनका उल्लेख किया गया था। रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत मानकों तथा सुधारों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ आंतरिक पहल की गई है - अनर्जक आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान बढ़ाना, ऋणोमुख म्यूचुअल फंडों में बैंकों की निवेश राशि पर विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित करना। कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं अर्थात् बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाना, पूंजी, चलनिधि तथा लीवरेज के लिए बासल III के अधीन प्रस्तावों को स्वीकार करना, प्रतिक्रिय बफर के लिए योजना तैयार करना, संशोधित लेखा मानकों, आदि पर सहमति जो भविष्य में विनियामकों तथा विनियामक ईकाइयों दोनों के लिए ही चुनौती होंगे।

बासल III के अधीन उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं

4.4 सामूहिक रूप से, विशिष्ट फर्म तथा व्यापक प्रणालीगत जोखिमों को “बासल III” कहा गया है, जिनकी मुख्य-मुख्य बातों को पिछली एफएसआर में रेखांकित किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि भारत में बैंकों की सहज पूंजी पर्याप्तता स्थिति को देखते हुए, भारतीय बैंकिंग को बासल III के अधीन कड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी। यह भी रेखांकित किया गया था कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, मजबूत वृद्धि की आवश्यकता, बुनियादी सुविधाओं की निवेश आवश्यकताएं तथा बढ़ते वित्तीय समावेशन को देखते हुए ऋण की मांग में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार, समग्र स्तर पर वर्तमान स्थिति के बावजूद, कुछ बैंकों को अपनी पूंजी में वृद्धि करनी पड़ेगी।

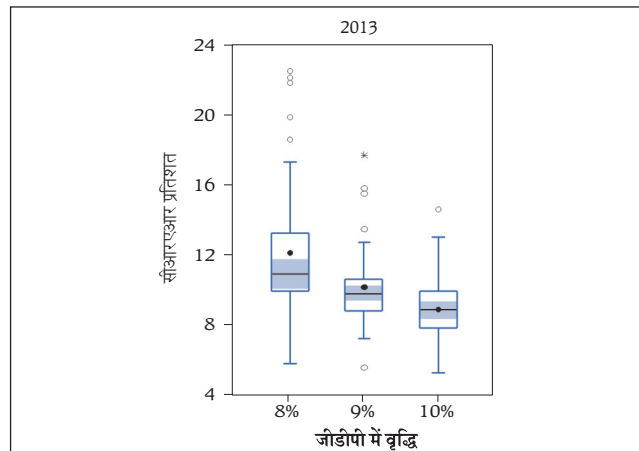
4.5 एक आंतरिक अध्ययन से पता चला है कि वस्तुतः यही स्थिति है। विभिन्न वृद्धि परिदृश्यों तथा 15 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आंतरिक प्राप्तियों के माध्यम से पूंजी निधियों को मानते हुए बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए कई रिग्रेसन विश्लेषण किए गए। विश्लेषण से पता चला कि कई बैंक बासल II परिदृश्य के अधीन भी न्यूनतम विनियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और आगामी वर्षों में उनकी पूंजी में वृद्धि करनी पड़ेगी (चार्ट 4.1 तथा 4.2)¹। इक्विटी बाजारों के मंद निष्पादन को देखते हुए यह बैंकिंग प्रणाली के लिए चुनौती बन सकता है और सरकारी

चार्ट 4.1: सीआरएआर अनुमान (2012)



स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक स्टाफ की गणना

चार्ट 4.2: सीआरएआर अनुमान (2013)



स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक स्टाफ की गणना

¹ आंतरिक अध्ययन में पाई गई अतिरिक्त पूंजी उस पूंजी को दर्शाती है, जो ऋण की अपेक्षित मजबूत वृद्धि, जो अध्ययन में वृद्धि दरों से मानी हुई है, के कारण बैंकों को अपना पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने के लिए जुटाने के आवश्यकता होगी।

वित्त पर दबाव भी डाल सकता है। आईएफआरएस अपनाने पर 1 अप्रैल, 2013 तक पेंशन देयताओं के भाग के कारण बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा।

प्रतिचक्रिय बफर तैयार करना चुनौतीपूर्ण

4.6 बासल III प्रस्तावों में बैंकिंग प्रणाली के लिए दो पूंजी बफर की परिकल्पना की गई है - पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रिय बफर (बाक्स 4.1)। बासल III के अधीन प्रस्तावित प्रतिचक्रिय बफर तैयार करने में बहुत सारी चुनौतियां हैं। बफर का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक समग्र ऋण वृद्धि की अवधियों में बैंकिंग क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के व्यापक समष्टि विवेकपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करना है जिसे अक्सर प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण से जोड़ा जाता है। इसलिए, प्रत्येक अधिकारक्षेत्र में विनियामक प्राधिकारियों को ऋण वृद्धि पर निगरानी रखनी होगी तथा यह आकलन करना होगा कि ऐसी वृद्धि अत्यधिक है तथा/या प्रणालीगत जोखिमों में निर्माण कर रही है। इस आकलन के आधार पर, उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित

करना होगा कि क्या कोई प्रतिचक्रिय बफर आवश्यकता लगानी होगी, किस हद तक लगानी चाहिए और क्या यह आवश्यकता हटा दी जानी चाहिए।

जीडीपी की तुलना में ऋण का अंतर बफर की सही मात्रा तय करने के लिए विश्वसनीय संकेतक नहीं

4.7 बासल समिति द्वारा सुझाए गए सांझे संदर्भ गाइड समग्र निजी क्षेत्र जीडीपी में ऋण अंतर पर आधारित हैं। यह संकेतक सभी समय सभी क्षेत्राधिकारों में अच्छी तरह से काम नहीं करता। यह विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्धव्यवस्था पर लागू होता है, जहां संरचनात्मक कारणों से यह बढ़ता है - उच्चतर वृद्धि तथा अधिकतर वित्तीय समावेशन के कारण उच्चतर ऋण लेना। साथ ही, कुछ आर्थिक क्षेत्र भारत के लिए नए हैं और कुछ समय पहले ही बैंकों ने बड़े पैमाने पर उनका वित्तपोषण करना प्रारंभ किया है। ऐसे जोखिम-निर्माण यदि कोई हो, का आकलन इस अनुपात द्वारा नहीं किया जा सकता।

बाक्स 4.1: बासल III के अधीन पूंजी बफर प्रस्ताव

पूंजी संरक्षण बफर: संरक्षण बफर का उद्देश्य यह है कि वित्तीय तथा आर्थिक दबाव के समय हानियां सहन करने के लिए बैंक पूंजी का बफर बनाए रखें। हालांकि बैंकों को दबाव की अवधियों में बफर आहरित करने की अनुमति है, लेकिन उनका विनियामक पूंजी अनुपात, न्यूनतम आवश्यकता के जितने अधिक निकट होगा, उनके अर्जन वितरण पर उतने ही अधिक प्रतिबंध होंगे। यह फ्रेमवर्क मजबूत पर्यवेक्षण तथा बैंक अधिशासन को सशक्त बनाएगा और उस सामूहिक कार्रवाई समस्या को दूर करेगा जो गिरती पूंजी स्थितियों में भी कुछ बैंकों को विवेकाधीन बोनस तथा उच्च डिविडेंड जैसे वितरणों को कम करने से रोकती है। पूंजी संरक्षण बफर का उद्देश्य जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) के 4.5 प्रतिशत सांझे ईक्विटी टीयर I न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के ऊपर एक नियत रेंज निर्धारित करना है। विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक इस बफर को अधिकतम 2.5 प्रतिशत पर तैयार करना होगा और कटौती के बाद सांझे ईक्विटी से पूरा करना होगा। इस प्रकार कुल सांझे 7 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाती है। पूंजी संरक्षण बफर 1 जनवरी 2016 तथा 2018 के बीच में लागू किया जाएगा और 1 जनवरी 2019 को पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा। यह जनवरी 2016 में आरडब्ल्यूए 0.625 प्रतिशत पर प्रारंभ होगा और प्रत्येक वर्ष में अतिरिक्त 0.625 प्रतिशत से बढ़ेगा और 01 जनवरी 2019 को आरडब्ल्यूए के 2.5 प्रतिशत के अंतिम स्तर पर पहुंच जाएगा। तथापि, अलग-अलग देशों को कम संक्रमण अवधियां लगाने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

प्रतिचक्रिय बफर: प्रतिचक्रिय पूंजी बफर अतिरिक्त ऋण वृद्धि की अवधियों में पूंजी संरक्षण बफर के आकार को बढ़ाने के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिचक्रिय बफर का उद्देश्य अत्यधिक समग्र ऋण वृद्धि के कारण जोखिम से बैंकिंग क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि अत्याधिक ऋण वृद्धि के बाद, जब वित्तीय प्रणाली पर दबाव पड़ता है तो अर्थक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाए बिना अर्धव्यवस्था में ऋण का प्रवाह बना रहे। प्रतिचक्रिय बफर आरडब्ल्यूए के 0 से 2.5 प्रतिशत की रेंज में तैयार किए जाएंगे। बासल समिति द्वारा अत्याधिक ऋण वृद्धि को मापने के लिए पीडीपी में निजी ऋण के अनुपात से विचलन को संकेतक के रूप में वरीयता दी जाती है, लेकिन प्रतिचक्रिय बफर को अपनाने या जोड़ने के संबंध में देशों को आस्ति मूल्यों, निधीयन अंतरों तथा सीडी अंतरों, ऋण स्थिति सर्वेक्षणों, वास्तविक जीडीपी वृद्धि, आदि जैसी अन्य बातों को भी ध्यान में रखना होगा। बफर को लगाते समय बैंकों को 12 महीने का लीड समय दिया जाएगा। बफर को रिलीज करने की अनुमति धीरे-धीरे उन स्थितियों में दी जा सकती है जहां ऋण वृद्धि कम हो जाए तथा प्रणाली में जोखिम कम हो जाए।

संदर्भ : बासल III: ए ग्लोबल रैगुलेटरी फ्रेमवर्क फार मोर रैसिलिरेंट बैंक्स एण्ड बैंकिंग सिस्टम्स, दिसंबर 2010.

: बीसीबीएस गाइडेंस नोट फार नेशनल अथारिटीज आपरेटिंग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, दिसंबर 2010.

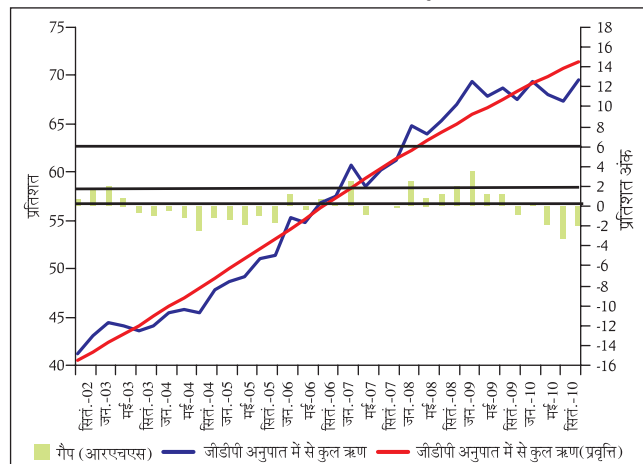
4.8 भारतीय संदर्भ में संकेतक का विश्लेषण (वार्षिक तथा गैर-वार्षिक आधार पर जीडीपी आंकड़े) यह दिखलाता है कि बफर लगाने तथा हटाने के संबंध में विश्वसनीय तथा सामयिक संकेत एकरूपता नहीं दिखलाते (चार्ट 4.3 तथा 4.4)। पहले मामले में, प्रवृत्ति से विचलन इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि ऐसे निर्णयों को दिशा दें जबकि दूसरे मामले में, अंतर में उतार-चढ़ाव कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है।

बफर तैयार करने के लिए मात्रात्मक तथा गुणवत्तात्मक संकेतक आवश्यक

4.9 भारतीय संदर्भ में, बासल समिति द्वारा सुझाव गए कुछ आय संकेतकों की जांच से पता चलता है कि प्रतिचक्रिय बफर तैयार करने के लिए कोई एक संकेतक विश्वसनीय नहीं है (चार्ट 4.5 तथा 4.8)। इसलिए, भारतीय संदर्भ में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों संकेतकों पर निर्भर रहना होगा तथा इसके लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना होगा इसके अतिरिक्त, भारत में प्रतिचक्रिय नीतियों के संबंध में क्षेत्रीय दृष्टिकोण खरे उतरे हैं। भारत में को सीमित करने के लिए प्रयुक्त साधन मानक आस्तियों के लिए प्रावधान करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विभेदक जोखिम होते हैं।

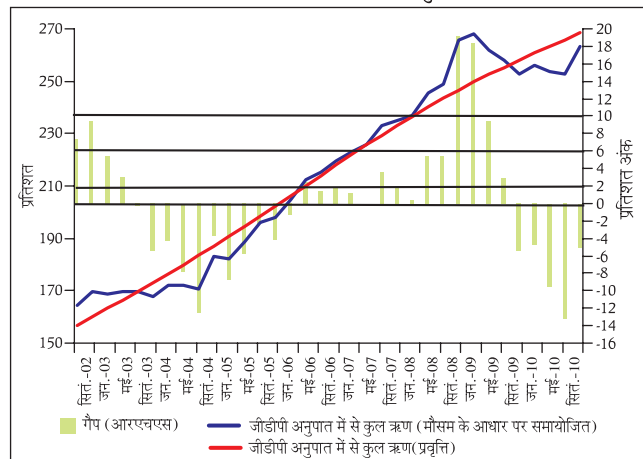
4.10 भारतीय रिजर्व बैंक में एक आंतरिक कार्यदल इस समय प्रतिचक्रिय पूंजी व्यवस्था के लिए फ्रेमवर्क की कार्यविधियों की जांच कर रहा है।

चार्ट 4.3: जीडीपी² में ऋण का अनुपात



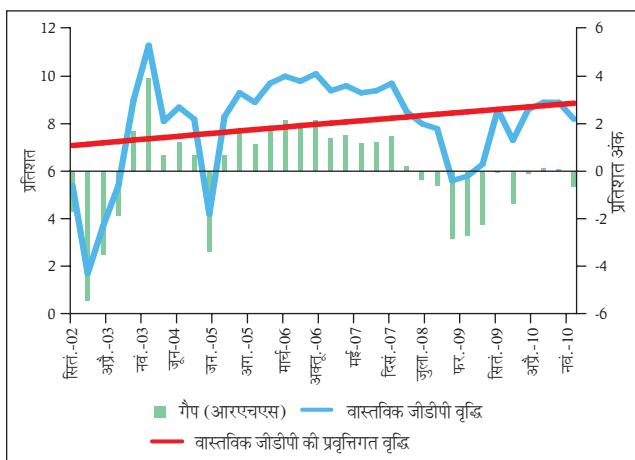
स्रोत: सीएसओ पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक स्टाफ की गणना

चार्ट 4.4: जीडीपी³ में ऋण का अनुपात

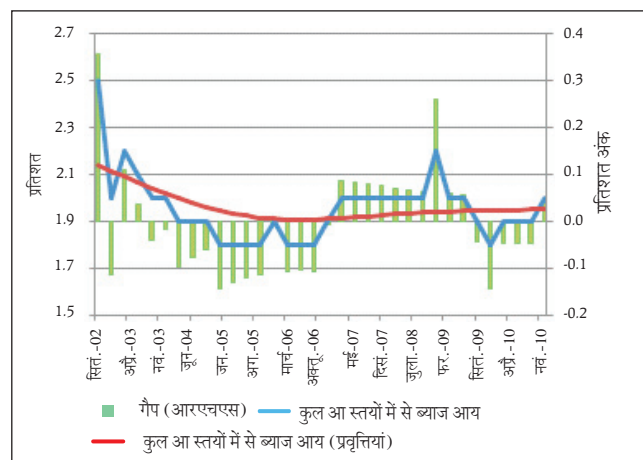


स्रोत: सीएसओ, पर्यवेक्षी विवरणियां तथा रिजर्व बैंक स्टाफ की गणना

चार्ट 4.5: वास्तविक जीडीपी वृद्धि



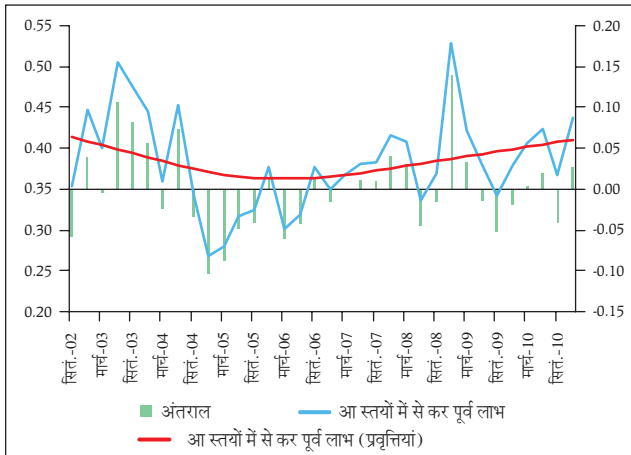
चार्ट 4.6: कुल आस्तियों में से ब्याज आय



² ऋण में बैंक ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार, कंपनी बांड, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-डी और शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। सकल देशी उत्पाद को वर्तमान बाजार की कीमतों पर लिया गया है, जो चार तिमाहियों की बदलती संख्या के आधार पर वार्षिक बना दी गई है। ऋण और सकल देशी उत्पाद की प्रवृत्ति का घटक हॉट्टिक-प्रेसकोट फिल्टर का उपयोग करते हुए निकाला गया है।

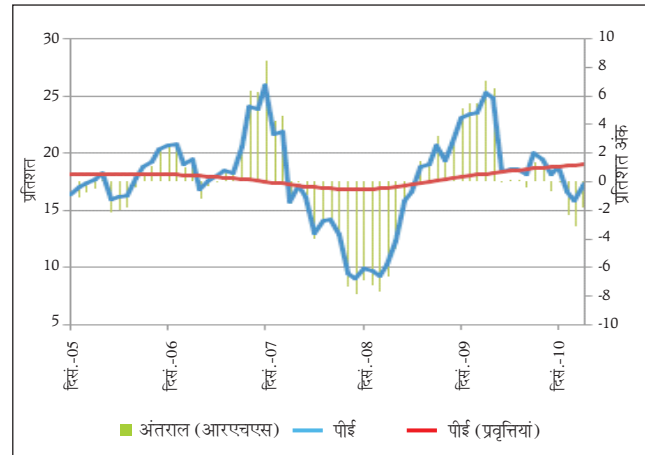
³ ऋण में बैंक ऋण, बाह्य वाणिज्यिक उधार, कंपनी बांड, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां-डी और शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। सकल देशी उत्पाद को वर्तमान बाजार की कीमतों पर लिया गया है। ऋण और सकल देशी उत्पाद की प्रवृत्ति का घटक हॉट्टिक-प्रेसकोट फिल्टर का उपयोग करते हुए निकाला गया है।

चार्ट 4.7: आ स्तयों में से कर पूर्व लाभ



स्रोत: सीएसओ, ब्यूमबर्ग, पर्यवेक्षी विवरणियां और आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 4.8: अर्जन पर कीमत (पीई) अनुपात



बासल II के अंतर्गत उच्चतर दृष्टिकोणों की ओर माइग्रेट करने के मार्ग में कई चुनौतियां हैं

4.11 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के लिए समय-सारणी अधिसूचित की गयी थी। अप्रैल 2010 में बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। परिचालन जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण/वैकल्पिक मानकीकृत दृष्टिकोण पर दिशा-निर्देश मार्च 2010 में जारी किए गए, जबकि परिचालन जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एडवांस्ड मेजरमेंट एपरोच) अप्रैल 2011 में जारी किए गए। ऋण जोखिम के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण संबंधी दिशा-निर्देश निरूपित किए जा रहे हैं। उन्नत दृष्टिकोणों की ओर बैंकों का माइग्रेट होना इसके लिए उनकी तैयारी के आंतरिक मूल्यांकन और रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन पर निर्भर होगा। भारत के बैंकों के पास एक या अधिक जोखिम श्रेणियों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाने का विकल्प होगा और एक साथ सभी जोखिम श्रेणियों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों को अपनाना जरूरी नहीं होगा।

4.12 बासल II मानदंडों के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों की ओर अंतरण से बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार पूँजी अपेक्षा के साथ, स्तंभ II जोखिमों के उन्नत परिमाणीकरण के साथ और वार्धित निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के साथ कनिष्ठ सहबद्धता संभव होगी। इसके बावजूद, अंतरण की प्रक्रिया के साथ अंतर्निहित चुनौतियां भी आती हैं। सबसे

प्रमुख अवरोध है -कुशल कार्मिकों के उन्नत परिमाणीकरण के साथ और खरे आंकड़ों, विशेष रूप से ऋण और परिचालन जोखिमों के मामले में। ऋण जोखिम के उन्नत दृष्टिकोण में चूक पर एक्सपोजर (ईएडी) और हानि अनुमानों को मापने के लिए आंतरिक रेटिंग प्रणाली गिरावट के प्रति ईएडी और हानि अनुमानों के बारे में जोखिम मॉडलों का सत्यापन अनिवार्य हैं। इन प्रणालियों के लिए लंबे समय का क्रमिक डाटा, ऋण चक्रों की समझ और समष्टि एवं व्यष्टि स्तर के जोखिम कारकों की संख्यात्मक मॉडलिंग की जरूरत होती है। दूसरी तरफ, परिचालन जोखिम मॉडलिंग अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र है और इसकी कार्य-प्रणालियां अभी तक विकसित हो रही हैं।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम पूँजी: क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर निर्भरता जारी रहेगी

4.13 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कहा गया कि बैंकों द्वारा बासल II के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण गिरावट के प्रति ईएडी और हानि अनुमानों के बारे में सोच विचार तथा प्रयोग करते हुए उनकी पूँजी संबंधी अपेक्षाओं को जानने के लिए बाहरी रेटिंग पर बैंकों की निर्भरता कुछ समय तक भारत सहित कई देशों में जारी रहने की संभावना है। बैंकों के रेटिंगयुक्त पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम पूँजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन के लिए अनुभवजन्य अध्ययन किया गया था।⁴ जोखिम भारिताओं को दबावग्रस्त संक्रमणों (दबाव परिदृश्यों में डाउनग्रेड में 50 प्रतिशत (परिदृश्य I) और 100 प्रतिशत (परिदृश्य II) की वृद्धि परिकल्पित सहित एक रेटिंग

⁴ यह अध्ययन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किए गए उनके पोर्टफोलियो के रेटिंगवार वितरण पर आधारित है। अध्ययन में पोर्टफोलियो के रेटिंग वितरण के आधार पर जोखिम भारिता को माना गया है जो तब निकलेगा जब रेटिंग एक वर्ष के औसत परिवर्तन मेट्रिक्स (क्रिसिल लि. के परिवर्तन मेट्रिक्स का प्रयोग किया है) के आधार पर माइग्रेट हो। उदाहरण के लिए, यदि एएए रेटिंग वाले 3% कार्पोरेटों के एए रेटिंग में माइग्रेट होने की संभावना है तो बैंकों की एएए रेटिंग वाले 3% पोर्टफोलियो की जोखिम भारिता 20% (एएए रेटिंग वाले खातों पर लागू) की बजाय 30% (एए रेटिंग वाले खातों पर लागू) हो जाएगी।

परिवर्तन मैट्रिक्स के आधार पर निर्दिष्ट किया गया। विश्लेषण ने उजागर किया कि किया कि जब अग्रदर्शी (फारवर्ड लुकिंग) रेटिंगों (दबावग्रस्त रेटिंगों सहित) के आधार पर गणना की गई तो जोखिम भारत आस्तियां लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ गईं (चार्ट 4.9)।

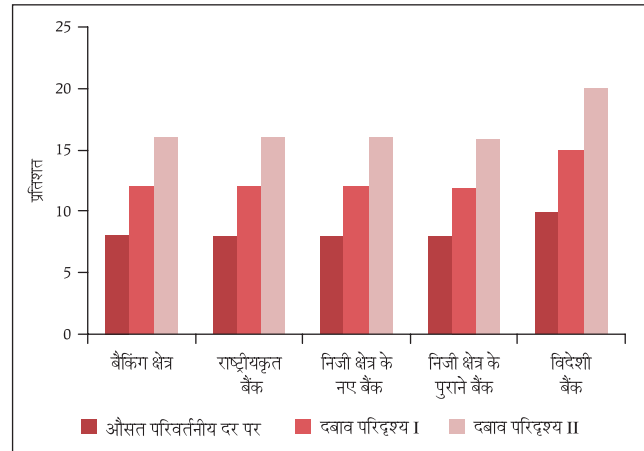
वित्तीय संगुटों के लिए पर्यवेक्षी ढांचा सशक्त किया जा रहा है - समाधान और अंतर-संबद्धता से जुड़े मामले सुसंगत बने रहेंगे

4.14 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों (एसआईएफआई) के लिए नीतियों में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से की जा रही पहलों को दर्शाया गया है जिसका उद्देश्य विफलता की संभाव्यता और उसके प्रभाव को कम करना, समाधान क्षमता में सुधार और प्रमुख वित्तीय आधारभूत संरचनाओं तथा बाजारों का सशक्तीकरण करना है। उन क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए, जिनमें इन बड़ी वित्तीय कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार अपेक्षित है, इसमें, भारत में बड़े वित्तीय संगुटों के पर्यवेक्षण की विद्यमान व्यवस्थाओं को भी दर्शाया गया है। वित्तीय संगुटों के व्यवस्थित समाधान में कठिनाइयों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के साथ अंतर-संबद्धता से संबंधित मामलों में रहेंगी। यद्यपि आगे चलकर वित्तीय संगुटों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड अपेक्षित हो सकते हैं, तथापि इन संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्थाओं में सुधार के लिए प्रयास पहले से ही किए जा रहे हैं। प्रमुख बैंकिंग समूहों के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाएं सशक्त की जा रही हैं: समूह जोखिम प्रोफाइल के अभिग्रहण में सुधार के लिए एक संशोधित परोक्ष रिपोर्टिंग फॉर्मेट की शुरुआत की गई है; बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन-पत्र से इतर स्थिति को शामिल करने के लिए वित्तीय संगुटों की पहचान के लिए मानदंड को संशोधित किया गया है; और कार्पोरेट अधिशासन के ढांचे एवं अंतः-समूह लेनेदेन और एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन/की निगरानी पर दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है।

वित्तीय नियंत्रक कंपनी मॉडल - भारत में अधिमान्य मॉडल

4.15 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) ने सुझाया कि बैंकिंग क्षेत्र में जोखिमों से बचाव के लिए देश में फिलहाल प्रचलित बैंक सब्सिडियरी मॉडल के मुकाबले वित्तीय कंपनियों के लिए नियंत्रक कंपनी संरचना बेहतर है। भारत में वित्तीय नियंत्रक कंपनी संरचना के आरंभ के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्य-दल⁵ ने इसी कारण भारत में वित्तीय क्षेत्र के लिए अधिमान्य मॉडल के रूप में वित्तीय नियंत्रक कंपनी मॉडल का अनुसरण करने की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई कि वित्तीय नियंत्रक कंपनियों के विनियमन

चार्ट 4.9: परिवर्तनीय और दबावग्रस्त रेटिंग आधारित जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि



स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां और आरबीआई स्टाफ गणना

⁵ http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=24444

के लिए पृथक कानून बनाया जाए और ऐसी कंपनियों के लिए विनियामक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाए। (बॉक्स 4.2)

सीमा पार के पर्यवेक्षी सहयोग को बढ़ाने के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ समझौता ज्ञापन

4.16 अंतरराष्ट्रीय पहल भारतीय बैंकों के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय परिचालनों और भारत में विदेशी बैंकों की बढ़ रही उपस्थिति को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान से प्राप्त लाभ के महत्व को रेखांकित करनेवाली अंतरराष्ट्रीय पहल का महत्व बढ़ता जा रहा है। हाल तक, विभिन्न विदेशी विनियामकों/पर्यवेक्षकों के साथ "जानने की जरूरत" के द्विपक्षीय आधार पर जानकारी के अनौपचारिक आदान-प्रदान और पर्यवेक्षी सहयोग की व्यवस्था थी। इसके बावजूद, चूंकि इस व्यवस्था को बढ़ाने और सुदृढ़ करने की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए गवर्नर के परामर्श से भारतीय रिजर्व बैंक ने उपलब्ध विधिक ढांचे के अंतर्गत पर्यवेक्षी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विदेशी विनियामकों के साथ समझौता ज्ञापन करने का निर्णय लिया।

ऐसे पहले समझौता ज्ञापन पर दिसम्बर 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक और चाइना बैंकिंग रेगुलेटरी कमीशन (सीबीआरसी) के बीच हस्ताक्षर हुआ और कुछ अन्य समझौता ज्ञापन प्रक्रियाधीन है।

विनियामक संरचना

एफएसडीसी और इसकी उप-समितियां - वित्तीय स्थिरता के लिए समन्वित पर्यवेक्षण

4.17 पूर्ववर्ती वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में वित्तीय स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंकों की मूलभूत भूमिका की दलीलें पेश की गई हैं, जबकि यह प्रस्ताव भी दिया है कि यह एकमात्र जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। भारतीय संदर्भ में, यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक निःसंदेह भारत में सर्वांगी विनियामक है तथापि वित्तीय क्षेत्र के दूसरे विनियामकों की जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं। विनियामकों से परे, वैश्विक संकट ने सरकार द्वारा निर्भाई जाने वाली समन्वयक भूमिका, विशेष तौर पर दबाव के समय में, महत्व को प्रदर्शित किया है। संकट के पश्चात विनियामकों और सरकार के बीच समन्वय के लिए संस्थागत व्यवस्था की स्थापना पर संकेद्रण की स्वरम परिणति केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एसएसडीसी)

बॉक्स 4.2: बैंक सहायक संस्था (सब्सिडियरी) मॉडल और वित्तीय नियंत्रक कंपनी मॉडल

पिछले कुछ वर्षों में, बैंकों ने म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस, बीमा, एनबीएफसी आदि जैसे विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में अनुषंगी व्यवसायों की स्थापना की है। इसके परिणामस्वरूप देश में कुछ बड़ी और जटिल वित्तीय संस्थाओं का विकास हुआ, जिन्हें आम तौर पर वित्तीय समूह (एफसी) के रूप में जाना जाता है। भारत में वित्तीय संगुटों के उद्भव ने ऐसी संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना के बारे में सवाल को सामने लाया है, जैसे, इन संस्थाओं के लिए अधिमन्यु कापोरेट मॉडल क्या होना चाहिए। यह विषय दो अलग किंतु अंतर-संबंधित परिप्रेक्ष्यों से प्रासंगिक हो जाता है - पहला, विभिन्न संस्थाओं की संवृद्धि और पूँजी अपेक्षाओं का समाधान करने वाले समूहों के भीतर कुशल कापोरेट प्रबंधन; और दूसरा, विभिन्न मॉडलों के साथ विशेष रूप से जोखिम संक्रमण से संबंधित चिंताओं के बारे में विनियामक सहजता का स्तर। वर्तमान में भारत के वित्तीय समूह (एफसी) आम तौर पर बैंक सहायक संस्था मॉडल के अंतर्गत संगठित हैं, जिसमें संगुट की सभी सहायक संस्थाओं का मूल बैंक होता है। इसके विपरीत, नियंत्रक कंपनी मॉडल (एचसीएम) ऐसा मॉडल है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकिंग, बीमा, निवेश बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियां एक ही कापोरेट ढांचे के अधीन संचालित की जाती हैं। भारत में वित्तीय नियंत्रक कंपनी संरचना के आरंभ के लिए गठित कार्य-दल को वैश्विक वित्तीय संकट से सबक लेते हुए भारतीय संदर्भ में वित्तीय नियंत्रक कंपनी संरचना की शुरुआत की आवश्यकता और व्यवहार्यता की जांच करने के लिए किया गया था। कार्य-दल ने पाया कि यद्यपि नियंत्रक कंपनी मॉडल (एचसीएम) निर्णायक रूप से बैंक सहायक संस्था मॉडल (बीएसएम) से बेहतर नहीं है तथापि इसके कुछ विशेष फायदे हैं, जैसे,

क. नियंत्रक कंपनी मॉडल (एचसीएम) पूँजी अवरोध को दूर करने और अन्य वित्तीय सेवाओं में विस्तार को सुलभ बनाने में बेहतर है। चूंकि एचसीएम के

अंतर्गत होने के कारण, सहायक संस्थाएं बैंक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित नहीं होंगी, इसलिए सहायक संस्थाओं में पूँजी डालने की जिम्मेदारी नियंत्रक कंपनी पर होगी;

ख. यह मॉडल सहायक संस्थाओं की हानियों के प्रत्यक्ष प्रभाव के मामले में भी बेहतर होगा जिसे नियंत्रक कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा, जो बैंक सहायक संस्था मॉडल (बीएसएम) से अलग है जिसमें इसका भार बैंक के समेकित तुलन-पत्र पर बढ़ेगा;

ग. बैंक सहायक संस्था मॉडल (बीएसएम) के प्रतिकूल, नियंत्रक कंपनी मॉडल (एचसीएम) के अंतर्गत बैंक के निदेशक-मंडल पर समूह की सहायक संस्थाओं कंपनियों का प्रबंधन करने के उत्तरदायित्व का भार नहीं होगा। अलग-अलग संरचना में एक-एक संस्था का प्रबंधन भी आसान और अधिक प्रभावी होने की संभावना है;

घ. नियंत्रक कंपनी मॉडल (एचसीएम) सर्वांगी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय समूहों के एक बेहतर विनियामक पर्यवेक्षण को सक्षम बना सकता है। यह संकट के पश्चात एक ऐसे अभिजात प्रणालीगत विनियामककर्ता के बारे में उभरती सहमति के अनुरूप भी होगा, जो सहायक संस्था अन्य बातों के साथ-साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा;

ङ. नियंत्रक कंपनी मॉडल अलग-अलग संस्थाओं की तुलना में नियंत्रक कंपनी के लिए विनियामक दृष्टिकोण में अपेक्षित विभिन्नता प्रदान करेगा और;

च. बैंक सहायक संस्था मॉडल, जिसमें मूल बैंक के परिसमापन से सहायक संस्थाओं का परिसमापन हो सकता है, की तुलना में नियंत्रक कंपनी मॉडल द्वारा विभिन्न संस्थाओं के बेहतर समाधान की अनुमति की संभावना है।

की दिसम्बर 2010 में स्थापना के रूप में हुई है। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) को एक उप-समिति द्वारा सहयोग दिया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर करेंगे। इस व्यवस्था में संकट की संभावना को कम करने हेतु वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के शासन के उद्देश्य तथा केंद्रीय बैंक तथा अन्य विनियामकों को शामिल करते हुए क्रियाशील व्यवस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यद्यपि ऐसी आशा है कि उप-समिति सामान्य परिस्थितियों में वित्तीय स्थिरता हेतु एक अधिक सक्रिय, व्यावहारिक संस्था के रूप में विकसित हों, एफएसडीसी एक व्यापक निगरानी रखेगा और संकट की स्थितियों में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

वैधानिक सुधार

वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग - वर्तमान नीति संरचना के साथ कानूनों में संशोधन

4.18 केंद्रीय बजट 2010 में वित्तीय क्षेत्र के कानूनों के पुनर्लेखन तथा उन्हें त्रुटिहीन बनाने हेतु एक पृथक वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है। तभी से एफएसएलआरसी का गठन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में किया गया है तथा आठ उप-समितियों का गठन किया गया है जो कि बैंकिंग, पेंशन, बीमा, पूंजी बाजारों, कर्ज प्रबंधन कार्यालय, वायदा बाजारों तथा कानूनी प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों की जांच करेंगी। जैसा कि पिछली एफएसआर में तर्क किया गया था, विभिन्न कानूनों की पुनःसमीक्षा करने की तथा इन्हें वर्तमान नीतिगत संरचनाओं के साथ फिर से लिखने की अत्यंत आवश्यकता है।

रिजर्व बैंक की विनियामक शक्तियों को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु बैंकों के लिए वैधानिक ढांचे में प्रस्तावित संशोधन

4.19 बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2011 को मार्च 2011 में संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसका लक्ष्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (अधिप्राप्ति तथा उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 तथा बैंकिंग कंपनी (अधिप्राप्ति तथा उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980 को, अन्य बातों के साथ-साथ, रिजर्व बैंक की विनियामक शक्तियों को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा पूंजी बाजार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की पहुंच बढ़ाने हेतु संशोधन करना है। (बॉक्स 4.3)

गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र

भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र - विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत

4.20 जी20 नेताओं द्वारा विनियामक का सुदृढ़ीकरण तथा बैंकिंग के पर्यवेक्षण की पहचान वित्तीय क्षेत्र विनियमन हेतु एक संवेदनशील विषय के रूप में की गई है। भारतीय संदर्भ में, जैसा कि पिछले एफएसआर में सूचित किया गया है, गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र सामान्य रूप से एक बैंकिंग क्षेत्र नहीं है, जैसा कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मामले में है, क्योंकि यह क्षेत्र मूल रूप से रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए तथा एनएचबी द्वारा नियंत्रित है। मुद्रा बाजार लिखतों जैसे वाणिज्य पत्र तथा अल्पकालिक अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) को रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि सेबी म्यूचुअल फंडों तथा लंबी अवधि के एनसीडी का विनियमन करता है।

संस्थाओं की करीबी अंतर-संबद्धता जारी रहने के बावजूद विनियमन में अंतराल बना हुआ है

4.21 पिछले एफएसआर में इस तथ्य को उजागर किया गया कि यद्यपि गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र विवेकपूर्ण विनियमनों के अधीन है, बैंकों की तुलना में विनियमन में असम्मतता है, क्योंकि बैंकों पर अधिक कठोर विनियमन लागू किए जा रहे हैं। यह भी उजागर किया गया कि एनबीएफसी हेतु बहुल विनियामकों के देश में उपस्थिति तथा विनियमन के प्रति एक संस्था आधारित दृष्टिकोण से विनियामक अंतराल की संभावना वैध होती है। कई संस्थाएं, जो कि बाजारों तथा बैंकों दोनों से ऋण ले रही हैं, उनके पास अधिक उधार लेने की क्षमता है, तथा अत्यधिक अंतर-संबद्ध होने के कारण वे प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती हैं। बैंक तथा म्यूचुअल फंड दोनों ही एनबीएफसी के कारपोरेट पेपर में भी निवेश करते हैं और इस प्रकार इन संस्थाओं को वित्तीय एकीकरण में वृद्धि होती है। बैंक एनबीएफसी एक्सपोजरों पर कुछ प्रतिबंध ले सकते हैं तथा रिजर्व बैंक ने हाल ही में कर्ज उन्मुख म्यूचुअल फंडों के लिए बैंकों के एक्सपोजरों पर विवेकपूर्ण अधिकतम सीमा की घोषणा की है। एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु कई उपायों की भी घोषणा की गई है, जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट के अध्याय III में की गई है। फिर भी, ये संस्थाएं एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।

4.22 इसी प्रकार की गतिविधियां करने वाली विभिन्न एनबीएफसी की विनियामक अपेक्षाओं में भी विविधताएं हैं तथा कतिपय संस्थाओं के विनियमन में अंतराल से विनियामक अंतरपणन की संभावना उत्पन्न होती है। पिछली एफएसआर में ऐसे कुछ उदाहरणों को प्रकट किया गया है। इसके अतिरिक्त, मार्जिन ट्रेडिंग हेतु ब्रोकरों

⁶ वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किया गया ऋण उन्मुख पारस्परिक निधियों की चलनिधि योजनाओं में बैंकों के निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को उनके निवल मूल्य के 10 प्रतिशत विवेकपूर्ण कैप के अधीन होंगे। (<http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Mode=o&Id=6376>)

बॉक्स 4.3 : बैंकिंग कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं

(क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं :

- (i) प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के प्रावधान लागू किए जाने से बैंकिंग कंपनियों के विलयों तथा अभिग्रहणों को मुक्त करना;
- (ii) अनुमोदित प्रतिभूतियों को निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिकार देना;
- (iii) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियामक दिशानिर्देशों के अधीन अधिमान शेरों को जारी करने हेतु बैंकिंग कंपनियों को सक्षम बनाना;
- (iv) बैंकिंग कंपनी के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत तक सीमित मताधिकारों पर लगे वर्तमान प्रतिबंधों को हटाना;
- (v) बैंकिंग कंपनी में 5 प्रतिशत या अधिक शेयरों की प्राप्ति तथा मताधिकारों हेतु रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की व्यवस्था करना;
- (vi) शेयरों के प्रदत्त मूल्य के बजाय उनके निर्गम मूल्य के साथ शेयरों की बिक्री पर कमीशन इत्यादि पर लगे प्रतिबंध को जारी करने हेतु पंक्तिबद्ध करना;
- (vii) चुनिंदा बैंकों हेतु नकद आरक्षित अनुपात को निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान करना;
- (viii) निष्क्रिय जमा खातों (जिन खातों पर दावा नहीं किया गया/जो दस वर्ष या अधिक अवधि से संचालित नहीं किए) के अभिग्रहण हेतु 'जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि' की स्थापना करना;

- (ix) बैंकिंग कंपनियों के सहभागी उद्यमों से सूचना तथा विवरणियों की मांग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका निरीक्षण करने हेतु रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान करना;
- (x) केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श करके कतिपय मामलों में बैंकिंग कंपनी के निदेशक बोर्ड को बदलने हेतु रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान करना;
- (xi) बैंककारी विनियमन अधिनियम के कुछ उल्लंघनों हेतु दंडों तथा जुमाने में पर्याप्त रूप से वृद्धि करना;
- (xii) सहकारी बैंकों के अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु जनहित में सहकारी बैंकों की अतिरिक्त लेखा-परीक्षा के आदेश देने हेतु रिजर्व बैंक को अधिकार प्रदान करना।

(ख) बैंकिंग कंपनी (प्राप्ति तथा उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 में प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं:

- (i) अधिकतम तीन हजार करोड़ रु. की उच्चतम सीमा द्वारा सीमित किए बिना केंद्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक से अनुमोदन के साथ प्राधिकृत पूंजी को बढ़ाने तथा घटाने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को सक्षम बनाना;
- (ii) बैंकिंग व्यवसाय के विस्तार हेतु अपेक्षित पूंजी को बढ़ाने हेतु पूंजी बाजार का मूल्यांकन करने हेतु दो अतिरिक्त लिखतों (बोनस शेयर तथा अधिकार निर्गमों) को जारी करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुमति देना;
- (iii) केंद्रीय सरकार से इतर शेयरधारकों हेतु मताधिकारों पर वर्तमान सीमा को 1% से बढ़ाकर 10% तक बढ़ाना।

पर लागू विनियामक अपेक्षाओं तथा एनबीएफसी पर लागू ऐसी अपेक्षाओं में काफी अंतर है, विशेष रूप से न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों, उधार राशियों पर प्रतिबंधों प्रतिबंधों, आईपीओ हेतु मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा की उपलब्धता तथा अन्य जोखिम प्रबंधन निर्देशों के संबंध में लागू अपेक्षाओं के मामले में पूंजी के निजी पूलों जैसे कि हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड इत्यादि सहित वैकल्पिक निवेश निधियों को विनियामक परिधि के भीतर लागू करने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों में की जा सकने वाली गतिविधियां चलाने हेतु बैंकों द्वारा स्थापित एनबीएफसी से आस्तियों तथा देयताओं दोनों ही दिशा पर विनियामक अंतरपणन का स्पष्ट मामला सामने आता है।

4.23 एनबीएफसी पर गठित एक कार्य दल, अन्य बातों के साथ-साथ, विनियामक अंतरालों से संबंधित मुद्दों की जांच कर रहा है तथा प्रकटीकरण अपेक्षाओं, उन्नत पर्यवेक्षीय कार्य प्रणालियों इत्यादि को बढ़ाते हुए प्रणाली में विद्यमान अंतरपणन अवसरों की पहचान कर रहा है।

सरकार द्वारा प्रायोजित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रणालीगत महत्व देखते हुए उन्हें विवेकसम्मत विनियमन के अधीन करना आवश्यक है

4.24 वर्तमान में सरकार के स्वामित्व की 37 एनबीएफसी (पांच एनबीएफसी केंद्र सरकार के तथा 32 विभिन्न राज्य सरकारों के स्वामित्व में) हैं। इनमें से 9 कंपनियां 31 मार्च 2010 तक लगभग रु.2,000 करोड़ की जमा राशि के साथ जमाराशि लेने वाली एनबीएफसी है (जबकि 37 कंपनियों का कुल अग्रिम लगभग रु.2.9 लाख करोड़ है)। इसके अतिरिक्त, इन कंपनियों की आस्तियां मूलतः सार्वजनिक बाजारों के द्वारा किए गए निधीकरण के साथ कई वर्षों से लगातार बढ़ रही हैं।

4.25 इन कंपनियों को अभी तक एनबीएफसी पर लागू विवेकसम्मत विनियामक ढांचे से बाहर रखा गया है क्योंकि ये सरकार के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। और यह माना गया है कि ये जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के संबंध में कम पर्यवेक्षणीय समस्या

उत्पन्न करती हैं। इस दौरान, सरकारी कंपनियों की प्रणालीगत महत्वपूर्णता उनके तुलन-पत्रों के आकार के बढ़ने तथा उनके वित्तीय प्रणाली के साथ बढ़ते संबंध के साथ बढ़ गई है। इसके साथ-साथ एनबीएफसी हेतु निर्धारित विनियामक ढांचे में इस क्षेत्र द्वारा रखे गए प्रणालीगत जोखिमों तथा विनियामक अंतरपणन पर भी स्पष्ट फोकस प्राप्त किया है। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया है कि सरकार के साथ विमर्श करके इन एनबीएफसी को दी गई छूटों पर पुनर्विचार किया जाए।

धन प्रबंधन सेवाओं हेतु विनियामक ढांचे के लिए जांच की आवश्यकता

4.26 हाल ही में देश में एक बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई धन प्रबंधन सेवाओं में एक उच्चस्तरीय धोखाधड़ी के खुलासे से ऐसी गतिविधियों के विनियमन तथा भारतीय वित्तीय क्षेत्र में हितों के टकराव के संबंध में कई मुद्दे सामने प्रकट हुए हैं। भारतीय संदर्भ में, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) से संबंधित गतिविधियां सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधकों) विनियम व नियम, 1993 द्वारा नियंत्रित हैं। बैंकों में से, सरकारी क्षेत्र के एक बड़े बैंक को कुछ पेंशन/सेवानिवृत्ति निधियों हेतु पीएमएस के प्रस्ताव की पेशकश करने की अनुमति दी गई है। अन्य बैंकों को रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ गैर-विवेकीय निवेश परामर्श देने की ही अनुमति दी गई है। तथापि इस दौरान परामर्श देने तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के बीच विभेद अधिकाधिक अस्पष्ट होता जा रहा है, यद्यपि वर्तमान समय पर बकाया संरचित उत्पादों की मात्रा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि उक्त धोखाधड़ी से स्पष्ट है।

4.27 अतः, निवेश परामर्शदाताओं हेतु विनियमों के निरूपण को शामिल करते हुए धन प्रबंधन सेवाओं के लिए तथा विभिन्न विनियामकों द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में समन्वय लाने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के पूरे सेट पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस उद्देश्य हेतु, रिजर्व बैंक बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही धन प्रबंधन गतिविधियों के संबंध में एक सर्वेक्षण कर रहा है। सेबी भी ऐसी गतिविधियों हेतु उचित विनियामक ढांचे को लागू करने पर विचार कर रहा है। विशेष रूप से तृतीय पक्षकार उत्पादों की बिक्री करने वाले बैंकों तथा हितों के टकरावों के मुद्दे की बड़े स्तर पर जांच की आवश्यकता है।

अविनियमित स्थान में संरचित उत्पादों के प्रसरण से प्रणालीगत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं:

4.28 भारतीय संदर्भ में, संरचित उत्पादों को इक्विटी, पण्य इत्यादि से जुड़े प्रतिफलों के साथ कर्ज प्रतिभूतियों के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा मुख्य रूप से जारी किया जा रहा है। ये उत्पाद,

जो कि डिबेंचरों के रूप में जारी किए जाते हैं तथा विशिष्ट रूप से निजी रूप में रखे जाते हैं, वर्तमान में किसी भी विशेष विनियामक पद्धति के अधीन नहीं हैं। इन्हें मुख्य रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा या बैंकों की धन प्रबंधन सेवाओं द्वारा उच्च निवल मालियत के निवेशकों को बेचा जाता है। ये जटिल प्रतिभूतियां हैं जहां निवेशक अंतर्निहित जोखिमों को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। उचित बचाव बनाने हेतु जारीकर्ता की समर्थता में भी जोखिम शामिल है। चूंकि ये अतरल लिखते हैं, अतः लिखतों के मूल्यांकन से समस्याएं जुड़ी हुई हैं। यद्यपि वर्तमान समय पर बकाया संरचित उत्पादों की मात्रा इतना महत्व नहीं रखती, ऐसे उत्पादों की जटिलता व अपारदर्शिता, उनके अतरलता तथा मूल्यांकन संबंधी समस्याओं व व्युत्पन्न लिखतों के बाजारों के द्वारा आस्ति मूल्यों को प्रभावित करने के उनके संभाव्य सामर्थ्य से प्रणालीगत समस्याएं बढ़ सकती हैं, विशेष रूप से उस समय जब ऐसे उत्पादों का प्रसरण एक अविनियमित स्थान में हो।

विवेकसम्मत मानकों के अधीन हुए बिना सहकारी समितियों की जमा जुटानेवाली गतिविधियों को अनुमति देने वाले विनियामक अंतरालों को रोकने की आवश्यकता है

4.29 सहकारी ऋण सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की बैंकिंग गतिविधियों को मूल रूप से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथा लागू) के प्रावधानों के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। यदि सहकारी सोसाइटी की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियां एक लाख रुपये से कम है और/या यदि सोसाइटी द्वारा स्वीकृत जमाराशियां मांग पर चुकौतीयोग्य नहीं हैं, तो अधिनियम के प्रावधान सोसाइटी पर लागू नहीं होंगे। अतः वर्तमान कानूनी वातावरण के अंतर्गत, एक सहकारी समिति कितनी भी संख्या में सदस्यों का नामांकन कर सकती है, सदस्यों से जमाराशियां ले सकती है, ऋण जुटा सकती है, बाहरी स्रोतों से अनुदान प्राप्त कर सकती है। बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसाइटी के मामले में बाहरी स्रोतों से प्राप्त की गई निधियों पर अधिकाधिक सीमा उसकी अभिदत्त शेयर पूंजी तथा संचित आरक्षित निधियों की दस गुना है तथा राज्य अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत की गई सोसाइटियों के मामले में सोसाइटी के उपनियमों में अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त स्थिति एक विनियामक अंतराल को दर्शाती है जो कि किसी भी विवेकसम्मत मानकों के अधीन हुए बिना जनता की जमाराशियों को जुटाने हेतु संस्थाओं को समर्थ बनाती है। विशेषतः निधियों को प्राप्त करने (बाहरी स्रोतों से) से जुड़े मामलों की पूरी श्रृंखला की जांच इन संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिए।

नेटवर्क विश्लेषण

4.30 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) ने मजबूत विश्लेषणात्मक तरीकों के महत्व को रेखांकित किया जो कि प्रणालीगत लिंकेज की पहचान, निगरानी, और समाधान करने में बेहतर मदद करते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में लिंकेज के अधिक अध्ययन हेतु प्रणाली की संबद्धता की स्थिति का आकलन करने और बैंक की असफलताओं के संभावित डॉमिनो प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए एकीकृत संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित एक नेटवर्क मॉडल⁷ विकसित किया गया है।

भारतीय अंतरबैंक बाजार के संरचनागत पहलू

4.31 संपूर्ण विश्लेषण के लिए दिसम्बर 2010⁸ की स्थिति के द्विपक्षीय आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इस ऋण जोखिम का कुल सकल मूल्य लगभग 6.9 लाख करोड़ के बराबर है। शुद्ध द्विपक्षीय ऋण जोखिम के नेटवर्क के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल मिलाकर बैंकिंग समूहों के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र और पुराने निजी क्षेत्र के बैंक प्रणाली में शुद्ध उधारदाता हैं जबकि नए निजी क्षेत्र और विदेशी बैंक शुद्ध उधारकर्ता हैं (चार्ट 4.10 से चार्ट 4.12 तक)।

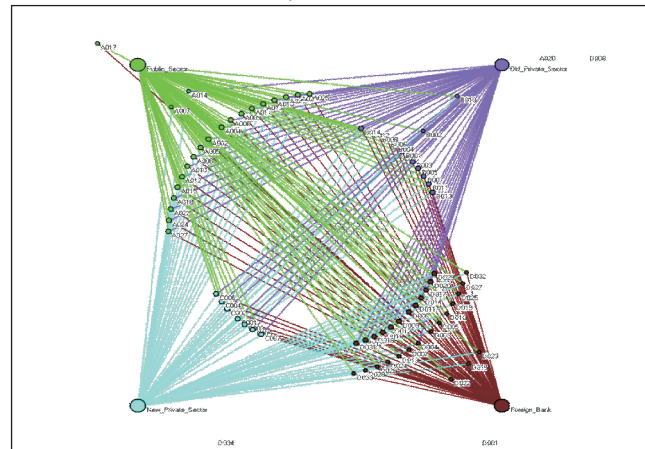
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र - सामूहिक और संबद्ध

4.32 भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी हद तक संबद्ध और सामूहिक है। साथ ही, जैसा कि केंद्रीय परिपत्र संरचना चार्ट 4.10 से स्पष्ट है, अधिकतर बैंकों का ऋण जोखिम सभी बैंकिंग समूहों के बैंकों में है। प्रणाली में कुल 1514 तीक्ष्णता (एजेज) (अर्थात् डिग्री और आउट डिग्री में समग्रतः 1514), 42 प्रतिशत का समूह गुणक (कोएफिशिएन्ट) और 27 प्रतिशत की संबद्धता (बॉक्स 4.4) है।

संक्रमण विश्लेषण - तनाव परीक्षण परिदृश्य

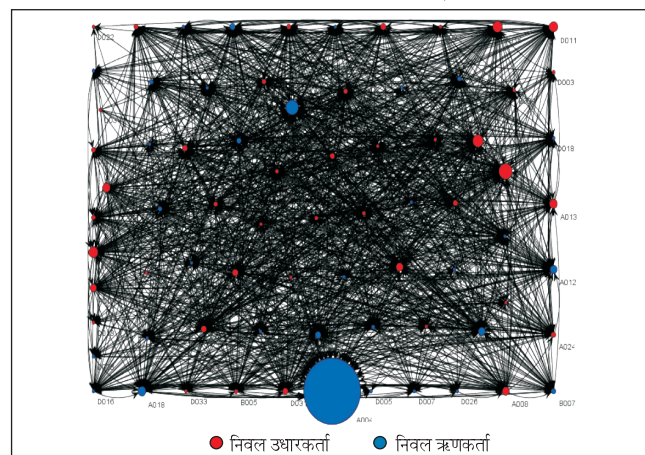
4.33 द्विपक्षीय ऋण जोखिम के उपर्युक्त नेटवर्क मॉडल का उपयोग बैंक की असफलताओं के प्रभाव को आकार देने के लिए किया जा सकता है। संक्रमण विश्लेषण (बॉक्स 4.4) इस बुनियादी सिद्धांत पर कार्य करता है कि असफल बैंक (संक्रमण चार्ट के केंद्र में ट्रिगर बैंक) के सभी शुद्ध उधारदाता संक्रमण के पहले दौर में प्रभावित हो जाएंगे। ट्रिगर बैंक (बैंकों) को असफल करने की विशेष प्रवृत्ति

चार्ट 4.10: चार बैंकिंग समूहों के अग्रणी बैंकों का द्विपक्षीय निरूपण

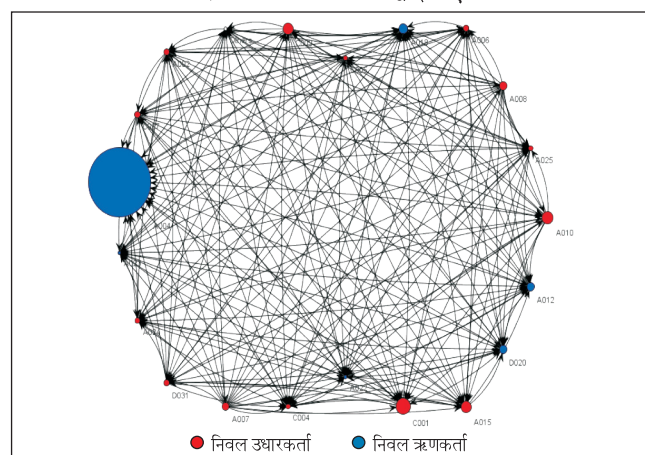


रंग कोड: हरा (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक), बैंगनी (निजी क्षेत्र के पुराने बैंक) समुद्री हरा (निजी क्षेत्र के नए बैंक) और भूरा (विदेशी बैंक)

चार्ट 4.11: सभी बैंकों का निवल द्विपक्षीय एक्सपोजर⁹



चार्ट 4.12: प्रथम बीस बैंकों का निवल द्विपक्षीय एक्सपोजर¹⁰



⁷ विश्लेषण में उपयोग किया गया नेटवर्क मॉडल प्रोफेसर शेरी मार्कोज (एसेक्स विश्वविद्यालय) और डॉ. सिमोन जियांसांते (बाथ विश्वविद्यालय) द्वारा वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है।

⁸ अंतर-बैंक ऋण जोखिम (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित दोनों) के संबंध में द्विपक्षीय आंकड़े 75 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नमूने के लिए।

⁹ नोड (बैंक) का आकार का श्रेणी-निर्धारण डिग्री की संख्या अर्थात् शुद्ध उधार द्वारा किया गया है।

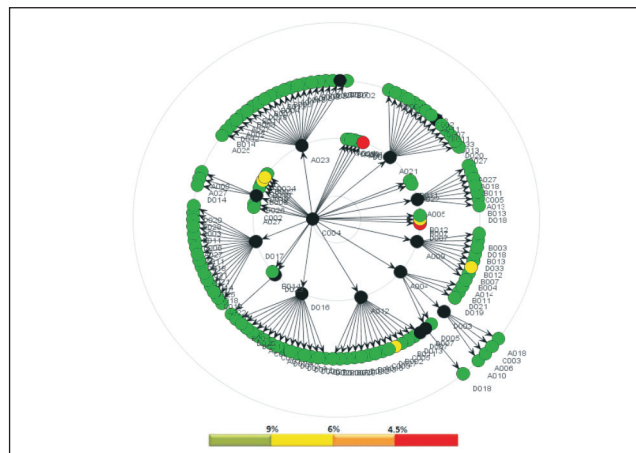
¹⁰ प्रबल आइजन मूल्यों (बॉक्स 4.4) के आधार पर शीर्ष 20 बैंकों का चयन किया गया है।

(इडियोसिंक्रेटिक) की घटना से परेशानी के अंतर्गत आने वाले बैंकों¹¹ के पास संक्रमण के बाद के दौरों में भी अधिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता होगी। संक्रमण अंततः तब समाप्त होता है जब प्रणाली संपूर्ण उत्पन्न नुकसान को अवशोषित कर लेती है। (चार्ट 4.13 और 4.14)।

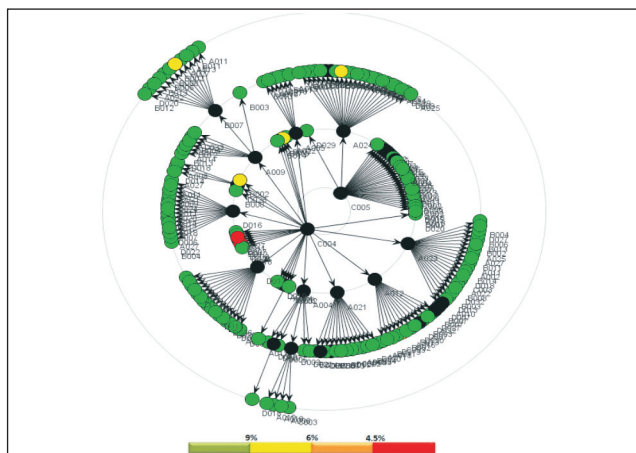
4.34 शीर्ष के 20 सबसे ज्यादा संबद्ध बैंकों की असफलता के परिणामस्वरूप प्रभाव को, एक समय में एक, और 10 जोड़ी बैंकों की असफलता, एक समय में एक जोड़ी, चार्ट 4.15 से 4.16 में प्रस्तुत किया गया है।

4.35 उपर्युक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से देश में बैंकिंग प्रणाली की आपस में गुंथी हुई प्रकृति को दर्शाता है और एक या एक से अधिक बैंकों के विशेष प्रवृत्ति (इडियोसिंक्रेटिक) असफलता की स्थिति में प्रणाली को डॉमिनो प्रभावों के लिए असुरक्षित छोड़ देता है। इस मॉडल में ऐसी असफलताओं का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि बैंक इस प्रणाली में अन्य बैंकों के साथ किस प्रकार संबद्ध है और अन्य बैंकों (उदाहरणार्थ ऋणदाता या उधारकर्ता) से उसके संबंध कैसे हैं। उपर्युक्त विश्लेषण दर्शाता है कि प्रणाली में संबद्ध अधिकतर बैंकों की असफलता बैंकिंग प्रणाली की स्थायी पूंजी को लगभग 14 प्रतिशत कम कर देती है। अंतरबैंक ऋण जोखिम पर विनियामक नियंत्रण के कारण संक्रमण प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है (उदाहरणार्थ, बैंकों में पूंजी की क्रॉस होल्डिंग पर नियंत्रण, मांग मुद्रा बाजार ऋण जोखिम में नियंत्रण और अंतरबैंक दायित्वों पर विवेकसम्मत नियंत्रण)। यदि वित्तीय प्रणाली की अन्य संस्थाओं (अन्य बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, म्यूचुअल फंड, आदि) को विश्लेषण के दायरे में लाया जाता है, तो प्रभाव और भी अधिक बढ़ सकता है। किसी भी स्थिति में, प्रणाली में जोखिम उत्पन्न होने/अधिकता होने की पहचान करने और उससे निपटने के लिए नीति कार्रवाई का मार्गदर्शन करने हेतु वित्तीय प्रणाली की अंतर-संबद्धता की सतत निगरानी करते रहने की आवश्यकता है।

चार्ट 4.13: एक ट्रिगर बैंक की असफलता का प्रभाव¹²



चार्ट 4.14: दो ट्रिगर बैंक की असफलता का प्रभाव



¹¹ विश्लेषण के उद्देश्य से, जिन बैंकों का जोखिम भारित आस्तियों के टियर I पूंजी का अनुपात 6 प्रतिशत से नीचे है उन्हें संकटग्रस्त माना जाता है।

¹² रंग संबंधी कूट :

ट्रिगर बैंक : काला

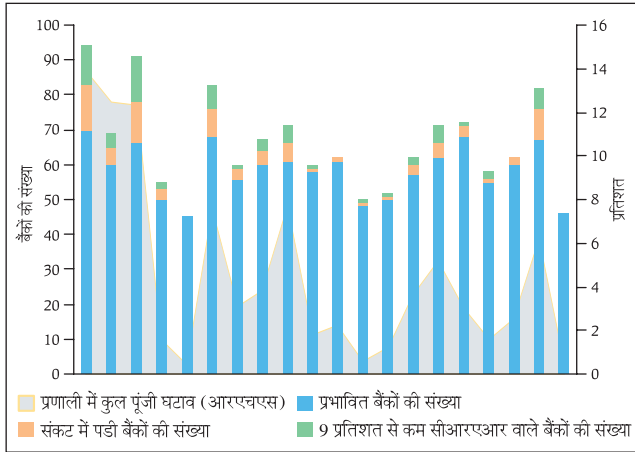
संकटग्रस्त बैंक :

- काला: जिन बैंकों का मूल पूंजी अनुपात 6 प्रतिशत के नीचे चला गया है
- नारंगी: जिन बैंकों का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 6 प्रतिशत के नीचे चला गया है
- लाल: जिन बैंकों का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 4.5 प्रतिशत के नीचे चला गया है

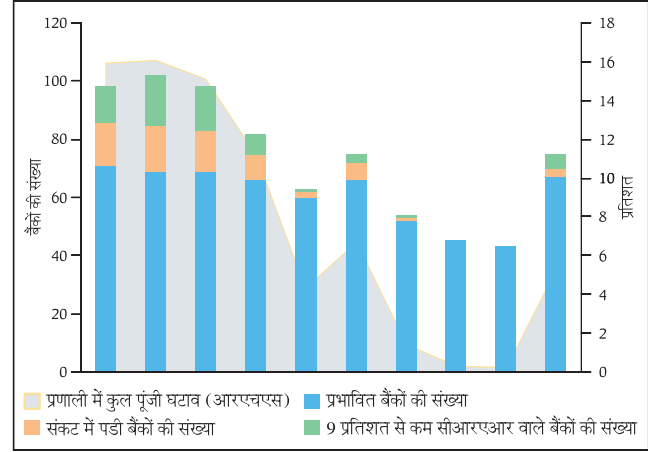
जो बैंक प्रभावित हैं, परंतु संकटग्रस्त नहीं हैं:

- हरा: ट्रिगर/संकटग्रस्त बैंकों की असफलता से प्रभावित बैंक परंतु जिनकी पूंजी पर्याप्तता विनियामक आवश्यकताओं से ऊपर है
- पीला: ट्रिगर/संकटग्रस्त बैंकों की असफलता से प्रभावित बैंक और परंतु जिनकी पूंजी पर्याप्तता 9 प्रतिशत के नीचे चली गयी है परंतु मूल पूंजी 6 प्रतिशत से ऊपर है

चार्ट 4.15: शीर्ष 20 बैंकों की असफलता का प्रभाव
(एक बार में एक ही)



चार्ट 4.16: दस जोड़ी ट्रिगर बैंक की असफलता का प्रभाव
(एक बार में एक जोड़ी ही)



बॉक्स 4.4: भारतीय अंतर-बैंक बाजार का नेटवर्क विश्लेषण - विश्लेषणात्मकता और पद्धति

विश्लेषण के मूल में मैट्रिक्स बीजगणित है, जिसमें उधार देने और उधार लेने के रूप में लिंक या संबंध, जो कि एन बैंकों के बीच है, को एन एक्स एन मैट्रिक्स में देखा जाता है। अनिर्दिष्ट ग्राफों द्वारा तैयार किया गया लिंकेज की प्रणाली में ये संबंध एक जैसे (सिमेट्रिक) मैट्रिक्स बनाते हैं, दो बैंकों के बीच लिंक के रूप में एक समान परिणाम देगा, दो में से जिस किसी बैंक ने भी इसकी पहल की हो। इसके विपरीत, सापेक्ष असमानताओं और लिंक बनाने तथा उसके वजन के अध्ययन में निर्दिष्ट ग्राफ उपयोगी हैं। नेटवर्क विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट ग्राफ उपयोग में लाये गये, जैसा कि हम बैंकों को उनके द्वारा चयनित किसी भी लिंक बनाने की पहल का पूर्ण विवेक होने का लक्ष्य रखते हैं।

नेटवर्क टोपोलॉजी की कुंजी बैंकों के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं जिसको एक समीपता मैट्रिक्स द्वारा दर्शाया जाता है। समीपता मैट्रिक्स इस प्रकार सकल प्रवाह मैट्रिक्स X बन जाता है कि X_{ij} उधारकर्ता i से ऋणदाता j को सकल वित्तीय दायित्वों के प्रवाह को दर्शाता है। एक द्विपक्षीय जाल के समान प्रविष्टियों ($X_{ij} - X_{ji}$) सहित मैट्रिक्स M मैट्रिक्स X से उत्पन्न हुई है। मैट्रिक्स M , जो कि तिरछा मैट्रिक्स X के समान है, बैंक i और j के बीच जाल जैसी स्थिति बनाता है। संक्रमण विश्लेषण के लिए, मैट्रिक्स M नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी बैंकों की शुद्ध देयताओं और प्राप्तियों को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण विशेषता है। बैंक (नोड) की दूसरों से शुद्ध प्राप्तियों को दर्शाने वाले लिंकों या दिशाओं की संख्या डिग्री के रूप में और शुद्ध देयताएं को दर्शाने वाले लिंकों या दिशाओं की संख्या को आउट डिग्री रूप में संदर्भित की जाती है।

संबद्धता संबंधी आंकड़े

प्रणाली में मौजूद अंतर-संबद्धता और गतिविधि के स्तर के निर्धारण हेतु बाद में पूर्वोक्त मैट्रिक्स का आंकड़ों संबंधी विश्लेषण किया जाता है। इनमें से उपयोग में लाये जा रहे कुछ उपकरण निम्नानुसार हैं:

क. संबद्धता (कनेक्टिविटी) : यह एक आंकड़ा है जो कि एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव लिंकों के सापेक्ष नोड्स के बीच लिंकों की सीमा की माप, आउट डिग्री की कुल संख्या का संकेत करते हुए $K = \sum_{i=1}^N k_i$ के बराबर और N नोड्स की कुल संख्या है, नेटवर्क की संबद्धता $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

ख. समूह गुणांक (क्लस्टर कोएफिशिएंट) : नेटवर्क का सामूहिकरण मापता है कि प्रत्येक नोड कैसे अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, बढ़ी हुई संभावना यह होनी चाहिए कि नोड के पड़ोसियों में से दो (वित्तीय नेटवर्क की स्थिति में बैंकों

के समकक्ष) एक दूसरे के भी पड़ोसी हैं। नेटवर्क के लिए उच्च सामूहिक गुणांक प्रणाली में प्रचलित उच्च अंतर-संबद्धता के अनुरूप होता है।

- ग. औसत पथ लंबाई :** इसका उपयोग नेटवर्क में किसी भी दो नोड्स के बीच मौजूद दूरी को मापने के लिए किया जाता है।
- घ. न्यूनतम पथ लंबाई :** एक नोड और नेटवर्क के प्रत्येक अन्य नोड्स के बीच निर्दिष्ट लिंक की औसत संख्या इससे प्राप्त होती है। न्यूनतम पथ वाले नोड्स की पहचान प्रणाली में केंद्र (हब) के रूप में पहचान की जा सकती है।
- ङ. बीच की स्थिति की केंद्रीयता :** यह आंकड़ा बताता है कि एक विशेष नोड में न्यूनतम पथ लंबाई कहां से गुजरती है।
- च. केंद्रीयता का आइजन्वेक्टर उपाय :** आइजन्वेक्टर केंद्रीयता नेटवर्क के एक नोड (बैंक) के महत्व की माप है। यह बताता है कि नोड के पड़ोसी कैसे संबद्ध हैं और एक नोड के आउट डिग्री या प्रत्यक्ष 'पड़ोसियों' की मात्र संख्या से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार यदि दो नोड्स के पास पड़ोसियों की संख्या समान है तो जिसके पास उच्च आइजन्वेक्टर केंद्रीयता होने की संभावना है वही वह नोड है जिसके पड़ोसियों के पास अधिक संख्या में पड़ोसी हैं। केंद्रीयता की यह माप उपर्युक्त सिद्धांत पर आधारित नेटवर्क के सभी नोड्स को सापेक्ष स्कोर देती है। सामान्यतः $N \times N$ मैट्रिक्स के लिए N भिन्न आइजन मूल्य λ होंगे जिसके लिए एक आइजन्वेक्टर समाधान मौजूद है। केंद्रीयता माप के लिए हम प्रबल आइजन मूल्य और संबंधित आइजन्वेक्टर लेते हैं। इस आइजन्वेक्टर का i^{th} घटक तब नेटवर्क के i^{th} बैंक का केंद्रीयता स्कोर देता है।

संक्रमण विश्लेषण

संक्रमण विश्लेषण मूल रूप से एक तनाव परीक्षण है जहां एक या अधिक बैंक की असफलता के डॉमिनो प्रभाव के कारण सकल हानि का पता लगाया जाता है। संक्रमण का अनुकरण करने के लिए हम एक दौर के बाद दूसरा दौर या अनुक्रमिक कलन विधि (एल्गोरिथ्म) अपनाते हैं जो कि फुरफाइन (Furfine) (2003) से प्रसिद्ध है। एक ट्रिगर बैंक i के साथ प्रारंभ जो कि 0 समय पर असफल होता है, हम बैंकों के समूह के रूप में संकेत करते हैं जो कि प्रत्येक दौर या आवृत्ति में D_q के द्वारा संकट में जाता है, $q = 1, 2, \dots$ इस विश्लेषण के लिए यदि बैंक का मूल सीआरएआर 6 प्रतिशत से नीचे जाता है तो उसे संकट में माना जाता है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए विनियामक व्यवस्था

4.36 भारत में रिजर्व बैंक को देश की भुगतान और निपटान प्रणाली की विनियामक निगरानी का कार्य सौंपा गया है। रिजर्व बैंक की इस निगरानी संबंधी भूमिका का कानूनी ढांचा भुगतान और निपटान प्रणाली (भुनिप्र) अधिनियम, 2007 और उसके तहत बनाई गयी भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 के द्वारा प्रदान किया गया है।

कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज - विनियमन की परिधि में अंतराल

4.37 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में भी, विशेष रूप से, विनियामक परिधि के कुछ अंतरालों की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी, यह तथ्य कि कुछ भुगतान प्रणालियां अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत स्थापित समाशोधन निगम भुनिप्र अधिनियम के दायरे से बाहर बने हुए हैं। इस संबंध में इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वह स्पॉट कमोडिटी एक्सचेंजों का कार्य है। ये एक्सचेंज कृषि वस्तुओं, धातुओं और सोना-चांदी सहित विनिर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद और बिक्री की सुविधा के लिए इन वस्तुओं हेतु स्पॉट सुपुर्दगी अनुबंध प्रदान करते हैं। यह बाजार इक्विटी के नकद प्रभाग की तरह कार्य करता है और सुविधाएं जैसे गारंटीकृत बहुपक्षीय नेटिंग के आधार पर व्यापार का समाशोधन और निपटान प्रदान करता है। वर्तमान में, देश में चार ऐसे एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

4.38 स्पॉट एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जा रही समाशोधन और निपटान सेवाओं के संबंध में एक मुद्दा उठता है जो कि इस समय भुनिप्र अधिनियम, 2007 या किसी भी अन्य विनियामक व्यवस्था के तहत विनियमित नहीं है।

भुगतान और निपटान प्रणाली का परिचालनगत निष्पादन परिचालनगत निष्पादन मजबूत बना हुआ है

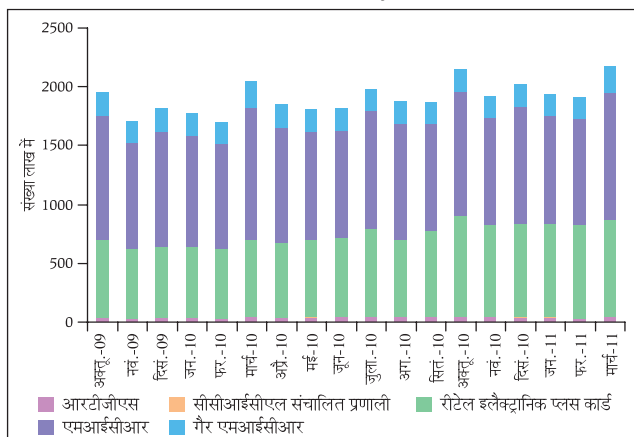
4.39 भारत में भुगतान और निपटान संबंधी बुनियादी सुविधाओं का परिचालनगत निष्पादन मजबूत बना हुआ है एवं भुगतान और निपटान प्रक्रिया (चार्ट 4.17 और 4.18) में कोई बड़ी बाधा नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन विधि की दिशा में अंतरण की प्रक्रिया जारी है

4.40 कागज आधारित भुगतान लिखत का व्यापक उपयोग जारी है, भारतीय भुगतान प्रणाली में जिनकी हिस्सेदारी मात्रा के संदर्भ में

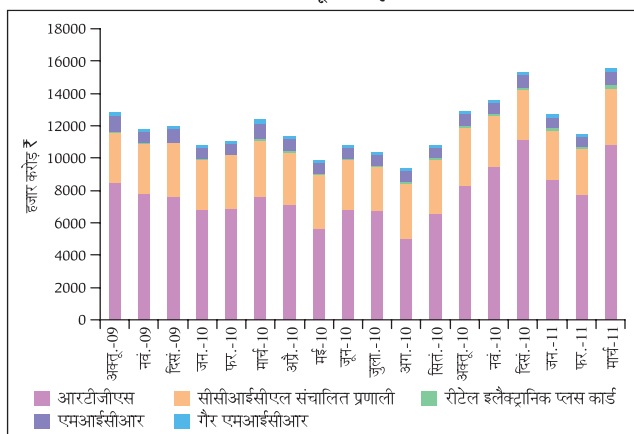
59 प्रतिशत है। यद्यपि, मूल्य के संदर्भ में उनकी हिस्सेदारी मात्रा 10 प्रतिशत थी। हाल ही में की गयी पहलों जैसे एनईएफटी लेनदेनों का प्रति घंटा निपटान के लिए टाइम विंडो का प्रारंभ, लाभार्थी को सकारात्मक पुष्टि की प्रणाली का प्रारंभ, एनईएफटी का विस्तार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेत्राबंध) तक करना और ईसीएस परिचालन के निपटान चक्र को कम करना, का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली की पहुंच का विस्तार करना रहा है तथा अधिक लेनदेनों का अंतरण इलेक्ट्रॉनिक विधि में करने की अपेक्षा की जा सकती है।

चार्ट 4.17: मात्रा में प्रवृत्तियां



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 4.18: मूल्य में प्रवृत्तियां



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

परिचालनगत जोखिम का कड़ाई से प्रबंधन किया गया तथा असुरक्षितताओं पर निगरानी रखी गई

4.41 भुगतान तथा निपटान प्रणाली में परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन रिजर्व बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। रिजर्व बैंक के तीन डेटा केंद्र हैं, दो शहर (मुंबई) में हैं और एक शहर से दूर है - जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि यदि किसी भी क्षेत्र/उपकरण में संकट की स्थिति में निर्माण हो जाती है तब पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त व्यवस्था उपलब्ध रहती है। संकट में से संभल पाने की नियमित कवायत से प्रणाली की चोट से अतिशीघ्र उबर पाने के सामर्थ्य की जांच की जाती है। 31 मार्च 2011 के समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान तीन अवसरों पर शहर से दूर के केंद्र पर भुगतान तथा निपटान प्रणाली का प्रत्यक्ष परिचालन किया गया। इस कवायतों में सदस्य संस्थाओं ने अपने प्राथमिक स्थानों से भाग लिया। इस कवायतों से नेटवर्क की धीमी-प्रतिक्रिया/बीच-बीच में संयोजन न होना जैसे प्रश्न सामने आए जिन्हें आवश्यक कार्रवाई/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिसूचना के रूप में लिया गया।

4.42 यह पाया गया कि कुछ ही क्रियाकलापों में विक्रेता केंद्रीभूत हो गए थे जैसे कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और बैंकों द्वारा आउटसोर्स की जानेवाली एटीएम सेवाओं में प्रयोग किए जा रहे कोर-बैंकिंग सोलूशन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रखरखाव।

बड़े मूल्यवाले लेनदेनों का निपटान

4.43 देश में निपटान तथा भुगतान एवं निपटान में अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण यह रहा है कि बड़े मूल्यवाले सभी लेनदेनों के निपटान को तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली में अथवा आस्थगित निवल भुगतान में अंतरित कर देना। बहुत सी संकट प्रणालियों के लिए गारंटी के आधार पर केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के द्वारा निपटान हो जाता है। जबकि भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआइएल) देश में मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियां और विदेशी मुद्रा बाजार के लिए सीसीपी के रूप में कार्य करता है तो ईक्विटी और वस्तु बाजार के लिए अन्य सीसीपी कार्य करते हैं। इससे पहले के एफएसआर ने सीसीआइएल के कार्य से संबंधित चिंताओं के कई मामलों की रूपरेखा बनाई थी जिसमें बहु उत्पाद सीसीपी के रूप में सीसीआइएल की रूपरेखा, सीबीएलओ भाग में निवल डेबिट उच्चतम सीमा का अभाव, विदेशी मुद्रा निपटान में हरस्टाट जोखिम आदि शामिल थे। विभिन्न खंडों में वर्तमान जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत से

कदम उठाए गए हैं जिसमें विदेशी मुद्रा वायदा खंड के लिए चूक निधि को सक्रिय बनाना और प्रतिभूति खंड में दिन में बाजार दर से मार्जिन शामिल है।

भारत में सीसीपी के लिए चलनिधि जोखिम बना रहा - इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है

4.44 चलनिधि जोखिम यह प्रमुख जोखिमों में से एक है जिसका सामना सीसीपी को करना पड़ता है। "वित्तीय बाजार संकलन के सिद्धांत"¹³ पर हाल ही के रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि सीसीपी को अपनी जोखिम को प्रभावी तरीके से आंकना, इसकी निगरानी और इसका प्रबंधन करना चाहिए। वतुतः बहुत से सुप्रबंधित सीसीपीओ ने चलनिधि जोखिम के प्रबंधन हेतु रक्षा के विभिन्न मार्ग - सदस्य मार्जिन, गारंटी निधि, सदस्य से इतर की वचनबद्धता और इसकी अपनी पूंजी के रूप में विकसित किए हैं। तथापि, सीसीपी के चूक की संभ्याव्य जोखिम बनी रहती है विशेषतः क्योंकि प्रणाली के विस्तृत तनाव के समय रक्षा के मार्ग शायद पर्याप्त न हो। बहरहाल, अन्य बातों के साथ-साथ सीसीपी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले संपार्श्विक की गुणवत्ता; प्रतियोगिता दबाव जिससे सीसीपी को आरंभिक मार्जिन कम करने पर प्रोत्साहित किया जाता है, वे विस्तृत प्रकार के संपार्श्विक स्वीकृत करते हैं अथवा इसे थोड़ा कम करने की अनुमति देते हैं; और अंतर्निहित नमूना जोखिम जो मूल्यन निर्माण करने पर निर्भर नमूनों से उत्पन्न होते हैं तथा जिन पर मार्जिन प्रणाली आधारित है - से असुरक्षितता निर्माण होती है।

4.45 भारतीय प्रणाली में भी इन जोखिमों से कुछ दिखाई देते हैं जबकि भारत में सीसीपी काफी मात्रा में विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन है। सीसीआइएल के मामले में, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष निगरानी के अधीन है, बाजार के महत्वपूर्ण खिलाड़ी वित्तीय संस्थाओं से निधियों और प्रतिभूतियों के लिए प्रतिबद्ध समर्थन चलनिधि पर निपटान हेतु निर्भरता होती है और प्रणालीगत तणाव के दौरान बैंक स्टॉप चलनिधि देना शायद संभव न हो। देश में कार्यरत अन्य सीसीपीओ (उदाहरण ईक्विटी बाजार के सीसीपी) के मामले में असुरक्षितता है जो बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजरों से उत्पन्न होती है जैसे कि बैंक जमा, बैंक गारंटी आदि के रूप में संपार्श्विक को मार्जिन और गारंटी निधियों के बदले में स्वीकृत किया जाता है। बहरहाल, सीसीपी के असफल हो जाने, जो कि असंभव है, के कारण होनेवाली संपार्श्विक हानि इन जोखिमों के मुकाबले बहुत अधिक होती है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।

¹³ "प्रिन्सिपल्स ऑफ फाइनेन्शियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर", मार्च 2011 पर संयुक्त सीपीएसएस-आइओएससीओ परामर्शदात्री रिपोर्ट! (<http://www.bis.org/publcpss94.htm>)

केंद्रीय बैंक चलनिधि सुलभता एक विकल्प है, व्यवस्था में निजी क्षेत्र के जमानत को खोजा जा सकता है

4.46 सीसीपी के चलनिधि जोखिमों से संबंधित चिंताओं के कारण केंद्रीय बैंक चलनिधि की सीसीपी के उपलब्धता की समस्या निर्माण होती है जो पिछले एसएसआर में मंद पड़ी थी। यह मामला सरल नहीं है क्योंकि प्रतिबद्ध केंद्रीय बैंक सहायता की अपेक्षा से, वस्तुतः, पुरातन नैतिक संकट समस्या के कारण वही जोखिम स्थायी बन जाती है। केंद्रीय बैंक चलनिधि का प्रावधान का अलग-अलग मामलों पर अलग-अलग असर हो सकेगा परंतु तो भी केंद्रीय बैंक के लिए यह आवश्यक होगा कि सीसीपी का विनियमन इसके द्वारा किया जाए अथवा कम-से-कम, मामले के मूल्यांकन के लिए इसके जोखिम प्रबंधन के बारे में संबंधित जानकारी उपलब्ध हो और उनके जोखिम प्रबंधन के अनुसार परिवर्तन कार्यान्वित करने हेतु सीसीपी से अनुरोध करने का उसे अधिकार है। भारतीय मामले में और अधिक समस्या यह है कि पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत सभी सीसीपीओ का केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमन नहीं होता है।

4.47 वैश्विक स्तर पर लेनदेन के निपटान के लिए अधिमाम्य तरीके के रूप में सीसीपी के उभरने के साथ "इतने बड़े की वे गिर ना सकेंगे" संस्था के नए सेट का निर्माण करने की जोखिम केवल बड़े जोखिमों से बड़ी होती है और विवाद के लिए सीसीपी के लिए निजी क्षेत्र की जमानत प्रणाली बढ़ाने के प्रयास आवश्यक है - ठीक वैसे जैसे प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों के लिए विचार किया जा रहा है।

काउंटर पर (ओटीसी) बाज़ार

4.48 भारत में ओटीसी बाज़ार कई समस्याओं और चुनौतियों का सामना करता है जैसे टेढ़ी सहभागिता संरचना, बड़ी मात्रा में मानकीकरण, केंद्रीय समाशोधन को प्रारंभ करना आदि जिन पर इससे पहले के एफएसआर में विशेष ध्यान दिया गया था। ये मामले सुसंगत होते हैं क्योंकि, विशेष रूप से कुछ डेरिवेटिव बाजारों में कम मात्रा में बने रहने के कारण इन बाजारों के लिए गारंटीत समाशोधन सौंपना कठिन हो जाता है।

सभी उत्पादों के लिए केंद्रीय निक्षेपागार से कई लाभ होते हैं परंतु इससे प्रशासन संबंधी समस्याएं निर्मित होती हैं

4.49 अंतर्राष्ट्रीय नीति बनाने वालों के बीच बतायी गई प्रमुख प्राथमिकता, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि सभी ओटीसी डेरिवेटिव उत्पादों की सूचना किसी व्यापार निक्षेपागार को दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से यह तर्क किया जा रहा है कि किसी भी विशिष्ट दस्तावेज के लिए पूरे विश्व में एक ही निक्षेपागार होना चाहिए। अन्यथा, डेटा को संकलित करने की योग्यता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा और स्थिति या जोखिमों का स्पष्ट चित्रण शायद संभव नहीं होगा विशेष रूप से तब जब लेनदेन से संबंधित दोनों पक्ष अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में स्थित हो। तथापि, क्या सभी उत्पादों के लिए भी एक

ही निक्षेपागार होना चाहिए - इस पर थोड़ी सी चर्चा होती है। इसके अलावा, इस प्रकार के निक्षेपागार जनोपयोगी होते हैं, अतः यह अत्यंत स्पष्ट है कि उनका कार्य लाभ के लिए नहीं होना चाहिए।

भारतीय संदर्भ में वर्तमान सूचना व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकता है

4.50 बहुत से अधिकार क्षेत्रों में जहां केंद्रीकृत व्यापार सूचना प्रणाली केवल संकट काल के पश्चात् प्रकाश में आई जिसके विपरीत लेनदेन स्तर के डेटा से संबंधित संक्षिप्त जानकारी से लेकर विभिन्न ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेनों की सूचना हेतु भारत में व्यवस्थाएं की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, लेनदेन सूचना प्रणाली के लिए विभिन्न मॉड्यूल विकसित करने हेतु सीसीआइएल के साथ मिलकर से कार्य कर रहा है। ओटीसी बाज़ार के लिए वर्तमान सूचना प्रणाली व्यवस्थाओं में विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, सरकारी प्रतिभूतियां, कार्पोरेट बांड और मुद्रा बाज़ार के दस्तावेज सम्मिलित है। अब सूचना प्रणाली व्यवस्थाओं का समेकन जरूरी है। चूंकि सीसीआइएल ने इससे पहले ही अपेक्षित मंच विकसित किए हैं, अतः बड़े पैमाने और प्रसार की किरफायतें, उन्नति की ओर बढ़ने के लाभ उठाना तर्कसंगत लगता है। तथापि, सीसीआइएल भी सीसीपी के जैसा ही कार्य करता है, अतः सीसीपी के कार्य से लेनदेन निक्षेपागार कार्य को अलग करने संबंधी प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

4.51 इस संबंध में रिजर्व बैंक के कार्यकारी समूह ने उन उत्पादों की सूची को विस्तारित करने पर कुछ सिफारिशों की हैं जिनकी सूचना दी जाती है और इस प्रकार की सूचना को दिया जाना विनियामक आदेशों के जरिए बाध्य किया जाता है।

संविभाग दबाव - ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन करना

4.52 2007-09 के वित्तीय संकट ने प्रणालीगत जोखिम को बढ़ाने में ओटीसी बाज़ार सहायक होने की संभाव्यता को प्रकट कर दिखाया। भारतीय संदर्भ में डेरिवेटिव बाज़ार का आकार सीमित रहता है और उत्पाद प्रोफाइल अधिकांश सादा वैनिला रहता है। तथापि, प्रणालीगत जोखिम बढ़ने की संभावना बनी रहती है बशर्ते वहां पर सक्रिय सहभागी बहुत कम हो। द्विपक्षीय समझौते के प्रारंभिक निष्कासन किसी स्थिति से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है (किसी विरोधी चुकाई के साथ लेनदेन में भाग लेने के अलावा), इसके साथ सकल अनुमानिक बकाया राशि में विविध प्रकार से वृद्धि होती है जिससे अधिक पूंजी अपेक्षाएं और प्रतिपक्ष के सीमाओं की उपलब्धता बढ़ जाती है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि सकल अनुमानित मूल्य से संविभागों के आर्थिक सार का ग्रहण नहीं होता।

4.53 सीसीपी निपटान की ओर स्थानांतरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय की दृष्टि से अधिमामिक उपाय बाजारों/उत्पादों में लागू नहीं होते जहां

अलग-अलग कारणों से, इस प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू करना संभव नहीं हैं। इन बाजारों/उत्पादों के लिए कुछ स्थानों पर एक उपाय तैनात करने पर विचार किया जा रहा है वह है संविभाग दबाव - यह एक बाजार व्यापी अभ्यास है जिससे अलग-अलग संविभागों के जोखिम प्रोफाइलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए बिना समग्र अनुमानित आकार कम हो जाता है और ओटीसी डेरिवेटिव संविभागों में बकाया संविदाओं की संख्या कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में उन लेनदेनों की पहचान करना शामिल है जिन्हें सभी प्रतिपक्षों द्वारा समय से पहले समाप्त किया जा सकता है। इस तरह हर एक प्रतिभागी द्वारा निर्धारित नियंत्रण/सहनशीलता की सीमाओं का समाधान किया जाता है। भारत के संदर्भ में फिलहाल सीसीआईएल रुपया डेरिवेटिव बाजार के लिए लेनदेन दबाव सेवाएं विकसित करने की प्रक्रिया में है।

भुगतान और निपटान में परस्पर निर्भरताएं

भुगतान प्रणाली में परस्पर निर्भरताओं के आघातों के प्रभावों से विघटन हो सका

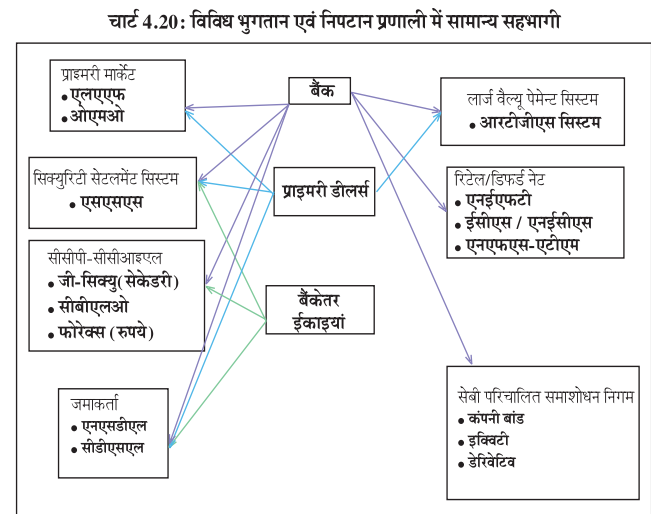
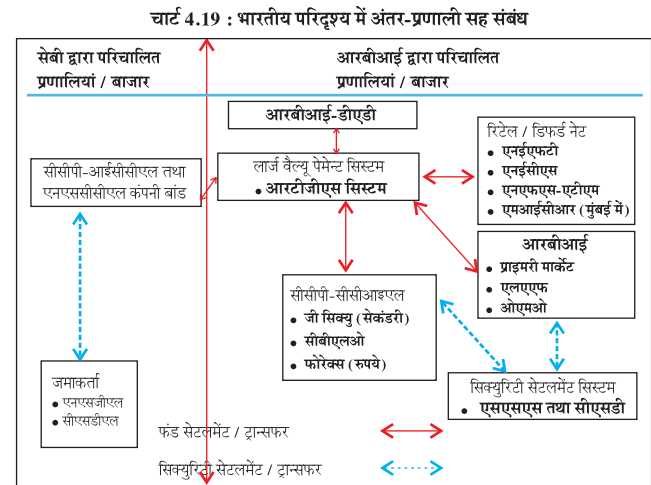
4.54 भुगतान प्रणाली आधारभूत संरचना में बढ़ती हुई परस्पर निर्भरताओं की जोखिमों और संभाव्य आघात के प्रभाव जिनका बहु-प्रणालियों पर, उनके परस्पर संबंधों पर हाल ही के रिपोर्ट में विशेष बल दिए जाने के कारण प्रभाव हो सका¹⁴। भारत के संदर्भ में भी भुगतान प्रणालियां और निपटान प्रवाह, परिचालनगत प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन कार्य प्रणालियां बड़ी संख्या में परस्पर निर्भर हो रही हैं। इससे किसी भी प्रणाली के टूटने पर संबंधित अन्य प्रणालियों के निर्बाध कार्य प्रणाली पर असर होने की संभावना बढ़ जाती है और किसी भी सकल प्रणाली की प्रभावित करने वाली किसी स्वभावगत विलक्षण घटना के कारण देश की समग्र भुगतान और निपटान संरचना टूटने की जोखिम बढ़ जाती है।

भारत में प्रणाली और संस्था आधारित परस्पर निर्भरता के सुदृढ़ साक्ष्य हैं

4.55 भारतीय संदर्भ में परस्पर निर्भरताओं में प्रत्यक्ष प्रणाली बीच के संबंधों से उत्पन्न होने वाली प्रणाली आधारित परस्पर निर्भरताएं शामिल हैं, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक और सीसीआईएल द्वारा परिचालित प्रणालियों तथा सेबी परिचालित समाशोधन निगमों के बीच संबंध जिससे आरटीजीएस प्रणाली में कार्पोरेट बांड के लेनदेन की निधियों की मंजिल निर्धारित की जाती है। (चार्ट- 4.19)

4.56 इसके अलावा, संस्था आधारित परस्पर निर्भरताएं होती हैं जो किसी एक सामान्य वित्तीय संस्था के जरिए दो अथवा इससे अधिक प्रणालियां अप्रत्यक्ष संबंधों से निकल आती हैं। भारत में यह बहुत ही स्पष्ट है क्योंकि सभी प्रणालियों में सहभागी सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं

होती हैं। इसके अतिरिक्त, सीबीएलओ और सरकारी प्रतिभूतियों के खंडों में कुछ अन्य सहभागियों के लिए निधि निपटान के लिए निपटान बैंकों के रूप में कुछ प्रमुख सहभागी कार्य करते हैं। इसके अलावा, सीसीआईएल और रिजर्व बैंक परिचालित प्रणालियों में कुछ प्रमुख बैंक ईक्विटी बाजारों के लिए निपटान बैंक हैं जबकि कुछ सीसीआईएल को निधि और प्रतिभूतियों की ऋण सहायता खंडों में देता है जिसमें वे भी प्रमुख खिलाड़ी होते हैं। (चार्ट 4.20)



¹⁴ सीपीएसएस रिपोर्ट: 'दी इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ पेमेंट एण्ड सेटलमेंट सिस्टम्स' जून 2008 (<http://www.bis.org/publ/cpps84htm>)

4.57 वित्तीय संस्थाओं का किसी प्रणाली विशेष के लिए समाशोधन बैंक के रूप में काम करनेवाली वित्तीय संस्था जैसे परिचालनकारकों (जैसे कि इक्विटी बाजार सीसीपी के लिए समाशोधन बैंकों के रूप में कार्य करनेवाले बैंकों के मामले में) या सामान्य बुनियादी संरचना उपलब्ध कराने (आई.डी.आर.बी.टी द्वारा परिचालित इंफ़ीनेट नेटवर्क) जैसे परिचालनात्मक कारकों के कारण अंतरनिर्भरता के दूसरे रूप भी विकसित हो जाते हैं।

स्वतंत्र प्रणालियों द्वारा जोखिम प्रबंधन की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता

4.58 इस प्रकार भारतीय भुगतान प्रणाली अंतरसंबंधों का एक अत्यंत एकीकृत और स्वतंत्र समूह है। कमोवेश पूरी दुनिया में ऐसी प्रणालियों की स्थिति ऐसी ही है। इस प्रकार की अंतरनिर्भरता के कारण विशेष सहभाव पनपे हैं जिससे परिचालनात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है और जोखिम भी कम हुई है (उदाहरण के लिए आर.टी.जी.एस सिस्टम में डी.वी.पी निपटान के कारण क्रेडिट जोखिम में कमी आयी है)। उच्चस्तरीय एकीकरण और अंतरनिर्भरता के कारण विभिन्न प्रणालियों में होनवाली निपटान प्रवाह प्रभावित होते हैं। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट और लिक्विडिटी जोखिम प्रणाली में बहुत तीव्र गति से फैल सकते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी अंतर्निहित वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित कर सकती है। यद्यपि केंद्रीय बैंक मुद्रा में प्रमुख भुगतान प्रणालियों में लेन-देन के निपटान, सी.सी.पी. निपटान की शुरुआत आदि जैसी व्यवस्थाओं के कारण ये जोखिम बहुत हद तक कम हुए हैं तथापि अंतरनिर्भरताओं के सजग प्रबंधन की आवश्यकता बनी हुई है। प्रत्येक भुगतान प्रणाली से संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के प्रणालीगत जोखिम के समग्र नियंत्रण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। भुगतान प्रणालियों में अंतरनिर्भरता के कारण पनपने वाले जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए इन सिस्टमों का व्यापक दृश्य और सिस्टमिक जोखिम पर इनके प्रभाव का महत्व बहुत अधिक होता है।

जमा बीमा

4.59 पूर्व के एफ.एस.आर. में किसी भी क्षेत्रविशेष में वित्तीय स्थिरता व्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में सुदृढ़ जमा बीमा प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डाला गया था। हाल के वित्तीय संकट के दौरान सुरक्षा नेट प्रणाली की प्रभावता की गहन जांच की गई थी और बैंकिंग प्रणाली में आम जनता के विश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से कई देशों ने जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए नीतियां अपनाईं। इस तरह की विशेष व्यवस्था से बाहर निकलना पूरे विश्व की जमा बीमा प्रणालियों के लिए एक प्रमुख चुनौती है। विभिन्न देशों की जमा बीमा एजेंसियां सीमा पार व्यवस्थाओं की प्रभावशालिता बढ़ाने के उपाय खोज रही हैं ताकि मेजबान देशों

पर देशी बैंकों के विफल होने के बुरे प्रभाव को कम किया जा सके। दूसरी प्रकार की नीतिगत पहल के तहत कमजोर/विफल होते बैंकों को उबारने के लिए जमा बीमा एजेंसियों की ओर से सक्रिय और प्रारंभिक सहभागिता उपलब्ध कराने का विचार है।

भारतीय जमा बीमा प्रणालियों से जुड़े व्यापक मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं

4.60 पूर्व के एफ.एस.आर. में भारतीय जमा बीमा प्रणाली से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ-साथ, इनमें जमा बीमा निधि की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति में लगने वाला समय कम करना, जमा बीमा प्रणाली की रक्षा राशि में वृद्धि करना, डी.आई.सी.जी.सी. को दिए गए अधिदेश को बढ़ाकर उसमें बैंक विघटन को शामिल करने और प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के लिए प्रभाव सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। ये मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। इस बीच डी.आई.सी.जी.सी. ने बहुत समय से लंबित निपटान के मामलों को निपटाने हेतु शुरुआती कदम उठाया है। उपर्युक्त निगम डेटा संग्रह प्रणाली में सुधार करने और निपटान के लिए लगने वाले समय को कम करने के लक्ष्य की दिशा में एकीकृत दावा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया पर भी काम कर रहा है। हालांकि जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति में विलंब होने के मुख्य कारण -परिसमापकों की जबावदारी सुनिश्चित करने के लिए निगम के पास पर्याप्त शक्ति की कमी - का हल निकालना अभी बाकी है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निगम निधि अनुपात कम बना हुआ है और जो निगम की अपनी कवरेज का विस्तार करने की क्षमता को प्रतिबंधित कर रहा है। डी.आई.सी.जी.सी. के अधिदेश को और व्यापक करने का मुद्दा यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण है तथापि इसे अमल में लाने के लिए विधायी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा।

4.61 जमा बीमा में सुधार से संबद्ध कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रुप) विभिन्न मुद्दों की समीक्षा कर रहा है, जिनमें जमा बीमा निधि, डी.आई.सी.जी.सी. के अधिदेश को व्यापक बनाना निधि प्रबंधन और वसूली प्रदर्शन में सुधार लाना जैसे मुद्दे शामिल हैं।

निष्कर्ष टिप्पणी

4.62 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली के लिए विनियामक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। आगे कई मुद्दे और चुनौतियां उभरने की संभावना है। क्रेडिट ऋण वृद्धि और बासल III की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बैंकों को अतिरिक्त पूंजी जुटानी होगी। इक्विटी बाजार के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पूंजी बाजार तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की पहुंच को सुगम बनाने की दिशा में बैंकिंग क्षेत्र संबंधी में संशोधन करने से इसमें कमी आ सकती

है। भारत जैसे उभरते बाजार में प्रतिचक्रिय बफर के निर्माण के लिए निर्धारित संकेतक उपयुक्त प्रतीत नहीं होते हैं और सोच-विचार करके बनाने के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक संकेतक एवं विनियामकीय विवेकाधिकार की पर्याप्त मात्रा दोनों के संगम का उपयोग करना होगा। बासल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर अंतरित होने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इससे कई चुनौतियां - सटीक डेटा और कुशल स्टाफ की उपलब्धता, चूक व हानि के अनुमान के परिमाणित के समर्थन के लिए आंतरिक रेटिंग प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता, सुदृढ़ प्रशिक्षण प्रक्रिया और वैधता प्राप्त जोखिम मॉडल आदि - उभरने की संभावना है। वित्तीय संगठनों के लिए पर्यवेक्षीय व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास जारी हैं हालांकि तर्कसंगत संकल्प जैसे मुद्दे अभी भी बने हुए हैं।

4.63 एफ.एस.डी.सी तथा उसकी उप समिति का ढांचा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के सरकार के उद्देश्य तथा केंद्रीय बैंक और अन्य विनियामकों से जुड़ी परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। बैंकिंग क्षेत्र के कानूनों में विधायी सुधारों से यह आशा की जाती है कि रिजर्व बैंक की विनायमक शक्तियां और अधिक प्रभावी होंगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक मानदंडों में अंतराल तथा विनायमक अंतरपणन की गुंजाइश बनी हुई है। इन मुद्दों के सारे पहलुओं की जांच रिजर्व बैंक द्वारा गठित एक कार्यदल द्वारा की जा रही है। सरकार द्वारा प्रायोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिजर्व बैंक के विनियमनों से मिलने वाली छूट के संबंध में पुनः विचार किया जाना है क्योंकि इन कंपनियों की प्रणालीगत महत्ता बढ़ गई है।

4.64 भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी सीमा तक संबद्ध और समूहित है जिससे एक या अधिक बैंकों के अपने विशिष्ट प्रवृत्तिगत कारणों से

विफल होने की स्थिति में पूरी प्रणाली संक्रामक प्रभाव से ग्रसित हो सकती है।

4.65 इस समय स्पॉट एक्सचेंज द्वारा दी गई समाशोधन व निपटान सुविधाएं भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 अथवा अन्य किसी व्यवस्था के अनुसार विनियमित नहीं की जा रही हैं। भारत में सीसीपी के लिए चलनिधि जोखिम, यदि वे हों तो, में उल्लेखनीय प्रणालीगत अंतर हो सकता है। सीसीपी के लिए केंद्रीय बैंक की चलनिधि तक पहुंचने में नैतिक खतरा संबंधी जोखिम है और सीसीपी के लिए निजी क्षेत्र के स्तर पर उबरने की प्रक्रियाओं में वृद्धि के प्रयास आवश्यक हैं, जैसाकि प्रणालीगत दृष्टि से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए विचार किया रहा है। सभी ओटीसी उत्पादों के लिए एकल आधान के कई फायदे हैं। भारतीय संदर्भ में इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा, ब्याज दर, सरकारी प्रतिभूति, कॉरपोरेट बॉण्ड और मुद्रा बाजार लिखतों के लिए सीसीआईएल द्वारा विकसित वर्तमान रिपोर्टिंग व्यवस्था का लाभ उठाया जा सकता है। ट्रेड रिपोजिटरी की शुरुआत से प्रणालीगत जोखिम कम करने की दृष्टि से बहुत हद तक डेरिवेटिव संविदाओं के पोर्टफोलियों संकुचित करने का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। भारतीय भुगतान प्रणालियों में सिस्टम और संस्था आधारित अंतरनिर्भरता का बहुत बड़ा प्रमाण है और इसका अर्थ यह है कि यदि एक सिस्टम तक को प्रभावित करनेवाली प्रवृत्तिगत घटना बहुत तेज गति से पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है।

4.66 डीआईसीजीसी के निधि अनुपात की पर्याप्तता सुनिश्चित करने, जमाकर्ताओं की प्रतिपूर्ति के लिए लगने वाले समय को कम करने, जमा बीमा प्रणाली के कवरेज को बढ़ाने और बैंक समाधान को शामिल करने के लिए डीआईसीजीसी के अधिदेश को और व्यापक बनाने से संबंधित मुद्दे बहुत प्रासंगिक बने हुए हैं और डीआईसीजीसी द्वारा स्थापित कार्यदल द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

अध्याय V

समष्टिवित्तीय स्ट्रेस टेस्टिंग

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वित्तीय क्षेत्र में जोखिम की प्रासंगिकता पर अधिक बल दिया जा रहा है। यह वित्तीय सेवाओं के विघटन का जोखिम है जो (i) वित्तीय प्रणाली के सभी या कुछेक घटकों में कमी के कारण घटित होता है और (ii) जिसमें वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर नकारात्मक परिणाम पैदा करने की संभावना होती है। वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम के माप का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वास्तव में, वित्तीय क्षेत्र के सकल जोखिम को मापना, अर्थात् ऐसी किसी प्रणालीगत घटना का होना जिसका प्रभाव न केवल वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर होगा बल्कि समूची अर्थव्यवस्था पर, पूरी दुनिया में शोध का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। प्रणालीगत जोखिम मापन वस्तुतः अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। सिस्टमिक जोखिम मापने की कई विधियां हैं जिनमें से वित्तीय विवरणी आधारित माप, एक्सपोजर-आधारित नेटवर्क मॉडल और पूंजी बाजार के डेटा पर आधारित माप कुछ प्रमुख हैं। हालांकि, ये माप पूर्णतः संगत नहीं होते और एक माप पर अति-निर्भर होने से पक्षपातपूर्ण परिणाम मिल सकते हैं। विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त किए गए माप पर विचार करते हुए निष्कर्षात्मक निर्णय लेने के लिए इस ओर व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी के लिए वित्तीय स्थिरता संकेतकों की निगरानी और दबाव परीक्षण संबंधी अभ्यास संचालित करना प्रमुख व्यावहारिक विधि है। दबाव परीक्षण भविष्य के प्रति हमारा नजरिया है और किसी दी हुई वित्तीय प्रणाली की आवश्यकतानुसार इसे ढाला जा सकता है। दबाव परीक्षण का उद्देश्य अति विपरीत लेकिन संभावित घटनाओं की स्थिति में अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय क्षेत्रों की आघात सहनीयता का मूल्यांकन करना है। इनका प्रयोग पर्यवेक्षीय जोखिम मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में, जिसमें वित्तीय संस्थाओं का मूल्यांकन अलग-अलग स्तर पर किया जाता है, तथा वित्तीय स्थिरता विश्लेषण के अंतर्गत समष्टि विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में, संवेदनशीलता मापने के लिए किया जाता है जिसमें प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रति संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र की आघातसहनीयता का परीक्षण किया जाता है, दोनों स्तरों पर असुरक्षितताओं की मात्रा के आकलन के लिए किया जाता है।

5.1 इस रिपोर्ट में संकट की संयुक्त संभाव्यता और बैंकिंग स्थिरता सूचकांक के माध्यम से बैंकों की स्थिरता का अध्ययन किया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्कों के माध्यम से एक बैंक के दूसरे बैंकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय लेकिन सहनीय योग्य आघात की परिस्थिति उत्पन्न कर दबाव परीक्षण के माध्यम से ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिम से संबंधित वाणिज्यिक बैंकों की आघात सहनीयता का अध्ययन भी किया गया। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए प्रस्तावित तुलन-पत्र पर दबाव परीक्षण किया गया, जिसमें मौलिक और दबावग्रस्त परिदृश्य दोनों शामिल हैं। समष्टि-दबाव परीक्षण मॉडल के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के ऋण जोखिम का परीक्षण भी किया गया, जो बहुआयामी पश्चगमन समीकरण और वेक्टर स्वतःपश्चगमन (वीएआर) विधि का प्रयोग करते हुए ऋण जोखिम की मात्रा को

समष्टिआर्थिक चरों से जोड़ता है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण जोखिम का एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया। इन स्ट्रेस टेस्ट में उपयोग की गई विधियों का वर्णन अनुलग्नक में किया गया है।

बैंकिंग स्थिरता माप ¹

5.2 विपत्ति की स्थिति में बैंकों की स्थिति में सहवर्ती तौर पर प्रत्यक्ष संपर्क या अप्रत्यक्ष संपर्क जिसमें बाजार भाव या आस्ति का मूल्य, अंतर-बैंक उधारी और सूचना असममिति शामिल हैं के माध्यम से प्रतिरूपी गिरावट आती है। यह खण्ड विपत्ति की स्थिति में मॉडल पर आधारित है क्योंकि इसके तहत वित्तीय प्रणाली को बैंकों के विशेष समूह का एक संविभाग माना गया है (सेगोविएनो और गुडहार्ट, 2009)²। विशेष रूप से, बीएसएमडी, जो बैंकों के

¹ भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए यह मॉडल श्री मिग्युअल ए. सेगोवियानो, सीएबीबी (कमिशन नेसोनल बंकारिया ये डी वोलोरेज:मेक्सिकन वित्तीय विनियामक पर्यवेक्षी एजेंसी ने बनाया है।

² इस अध्ययन में 20 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर विचार किया गया जो वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों के 75 प्रतिशत के आसपास है।

पोर्टफोलियो के अलग-अलग तथा संयुक्त आस्ति मूल्य में घट-बढ़ के संबंध में होता है, विश्लेषणाधीन बैंकों (बाक्स 5.1 सीआइएमडीओ दृष्टिकोण)³ के पीओडी से निकाला जाता है। बीएसएमडी में बैंकों की संकट निर्भरता निहित है, जो बैंकों की लीनियर (परस्पर संबंध) तथा गैर-लीनियर संकट निर्भरता, तथा आर्थिक चक्र में उनके परिवर्तन, जो यह दिखलाता है कि संकट के समय निर्भरता बढ़ जाती है। प्रणाली के बारे में (पूरी) पोर्टफोलियो मल्टिवेरिएट डैसिटी, सीआइएमडीओ दृष्टिकोण वित्तीय स्थिरता का तीन अलग

अलग तरीकों से विश्लेषण करता है : (i) किसी प्रणाली में वित्तीय संस्थाओं का सांझा संकट, (ii) विशिष्ट संस्थाओं के बीच संकट, तथा (iii) किसी विशिष्ट संस्था में संकट से सम्बद्ध संकट पूरक दृष्टिकोण से वित्तीय स्थिरता के विश्लेषण की संभावना में किसी एक दृष्टिकोण की तुलना में यह कार्यविधि कार्यान्वयन के लिए बेहतर नियंत्रण प्रदान करती है, क्योंकि अलग-अलग बैंक का पीओडी इन्पुट दिखलाता है, जिसका अनुमान वैकल्पिक दृष्टिकोणों का प्रयोग करके लगाया जा सकता है।⁴

बाक्स 5.1: सीआईएमडीओ -दृष्टिकोण

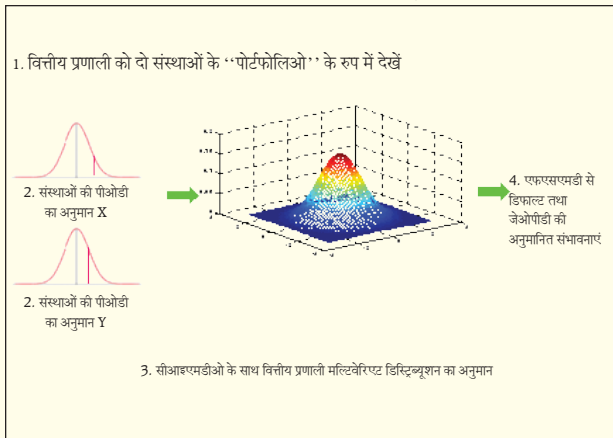
संकट निर्भरता का माडल बनाते समय, गुडहार्ट तथा सोगोविआनो (2009) द्वारा बताई गई कार्यविधि अपनाई गई है। पहला, वित्तीय प्रणाली को संस्थाओं के पोर्टफोलियो के रूप में परिकल्पित किया गया है। फिर, अलग-अलग संस्थाओं के पीओडी (पोर्टफोलियो) को इक्विटी मूल्यों से निकाला गया है (चित्र 5.1) बाद में, पीओडी जैसे इन्पुट का प्रयोग करते हुए (बहिर्जात चर), तथा सीआइएमडीओ कार्यविधि अपनाते हुए क्रास-एन्ट्रपी के आधार पर एक नयी गैर-पैरामीट्रिक वित्तीय प्रणाली की

एफएसएमडी तैयार की गई हैं। अंत में, एफएसएमडी से वित्तीय संस्थाओं के पीओडी तथा वित्तीय प्रणाली के जेपीओडी का अनुमान लगाया गया है।

एफएसएमडी तथा इस प्रकार, अनुमानित संभावनाएं तथा जेपीओडी में संस्थाओं की संकट निर्भरता निहित है। यह पोर्टफोलियो में वित्तीय संस्थाओं की लीनियर निर्भरता बतलाता है तथा पूरे आर्थिक चक्र में इन में परिवर्तन आता है। ये पारंपरिक जोखिम माडलों में बेहतर है तथा यह मानकों है वे पूरे आर्थिक चक्र में बदलते नहीं।

एफएसएमडी में निहित संकट निर्भरता संघटन सीआईएमडीओ - कोपुला द्वारा वर्णित है (सोगोविआनो 2006)। किसी पोर्टफोलियो में आस्तियों के बीच निर्भरता का लीनियर तथा गैर-लीनियर संघटन कोपूला कार्यों द्वारा बतलाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में कोपूला सीधे ही अलग-अलग पीओडी की संयुक्त हलचल से ली जा सकती है। यह पैरामेट्रिक कोपूला दृष्टिकोण से अलग है, जिसमें पैरामीट्रिक कोपूला कार्यों का चयन तथा निर्धारण स्पष्ट रूप से किया जाता है। सामान्यतया एक कठिन कार्य, विशेषकर आकड़ों की सीमा के अधीन।

चित्र 5.1: वित्तीय प्रणाली की मल्टिवेरिएट डैसिटी



स्रोत: गुडहार्ट एण्ड सोगोविनो 2009

³ कन्सिस्टेंट इन्फर्मेंशन मल्टिवेरिएट डैसिटी ऑप्टिमाइजिंग (सीआईएमडीओ) मेथडॉलॉजी सेगोवियानो माइग्युअल (2006) का उपयोग करते हुए बीएसएमडी को वसूल किया गया जो गैर-मापदण्डीय ढांचा है जो परस्पर उत्क्रम दृष्टिकोण पर आधारित है (कुलबक, 1959)। सेगोवियानो मिग्युअल (2006): कन्सिस्टेंट इन्फर्मेंशन मल्टिवेरिएट डैसिटी ऑप्टिमाइजिंग मेथडॉलॉजी: वित्तीय बाजार समूह, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, डिस्कशन पेपर 557।

⁴ संकट की संभावनाओं (पीओडीज) का अनुमान लगाने के लिए और भी पद्धतियां हैं, विशेष रूप से कैमल रेटिंग, मेरटन दृष्टिकोण आदि का उपयोग करके। बैंको की इक्विटी रिटर्न डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर उनकी पीओडीज का अनुमान लगाया जाता था। हम दृष्टिकोण के अंतर्गत पहले बैंको के इक्विटी रिटर्न के ऐतिहासिक डिस्ट्रिब्यूशन पर अनुमान लगाया जाता था। बाद में ऐतिहासिक के अंतर्गत आनेवाले रिटर्नों की संभाव्यता कुल मामलों (99.5 वीएआर) में से 0.5 प्रतिशत से भी बदतर रही। अतएव, विशिष्ट बैंक की पीओडी बैंक के इक्विटी रिटर्न के 0.5 ऐतिहासिक प्रतिशत से भी बदतर होने की संभावना प्रदर्शित करती है।

प्रणाली में संपूर्ण संकट: जेपीओडी तथा बीआईएस

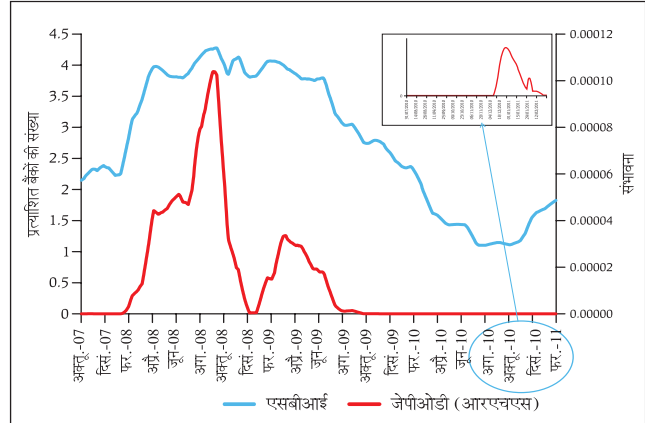
संकट के बाद संकट निर्भरता कम हुई है, लेकिन फिर से बढ़ रही है

5.3 पहले दृष्टिकोण के लिए, दो संकेत, संकट की संयुक्त संभावना (जेपीओडी) तथा बैंकिंग स्थिरता सूचकांक (बीएसआई) का प्रयोग किया गया है।⁵ जेपीओडी प्रणाली (पोर्टफोलियो) सभी बैंकों के संकट में आ जाने की संभावना दिखलाता है। जबकि बीएसआई यह मानते हुए कि कम से कम एक बैंक संकट में आ गया है, उन बैंकों की संख्या का अनुमान लगाता है जो संकट में आ जाएंगे। अक्टूबर 2007 से फरवरी 2011 तक की अवधि के लिए जेपीओडी तथा बीएसआई का अनुमान लगाया गया था। इन्हें चार्ट 5.1 में प्रस्तुत किया गया है। यह देखा जा सकता है कि संकट के दौरान संकटाधीन बैंकों की संख्या 4 थी (20 के नमूने में से) वह 2010 की अंतिम तिमाही तक कम हो कर 1 रह गई। लेकिन, 2011 की पहली तिमाही में यह बढ़ कर फिर 2 हो गई है। संकट के समय सभी बैंकों की संकट निर्भरता बढ़ जाती है, जो यह दिखलाता है कि जेपीओडी तथा बीएसआई के निहितार्थ के अनुसार अलग-अलग जोखिम तीव्रता से बढ़ते हैं। जेपीओडी तथा बीएसआई न केवल अलग-अलग बैंकों के संकट की संभावना को ध्यान में रखते हैं बल्कि इन उपायों में बैंकों की संकट निर्भरता भी निहित है। इसलिए, अलग-अलग बैंकों के पीओडी की तुलना में ये उपाय बड़े और गैर लीनियर वृद्धि देख सकते हैं। चार्ट 5.2 दिखलाता अलग-अलग पीओडी के औसत की तुलना के दैनिक प्रतिशतता परिवर्तनों की तुलना में जेपीओडी के दैनिक प्रतिशत परिवर्तन अधिक बढ़े हैं। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि संकट के समय, न केवल अलग-अलग पीओडी बढ़ते हैं, बल्कि संकट निर्भरता भी बढ़ जाती है। इसलिए औसतों या सूचकांकों पर आधारित वित्तीय स्थिरता के उपाय, हो सकता है कि सही अनुमान न दें।

विशिष्ट संस्थाओं के बीच संकट

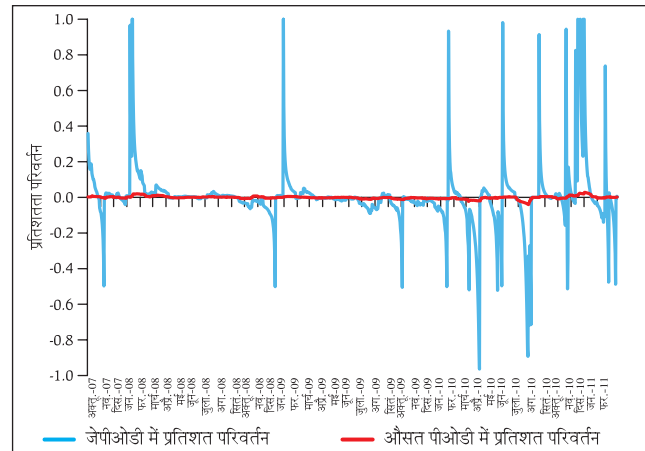
5.4 दूसरे दृष्टिकोण से स्थिरता के विश्लेषण के लिए, संकट की संभावना के सेट का अनुमान लगाया गया है जिन्हें डीआईडीई मैट्रिक्स के रूप में वर्णित किया गया है। मैट्रिक्स यह मानते हुए कि कालम का बैंक संकट में है, बैंक के संकट की सशर्त संभावना दिखलाता है। संकट निर्भरता का अनुमान दैनिक आधार पर किया जाता है। बैंक की संकट निर्भरता का विश्लेषण एक टॉक्सिटी सूचकांक के माध्यम से किया जाता है जो यह दिखलाता है कि यदि वह बैंक संकट में है तो उसके द्वारा दूसरे बैंक को संकट में डाल देने की क्या संभावना है।

चार्ट 5.1: जेपीओडी तथा बीएसआई



स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 5.2: अलग-अलग पीओडी तथा जेपीओडी प्रतिशतता परिवर्तन



⁵ व्याख्याओं के लिए देखें सेगोवियानो एण्ड गुडहार्ट (2009): बैंकिंग स्टेबिलिटी मेजर्स, आईएमएफ: डब्ल्यूपी/09/4

5.5 सभी प्रमुख बैंकों में संकट निर्भरता काफी बढ़ गई (चार्ट 5.3)। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए, 10 अक्टूबर 2007 तथा 20 सितंबर 2008 को चुना गया है ताकि यह आकलन किया जा सके कि संकट के प्रारंभिक चरण से लेहमन ब्रदर्स द्वारा दिवालियेपन के लिए अनुरोध करने तक संकट की निर्भरता कैसे आगे बढ़ी। औसतन, यदि कोई बैंक संकट में आ गया, तो अन्य बैंकों के संकट में आ जाने की औसत संभावना 10 अक्टूबर 2007 को 17 प्रतिशत से बढ़ कर 20 सितंबर 2008 को 42 प्रतिशत हो गई। इसके अतिरिक्त, औसतन, किसी विशिष्ट बैंक का संकट अक्टूबर 2007 में (29 प्रतिशत) प्रणाली में उच्चतम संकट (टैक्सिटी) डालता, जबकि सितंबर 2008 में किसी दूसरे बैंक से उच्चतम टैक्सिटी (53 प्रतिशत) होती।

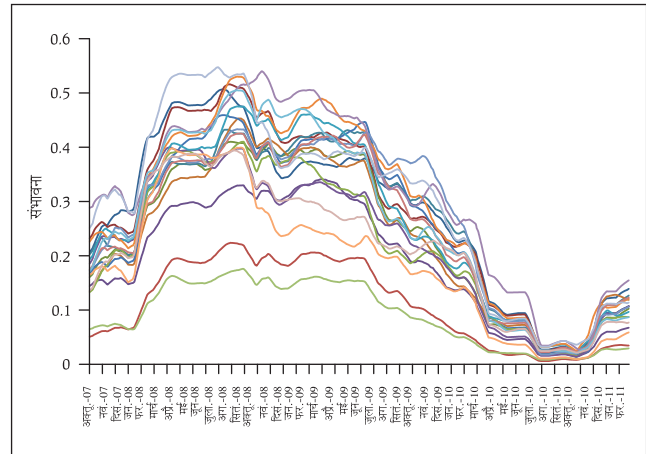
5.6 डीआईडीई मैट्रिक्स से, असुरक्षा सूचकांक (VI) निकाला जाता है जो प्रणाली में दूसरे बैंकों⁶ के संकट से एक बैंक की आघातोन्मुखता असुरक्षा को मापता है और यह चार्ट 5.4 में प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से यह देखा जा सकता है कि हाल ही के वित्तीय संकट में बैंकों की असुरक्षा उच्च थी लेकिन बाद की अवधि में काफी कम हो गई। हाल ही की अवधि में असुरक्षा में मामूली वृद्धि देखने में आई है।

हालांकि संकट निर्भरता आकस्मिकता नहीं दिखलाती लेकिन ये परिणाम दिखलाते हैं, कि संकट की घटना के कई सप्ताह पहले भी, संकट निर्भरता का विश्लेषण इस बारे में लाभदायक जानकारी दे सकता है कि किसी विशिष्ट संस्था में संकट अन्य संस्थाओं तथा अन्ततः प्रणाली की स्थिरता को कैसे प्रभावित कर सकता है।

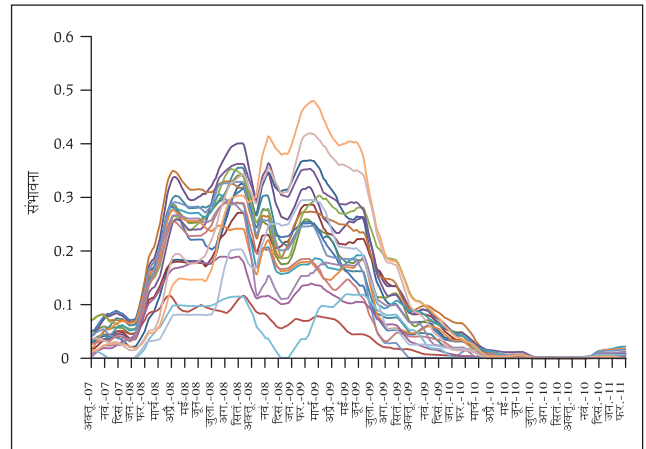
प्रपाती प्रभाव

5.7 तीसरे दृष्टिकोण से स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए, प्रपाती प्रभाव के अनुमान की विधि का प्रयोग किया गया है। यह वह संभावना दिखलाता है जो किसी बैंक के संकट में आ जाने पर किसी एक या ज्यादा बैंकों के संकट में आने की संभावना दिखलाता है। इस प्रकार, किसी बैंक के संकट में आ जाने पर यह संकेतक किसी बैंक की प्रणालीगत महत्ता को मापने में सहायक है, जो उस विशिष्ट संस्था के “डॉमिनो” प्रभाव की ओर संकेत करता है। चार्ट 5.5 कुछ चुनिंदा बैंकों के लिए अलग-अलग समय पर बैंकवार संकेतक दिखलाता है। चार्ट से यह स्पष्ट है कि संकट की अवधि के बाद कुछ चुनिंदा बैंकों का प्रपाती प्रभाव काफी कम हो गया।

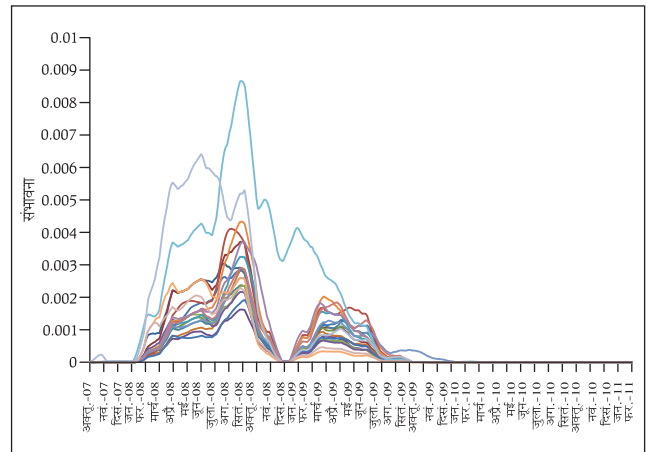
चार्ट 5.3: टॉक्सिसिटी: बैंकवार



चार्ट 5.4: असुरक्षा सूचकांक: बैंकवार



चार्ट 5.5: प्रपाती प्रभाव: बैंकवार



⁶ उदाहरण के लिए तीन प्रणालियों के किसी प्रणाली के लिए वित्तीय संस्था ए के लिए VI इस प्रकार अनुमानित किया जाएगा पी(ए/बी)* पी(बी)+पी(ए/सी)*पी(सी)

ऋण जोखिम

तनाव की स्थिति में लाभ निम्नतर हुए, परंतु पूंजी पर्याप्तता पर अधिक दबाव नहीं आया

5.8 तुलन-पत्र की दृष्टि से ऋण जोखिम का परीक्षण करने के लिए परिदृश्य विश्लेषण हाथ में लिया गया था। बैंकों का तुलन-पत्र तथा लाभ हानि खाता मार्च 2012 के लिए पूर्वानुमानित किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं में वृद्धि के साथ परिदृश्य रूपरेखा में यह भी माना गया कि पुनःसंचित मानक आस्तियों में से 30 प्रतिशत अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तित होंगी। बैंकों की पूर्वानुमानित वित्तीय स्थितियों पर सत्याभासी आघात लगाये गये ताकि उनका प्रभाव और प्रणाली की आघातसहनीयता नापी जा सके। यह विश्लेषण सकल और व्यक्तिगत दोनों पर, मार्च 2011 के पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर किया गया।

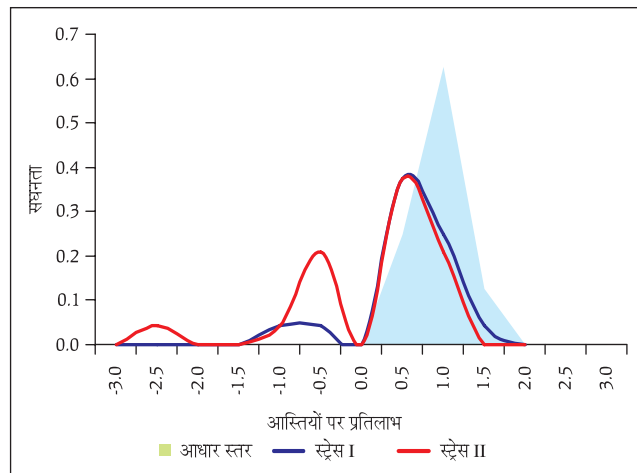
5.9 तनाव की स्थिति में बैंकों की लाभप्रदता विपरीत रूप से प्रभावित हो गई (चार्ट 5.6)। तनाव की स्थिति में आस्तियों पर प्रतिलाभ सघनता ऋणात्मक मूल्यों की तरफ झुक गयी, जो यह संकेत दे रही थी कि कल्पित तनाव की स्थिति के अधीन घनात्मक प्रतिलाभ पाना ज्यादातर बैंकों के लिए संभव नहीं था। तथापि, बैंकिंग प्रणाली तर्कसंगत रूप से अपनी पूंजी निधि के साथ विपरीत अनुत्पादक आस्तियों के आघातों का मुकाबला करने के लिए सक्षम थी (सारणी 5.1)। मार्च 2012 के अंत में पूर्वानुमानित प्रणाली स्तर सीआरएआर 11.27 प्रतिशत पर रहा, जब कि अलग-अलग बैंक स्तर पर, केवल एक छोटे बैंक को छोड़कर सभी बैंकों ने सीआरएआर 9 प्रतिशत के ऊपर बनाये रखा। कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत मार्च 2011 के अंत के 2.34 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2012 के अंत में 2.92 प्रतिशत हो गया, जिसका कारण मुख्यतः यह धारणा थी कि 30 प्रतिशत पुनःसंचित मानक आस्तियां अनुत्पादक आस्तियों में परिवर्तित हो जाएंगी। आधार स्तर पर 150 प्रतिशत की अत्यंत सख्त ऋण गुणवत्ता के आघात के अंतर्गत जब अनुत्पादक आस्तियों का स्तर बढ़कर 6.33 प्रतिशत हो गया, उस समय प्रणाली स्तर पर सीआरएआर 9.33 प्रतिशत पर रहा। तथापि प्रणाली स्तर पर सीआरएआर आस्ति गुणवत्ता की अत्यंत खराब स्थिति में उस समय विपरीत रूप से प्रभावित हुआ जब अनुत्पादक आस्तियां 168 प्रतिशत से बढ़ गईं, जिसका प्रभाव 25 बैंकों पर पड़ा। इन बैंकों का कुल आस्तियों में 46.00 प्रतिशत का हिस्सा था जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे चला गया।

ब्याज दर जोखिम -इक्विटी की अवधि

इक्विटी का डयूरेशन उच्चतर हुए स्तर पर, यद्यपि... पूंजी पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं

5.10 वाणिज्य बैंकों की इक्विटी का डयूरेशन, जो ब्याज दरों में प्रति इकाई वृद्धि के कारण पूंजी में क्षरण की मात्रा दर्शाता है, उच्चतर स्तर पर बना रहा, हालांकि, हाल की तिमाहियों में इसका थोड़ा प्रभाव

चार्ट 5.6: तनाव की स्थिति का अनुरूपण सकल जोखिम संकेतकों की सघनता में परिवर्तन -आस्तियों पर प्रतिलाभ -मार्च 2011



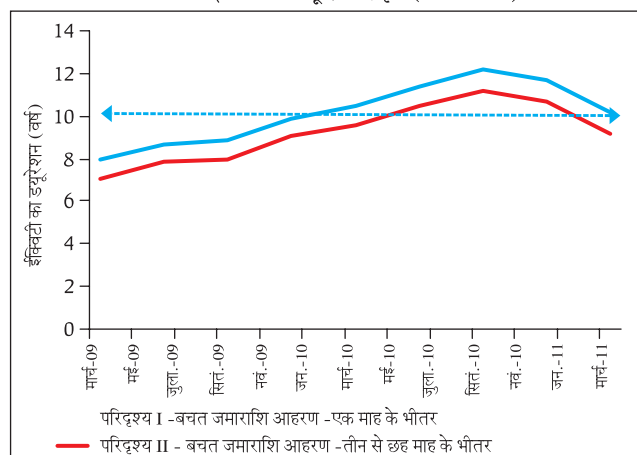
स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भार.रि.बैंक स्टाफ गणना

सारणी 5.1: पूर्वानुमानित तुलन-पत्र पर तनाव परीक्षण

	कुल अग्रिमों पर सकल अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत (%)	सीआरएआर (%)	उन बैंकों की संख्या, जिनका सीआरएआर 9% से नीचे चला जाता है	उन बैंकों की कुल आस्तियों का हिस्सा, जिनका सीआरएआर 9% से नीचे चला जाता है (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मार्च 2011	2.34	13.09	0	0
अनुमानित आधार स्तर: मार्च 2012				
आधार स्तर	2.92	11.27	1	0.15
अनुमानित आधार स्तर: मार्च 2012 अनुत्पादक आस्तियों में वृद्धि				
50 %	4.06	10.79	8	23.27
100 %	5.19	10.15	15	34.58
150 %	6.33	9.33	22	43.41
परिवर्तित तनाव परीक्षण: मार्च 2012 प्रारंभिक स्तर (प्रणाली स्तरीय सीआरएआर)				
168 %	6.74	9.00	25	46.00

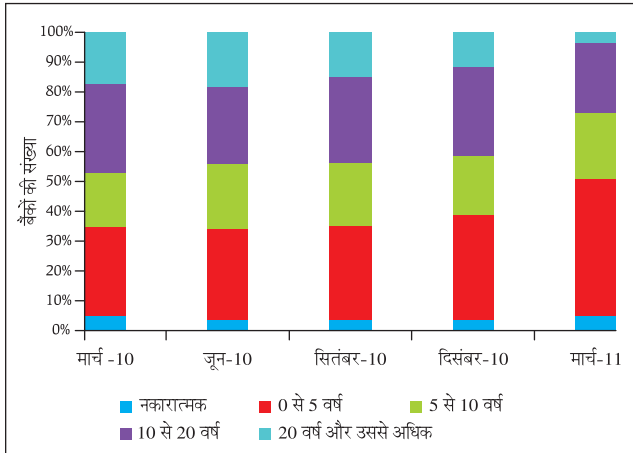
स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भार.रि.बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 5.7: इक्विटी का डयूरेशन - प्रवृत्ति (वाणिज्य बैंक)



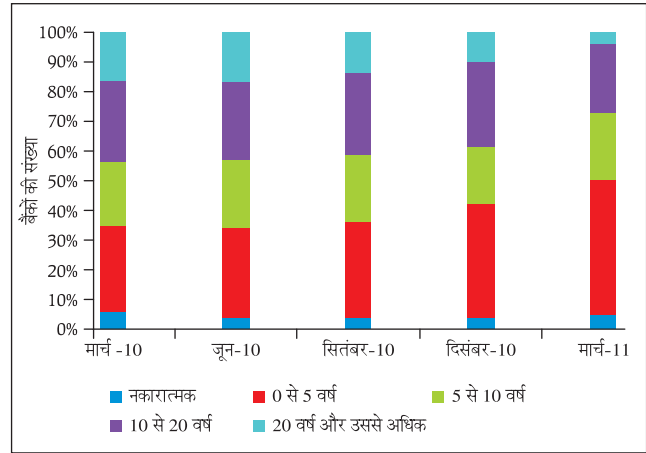
स्रोत: पर्यवेक्षी डाटा और भार.रि.बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 5.8: इक्विटी का ड्यूरेशन - बारंबारता वितरण (परिदृश्य I - बचत जमाराशि आहरण - एक माह के भीतर)



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 5.9: इक्विटी का ड्यूरेशन - बारंबारता वितरण (परिदृश्य II - बचत जमाराशियां आहरण - 3 से 6 माह के भीतर)



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

दृष्टिगत हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि ब्याज दर जोखिम का प्रबंध करने में बैंकों का कितना सक्रिय योगदान था (चार्ट 5.7)। साथ ही, बैंकों का उच्चतर ड्यूरेशन से निम्नतर ड्यूरेशन वाले कालखंड में अंतर्गत होना दर्शानेवाले के दो परिदृश्यों (चार्ट 5.8 और 5.9) के अंतर्गत इक्विटी के ड्यूरेशन का वितरण यह दर्शाता है कि सामान्य स्थितियों में ब्याज दर में वृद्धि के प्रति बैंकों की असुरक्षितता बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगी। अंततः, स्थिर आधार पर ईक्विटी ड्यूरेशन के निम्नतर स्तर को बनाये रखने की आवश्यकता बैंकों के लिए एक संभाव्य सहारा बन सकती है।

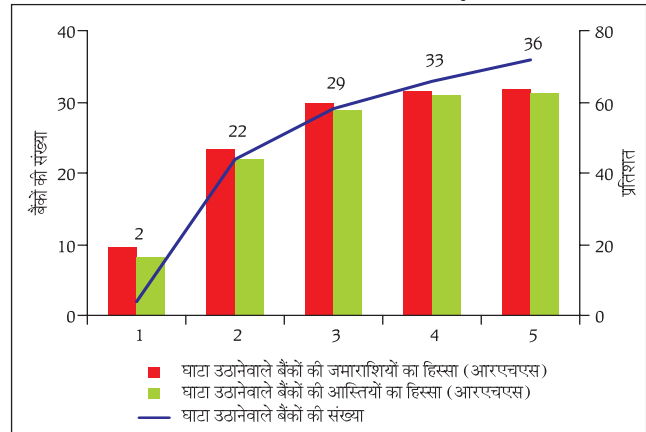
चलनिधि जोखिम

कोई संभाव्य तनाव मौजूद न होने पर भी सख्त दबाव के परिवेश में चलनिधि संबंधी अप्रकट बाधाएं

5.11 चलनिधि दबाव परीक्षण से यह पता चला है कि कुछ बैंकों के पास पहले दिन के आहरण को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि आस्तियां नहीं हैं। ऐसे बैंकों की संख्या मार्च 2010 की तुलना में मार्च 2011 में बढ़ गयी। तथापि, पांच दिन के अंत में दबाव परिदृश्य का मुकाबला करने में असमर्थ बैंकों की कुल संख्या मार्च 2010 में अधिक थी (चार्ट 5.10 और चार्ट 5.11) जो पहले के मूल्यांकन की तुलना में चलनिधि दबाव परीक्षण के अंतर्गत स्थिति में थोड़ा सुधार दर्शा रही थी।

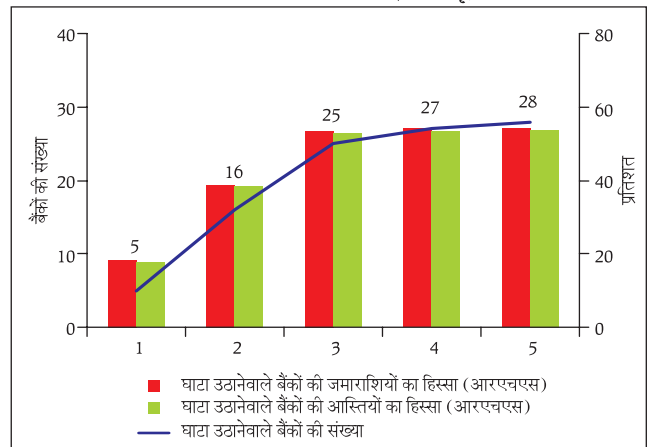
5.12 मार्च 2011 की तिमाही के लिए बैंकों की चलनिधि का विश्लेषण भी चलनिधि धारणीयता अनुपात का उपयोग करते हुए किया गया है, जिसे 1-14 दिनों के कालखंडवाली चलनिधि आस्ति/बहिर्वाह के रूप में परिभाषित किया गया है। दबाव परिदृश्य के अंतर्गत बहिर्वाह 3 के गुणक में बढ़ेगा ऐसा माना गया है। आधार स्तरीय परिदृश्य में केवल 5 बैंकों का चलनिधि धारणीयता अनुपात 1 से कम था, जो दबाव परिदृश्य के अंतर्गत बढ़कर 29 बैंकों तक हो गया। इन बैंकों को खरीदी हुई चलनिधि के माध्यम से बहिर्वाह पूरा करना पड़ता है जो

चार्ट 5.10: बैंकों की चलनिधि स्थिति मार्च 2010 का आधार स्तर और दबाव परिदृश्य



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 5.11: बैंकों की चलनिधि स्थिति मार्च 2011 का आधार स्तर और दबाव परिदृश्य



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

खर्चीला है। साथ ही, दबाव की स्थिति के अंतर्गत, गिरते हुए आत्मविश्वास के साथ इन बैंकों को चलनिधि की अत्यधिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जो प्रणाली के लिए असुरक्षितता का संकेत दर्शाता है। (चार्ट 5.12)।

समष्टि-दबाव परीक्षण: बहुचरीय प्रतिगमन⁷

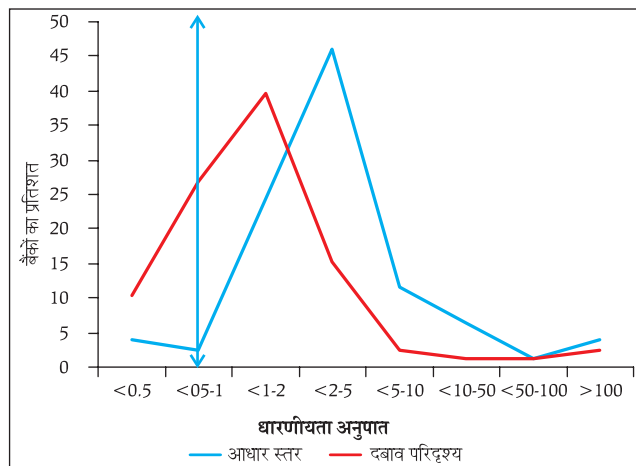
बैंकिंग क्षेत्र पर समष्टि आर्थिक आघातों का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है

5.13 समष्टि दबाव परीक्षण के लिए नमूने पर आधारित दृष्टिकोण में बहुचरीय समीकरण का इस्तेमाल किया गया जो समष्टि आर्थिक चरों को सीधे बैंक के निष्पादन की माप के साथ जोड़ता है। अनुत्पादक अग्रिमों पर समष्टि स्तरीय चरों के प्रभाव का अनुमान लगाया गया जिन्हें कुल अग्रिमों की तुलना में अनुत्पादक अग्रिमों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुत्पादक आस्तियों का अनुपात सुदृढ़ रूप से स्वतः सहसंबद्ध पाया गया। यद्यपि यह अनुपात कृषि और औद्योगिक सकल देशी उत्पाद वृद्धि दरों से ऋणात्मक रूप से संबंधित था, यह देखा गया कि वह अल्पावधि सांकेतिक ब्याज दर से धनात्मक रूप से और सकल देशी उत्पाद निर्यात अनुपात से विपरीत रूप से संबंधित है।

5.14 इस नमूने का इस्तेमाल आधार स्तर अनुत्पादक आस्तियों का अनुमान लगाने के लिए, और दबाव परिदृश्य के अंतर्गत एक वर्ष की दबाव परीक्षण जोखिम सीमा के साथ किया गया। आधार स्तर और दबाव परिदृश्य सारणी 5.2 और 5.3 में ब्योरेवार दी गयी मान्यताओं के आधार पर बनाये गये थे।

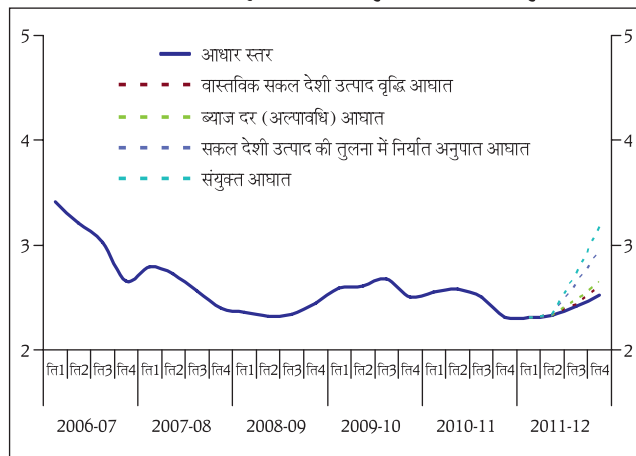
5.15 परिणाम (चार्ट 5.13 और 5.14) यह दर्शाते हैं कि पूर्वोक्त समष्टि दबाव परीक्षण नमूने में चुनिंदा समष्टि आर्थिक चरों का प्रभाव

चार्ट 5.12: चलनिधि धारणीयता अनुपात: मार्च 2011



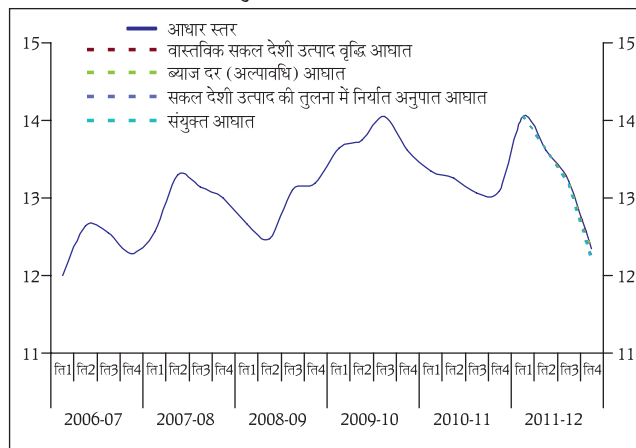
स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 5.13: दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत अनुत्पादक अग्रिमों का अनुपात



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 5.14: बैंकों का पूंजी पर्याप्तता अनुपात: दबाव परिदृश्य के अंतर्गत अनुत्पादक आस्तियों से अंतरित



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े और भा.रि.बैंक स्टाफ गणना

सारणी 5.2: आधार स्तरीय पूर्वानुमान				
पूर्वानुमान अवधि	वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि	सांकेतिक ब्याज दर (अल्पावधि)	सकल देशी उत्पाद की तुलना में निर्यात का अनुपात	
2011-12	Q1	8.00	7.00	14.40
	Q2	7.80	7.00	14.30
	Q3	7.30	7.00	15.40
	Q4	7.00	7.00	15.60

सारणी 5.3: दबाव परिदृश्य			
समय सीमा	आघात स्तर (आधार अंक)		
	वास्तविक सकल देशी उत्पाद वृद्धि आघात	सांकेतिक ब्याज दर (अल्पावधि) आघात	सकल देशी उत्पाद की तुलना में निर्यात अनुपात आघात
2011-12	- 150	+ 150	- 300

⁷ i) चिह्नाक एम.(2007)। इटोडक्शन टू एप्लाइड स्ट्रेस टेस्टिंग आइएमएफ वर्किंग पेपर डब्ल्यूपी/07/59
 ii) जुराज जेमेन, पावोल जुर्का (2008): मॅक्रो स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ स्लोवक बैंकिंग सेक्टर। वर्किंग पेपर 1/2008। नेशनल बैंक ऑफ स्लोवाकिया
 iii) मॅक्रो, सोर्ज (2004), स्ट्रेस टेस्टिंग फाइनेन्शियल सिस्टम्स: एन ओवर व्यू ऑफ करंट मेथडॉलॉजीज। बीआइएस वर्किंग पेपर्स सं. 165
 iv) फिलिपीन्स: फाइनेन्शियल सिस्टम स्टेबिलिटी एसेसमेंट अपडेट (2010) आइएमएफ कंट्री रिपोर्ट सं.10/90 अप्रैल 2010

बहुत उल्लेखनीय नहीं है। अतः विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत परिणाम यह बताते हैं कि समष्टि-आर्थिक आघातों से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को वास्तविक रूप से कोई खतरा नहीं है।

समष्टि -दबाव परीक्षण : वीएआर माडल

ब्याज दरों में वृद्धि के चलते ऋण हानियां हो सकती हैं

5.16 साहित्य की काफी सामग्री इस बात को रेखांकित करती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की समष्टिआर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों का या तो साथ-साथ या कुछ समय के बाद बैंकों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। यह भी संभव है कि वास्तविक आर्थिक गतिविधि पर बैंक अस्थिरता के फीड बैक प्रभाव मंदी के दौरान उतार-चढ़ाव में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न समष्टि आर्थिक आघातों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र की समुत्थानशक्ति का जायजा लेने के लिए वेक्टर स्वतः पक्षगमन (वीएआर) दृष्टिकोण अपनाया गया है। वीएआर माडल का लाभ यह है कि यह समष्टि आर्थिक चर तथा बैंकों के स्थिरता चर के बीच गतिविधि को पूरी तरह से उजागर करता है। यह आवश्यक फीडबैक प्रभाव को भी दिखलाता है।

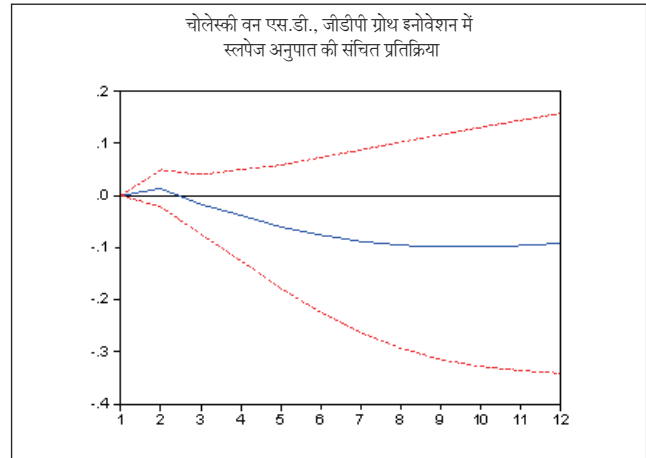
5.17 2001-02 के ति1 से 2010-11 के ति4 के बीच चार समष्टिआर्थिक चर, मुख्यतया, जीडीपी वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति, मांग मुद्रा दर तथा आरईईआर के संबंध में आंकड़ों का प्रयोग करते हुए यह कार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों की स्थिरता को दिखलाने के लिए, स्लिपेज अनुपात को भी ध्यान में रखा गया है।

5.18 अनुमानित वीएआर (2) के आधार पर, आवेग प्रतिक्रिया सृजित की गई। वृद्धि दर में नवोन्मेष, मुद्रास्फीति, मांग दर तथा आरईईआर में स्लिपेज अनुपात की संचित प्रतिक्रिया चार्ट 5.15 में दी गई है। यह देखा गया कि जीडीपी वृद्धि में एक मानक विचलन (सकारात्मक) आघात के कारण नौ तिमाहियों में स्लिपेज अनुपात में 0.10 की कमी हो जाएगी। हालांकि स्लिपेज अनुपात पर मुद्रास्फीति का प्रभाव सकारात्मक होता है, लेकिन यह प्रभाव बहुत मामूली सा था: मुद्रास्फीति में एक मानक विचलन (सकारात्मक) से दो तिमाहियों में स्लिपेज अनुपात में 0.02 की वृद्धि हो जाएगी। तथापि, ब्याज दर का न केवल स्लिपेज अनुपात पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है बल्कि यह प्रभाव स्थायी रहता है। मांग दर में एक मानक विचलन (सकारात्मक) से बारह तिमाहियों में स्लिपेज अनुपात में 0.22 की वृद्धि हो गई। हालांकि आरईईआर का स्लिपेज अनुपात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन आरईईआर में एक मानक विचलन (सकारात्मक) आघात से छह तिमाहियों में स्लिपेज अनुपात में 0.07 की कमी हो गई।

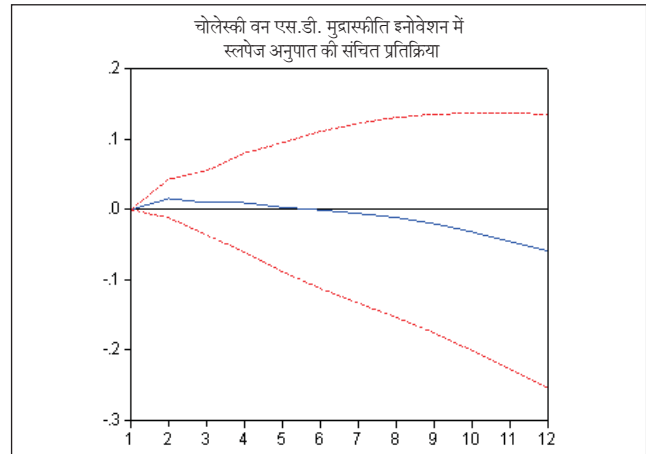
निम्नतर जीडीपी वृद्धि तथा उच्चतर मुद्रास्फीति और ब्याज दरों के दबाव परिदृश्यों में, एनपीए अनुपात और भी बढ़ जाएंगे

5.19 वीएआर के आवेग प्रतिक्रिया कार्य के आधार पर, सकल एनपीए अनुपात का अनुमान दो दबाव परिदृश्यों में लगाया गया और सारणी 5.4 में दिया गया है।

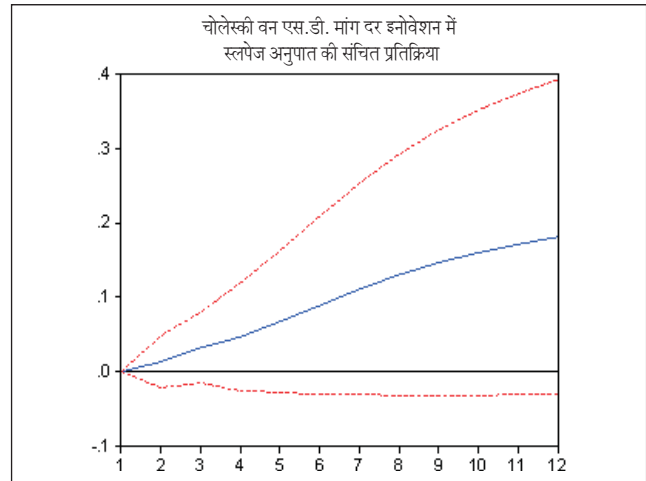
चार्ट 5.15: संचित इम्पल्स रिस्पॉन्स में घट-बढ़



चोलेस्की वन एस.डी. मुद्रास्फीति इनोवेशन में स्लिपेज अनुपात की संचित प्रतिक्रिया



चोलेस्की वन एस.डी. मांग दर इनोवेशन में स्लिपेज अनुपात की संचित प्रतिक्रिया



सारणी 5.4: दबावयुक्त परिस्थितियों में अनर्जक अग्रिम अनुपात

तिमाही	आधार स्तर	परिदृश्य I	परिदृश्य II
जून-11	2.53	2.53	2.53
सितं.-11	2.69	2.71	2.74
दिसं.-11	2.79	2.87	2.95
मार्च-12	2.95	3.13	3.31

परिदृश्य I: जीडीपी वृद्धि में 150 आधार अंकों की कमी होगी (नकारात्मक आघात), थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में 150 आधार अंकों की वृद्धि होगी, ब्याज दरों में 100 आधार अंकों की वृद्धि होगी और रुपये में 10 प्रतिशत की गिरावट होगी (नकारात्मक आघात)।

परिदृश्य II: जीडीपी वृद्धि में 250 आधार अंकों की गिरावट होगी (नकारात्मक आघात), थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में 250 आधार अंकों की वृद्धि होगी, ब्याज दर में 200 आधार अंकों की वृद्धि होगी और रुपये में 20 प्रतिशत की गिरावट होगी (नकारात्मक आघात)।

परिणामों से यह पता चला कि बेसलाइन परिदृश्य में, मार्च 2012 तक सकल एनपीए अनुपात लगभग 2.95 प्रतिशत होगा जो मार्च 2011 के आंकड़ों की तुलना में 64 आधार अंकों की वृद्धि दिखलाता है, जबकि अत्यधिक दबाववाली परिस्थितियों में, यह अनुपात और भी बढ़ कर लगभग 3.31 प्रतिशत हो जाएगा।

5.20 आवेग प्रतिक्रिया तथा वेरियन्स डीकंपोजिशन से यह देखा गया है कि सभी चारों चुनींदा समष्टि आर्थिक चर अर्थात् जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दर तथा विनिमय दर के बीच, बैंकों के स्लिपेज अनुपात पर ब्याज दर का प्रभाव सबसे अधिक (नकारात्मक) था। इसके महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे क्योंकि लगातार बनी रहने वाली मुद्रास्फीति दर से ब्याज दरें भी बढ़ेंगी जो बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी।

शहरी सहकारी बैंक

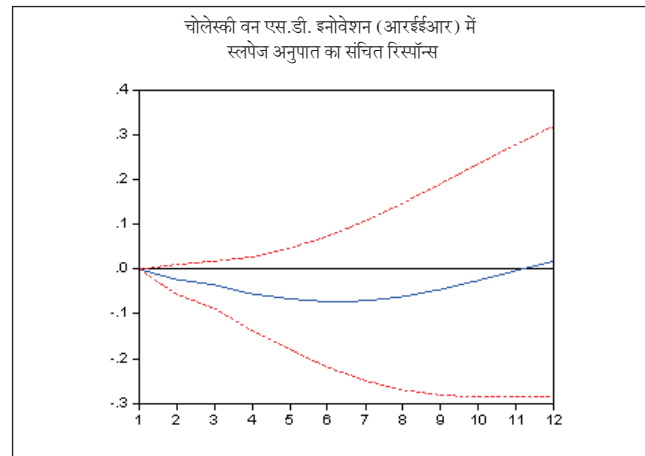
ऋण जोखिम बहुत चिंताजनक नहीं है

5.21 मार्च 2011 के अंत में आस्ति पोर्ट फोलियो का प्रयोग करते हुए अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों पर ऋण जोखिमों के संबंध में दबाव परीक्षण किए गए। ये परिणाम एकल फैक्टर संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित हैं। सीआरएआर पर आघातों के प्रभाव का तीन विभिन्न परिदृश्यों के अधीन परीक्षण किया गया। ये हैं (i) एनपीए अनुपात में 50 प्रतिशत की वृद्धि, (ii) एनपीए अनुपात में 100 प्रतिशत की वृद्धि तथा (iii) बैंकों द्वारा कोई लाभ अर्जित नहीं किया गया (चार्ट 5.16)। यह देखा गया कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक परिदृश्य I तथा परिदृश्य III में आसानी से आघात झेल सकते थे। लेकिन, परिदृश्य II में यह क्षेत्र कुछ दबाव में आ जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनडी -एसआई)

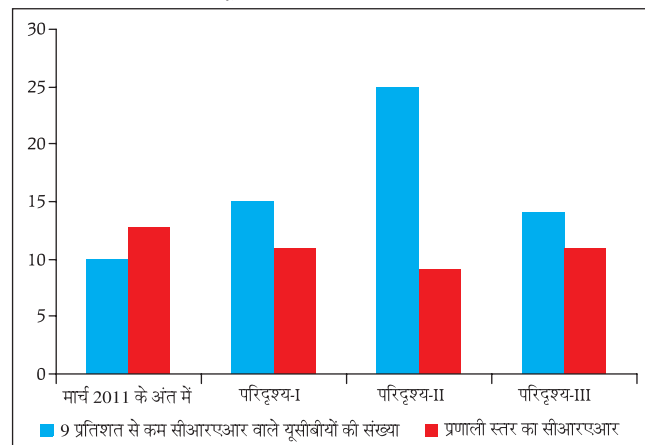
पूंजी पर ऋण जोखिम का प्रभाव बहुत अधिक नहीं

5.22 एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र के लिए ऋण जोखिम पर एक दबाव परीक्षण मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार दो परिदृश्यों के अधीन किया गया (i) सकल एनपीए दो गुणा बढ़ गए तथा



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े तथा रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणना

चार्ट 5.16: अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का दबाव परीक्षण: पूंजी स्थिति पर आघातों का प्रभाव



स्रोत: पर्यवेक्षी आंकड़े तथा रिजर्व बैंक के स्टाफ की गणना

(ii) सकल एनपीए वर्तमान स्तर से 5 गुणा बढ़ गए। यह देखा गया कि पहले परिदृश्य में किसी अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इस क्षेत्र में एनपीए के लिए अत्यधिक प्रावधान किया था जबकि दूसरे परिदृश्य में, यह देखा गया कि प्रावधान में कमी होने के बावजूद सीआरएआर पर प्रभाव नगण्य था क्योंकि इस क्षेत्र में 12 प्रतिशत के वांछित स्तर की तुलना में सीआरएआर का स्तर 37.1 प्रतिशत था।

निष्कर्ष टिप्पणी

5.23 संकट के समय सभी बैंकों में संकट निर्भरता बढ़ जाती है, जो यह दिखलाती है कि जेपीओडी तथा बीएसआई के अनुसार अलग-अलग जोखिमों की तुलना में प्रणालीगत जोखिम शीघ्रता से बढ़ते हैं। वैश्विक संकट के दौरान सभी बैंकों में संकट निर्भरता उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। हाल ही के वित्तीय संकट के दौरान बैंकों की सुरक्षा उच्च थी लेकिन बाद की अवधि में काफी कम हो गई। तथापि, हाल ही की अवधि में, भारतीय बैंकों की असुरक्षा में मामूली सी वृद्धि देखने में आई। किसी विशेष बैंक के संकट में होने पर कैस्केड संकेतक प्रणालीगत महत्व की गणना करता है, जो उस विशेष संस्था के संभावित “डौमिनो” प्रभाव का आभास देता है। संकट के बाद कुछ चुनींदा बैंकों का कास्केड प्रभाव उल्लेखनीय रूप से कम हो गया।

5.24 अनुमानित तुलन पत्र विश्लेषण से यह पता चला कि दबावयुक्त परिस्थितियों में, वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली किसी प्रतिकूल एनपीए आघात को यथोचित रूप से सहन कर लेगी क्योंकि उसके पास उच्चस्तरों की पूंजी है। डीओई विधि से ब्याज दर जोखिम से पता चला कि हाल ही की तिमाहियों में सुधार के चलते, डीओई उच्च स्तर पर बनी रही, जो ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करने में बैंकों की सक्रिय सहभागिता दिखलाती है। कड़े दबाव की स्थिति में, जब बाजार भावना दुर्बल होती है, कुछ बैंक अत्यधिक चलनिधि समस्या का सामना कर सकते हैं और असुरक्षित हो सकते हैं। विभिन्न परिदृश्यों में समष्टि दबाव परीक्षण के परिणाम से पता चला कि समष्टि आर्थिक आघात भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वीएआर क्रियाविधि से पता चला कि लगातार मुद्रास्फीति के वर्तमान परिवेश से ब्याज दरें बढ़ जाने के कारण बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। एनबीएफसी-एनडी-एसआई तथा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में ऋण जोखिम परीक्षण से पता चला कि विभिन्न परिदृश्यों में सीआरएआर पर प्रभाव चिंताजनक नहीं होगा।

अनुबंध: दबाव परीक्षण कार्यविधाएं

तिमाही निगरानी के एक भाग के रूप में, निम्नलिखित जोखिमों के संबंध में दबाव परीक्षण किए गए:

- ऋण जोखिम, जो पूरे ऋण पोर्टफोलियो के लिए एनपीए पर जोर देते हुए पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव का अनुमान लगाता है। यह परिदृश्य विश्लेषण, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन माडल तथा वेक्टर स्वतः पक्षगमन दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए किया गया।
- प्रणाली तथा अलग-अलग बैंक स्तरों पर “डीओई” कार्यविधि का प्रयोग करते हुए ब्याज दर जोखिम जो किसी ब्याज आघात के लिए तुलन-पत्र के आर्थिक मूल्य में मूल्यहास का अनुमान लगाता है।
- भिन्न परिदृश्यों का प्रयोग करते हुए चलनिधि जोखिम, जिसमें प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण विश्वास की कमी के चलते अचानक जमाराशियां निकाल लेना शामिल है।

उपर्युक्त आघातों के प्रति वाणिज्य बैंकों की समुत्थान शक्ति का अध्ययन उपर्युक्त तीन परिदृश्यों में किया गया है। इस विश्लेषण में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल किए गए थे। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण जोखिम पर एकल फेक्टर संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया। दबाव परीक्षणों के लिए अपनाई गई कार्यविधि पहली एफएसआर तथा दूसरी एफएसआर के लिए किए गए दबाव परीक्षणों के अनुरूप है तथा कुछ कार्यविधियों में कुछ सुधार किया गया है।

ऋण जोखिम - परिदृश्य विश्लेषण

परिदृश्य विश्लेषण के लिए, बैंकों के तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते का मार्च 2012 के लिए अनुमान लगाया गया है। बैंकों के अनुमानित वित्तीय विवरणों पर संभावित आघात लगा कर प्रणाली का आकलन किया जाता है। मार्च 2011 के लिए पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण समग्र स्तर तथा अलग-अलग बैंक स्तर पर किया गया है। अनुमानित बेसलाइन परिदृश्य में, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि संघटकों के लिए वृद्धि का अनुमान कंपाउंड वृद्धि दरों तथा मार्च 2011 अनुपातों को लगा कर तथा उन पर प्रतिकूल प्रभाव फैक्टर लगा कर किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि विनियामक रिजर्व खाते में लाभ के कम से कम पच्चीस प्रतिशत न्यूनतम अंतरण के बाद विनियामक पूंजी वृद्धि न्यूनतम पर रहेगी। वर्ष 2011-12 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य में प्रस्तावित प्रावधान आवश्यकताओं में वृद्धि के अतिरिक्त, यह भी माना गया है कि बकाया पुनर्गठित मानक आस्तियों का 30 प्रतिशत एनपीए हो जाता है। बेसलाइन यह मानता है कि वर्तमान ऋण हानि प्रावधान कवरेज अनुपात बने रहेंगे। बेसलाइन परिदृश्य में इस प्रकार प्राप्त किये गये परिणाम को प्रत्येक बैंक के लिए समग्र ऋण पोर्टफोलियो में एनपीए में 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तथा 150 प्रतिशत की वृद्धि के अधीन लाया गया है। इन आघातों के प्रणालीगत प्रभाव का भी आकलन किया गया है।

ब्याज दर जोखिम

दबाव परीक्षणों में डीओई या नेट वर्थ डयूरेशन दृष्टिकोण से ब्याज दरों में यूनिट वृद्धि होने के कारण पूंजी में हास की गणना में सहायता मिल सकती है। यह विश्लेषण बैंकों के पोर्टफोलियो के तुलन पत्र में ब्याज दर संवेदी मदों तथा तुलन पत्र से इतर मदों को ध्यान में रखता है। कुछ सीमाओं के अधीन, डीओई ब्याज दर जोखिम का आकलन करता है तथा जोखिम पर आधारित पूंजी के आकलन में अग्रसर होने में सहायता करता है। इक्विटी की अवधि जितनी अधिक होगी, ब्याज दर जोखिम उतना ही अधिक होगा तथा तदनुसार पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी।

- डयूरेशन गैप = (डयूरेशन आफ ऐसेट्स * टोटल ऐसेट्स - डयूरेशन आफ लायबिलिटीज * टोटल लाइबिलिटीज) / टोटल ऐसेट्स
- डयूरेशन आफ इक्विटी = डयूरेशन गैप * लीवरेज रेशो
= (डयूरेशन आफ ऐसेट्स * टोटल ऐसेट्स - डयूरेशन आफ लायबिलिटीज * टोटल लाइबिलिटीज) / कैपिटल एण्ड रिजर्वज
- पूंजी निधियों की समाप्ति के लिए वांछित ब्याज दर आघात = मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन / डीओई = 100 / डीओई

इस दृष्टिकोण के अधीन, किसी बैंक के पोर्ट फोलियो की इक्विटी की अवधि की दो परिदृश्यों में गणना की गई है। यह माना गया कि बचत जमा राशियां पहले समय बैंड अर्थात् 1 से 28 दिनों (परिदृश्य I) में आहरित की गईं: यह माना गया कि बचत जमाराशियां 3 से 6 महीने के बैंड में (परिदृश्य II) आहरित की गईं। समय बैंडवार दर संवेदी देयताएं तदनुसार दो परिदृश्यों के अधीन समायोजित की गई हैं।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव परीक्षणों का उद्देश्य किसी बैंक द्वारा बाहरी चलनिधि सहायता के बिना अप्रत्याशित चलनिधि निकास के दबाव को सह सकने की क्षमता को जांचना है। इसके लिए तय परिस्थितियाँ बहुत कठोर अवधारणाओं पर आधारित हैं, जो कि अधिक से अधिक प्रतिकूल हो सकती हैं। यह विश्लेषण मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार किया गया है।

यह परिदृश्य जमाकर्ताओं के विश्वास में अचानक कमी के कारण अप्रत्याशित जमा राशि निकासी के विभिन्न चल अनुपातों (जमा राशियों के प्रकार के अनुसार) को दर्शाता है तथा उन्हें अदा करने के लिए उपलब्ध अस्तियों की पर्याप्तता को आंकता है। यह माना गया है कि जमा प्रवाह पांच दिनों तक जारी रहेगा।

- इसका उद्देश्य किसी प्रकार का बाहरी सहयोग लिए बिना उपलब्ध चल अस्तियों को बेचकर जमा राशियों की अप्रत्याशित निकासी को पूरा करने की बैंक की क्षमता को जांचना है।
- जमा राशियों को तीन प्रकारों में बांटा गया है, चालू जमा राशियाँ, बचत जमा राशियाँ और आवधिक जमा राशियाँ।
- चलनिधि में नकद राशि, रिजर्व बैंक के पास जमा अतिरिक्त सीआरआर, एक साल के भीतर प्राप्त होने वाले अन्य बैंक के पास जमा राशि तथा 1 साल के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश।
- दबाव परिस्थितियों में, जमा राशियों की कुल अप्रत्याशित निकासी को निम्नलिखित अनुपात में संपन्न माना जाता है:
 - चालू जमा राशियाँ- 1-14 दिनों की अवधि में चालू जमा राशियों से रिपोर्ट किए गए निकास का तीन गुणा।
 - बचत जमा राशियाँ- 1-14 दिनों की अवधि में बचत जमा राशियों से रिपोर्ट किए गए निकास का तीन गुणा।
 - आवधिक जमा राशियाँ- 1-14 दिनों की अवधि में आवधिक जमा राशियों से रिपोर्ट किए गए निकास का दो गुणा।
- यह माना गया है कि बैंक चल अस्तियों को बेचकर अधिक दबाव युक्त निकासी को पूरा करे।
- निवेशित को उनके बाजार मूल्य में 10 प्रतिशत की कटौती के बाद बेचा जाता है।
- दबाव परीक्षण स्थिर विधि से किया गया है।

चलनिधि सहनीयता अनुपात = चलनिधि अस्तियाँ / 1-14 दिनों की अवधि में निकासी

समष्टि दबाव परीक्षण- बहुभिन्नरूपी निकासी

बैंकों के लचीलेपन का पता लगाने के लिए, जमा जोखिम का मॉडल समष्टि अर्थशास्त्र चरों के कार्यों के आधार पर तैयार किया गया। वाणिज्यिक बैंकिंग के लिए इसकी संपूर्णता में कुल अग्रिम के साथ अनर्जक अग्रिमों के अनुपात का विश्लेषण किया गया। इस विकसित मॉडल की मदद से अगली कुछ तिमाहियों के लिए एनपीए अनुपात का अनुमान लगाया गया। इसमें आधारभूत तथा दबाव परिदृश्य दोनों को शामिल किया गया। वर्तमान ऋण हानि के प्रावधान को यथावत रखते हुए एनपीए के अनुमानित मूल्य के आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात निकाला गया। इस पर विस्तृत वर्णन वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - दिसंबर 2010 में दिया गया है।

समष्टि दबाव परीक्षण- वीएआर मॉडल

अनेक साहित्यिक कृतियों से यह तथ्य सामने आता है कि अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन से बैंकों के निष्पादन पर तत्काल अथवा कुछ समय पश्चात असर पड़ता है। यह भी संभव है कि बैंकों की अस्थिरता का प्रभाव वास्तविक आर्थिक गतिविधियों पर पड़े और इससे, विशेष रूप से मंदी के समय, उतार-चढ़ाव में और तेजी आ जाए। अतः विभिन्न समष्टि अर्थशास्त्रीय उथल-पुथल का बैंकिंग स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए होगार्थ, सोरेन्सेन और जिकोनो (2005), मार्कुसी और क्वालियारिलो (2005) और रिनाटो फिलोसा (2007) द्वारा विकसित वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव (वीएआर) पद्धति को अपनाया गया है। वीएआर मॉडल का लाभ यह है कि यह समष्टि अर्थशास्त्रीय परिवर्तनों तथा बैंकिंग स्थिरता परिवर्तनों के बीच क्रिया को पूरी तरह समाहित करता है। इसमें सम्मिलित प्रतिक्रियात्मक कदमों के प्रभाव को शामिल किया जाता है। अंकन पद्धति में पी(वीएआर(पी)) क्रम के लिए माध्य -समायोजित वीएआर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है-

$$Y_t = A_1 Y_{t-1} + \dots + A_p Y_{t-1} + u_t; t=0,1,2,3, \dots$$

जहां, $y_t = y_{1t} \dots y_{kt}$ समय t पर वेरिएबल का $(K \times 1)$ वेक्टर है $A_1 (i=1,2,\dots,P) (K \times K)$ नियत को एफ्रीशिएंट मैट्रिक्स है तथा $U_t = (U_{1t} \dots U_{kt})$ K डायमैन्शनल वाइट नोइस या इनोवेशन प्रोसेस है।

यह प्रयोग 2001-02 की पहली तिमाही से 2010-11 की तीसरी तिमाही तक चार समष्टि आर्थिक वेरिएबल अर्थात् जीपी की वृद्धि, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मांग मुद्रा दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संबंध में तिमाही आंकड़ों का उपयोग करते हुए किया गया है। तथापि, बैंकों की स्थिरता का आकलन करने के लिए स्लिपेज अनुपात को ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, मांग दर, आरईईआर तथा स्लिपेज अनुपात का आवधिकता की दृष्टि से परीक्षण किया गया और चूंकि मांग दर तथा स्लिपेज अनुपात में आवधिकता पाई गई इसलिए इन वेरिएबलों को आवधिकता के लिए समायोजित किया गया।

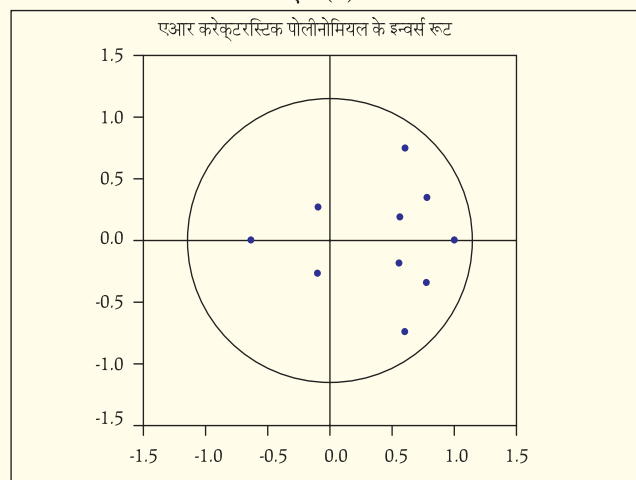
संवर्धित डिफी फुलर टेस्ट के आधार पर वेरिएबल की स्थिरता का परीक्षण किया गया। यह शून्य परिकल्पना कि उक्त वेरिएबल में यूनिट रूट है स्लिपेज अनुपात, मुद्रास्फीति, मांग दर तथा आरईईआर के लिए 5 प्रतिशत के उल्लेखनीय स्तर पर तथा वृद्धि के लिए 10 प्रतिशत के उल्लेखनीय स्तर पर नकारात्मक पाया गया इसलिए सभी चुनिंदा वेरिएबल स्थिर पाए गए।

सारणी: यूनिट-रूट परीक्षण

	स्लिपेज अनुपात	वृद्धि	मुद्रास्फीति	मांग दर	आरईईआर
एडीएफ टेस्ट सांख्यिकी	-3.102467	-2.860975	-5.486368	-3.927392	-3.291593
पी -वैल्यू	0.0350	0.0595	0.0001	0.0044	0.0227

न्यूनतम सूचना मानदंड तथा अन्य निदानों के आधार पर वीएआर के यथोचित क्रम का पता लगाया गया और यह पाया गया कि यह 2 था। तदनुसार, क्रम 2 के वीएआर (वीएआर (2)) का अनुमान लगाया गया तथा ए आर करेक्टरस्टिक पोलिनोमियल के रूट के आधार पर मॉडल की स्थिरता की जांच की गई। चूंकि सभी रूटों को यूनिट सर्किल के भीतर पाया गया, इसलिए यह देखा गया कि यह चयनित मॉडल स्थिरता संबंधी शर्त को पूरा कर रहा था।

चार्ट: वीएआर(2) की स्थिरता



शहरी सहकारी बैंक - ऋण जोखिम

मार्च 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबीज) के आस्ति पोर्टफोलियों का प्रयोग करते हुए ऋण जोखिम के संबंध में उनके दबाव परीक्षण किये गए। ये परीक्षण एकल फैक्टर सेन्सिटिविटी विश्लेषण में आधार पर किए गए। तीन विभिन्न परिदृश्यों के अधीन सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। यह परिदृश्य निम्नानुसार है:

परिदृश्य I:

- प्रयुक्त आघात: कुल एनपीए में 50 प्रतिशत वृद्धि
- प्रावधान आवश्यकता में 50 प्रतिशत वृद्धि
- पूंजी में (टियर I और II) अतिरिक्त प्रावधान करके कमी

परिदृश्य II:

- प्रयुक्त आघात: कुल एनपीए में 100 प्रतिशत वृद्धि
- प्रावधान आवश्यकता में 100 प्रतिशत वृद्धि
- पूंजी में (टियर I और II) अतिरिक्त प्रावधान करके कमी

परिदृश्य III

- प्रयुक्त आघात: प्रतिकूल समष्टि आर्थिक परिस्थितियों के कारण सभी अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा हानि या शून्य लाभ
- पूंजी (टियर I और II) में उन बैंकों के संबंध में लाभ की राशि कम कर दी गई जिन्होंने लाभ होने की सूचना दी थी। (यदि हानि की सूचना दी गई है तो कोई परिवर्तन नहीं।)

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनडी-एसआई) - ऋण जोखिम

मार्च 2010 के अंत की स्थिति के अनुसार आस्ति पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हुए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण किए गए। यह परीक्षण एकल फैक्टर संवेदनशीलता विश्लेषण आधार पर किए गए। दो विभिन्न परिदृश्यों के अधीन सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन किया गया। परिदृश्य में यह माना गया कि एनपीए में वर्तमान स्टाक में 200 तथा 500 % की वृद्धि होगी। एनपीए में अनुमानित वृद्धि का वितरण उप मानक, संदिग्ध तथा हानि श्रेणियों में उसी अनुपात में किया गया जैसा कि एनपीए के वर्तमान स्टाक में था। अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकता का समायोजन वर्तमान पूंजी स्थिति से किया गया।